



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 1985/ज्येष्ठ 11, 1907

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 1985/JYAISTHA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the
Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 1985

सूचना

कां० 2300.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री आर. एन. झुंजुनवाला एडवोकेट और मोलिसिटर सी/ओ खैतान अन्ड को० 9, पुराना पोस्ट आफिस गली, मालवी मजिल, कलकत्ता-700001, ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया जा रहा है कि उसे समस्त भारत व्यवसाय करने के लिए नोटरी रूप में नियुक्त किया जाए।

2 उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में भेजे पाये भेजा जाए।

[सं० 5(8)/85-न्या]

एस गुप्ता, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 15th May, 1985

NOTICE

S.O. 2300.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri R. N. Jhunjhunwala, Advocate and Solicitor C/o Khaitan, Co. 9, Old Post Office Street, 7th Floor, Calcutta-700001 for appointment as a Notary to practise in whole of India.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(8)/85-JudI.]

S. GOOPTU, Competent Authority

विरत मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1985

आयकर

कां० 2301.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) का अनुसरण करते हुए,

केन्द्रीय सरकार एन० 4 में उल्लिखित अधिभूता (सि-सूचनाओं) का अधिलेखन करन हुए, नीचे स्तम्भ 3 में उल्लिखित कर वसूली अधिकारियों के स्थान पर, नीचे स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी (अधिकारियों) की शक्तियां या प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करनी है

अ० उन व्यक्तियों के उन कर वसूली अधि- अधिलेखन किए जाने स० नाम जिन्हें कर वसूली कारी (अधिकारियों) वाली पुरानी अधि- अधिकारी (अधिकारियों) के नाम जिनके स्थान सूचना की शक्तियां की शक्तियों का प्रयोग पर स्तम्भ 2 में और तारीख करने के लिए प्राधिकृत उल्लिखित व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाना है।

1	2	3	4
संबंधी	संबंधी		
1. एम० बी० लक्ष्मीकान्थर	बी० बी० बालसुब्रह्मण्यन	सं० 4813 [फा० सं० 398/11/81-आ० क० (ब०) दिनांक 17-7-82]	
2. बी० के० बालकृष्णन	सी० वेकटेश्वरन्तु	सं० 5525 [फा० सं० 398/18/83-आ० क० (ब०) दिनांक 14-12-83]	
3. एम० अनन्तरामन	एम० मुनियंदी	सं० 5251 [फा० सं० 398/18/83-आ० क० (ब०) दिनांक 4-6-83]	
4. टी० सुब्रह्मण्यम	बी० वेकटकृष्णन	सं० 5249 [फा० सं० 398/18/83-आ० क० (ब०) दिनांक 4-6-83]	
5. डेविड राजकुमार मोसिस	के० एस सुन्दरराजन	सं० 5523 [फा० सं० 398/11/83-आ० क० (ब०) दिनांक 14-12-83]	
6. बी० श्रीनिवासन	आर० गणेश	सं० 5253 [फा० सं० 398/18/83-आ० क० (ब०) दिनांक 4-6-83]	
7. पी० सी० प्रदीपकुमार	बी० सुर्यनारायणन	सं० 4536 [फा० सं० 398/11/83-आ० क० (ब०) दिनांक 24-3-82]	
8. के० मीनाक्षीसुन्दरम	एस. जानकीरामन	सं० 566 [फा० सं० 398/11/83-आ० क० (ब०) दिनांक 31-1-84]	
9. एम० सी० बालसुब्रह्मण्य गुप्ता	पी० राजाराम	सं० 4809 [फा० सं० 398/11/81-आ० क० (ब०) दिनांक 17-7-82]	

1	2	3	4
10. एस राधाकृष्णन	एस० रिदटो मावयन	सं० 5255 [फा० सं० 398/18/83-आ० क० (ब०) दिनांक 4-6-83]	

3 यह अधिसूचना तत्काल लागू होगी और जहाँ तक स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों का संबंध है कर वसूली अधिकारियों के रूप में उनके कार्यभार सभालन की तारीख में लागू होगी।

[सं० 6181/फा० सं० 398/8/83-आ० क० (ब०)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 10th April, 1985

INCOME-TAX

S.O. 2301.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises the persons mentioned below column 2, being the Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer(s) under the said, Act in place of the Tax Recovery Officers mentioned below in column 3 in supersession of the Notification(s) mentioned below in column 4 :

S. No.	Name of the persons to be authorised to exercise powers of Tax Recovery Officer(s)	Name of Tax Recovery Officer(s) in place of whom the persons mentioned in column 2 are to be authorised.	Old Notification No and date to be superseded.
1.	2.	3.	4.
S/Shri	S/Shri		
1.	M.V. Lakshmi-kanthar	V.V. Bala-subramanian	No. 4813 [F. No. 398/11/81-IT (B) dt. 17-7-82.]
2.	V.K. Bala, krishnan	C. Venkateswaralu	No. 5525 [F. No. 398/18/83-IT (B) Dt. 14-12-83.]
3.	S. Anantharaman	M Muniyandi	No. 5251 [F. No. 398/18/83-IT (B) dt. 4-6-83.]
4.	T. Subramanian	V. Venkata-krishnan	No. 5249 [F. No. 398/18/83-IT (B) dt. 4-6-83.]
5.	David Rajkumar Moses	K.S. Sundararajan	No. 5523 [F. No. 398/18/83-IT (B) dt. 14-12-83.]
6.	V. Srinivasan	P. Ganesh	No. 5253 [F. No. 398/18/83-IT (B) dt. 4-6-83.]
7.	P.C. Alexander	V. Suryanarayana-nan	No. 4536 [F. No. 398/18/83-IT (B) dt. 24-3-82.]

1	2	3	4
8.	H. M. cnakshi-sundaram	S. Janakiraman	No. 5601 [F. No. 398/11/83-IT (B) dt. 31-1-1984.]
9.	M.C. Bala-subramania Gupta	P. Rajaram	No. 4809 [F. No. 398/11/81-JT (B) dt. 17-7-1982.]
10.	A. Radha-krishnan	S. Britto Madhavan	No. 5255 [F. No. 398/18/83-IT (B) dt. 4-6-1983.]

(2) उक्त अनुसूची में अपीलीय महायुक्त आयुक्त, रेंज-XVIII कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के सामने निम्नलिखित को मद संख्या

(3) के रूप में जोड़ा जाएगा.—

“3 हुगली”

यह अधिसूचना 1-4-1985 में लागू होगी।

[सं. 6177 (फा. सं. 261/1/84-आ. क. न्या.)]

कल्याण चन्द, प्रवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 26th March, 1985

INCOME-TAX

S.O. 2303.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the schedule appended to the Board's notification No. 607 (F. No. 261/1/84-ITJ) dated 19-12-84.

1. In the said schedule against the jurisdiction of AAC, Range Asansol item No. (8) “Hooghly” shall be deleted and item No. 9 shall be renumbered as item No. ‘8’.

2. In the said schedule against the jurisdiction of AAC, Range-XVIII, Calcutta the following shall be added as item No. (3).

“3 Hooghly”

This notification shall take effect from 1-4-85.

[No. 6177/F. No. 261/1/84-ITJ]

KALYAN CHAND, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 10 मई, 1985

फा. आ. 2304.—भारतीय स्टेट बैंक (अनुसूची बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से, एतद्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के उप सचिव श्री यशपाल सेठी को धोमनी ताजवर रहमान साहनी के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंदोर के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[संख्या एक. 9/24/85-बी. प्रो.-1]

एस. एस. हसूरकर, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 10th May, 1985

S.O. 2304.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (1) of section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the Central Government, in consultation with the State Bank of India, hereby nominates Shri Y. P. Sethi, Deputy Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi to be a Director of the State Bank of Indore vice Smt. Tajwar Rahman Sahni.

[No. F. 9/24/85-BO. 1]

S. S. HASURKAR, Director

नई दिल्ली, 10 मई, 1985

फा. आ. 2305.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

2. This notification shall come into force with immediate effect and in so far as persons mentioned in column 2 from the date(s) they take over charge(s) as Tax Recovery Officers.

[No. 6184/F.No. 398/8/85-IT (B)]

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1985

आयकर

फा. आ. 2302.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उप-खंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 2 मार्च, 1985 की अधिसूचना सं. 5114 (फा. सं. 398/32/83-आ. क. (ब.)) का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री ए. के. मोंगा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री ए. के. मोंगा द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 6206/फा. सं. 398/4/85-आ. क. (ब.)]

बी. ई. अलेक्जेंडर, प्रवर सचिव

New Delhi, the 25th April, 1985

INCOME-TAX

S.O. 2302.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 5114 [F. No. 398/7/83-IT(B)] dated the 2-3-83, the Central Government hereby authorises Shri A. K. Monga being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2 This Notification shall come into force with effect from the date Shri A. K. Monga takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6206/F. No. 398/4/85-IT(B)]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1985

आयकर

फा. आ. 2303.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा बोर्ड के दिनांक 19-12-84 की अपूर्वा सं. 6071/फा. सं. 261/1/84-आ. क. न्या.) में संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :

(1) उक्त अनुसूची में अपीलीय महायुक्त आयुक्त, रेंज आसनसोल के क्षेत्राधिकार के सामने मद सं. (8) “हुगली” का हटा दिया जाएगा और मद संख्या 9 की मद संख्या “8” के रूप में पुनर्स्थापित किया जाएगा।

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एस. एल. बसेर को मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी (बिहार) का अध्यक्ष नियुक्त करती है और 31-3-1985 को शुरू होने वाली तथा 31-3-1988 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एस. एल. बसेर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 2-56/82-आर. आर. बी.]

New Delhi, the 10th May, 1985

S.O. 2305.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. L. Baser as the Chairman of the Madhubani Kshetriya Gramin Bank, Madhubani (Bihar) and specifies the period commencing on the 31-3-1985 and ending with the 31-3-1988 as the period for which the said Shri S. L. Baser shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-56/82-RRB]

का. आ. 2306—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री के. एन. सिंह को छत्तसाल ग्रामीण बैंक, उरई का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 6-4-1985 से प्रारम्भ होकर 30-4-1988 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री के. एन. सिंह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 2-1/85-आर. आर. बी.]

ज. वा. मीरचन्दानी, निदेशक

S.O. 2306.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Dr. K. N. Singh as the Chairman of the Ghatrasal Gramin Bank, Orai and specifies the period commencing on the 6-4-1985 and ending with the 30-4-1988 as the period for which the said Dr. K. N. Singh shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-1/85-RRB]

C. W. MIRCHANDANI, Director

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1985

आदेश

का. आ. 2307:—मैसर्स चौगले इंडस्ट्रीज लि., मोरमुगोवा हार्बर, गोवा को फालतू पुर्जों के आयात के लिए केवल 97,508/- रुपए का एक आयात लाइसेंस सं. पी/एफ/2030857, दिनांक 25-10-83 दिया गया था।

2. अब फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के गम पंजीकृत कराए बिना ही खो गई/अव्ययनस्थ हो गई है। अब फर्म सहमत है और बचन देती है कि यदि बाद में मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति मिल गई तो इस कार्यालय को रिक्ताई के लिए लौटा देगी।

3. अपने तर्क के समर्थन में, मैसर्स चौगले इंडस्ट्रीज लि., गोवा ने 1984-85 की आयात-निर्यात प्रियाधिशि हैडबुक के अध्याय 15 के पैरा 353 के अनुसार यथा अपेक्षित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोद्विभाजित संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं. पी/एफ/2030857, दिनांक 25-10-83 की मूल मुद्रा-विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है और विदेश देना है कि आवेदक को अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी

की जाए। मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्वारा रद्द की गई समझी जाती है।

4. आयात लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[का. सं. 6-सी/स्पेयर्स/एएम-83/जीएसएस]

पॉल बेक, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
छूने मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 25th March, 1985

ORDER

S.O. 2307.—M/s. Chowgule Industries Ltd., Mormugoa Harbour, Goa was granted an Import Licence No. P/F/2030857 dated 25-10-83 for Rs 97,508 only for the import of spares.

2. The firm have now requested for issue of Duplicate Custom Purpose Copy of the above licence on the ground that the original Custom Purposes Copy has been lost/misplaced without having being registered with any Custom Authority. Now the firm agrees and undertakes to return the original Custom Purpose Copy, if traced later on to this office for record.

3. In support of their contention, M/s. Chowgule Industries Ltd., Goa have filed an affidavit as required in terms of Para 353 of Chapter XV of Hand Book of Import-Export Procedures for 1984-85. The undersigned is satisfied that the original Exchange Control Copy of Import Licence No. P/F/2030857 dated 25-10-83 has been lost and directs that duplicate Custom Purpose Copy may be issued to the applicant. The original custom purpose copy is hereby treated as cancelled.

4. The duplicate Custom Purposes Copy of the Import Licence is being issued separately.

[F. No. 6-C/Spares/AM-83/GLS]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of

Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Exports

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 1985

का. आ. 2308:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाय अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अधिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा अधि-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. राजस्व 114/84, तारीख 17 अगस्त, 1984 का निरीक्षण मैट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राजस्व अनुभाग, धरभंगा हाउस, रांची-834001 (बिहार) के कार्यालय में या उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में प्रेषण कोयला नियंत्रक, 1-काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हिमबद्ध कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में त्विष्ट सभी नक्शों, चाटों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी, मैट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, धरभंगा हाउस, रांची-834001 (बिहार) को भेजेगा।

अनुसूच
उत्तर बुंदू ब्लॉक
दक्षिण करणपुरा कोयला क्षेत्र
जिला हजारीबाग (बिहार)

पूर्वक्षेत्र के लिए अधिसूचित भूमि

ब्लॉक	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
क	बमारिया	मांडू	38	हजारीबाग	179.00	भाग
	बुंदू	"	35	"	320.00	भाग
	टोंग	"	135	"	224.00	भाग
ख	चोरधारा या खरपतनगर	रामगढ़	55	हजारीबाग	93.50	भाग

कुल क्षेत्र :- 816.50 एकड़ (लगभग)

या 330.42 हेक्टर (लगभग)

ब्लॉक "क" का सीमा वर्णन :

क-ख रेखा बमारिया ग्राम से दामोदर नदी के उत्तर सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है।

ख-ग रेखा, बुंदू ग्राम से, दामोदर नदी के पूर्वी सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है।

ग-घ रेखा, बुंदू ग्राम से होकर जाती है (जो बुंदू ग्राम में 270 एकड़ के अधिसूचित क्षेत्र की सम्मिलित सीमा का भाग बनाती है)

घ-ङ-च रेखा, बुंदू ग्राम से होकर और बुंदू और टोंगी ग्रामों की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है (जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित 102 एकड़ क्षेत्र की सम्मिलित सीमा का भाग बनाती है)।

च-छ रेखा, टोंगी ग्राम से होकर जाती है (जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र 102 एकड़ की सम्मिलित सीमा का भाग बनाती है)।

छ-ज रेखा, टोंगी और मिरका ग्रामों की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है।

ज-झ रेखा, टोंगी ग्राम से होकर जाती है (जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र 140.00 एकड़ क्षेत्र की सम्मिलित सीमा का भाग बनाती है)।

झ-ञ रेखा, टोंगी ग्राम से होकर जाती है।

ञ-क रेखा, टोंगी और बुंदू और बमारिया ग्रामों से होकर जाती है और बिंदु "क" पर मिलती है।

ब्लॉक "ख" का सीमा वर्णन :

ङ-ड रेखा, चोरधारा ग्राम से होकर जाती है (जो खपांगा ब्लॉक विस्तार के लिए कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र से मिलकर सम्मिलित सीमा बनाती है)।

ड-ड रेखा, चोरधारा ग्राम से होकर जाती है (जो चोरधारा ब्लॉक के लिए कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र से मिलकर सम्मिलित सीमा बनाती है)।

ड-ट रेखा, दामोदर नदी की बागल पूर्वी उत्तरी-पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और आरंभिक बिंदु "ट" से जा मिलती है।

[म. 43019/33/84-सी. ए.]

मध्य मिरा, अदर सचिव

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

(Department of Coal)

New Delhi, the 15th May, 1985

S.O. 2308—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan No. Rev/114/84 dated the 17th August, 1984 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Central Coalfields Limited, Revenue Section, Darbhanga House, Ranchi-834001 (Bihar) or in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-700001.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834001, (Bihar) within ninety days from the date of the publication of this notification.

SCHEDULE

NORTH BUNDU BLOCK

SOUTH KARANPURA COALFIELD

DISTRICT HAZARIBAGH (BIHAR)

Lands notified for prospecting

Block	Village	Thana	Thana Dis- number trict	Area	Re- marks
1	2	3	4	5	6
A	Basaria	Mandu	38	Hazari- bagh	179.00 Part
	Bundu	"	39	"	320.00 Part
	Tongi	"	135	"	224.00 Part

1	2	3	4	5	6
B Chordhara or Kharpatnagar	Ram- garh	55	Hazribagh	93.50	Part
Total Area -- 816.50 acres (approximately) or 330.42 hectares (approximately)					

Boundary Description of Block 'A'

- A-B line passes along the part Northern boundary of Damodar River in village Basaria.
- B-C line passes along the part eastern boundary of Damodar River in village Bundu.
- C-D line passes through village Bundu which forms part common boundary of the area notified for 270 acres in village Bundu.
- D-E-F lines pass through village Bundu and along part common boundary of villages Bundu and Tongi which forms part common boundary of the area acquired under section 9 (1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 for an area of 102 acres).
- F-G line passes through village Tongi which forms part common boundary of the area notified under section (9) of the Coal Bearing (Areas Acquisition and Development) Act, 1957 for 102 acres);
- G-H line passes along the part common boundary of villages Tongi and Sirka.
- H-I line passes through village Tongi which forms part common boundary of the area notified under section 9 (1) of the Coal Bearing (Areas Acquisition and Development) Act, 1957 for an area of 140.00 acres).
- I-J line passes through village Tongi.
- J-A line passes through villages Tongi and Bundu and Basaria and meets at point 'A'.

Boundary description of Block 'B'

- K-L line passes through village Chordhara (which forms common boundary with the area acquired under section 9 (1) of the Coal Bearing Areas Acquisition and Development) Act, 1957 for Lapanga Block Extension).
- L-M line passes through village Chordhara which forms common boundary with the area acquired under section 9 (1) of the Coal Bearing areas Acquisition and Development) Act, 1957 for chordhara Block).
- M-K line passes along the part eastern, Northern, Western boundary of Damodar River and meets at starting point 'K'.

[No. 43019/33/84-CZA]

SAMAY SINGH, Under Secy.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 मई, 1985

सं. पा. 109-यन केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों तथा निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा

लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भंडारण, संचलन परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बंद कर दिया है, जोकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं।

श्रीर यन. खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, तथा निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे श्रीर उपरिर्चित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों श्रीर कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उनमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी बनने के अपने आग्रह को उक्त अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है।

अन अथ खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) तथा अद्यतन संशोधन की धारा 12ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है:—

क. अधिकारी/कर्मचारी का नाम	स्थानान्तरण के कार के अधीन समय केन्द्रीय सर- स्थायी पद	भारतीय खाद्य निगम में स्था- नान्तरण की तारीख
----------------------------	--	--

1. श्री निर्मल सिंह	चपरासी	चपरासी	1-3-69
---------------------	--------	--------	--------

[सं. 52/1/84-फ.सी. III]

एस०के० स्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 16th May, 1985

S.O. 2309.—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the procurement Directors and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under section 13 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India;

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food, the procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not in response to the circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated, with in the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-section (1) of Section 12A of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto-date the Central Government hereby transfer the following employee to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against him.

S. No.	Name of the employee	Permanent post held under the Central Govt. at the time of transfer	Permanent post held under the Food Corp. transfer
--------	----------------------	---	---

1	Sri Nirmal Singh	Peon	Peon
---	------------------	------	------

[No. 52/1/82-F.C. III]

S. K. SWAMI, Under Secy.

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL, MINES & COAL

इस्पात विभाग

(Department of Steel)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1985

New Delhi, the 7th April, 1985

का. या. 2310.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (सब के भाषायीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में मेणनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (सूर्य किरण भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली) को, जिसके कर्मचारी वृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करता है।

S.O. 2310.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules 1976, the Central Government hereby notifies New Delhi Regional Office (Surya Kuan Building, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi) of National Mineral Development Corporation Ltd., the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[संई-11011/3/85-हिंदी]

[No. E 11011/3/85-HINDI]

अर्जुन कुमार अग्रवाल, सयुक्त सचिव

A. K. AGGARWAL, Jt. Secy.

साहस और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1985

का.आ. 2311.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन मुहर) अधिनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था एतद्वारा अधिसूचित करती है कि साहस सं. सीएम/एल-0589365, जिसके विवरण नीचे दिये गए हैं, 85-02-15 से रद्द कर दिया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	साहस संख्या और दिनांक	साहसेन, रा का नाम और पता	रद्द साहस अधीन वस्तु/प्रक्रिया	सम्बन्ध भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1.	सीएम/एल-0589365 77-02-28	मेमर्स स्वास्तिक पेस्टीसाइड्स एण्ड केमिकल्स, भूप रोड, मुजफ्फरनगर-252002	डाइमेथाट पायसर्तीय साहस	IS : 3903-75 डाइमेथाट पायसर्तीय साहस की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)

[संमिडी/55 : 0589365]

पु. एम. बीमा, अपर महानिदेशक (मार्क)

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 29th April, 1985

S.O. 2311.— In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation 1955 as amended from time to time the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. CM/L-0589365 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 85-02-15.

SCHEDULE

S.I Licence No. No. & Date	Name and Address of the licensee	Article/Process Covered by the licence cancelled	Relevant Indian Standards
1. CM/L-0589365 77-02-28	M/s. Swastik Pesticides and Chemicals, Bhopa Road, Muzaffarnagar-251001.	Dimethoate EC	IS : 3903-75 Specification for Dimethoate Emulsifiable Concentrates. (First Revision)

[CMD/55 : 0589365]

A.S. CHEEMA, Addl. Director General (Marks)

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मई 1985

का आ ११। —कन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मोरठिन म यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हरीरा म वरेनी में जगदीशपुर तऱ पेट्रोलियम में परिवर्तन के लिये पाएष लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यन यह प्रतीत हुआ है कि ऐसी लाईनों का बिछाने के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची म बणित भूमि म उपयोग अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अन अक्ष पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग व अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करत हुए केन्द्रीय सरकार न उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदु द्वारा घाषित किया है।

अशन वि उक्त भूमि म लिबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने क लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयाग एच बी ज पाइप लाइन 45 मुभाष नगर माबेर रोड उज्जैन (म प्र) 456001 का इस अधिमुचना की तारीख 21 घिना के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो यः किमी बिधि व्यवसायी की भाफल।

एच बा जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम—इगासरा तहसील—हमागढ़ जिला—गुना राज्य—मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु प्र / खमरा नं / उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)

1	2	3
1	1589/1	0 063
2	1604/1	0 192
3	1603	0 448
4	1609/1	0 014
5	1600/1	0 515
6	1613/8	0 261
7	1596/1क	0 436
8	1596/10	0 133
9	1644/27/1	0 063
10	1644/27/2	0 403
11	1430	0 623
12	1434	0 011
13	1437/1	0 153
14	1438	0 209
15	1599/5	0 153
16	1439	0 184
17	1412	0 361
18	1411/1	0 051
19	1410	0 240
20	1409	0 263

1	2	3
१1	1387/1क	0 331
22	1233/4	0 105
33	1394	0 209
44	1393/2क	0 230
55	1393/1क	—
26	1232/1	0 209
37	1208	0 335
28	1209	—
29	1210	—
30	1161	0 219
31	1189/1	—
32	1191	0 155
33	1190	0 105
34	1189/2	0 281
35	586	0 093
36	588	0 063
37	585	0 249
38	584	0 162
39	580	0 052
40	552/1	0 021
11	503/1	0 314
42	503/2	0 072
43	500	0 229
44	499	0 125
45	497	0 209
46	496	0 249
47	474	0 209
48	473	0 209
49	472	0 361
50	469	0 209
51	466/1	0 418
52	441	0 173
53	422/1	0 300
54	443	0 350
55	425	0 315
56	423/1	0 503
57	423/2	—
58	416/1	0 252
59	1197	0 175
60	564	0 398
61	482	0 354
62	450/1	0 209
63	422	0 304
64	1574	0 042
65	1590	0 021
66	1606	0 105
67	1393/1क	0 092
68	1393/2क	—
69	1596/1क	0 145
70	1644/27/3	0 360
71	1443	0 011
72	1408	0 010
73	1396/1क	0 030
74	1231	0 124
75	1211	0 010

1	2	3
76.	587	0.363
77.	581	0.200
78.	556/2	0.199
79.	486/2	0.042
80.	442/2	0.414
81.	416/2	0.376
82.	1398	0.052
83.	1169	0.052
84.	468	0.042
85.	1591/2	0.010
86.	1602/3	0.314
87.	1630	0.334
88.	1611/2	0.031
89.	1613/7	0.042
90.	1572	0.042
91.	1596/5	0.178
92.	1596/11	0.052
93.	1644/27/5	0.311
94.	1644/26	0.052
95.	1644/12	0.010
96.	1445	0.042
97.	1431	0.005
98.	1428/1	0.005
99.	1233/2	0.230
100.	1232/2	0.005
101.	1162	0.219
102.	1163	0.031
103.	1164	0.031
104.	1165	0.062
105.	589	0.240
106.	590	0.010
107.	561	0.052
108.	562	0.153
109.	557	0.105
110.	551/1	0.261
111.	483	0.042
112.	436	0.010
113.	415/2	0.021
114.	551/3	0.209
115.	493/1-2-3	0.042
116.	551/2	0.073
117.	542/1	0.084
118.	501/2	0.011
119.	502	0.010
120.	498	0.005
121.	494	0.073
122.	495	--
योग : कुल क्षेत्रफल		19.616

[सं. O-14018/328/85-जी०पी०]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 18th May, 1985

S.O. 2312.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazra Barelly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil Authority of India Limited.

211 G of I/85—2.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwar Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Dungasara Tehsil Isagarh Distt. Guna

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired R.O.U. in Hectare
1.	1589/1	0.063
2.	1604/1	0.192
3.	1603	0.448
4.	1609/1	0.014
5.	1600/1	0.515
6.	1613/8	0.261
7.	1596/1 K	0.436
8.	1596/10	0.133
9.	1644/27/1	0.063
10.	1644/27/2	0.403
11.	1430	0.623
12.	1434	0.011
13.	1437/1	0.153
14.	1438	0.209
15.	1599/5	0.153
16.	1439	0.184
17.	1412	0.361
18.	1411/1	0.031
19.	1410	0.249
20.	1409	0.263
21.	1387/1 K	0.331
22.	1233/4	0.105
23.	1394	0.209
24.	1393/2 K	0.230
25.	1393/1 K	..
26.	1232/1	0.209
27.	1208	0.335
28.	1209	..
29.	1210	..
30.	1161	0.219
31.	1189/1	..
32.	1191	0.155
33.	1190	0.105
34.	1189/2	0.281
35.	586	0.083
36.	588	0.063
37.	585	0.249
38.	584	0.162

1	2	3	1		
39.	580	0.052	104.	1165	0.062
40.	552/1	0.021	105.	589	0.240
41.	503/1	0.314	106.	590	0.010
42.	503/2	0.072	107.	561	0.052
43.	500	0.229	108.	562	0.153
44.	499	0.125	109.	557	0.105
45.	497	0.209	110.	551/1	0.261
46.	496	0.249	111.	483	0.042
47.	474	0.209	112.	436	0.010
48.	473	0.209	113.	415/2	0.021
49.	472	0.361	114.	551/3	0.209
50.	469	0.209	115.	493/1-2-3	0.042
51.	466/1	0.418	116.	551/2	0.073
52.	441	0.173	117.	542/1	0.084
53.	422/1	0.300	118.	501/2	0.011
54.	443	0.350	119.	502	0.010
55.	425	0.315	120.	498	0.005
56.	421/1 }	0.503	121.	494 }	0.073
57.	423/2 }	..	122.	495 }	..
58.	116/1	0.252	Total Area		19.616
59.	1197	0.175	[No. O-14016/328/85-GP]		
60.	564	0.398			
61.	482	0.354			
62.	450/1	0.209			
63.	422	0.304			
64.	1574	0.042			
65.	1590	0.021			
66.	1606	0.105			
67.	1393/1 KH }	0.092			
68.	1393/2 KH }	0.145			
69.	1596/1/KH }	0.360			
70.	1644/27/3	0.011			
71.	1443	0.010			
72.	1408	0.030			
73.	1396/1 K	0.129			
74.	1231	0.010			
75.	1211	0.363			
76.	587	0.200			
77.	581	0.199			
78.	556/2	0.042			
79.	466/2	0.414			
80.	442/2	0.376			
81.	416/2	0.052			
82.	1398	0.052			
83.	1169	0.042			
84.	468	0.010			
85.	1591/2	0.314			
86.	1602/3	0.334			
87.	1610	0.031			
88.	1611/2	0.042			
89.	1613/7	0.042			
90.	1572	0.042			
91.	1596/5	0.178			
92.	1596/11	0.052			
93.	1644/27/5	0.314			
94.	1644/26	0.052			
95.	1644/12	0.010			
96.	1445	0.042			
97.	1431	0.005			
98.	1428/1	0.005			
99.	1233/2	0.230			
100.	1232/2	0.005			
101.	1162	0.219			
102.	1163	0.031			
103.	1164	0.031			

का. धा 2313—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में इजोरा से खरेदी से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बर्णन कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 45, मुम्बई नगर साविर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति, जिम्मेदारता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम पिरोठ तहसील कोलारस जिला—शिवपुरी राज्य (मध्यप्रदेश)		
अनुसूची		
अनु. क्र.	खसरा न.	उपयोग का अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
1	2	3
1.	919	0.042
2.	920	0.136
3.	921	0.314
4.	898	0.010

1	2	3	1	2	3
5.	883	0.020	60.	2121/2430	0.418
6	876	0.010	61.	2143	0.314
7	826	0.272	62.	2144	0.073
8	2110	0.021	63.	2101	0.031
9.	2012	0.314	64	2014	0.125
10.	922	0.314	65.	2019	0.157
11	2030	0.010	66	2013	0.063
12.	2063	0.010	67	2023	0.209
13	923	0.157	68.	2025	0.084
14	924	0.021	69	2022	0.042
15	925	0.408	70	2024	0.073
16	900	0.146	71.	2029	0.178
17.	899	0.209	72	2082	0.188
18.	890	0.606	73	2069	0.282
19	884	0.303	74	2074	0.051
20	1173	0.345	75	2073	0.209
21	885	0.082	76.	2070	0.010
22	870	0.105	77	2061	0.084
23	877	0.261	78.	2062	0.261
24	843	0.324	79.	2048	0.167
25	1185	0.167	80	2047 मी	0.105
26	841	0.031	81	2265 मी.	0.470
27	869	0.052	82	926	0.105
28	844	0.136	83.	1027	0.105
29	839	0.345	84	1038	0.031
30	840	0.251	85	1043	0.042
31	1186	0.010	86.	1169	0.031
32.	828	0.042	87.	2289	0.031
33	829	0.282	88	2290	0.010
34	825/1	0.157	89.	2291	0.021
35	1023	0.042	90	2299	0.054
36	1039	0.188	91.	2309	0.063
37	1015	0.167	92	2280	0.010
38	1036	0.125	93	2279	0.010
39.	1024	0.366	94.	2273	0.010
40	1025	0.021	95	2269	0.031
41	1024/2418	0.167	96.	2355	0.156
42	1035	0.136	97.	2268	0.063
43.	1040	0.188	98	2267	0.042
44.	1174	0.052	99	2261	0.700
45	1173/2423	0.010	100	2260	0.052
46	1184	0.146	101.	2257	0.157
47	2298 मी	0.167	102.	2256	0.315
48	1303	0.391	103.	2120	0.157
49.	2306	0.199	104.	2112	0.805
50	2307 मी	0.084	105.	2109	0.063
51	2277	0.021	106	2108	0.084
52	2308	0.230	107	2107	0.063
53	2278	0.115	108.	2104	0.010
54.	2272	0.157	109.	2102	0.452
55	2356	0.073	110	2100	5.653
56.	2262	0.261	111.	2098	0.021
57	2263	0.021	112.	2010	0.523
58.	2264	0.136	113.	2034	0.157
59.	2121	0.010			

1	2	3
114.	2035	0.042
115.	2083	0.167
योग: क्षेत्रफल		18.216

[सं. O-14016/329/85-जीपी]

S.O. 2313.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barelilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1961 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipeline, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Pirotha Tehsil Kolaras Distt. Shivpuri

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hecter
1.	919	0.042
2.	920	0.136
3.	921	0.314
4.	898	0.010
5.	883	0.020
6.	876	0.010
7.	826	0.272
8.	2110	0.021
9.	2012	0.314
10.	922	0.314
11.	2030	0.010
12.	2063	0.010
13.	923	0.157
14.	924	0.021
15.	925	0.408
16.	900	0.146
17.	899	0.209
18.	890	0.606
19.	884	0.303
20.	1173	0.345
21.	885	0.082
22.	870	0.105
23.	877	0.261
24.	843	0.324
25.	1185	0.167
26.	841	0.031

1	2	3
27.	869	0.052
28.	844	0.136
29.	839	0.345
30.	840	0.251
31.	1186	0.010
32.	828	0.042
33.	829	0.282
34.	825/1	0.157
35.	1023	0.042
36.	1039	0.188
37.	1015	0.167
38.	1036	0.125
39.	1024	0.366
40.	1025	0.021
41.	1024/2418	0.167
42.	1035	0.136
43.	1040	0.188
44.	1174	0.052
45.	1173/2423	0.010
46.	1184	0.146
47.	2298M.	0.167
48.	2303	0.391
49.	2306	0.199
50.	2307 M.	0.084
51.	2277	0.021
52.	2308	0.230
53.	2278	0.115
54.	2272	0.157
55.	2356	0.073
56.	2262	0.261
57.	2263	0.021
58.	2264	0.136
59.	2121	0.010
60.	2121/2430	0.418
61.	2143	0.314
62.	2144	0.073
63.	2101	0.031
64.	2014	0.125
65.	2019	0.157
66.	2013	0.063
67.	2023	0.209
68.	2025	0.084
69.	2022	0.042
70.	2024	0.073
71.	2029	0.178
72.	2082	0.188
73.	2069	0.282
74.	2074	0.051
75.	2073	0.209
76.	2070	0.010
77.	2061	0.084
78.	2062	0.261
79.	2048	0.167
80.	2047M.	0.105
81.	2265M.	0.470
82.	926	0.105
83.	1027	0.105
84.	1038	0.031
85.	1043	0.042
86.	1169	0.031
87.	2289	0.031
88.	2290	0.010
89.	2291	0.021
90.	2299	0.054
91.	2309	0.063
92.	2280	1.010
93.	2279	0.010

1	2	3
94. 2273		0.010
95. 2269		0.031
96. 2355		0.156
97. 2268		0.063
98. 2267		0.042
99. 2261		0.700
100. 2260		0.052
101. 2257		0.157
102. 2256		0.315
103. 2120		0.157
104. 2112		0.805
105. 2109		0.063
106. 2108		0.084
107. 2107		0.063
108. 2104		0.010
109. 2102		0.452
110. 2100		0.653
111. 2098		0.021
112. 2010		0.523
113. 2034		0.157
114. 2035		0.042
115. 2083		0.167
TOTAL AREA		18.216

[No. O-14016/329/85—GP]

का. मा. 2314.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजौरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्व्याप्य धनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रस्ताव शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवन् कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाईप लाइन 45, सुभाष नगर साँवर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख 21 से दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कबन करेगा कि क्या वह यह चाहता कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम कुसुवन तहसील कोलाराम शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)		
धनसूची		
अनु०	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1.	2	3
1	280/2	0.418
2	664	0.340

1	2	3
3.	661	0.232
4.	660	0.139
5.	657	0.397
6.	740	0.188
7.	742/1	0.392
8.	741	0.374
9.	264	0.251
11.	665	0.153
12.	249	0.393
13.	92	0.209
14.	273	0.073
15.	265	0.232
16.	260	0.163
17.	262	0.105
18.	261	0.012
19.	321	0.481
20.	344	0.094
21.	280/1	0.158
22.	313	0.356
23.	312	0.566
24.	631	0.167
25.	309	0.103
26.	319	0.282
27.	306	0.047
28.	272	0.389
29.	365	0.042
30.	184	0.031
31.	627	0.042
32.	629	0.125
33.	632/1	0.031
34.	632/2	0.608
35.	743	0.052
36.	634	0.042
37.	722	0.031
38.	744	0.040
39.	325/1	0.010
40.	248	0.105
41.	320	0.476
42.	268	0.209
43.	91	0.178
44.	90	0.081
योग :—कुल क्षेत्रफल		8.817

[सं. O-14016/330/85-जी. पी.]

S.O. 2314.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, land described in the schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwar Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Kusvan	Tehsil Kolaras	Distt. Shiv Puri
SCHEDULE		
S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecter
1.	280/2	0.418
2.	664	0.340
3.	661	0.232
4.	660	0.139
5.	657	0.397
6.	740	0.188
7.	742/1	0.392
8.	741	0.374
9.	264	0.251
11.	665	0.153
12.	249	0.393
13.	92	0.209
14.	273	0.073
15.	265	0.232
16.	260	0.163
17.	262	0.105
18.	261	0.012
19.	321	0.481
20.	344	0.094
21.	280/1	0.158
22.	313	0.356
23.	312	0.566
24.	631	0.167
25.	309	0.103
26.	319	0.282
27.	306	0.047
28.	272	0.389
29.	365	0.042
30.	184	0.031
31.	627	0.042
32.	629	0.125
33.	632/1	0.031
34.	632/2	0.608
35.	743	0.052
36.	634	0.042
37.	722	0.031
38.	744	0.040
39.	325/1	0.010
40.	248	0.105
41.	320	0.476
42.	268	0.209
43.	91	0.178
44.	90	0.081
TOTAL AREA		8.817

[No. O-14016/330/85—GP]

का. भा. 2315.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजौरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाठ्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बसतः कि उक्त भूमि में हितवन् कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 45, मुभाष नगर सांभर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम मेघोनाचड़ा तहसील कोलारस जिला—शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची		
अनु क्र०	खमरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	1825	0.327
2	1834	0.157
3	645	0.021
4	462	0.052
5.	489	0.010
6	496	0.021
7	499	0.052
8.	537	0.031
9.	1834/2367	0.419
10	534	0.010
11.	643	0.105
12.	639	0.084
13.	638	0.084
14.	637	0.209
15.	1720	0.207
16.	1558	0.042
17	1536	0.042
18.	1578	0.094
19.	1447/1	0.209
20	1581	0.010
21	1576	0.021
22.	1608	0.042
23.	1826	0.105
24.	1827	0.021
25.	1456/1	0.104
26.	1828	0.084
27	1833	0.049
28	1835 मी.	0.042
29.	1835 मी	0.210

1	2	3
30.	1718	0.020
31.	1454	0.314
32.	1453	0.125
33.	1465	0.110
34.	1469	0.209
35.	644/2	0.200
36.	1468	0.210
37.	1471	0.210
38.	1513	0.157
39.	1527	0.020
40.	1511	0.104
41.	1530	0.157
42.	1510	0.050
43.	1542	0.110
44.	1540	0.150
45.	1541	0.060
46.	1543	0.050
47.	1545	0.20
48.	1546	0.010
49.	1556	0.110
50.	1579	0.170
51.	1557	0.209
52.	501	0.300
53.	1580	0.190
54.	1582	0.320
55.	466	0.210
56.	461	0.037
57.	648	0.618
58.	463	0.590
59.	467	0.010
60.	520	0.140
61.	487	0.157
62.	488	0.523
63.	497	0.410
64.	498	0.155
65.	504	0.167
66.	523	0.210
67.	524	0.300
68.	535	0.110
69.	525	0.300
70.	526	0.042
71.	1280	0.178
72.	1822	0.815
73.	1841	0.240
74.	1834	0.417
75.	1840	0.961
76.	1839	0.375
77.	1457	0.073
78.	647	0.010
79.	1513/2380	0.188
80.	1531	0.094
81.	1560	0.121
82.	677	0.105
83.	528	0.031
84.	1528	0.146

1	2	3
85.	1544	0.157
86.	1452	0.009
87.	1719	0.390
88.	1721 मी.	0.199
89.	1829	0.180
योग :—कुल क्षेत्रफल		15.127

[सं. O-14016/331/85-जी. पी.]

S.O. 2315.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Banilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares, its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Meghonaawara Tehsil Kolaras Distt. Shivpuri

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectore
1	2	3
1.	1825	0.327
2.	1834	0.157
3.	645	0.021
4.	462	0.052
5.	489	0.010
6.	496	0.021
7.	499	0.052
8.	537	0.031
9.	1834/2367	0.419
10.	534	0.010
11.	643	0.105
12.	639	0.084
13.	638	0.084
14.	637	0.209
15.	1720	0.207
16.	1558	0.042
17.	1536	0.042
18.	1578	0.094
19.	1447/1	0.209
20.	1581	0.010
21.	1576	0.021
22.	1608	0.042
23.	1826	0.105
24.	1827	0.021
25.	1456/1	0.104
26.	1828	0.084
27.	1833	0.049
28.	1835M	0.042
29.	1835M	0.210
30.	1718	0.020

1	2	3
31.	1454	0.314
32.	1453	0.125
33.	1465	0.110
34.	1469	0.209
35.	644/2	0.200
36.	1468	0.210
37.	1471	0.210
38.	1513	0.157
39.	1527	0.020
40.	1511	0.104
41.	1530	0.157
42.	1510	0.050
43.	1542	0.110
44.	1540	0.150
45.	1541	0.060
46.	1543	0.050
47.	1545	0.020
48.	1546	0.010
49.	1556	0.110
50.	1579	0.170
51.	1557	0.209
52.	501	0.300
53.	1580	0.190
54.	1582	0.320
55.	466	0.210
56.	461	0.037
57.	648	0.618
58.	463	0.590
59.	467	0.010
60.	520	0.140
61.	487	0.157
62.	488	0.523
63.	497	0.410
64.	498	0.155
65.	504	0.167
66.	523	0.210
67.	524	0.300
68.	535	0.110
69.	425	0.300
70.	526	0.042
71.	1280	0.178
72.	1822	0.815
73.	1841	0.240
74.	1824	0.417
75.	1840	0.961
76.	1839	0.375
77.	1457	0.073
78.	647	0.010
79.	1513/2380	0.188
80.	1531	00.94
81.	1560	0.021
82.	677	0.105
83.	528	0.031
84.	1528	0.146
85.	1544	0.157
86.	1452	0.009
87.	1719	0.390
88.	1721 M	0.199
89.	1829	0.190
TOTAL AREA		15.127

[No O-14016/331/85—G P]

का. आ. 2316.—यत्. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये ;

और यत्: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है ;

अर्थात् कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर, साँवर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिवृष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत् ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम छापी	तहसील	कोलारस्त	जिला	शिवपुरी	राज्य (मध्य प्रदेश)
अनुसूची					
अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)			
1.	92	0.033			
2.	237	0.052			
3.	93	0.297			
4.	263	0.157			
5.	54	0.314			
6.	264	0.031			
7.	262	0.502			
8.	238	0.932			
9.	133	0.042			
10.	125	0.199			
11.	134	0.544			
12.	261	0.137			
13.	293	0.031			
14.	94	0.042			
15.	136	0.136			
16.	57	0.167			
17.	73	0.114			
18.	132	0.010			
19.	156	0.010			
20.	75	0.084			
21.	78	0.334			
22.	379/1	0.158			
23.	77	0.111			
24.	80	0.209			
25.	131	0.282			
26.	81	0.337			
27.	82	0.264			
28.	137	0.142			
योग :—कुल क्षेत्रफल		5.671			

[सं. O-14016/332/85-जी. पी.]

S.O. 2316.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from HAZIRA-BARILLY to JAGADISHPUR in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipeline, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipeline Project

Village : Chhapi, Tehsil : Kolaras, Distt. : Shivpuri

SCHEDULE

Sl. Survey No. No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hector	
1, 92	0.033	
2, 237	0.052	
3, 93	0.297	
4, 263	0.157	
5, 54	0.314	
6, 264	0.031	
7, 262	0.502	
8, 238	0.932	
9, 133	0.042	
10, 125	0.199	
11, 134	0.544	
12, 261	0.137	
13, 293	0.031	
14, 94	0.042	
15, 136	0.136	
16, 57	0.167	
17, 73	0.114	
18, 132	0.010	
19, 156	0.010	
20, 75	0.084	
21, 78	0.334	
22, 79/1	0.158	
23, 77	0.111	
24, 80	0.209	
25, 131	0.282	
26, 81	0.337	
27, 82	0.264	
28, 137	0.142	
Total Area		5.671

[No. O-14016/332/85-GP]

का. भा. 2317.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से अगशीरापुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपायक अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

211GI/85—3

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

यहाँ कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप-लाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइपलाइन, 45, सुभाष नगर, सांवर रोड, उज्जैन-456001 (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : बनियानी, तहसील : पिछोर, जिला : शिवपुरी, राज्य (मध्यप्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
1	2	3
1.	319/392	0.080
2.	172	0.360
3.	25	0.260
4.	240	0.330
5.	319	0.140
6.	5	0.250
7.	302	0.630
8.	238	0.670
9.	242	0.250
10.	318	0.270
11.	144	0.440
12.	18	0.340
13.	10	0.410
14.	3	0.460
15.	99	0.250
16.	40	0.190
17.	107	0.150
18.	38	0.200
19.	145	0.230
20.	177	0.120
21.	303	0.510
22.	169	0.570
23.	312	0.290
24.	313	0.200
25.	23	0.310
26.	174	0.620
27.	12	0.520
28.	32	0.150
29.	41	0.250
30.	105	0.450
31.	95	0.550
32.	101	0.300
33.	103	0.010
34.	96	0.300
35.	48	0.080

1	2	3
36	102	0.010
37	104	0.140
38	106	0.290
39	143	0.360
40	91	0.370
41	170	0.560
42	243	0.020
43	391	0.030
योग :—कुल क्षेत्रफल		12.920

[सं. O-14016/333/85-जी पी.]

S.O. 2317—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from HAZIRA-BARILLY to JACADISHPUR in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipeline, 45, Subhash Nagar, Sanwar Road, Ujjain (M.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Pipeline Project

Village : Baniyani, Tehsil : Pichhore, Distt. Shivpuri

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.D.U. in Hectar
1	2	3
1.	319/392	0.080
2.	172	0.360
3.	25	0.260
4.	240	0.330
5.	319	0.140
6.	5	0.250
7.	302	0.630
8.	238	0.670
9.	242	0.250
10.	318	0.270
11.	144	0.440
12.	18	0.340
13.	10	0.410
14.	3	0.460
15.	99	0.250
16.	40	0.190
17.	107	0.150
18.	38	0.200
19.	145	0.230
20.	177	0.120
21.	303	0.510
22.	169	0.570
23.	312	0.290
24.	313	0.200
25.	23	0.310

1	2	3
26.	174	0.620
27.	12	0.520
28.	32	0.150
29.	41	0.250
30.	105	0.450
31.	95	0.550
32.	101	0.300
33.	103	0.010
34.	96	0.300
35.	48	0.080
36.	102	0.010
37.	104	0.140
38.	106	0.290
39.	143	0.360
40.	91	0.370
41.	170	0.560
42.	243	0.020
43.	391	0.030
Total Area		12.920

[No. O-14016/333/85-GP]

का. आ. 2318 —यन्त केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजौरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जाना चाहिये।

और यन्त यह प्रतीत होता है कि ऐसी राहों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जन करता आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 1 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जन करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के लिये पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सज्जम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस बोर्ड, एच. बी. जे. पाइपलाइन 45, सुभाष नगर, नखेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : कडेसरा, तहसील : पिछोर, जिला : शिवपुरी राज्य : मध्यप्रदेश

अनुसूची

अनु.क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
1	2	3
1.	164	0.020
2.	243	0.020
3.	244	0.150
4.	245	0.010
5.	283	0.050
6.	284	0.040

1	2	3
7.	286	0.030
8.	288	0.090
9.	125	0.200
10	128	0.240
11.	126	0.100
12.	218	0.020
13.	150	0.140
14.	151	0.080
15.	161	0.040
16.	262	0.120
17.	165	0.320
18.	270	0.150
19.	275	0.250
20.	276	0.140
21.	279	0.200
22	291	0.300
23.	304	0.080
24.	305	0.100
25	306	0.120
26	308	0.020
27.	217	0.380
28.	219	0.120
29	295	0.140
30.	259	0.150
31.	258	0.040
32	280	0.010
33.	282	0.200
34.	297	0.030
35.	298	0.180
36.	299	0.070
37.	301	0.180
38	293	0.010
39	267	0.250
40.	269	0.040
41.	273	0.230
42.	261	0.100
43.	309	0.150
44.	127	0.120
45	166	0.390
46	149	0.020
47.	265	0.100
48.	266	0.030
49.	1	0.020
50	131	0.020
51.	216	0.050
52	378	0.160
53	118	0.010
योग :— कुल क्षेत्रफल		6.220

[स. O-14016/334/85-जी. पी.]

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipeline, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipeline Project

Village : Kandesara, Tehsil : Pichhore, Distt. Shivpuri

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectar
1	2	3
1.	164	0.020
2.	243	0.020
3.	244	0.150
4.	245	0.010
5.	283	0.050
6.	284	0.040
7.	286	0.030
8.	288	0.090
9.	125	0.200
10.	128	0.240
11.	126	0.100
12.	218	0.020
13.	150	0.140
14.	151	0.080
15.	161	0.040
16.	262	0.120
17.	165	0.320
18.	270	0.150
19.	275	0.250
20.	276	0.140
21.	279	0.200
22.	291	0.300
23.	304	0.080
24.	305	0.100
25.	306	0.120
26.	308	0.020
27.	217	0.380
28.	219	0.120
29.	295	0.140
30.	259	0.150
31.	258	0.040
32.	280	0.010
33.	282	0.200
34.	297	0.030
35.	298	0.180
36.	299	0.070
37.	301	0.180
38.	293	0.010
39.	267	0.250
40.	269	0.040
41.	273	0.230
42.	261	0.100
43.	309	0.150
44.	127	0.120
45.	166	0.390

S.O. 2318.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from HAZIRA-BARILLY to JAGDISHPUR in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

1	2	3
46.	149	0.020
47.	265	0.100
48.	266	0.020
49.	1	0.020
50.	131	0.070
51.	216	0.050
52.	378	0.160
53.	118	0.010
Total Area		6.220

[No. O—14016/334/85—GP]

का. आ. 2319:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजौरा से बरेली से जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बर्तते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाईप लाईन 45, सुभाष नगर सावर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफ़त।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम मायापुर तहसील पिछोर जिला शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनुक्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर) में)
1	2	3
1.	8	0.742
2.	12	1.202
3.	18	0.157
4.	19	0.961
5.	21	0.021
6.	22	0.376
7.	40	0.157
8.	43	0.281
9.	47	0.094
10.	49	0.167
11.	52	0.031
12.	64	0.261
13.	65	0.596

1	2	3
14.	66	0.073
15.	67	0.439
16.	68	0.878
17.	69	0.031
18.	54	0.010
19.	11	1.735
20.	10	0.115
21.	658	1.369
22.	16	0.755
23.	659	0.303
24.	44	0.042
25.	51	0.031
26.	53	0.084
27.	189	0.084
28.	33	0.083
29.	48	0.021
30.	50	0.042
31.	55	0.084
32.	59	0.125
33.	13	0.951
34.	61	0.167
35.	17	0.397
36.	62	0.125
37.	45	0.010
38.	63	0.021
योग:—कुल क्षेत्रफल		13.021

[सं. O-14019 / 335 / 85-जी. पी.]

S.O. 2319.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from HAZIRA-BAREILLY to JAGDISHPUR in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe line 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Mayapur Tehsil : Pichhore Distt. : Shivpuri

SCHEDULE

Sl. Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectore
1	2
1.	8
2.	12
	0.742
	1.202

1	2	3
3.	18	0.157
4.	19	0.961
5.	21	0.021
6.	22	0.376
7.	40	0.157
8.	43	0.281
9.	47	0.094
10.	49	0.167
11.	52	0.031
12.	64	0.261
13.	65	0.596
14.	66	0.073
15.	67	0.439
16.	68	0.878
17.	69	0.031
18.	54	0.010
19.	11	1.735
20.	10	0.115
21.	658	1.369
22.	16	0.755
23.	659	0.303
24.	44	0.042
25.	51	0.031
26.	53	0.084
27.	189	0.084
28.	38	0.083
29.	48	0.021
30.	50	0.042
31.	55	0.084
32.	59	0.125
33.	13	0.951
34.	61	0.167
35.	17	0.397
36.	62	0.125
37.	45	0.010
38.	63	0.021
Total Area		13.021

[No. O —14016/335/85—GP]

का. आ. 2320—यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजौरा से बरेली में त्रगरीशपुर पेट्रोलियम के परियोजना के लिए पार्श्व लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यन, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्प्रावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पार्श्व लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) का धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

अर्थात् कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पार्श्व लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, नेशनल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पार्श्व लाइन 45, मुम्बई नगर साबेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट, यह भी ध्यान देने का कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुलवाई व्यक्तिगत रूप से हो यह किसी विधि व्यवसायी की सफाई।

एच. बी. जे. गैस पार्श्व लाइन प्रोजेक्ट
ग्राम खड्की तहसील पिछोर जिला—बिंदूपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं. / उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)	
1.	2.	3.
1	777	0.080
2	778	0.010
3	326	0.010
4	826	0.020
5	774	0.120
6	773	0.100
7	776	0.110
8	325	0.160
9	760	0.050
10	781	0.130
11	836	0.240
12	775	0.120
13	761	0.070
14	764	0.060
15	763	0.070
16	805	0.080
17	824	0.070
18	867	0.020
19	873	0.140
20	772	0.090
21	782	0.090
22	794	0.060
23	825	0.160
24	851	0.010
25	865	0.230
26	893	0.020
27	897	0.140
28	765	0.140
29	766	0.060
30	767	0.120
31	768	0.130
32	803	0.160
33	804	0.180
34	868	0.030
35	869	0.060
36	870	0.080
37	871	0.070
38	872	0.080
39	874	0.260
40	780	0.060
41	853	0.010
42	770	0.120
43	793	0.070
44	795	0.060
45	802	0.100
46	828	0.080
47	829	0.030
48	852	0.050
49	863	0.080
50	764	0.050

[सं. O-14016/336/85-जीपि]

वर्गों कि उक्त भूमि में हितवादी कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे प्रादुर्भावित ब्रिह्मते के लिए आश्रय प्रदानकारी, सेवा तथा प्राकृतिक

गैस प्रायोग, ए.ए.सी.जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड
उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 1 दिनों
के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा अधिप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह यह भी
कथन करेगा कि उसा यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

एच बीजे.गैस पाइप लाइन प्राकट

ग्राम—पिपारा—तहसील—पिछोर जिला—शिवपुरी राज्य(मध्य प्रदेश)

अनसूची

अनु. क्र०	खमरा न०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2.	3.
1	1611	0.300
2	1630	0.010
3	1631	0.030
4	1573	0.010
5	1574	0.060
6.	926/1689	0.010
7	1572	0.230
8.	904	0.030
9.	905	0.050
10.	1616	0.040
11.	1617	0.190
12	1618	0.030
13.	913	0.050
14.	914	0.050
15.	1615	0.160
16.	918	0.120
17.	1623	0.010
18.	1626	0.120
19.	896	0.010
20	897	0.010
21.	1627	0.070
22	1629	0.020
23.	916	0.120
24.	898	0.570
25.	915	0.050
26.	899	0.390
27.	909	0.040
28.	910	0.080
29.	911	0.080
30.	912	0.030
31.	903	0.250
32	926	0.270
33.	1569	0.120
34.	884/1687	0.200
35.	1632	0.160
36.	1634	0.110
37.	1622	0.010
38.	1612	0.040
39.	1613	0.060
40.	900/1686	0.080
41.	900	0.030
42.	1575	0.320

1	2	3
43	1653	0.030
44.	927	0.040
45.	1643	0.100
46	1633	0.040
योग--कुल क्षेत्रफल		4.830

[न. O-14016 / 337 / 85-आ. प.]

S.O. 2321.--Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from HAZIRA BARILLY to JAGADISHPUR in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) of the Central Government hereby declared its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village—Piparo Tehsil -Pichhore Distt.—Shivpuri

SCHEDULE

S. Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hector	
No.		
1	2	3
1.	1611	0.300
2.	1630	0.010
3.	1631	0.030
4.	1573	0.010
5.	1574	0.060
6.	926/1689	0.010
7.	1572	0.230
8.	904	0.030
9.	905	0.050
10.	1616	0.040
11.	1617	0.190
12.	1618	0.030
13.	913	0.050
14.	914	0.050
15.	1615	0.160
16.	918	0.120
17.	1623	0.010
18.	1626	0.120
19.	896	0.010
20.	897	0.010
21.	1627	0.070
22.	1629	0.020
23.	916	0.120
24.	898	0.570
25.	915	0.050

1	2	3
26. 899		0 390
27. 909		0 040
28. 910		0 080
29. 911		0 080
30. 912		0 030
31. 903		0 250
32. 926		0 270
33. 1569		0 120
34. 884/1687		0 200
35. 1632		0 160
36. 1634		0 110
37. 1622		0 010
38. 1612		0 040
39. 1613		0 060
40. 900/1686		0 080
41. 900		0 030
42. 1575		0 320
43. 1653		0 030
44. 927		0.040
45. 1643		0 100
46. 1633		0 040
Total Area		4 830

[No. O-14016/337/85-GP]

का. आ. 2122:—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हज़ारा से बरतों से जमदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन लिये एतद्पाठ्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अन्य अथ पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के लोके पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सज्जम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर सांवर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना के तारिख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह कि कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या कितां विधि व्यवसाया की माफत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम—महार सहसोल—पिछोर जिला—शिवपुरी राज्य (मध्यप्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र. बसरा न.		उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1	229	0.593
2	228	0.094
3	227	0.852

1	2	3
4	225	1.354
5	224	0 010
6	222	0 261
7	221	0.199
8	220	0 394
9	219	0 094
10.	218	0.293
11.	212	0.115
12	213	0.236
13	214	0.210
14	197	0.115
15.	198	0 142
16.	195	0 118
17.	194	0 178
18.	181	0.219
19	179/2	0.539
20.	165	0.188
21	164	0.523
22	142	0 890
23	144	0.146
24	145	0 397
25	127	0 209
26.	125	0.543
27	115	0 021
28.	126	0 031
29.	92	0 094
30.	138	0.073
31.	151	0.042
32	152	0.052
33.	167	0.105
34	182	0.010
35	201	0 157
36	211	0.073
योग कुल क्षेत्रफल		9.579

[स. O--14016/338/85-जी.पी.]

S.O. 2322.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from HAZIRA-BAREILLY to JAGDISHPUR in Madhya Pradesh State Pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45 Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Muhar Tehsil : Pichhore Distt : Shivpuri

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectar
1	2	3
1.	229	0.593
2.	228	0.094
3.	227	0.852
4.	225	1.354
5.	224	0.010
6.	222	0.261
7.	221	0.199
8.	220	0.394
9.	219	0.094
10.	218	0.293
11.	212	0.115
12.	213	0.236
13.	214	0.240
14.	197	0.115
15.	198	0.142
16.	1195	0.118
17.	194	0.178
18.	181	0.219
19.	179 2	0.539
20.	165	0.188
21.	164	0.523
22.	142	0.890
23.	144	0.146
24.	145	0.397
25.	127	0.209
26.	125	0.543
27.	115	0.021
28.	126	0.031
29.	92	0.094
30.	138	0.073
31.	151	0.042
32.	152	0.052
33.	167	0.105
34.	182	0.010
35.	201	0.157
36.	211	0.073
Total Area		9.579

[No. O-14016/338/85-GP]

का. भा. 2323 :- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) को धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा धोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सख्त प्राधिकारी, भारतीय गैस

प्राधिकरण लि. एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन परियोजना 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर को इस अधिसूचना को जारी करने से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान	जिला : कोटा	तहसील : पीपल्दा		
गांव	खसरा न.	हेक्टर	आर	सेन्टायर
1	2	3		
डोली	1	0	02	72
	6	0	57	62
	7	0	09	92
	8	0	12	01
	13	0	01	72
	14	0	00	96
	15	0	02	99
	16	0	00	96
	91	0	08	97
	17	0	08	89
	90	0	17	74
	89	0	01	17
	83	0	00	26
	88	0	15	88
	28	0	04	62
	87	0	19	04
	85	0	26	34
	86	0	00	38
	69	0	02	99
	68	0	45	53
	66	0	03	71
	67	0	05	03
	54	0	00	58
	53	0	00	21
	52	0	13	35
	51	0	11	96
	49	0	08	42
	48	0	45	40
	540/391	0	13	70
	109	0	28	32
	224	0	01	92
	389	0	11	96
	388	0	07	98
	387	0	17	39
	595/238	0	26	23
	238	0	14	95
	380	0	61	88
	382	0	14	95
	378	0	05	71
	533/346	0	02	45
	345	0	79	79
	353	0	24	46
	354	0	05	49

1	2	3	4	5
	338	0	22	13
	355	0	01	35
	336/511	0	18	62
	336	0	00	05
	356	0	00	21
	357	0	08	18
	358	0	32	80
	359	0	04	01
	362	0	56	21

[सं. O-14016/339/85-जं की]

S.O. 2323.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (MP) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil - Piplada

Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centiare
1	2			3
Doli	1	0	02	72
	6	0	57	62
	7	0	09	92
	8	0	12	01
	13	0	01	72
	14	0	00	96
	15	0	02	99
	16	0	00	96
	91	0	08	97
	17	0	08	89
	90	6	17	74
	89	0	01	17
	83	0	00	26
	88	0	15	88
	28	0	04	62
	87	0	19	04
	85	0	26	34
	86	0	00	38
	69	0	02	99
	68	0	45	53
	66	0	05	71
	67	0	05	03
	54	0	00	58
	53	0	00	21
	52	0	13	35

1	2	3	4
	51	0	11
	49	0	08
	48	0	45
	540/391	0	13
	109	0	28
	224	0	01
	389	0	11
	388	0	07
	387	0	17
	595/238	0	26
	238	0	14
	380	0	61
	382	0	14
	378	0	05
	533/346	0	02
	345	0	79
	353	0	24
	354	0	05
	338	0	22
	355	0	01
	336/511	0	18
	336	0	00
	356	0	00
	357	0	08
	358	0	32
	359	0	04
	362	0	66

[No. O-14016/339/85-GP]

का. ग्रा. 2324.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म. प्र.) में सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी माहनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपायधन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अर्जत कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मध्यम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि. एवं बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की म.रीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिवृत्ततया यह भी कथन करेगा, कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सूतवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) में सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य . राजस्थान	जिला : कोटा	तहसील : पीपल्हा
गांव	खमरा नं.	हैक्टर
1	2	3
गर्नश गंज	220	0 00
	221	0 20

1	2	3	4	5
गणेश गंज (जारी)	266	0	27	38
	226	0	02	60
	265	0	55	31
	259	0	13	83
	264	0	32	31
	261	0	23	55
	262	0	40	59
	254	0	14	18
	278	0	81	93
	279	0	07	88
	280	0	06	90
	282	0	31	43
	287	0	30	12
	288	0	17	39
	303	0	01	91
	530/314	0	14	08
	521/314	0	02	90
	315	0	01	10
	316	0	03	97
	317	0	18	67
	318	0	03	05
	331	0	04	83
	312	0	00	17
	332	1	00	33
	334	0	52	70
	353	0	00	03
	352	0	59	39
	352/465	0	00	96
	351	0	61	33
	350	1	33	32
	344	0	00	58
	348	0	23	02
	349	0	01	07
	347	0	10	40
	346	0	46	83
	355	0	09	03
	399	0	41	36
	400	0	03	83

[सं. O-14016/340/85-जीपी]

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline from Dijiapur(M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil - Piplada

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Ganesh Ganj	220	0	00	36
	221	0	20	18
	266	0	27	38
	226	0	02	60
	265	0	55	31
	259	0	13	83
	264	0	32	31
	261	0	23	55
	262	0	40	59
	254	0	14	18
	278	0	81	93
	279	0	07	88
	280	0	06	90
	282	0	31	43
	287	0	30	12
	288	0	17	39
	303	0	01	91
	513/314	0	14	08
	521/314	0	02	90
	315	0	01	10
	316	0	03	97
	317	0	18	67
	318	0	03	05
	331	0	04	83
	312	0	00	17
	332	1	00	33
	334	0	52	70
	353	0	00	03
	352	0	59	39
	352/465	0	00	96
	351	0	61	33
	350	1	33	32
	344	0	00	58
	348	0	23	02
	349	0	01	07
	347	0	10	40
	346	0	46	83
	355	0	09	03
	399	0	41	36
	400	0	03	83

[No. O-14016/340/85-GP]

S.O. 2324.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. I Gas Pipeline Project 49, Indra Colony, Sawai Madhopur,

का.आ. 2325.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य इन्दौर से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी ज़ादनों को खिछाने के प्रयोजन के लिये एनदपावड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्वारा घोषित किया है।

बराह कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उक्त भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर सांवर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेंगे।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित्य यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी गुनबाई अभिसंगत रूप से हो या किसी बिधि व्यवसायी की मार्फत।

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : बामोरदामरान तहसील : पिछोरा जिला : शिवपुरी राज्य मध्य प्रदेश

अनुसूची

क्र. सं. खसरा न.

उपयोग अधिकार
अर्जन का क्षेत्र
(हेक्टेर्स में)

1	2	3
1.	824	0.335
2.	828	0.063
3.	831	0.146
1	827	0.010
5	838	0.073
6.	840	0.428
7.	841	0.031
8.	2952	0.282
9.	2956	0.010
10.	2951	0.293
11.	2950	0.031
12.	2949	0.052
13.	2948	0.199
14.	2943	0.314
15.	2937	0.146
16.	2936	0.261
17.	2936/3005	0.021
18.	2929	0.136
19.	2930	0.010
20.	2904	0.031
21.	2932	0.084
22.	2931	0.021
23.	2885	0.100
24.	2886	0.105
25.	2887	0.010
26.	2890	0.481
27.	2892	0.282
28.	2837	0.010
29.	2834	0.308
30.	2833	0.010
31.	2832	0.199
32.	2831	0.282
33.	2817	0.199
34.	2816	0.136
35.	2815	0.178
36.	2736	0.199
37.	2734	0.115
38.	2725	0.251
39.	2727	0.031

1	2	3
40.	2688	0.314
41.	2729	0.042
42.	2726	0.005
43.	833	0.052
44.	837	0.052
45.	2730	0.105
46.	2732	0.115
47.	2888	0.010
48.	2891	0.021
49.	2947	0.021
योग-कुल क्षेत्रफल		6.610

[स. O-14016/341/85-जी पी]

S.O. 2325.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from HAZIRA-BAREILLY to JAGDISHPUR in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Bamoradamrone Tehsil : Pichhore Distt : Shivpuri

SCHEDULE

Sl No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	824	0.335
2.	828	0.063
3.	831	0.146
4.	827	0.010
5.	838	0.073
6.	840	0.428
7.	841	0.031
8.	2952	0.282
9.	2956	0.010
10.	2951	0.293
11.	2950	0.031
12.	2949	0.052
13.	2948	0.199
14.	2943	0.314
15.	2937	0.146
16.	2936	0.261
17.	2936/3005	0.021
18.	2929	0.136
19.	2930	0.010

1	2	3
20. 2904		0.031
21. 2932		0.084
22. 2931		0.021
23. 2885		0.100
24. 2886		0.105
25. 2887		0.010
26. 2890		0.481
27. 2892		0.282
28. 2837		0.010
29. 2834		0.308
30. 2833		0.010
31. 2832		0.199
32. 2831		0.282
33. 2817		0.199
34. 2816		0.136
35. 2815		0.170
36. 2736		0.199
37. 2734		0.115
38. 2725		0.251
39. 2727		0.031
40. 2688		0.314
41. 2729		0.042
42. 2726		0.005
43. 833		0.052
44. 837		0.052
45. 2730		0.105
46. 2732		0.115
47. 2888		0.010
48. 2891		0.021
49. 2947		0.021
Total Area		6.610

[No. O-14016/341/85-GP]

क।०आ० 2326—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म०प्र०) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पार्श्व लाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पार्श्व लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पार्श्व लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सभ्य प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० एच० बी० जे० गैस पार्श्व लाईन परियोजना, 49 इन्द्रा काकोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निर्निष्ठतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी गुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची
विजयपुर (म०प्र०), से सवाई माधोपुर (राज०) तक पार्श्व लाईन बिछाने के लिये राज्य राजस्थान जिला कोटा सहयोग बिलिया

गांव	खसरा नं०	हेक्टेयर	जार	सेक्टर
1	2	3	4	5
रामपुरा	435	0	02	51
	434	0	51	33
	439	0	14	82
	440	0	37	57
	441	0	25	03
	442	0	00	37
	443	0	06	35
	446	0	42	36
	519	0	10	58
	521	0	55	29
	522	0	30	31
	565	0	03	08
	523/1	0	00	12
	564	0	33	17
	563	0	34	93
	573	0	08	35
	580	0	04	25
	581	0	27	77
	582	0	32	01
	583	0	23	05
	584	0	00	23
	602	0	05	56
	596	0	01	80
	592/3	0	14	94
	592/1	0	08	62
	592/2	0	14	02
	623	0	13	49
	624	0	43	13
	625	0	51	28
	626	0	10	11
महर		0	07	37
	693	0	66	68
	687	0	15	78
	692	0	41	13
	688	0	04	05
	689	0	04	15
	690	0	04	05
	691	0	19	74
	643	0	07	94
	707	0	33	34
	707/2	0	06	88

[नं० O-14016/342/85जीपी]

S.O. 2326.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user thereon,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. HBJ Gas Pipe Line Project 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE I

Pipeline from Vijay pur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District Kota; Tehsil : Pipluda

MMMM

Village	Survey No.	Hectare	Acre	Conti- are
RAMPURA	415	0	02	51
	434	0	51	33
	439	0	14	82
	440	0	37	57
	441	0	25	03
	442	0	00	37
	443	0	06	35
	446	0	42	35
	519	0	10	58
	521	0	55	29
	522	0	30	31
	565	0	03	08
	523/1	0	00	12
	564	0	33	17
	563	0	34	93
	573	0	06	35
	580	0	04	25
	581	0	27	77
	582	0	32	01
	583	0	23	05
	584	0	00	23
	602	0	05	56
	596	0	01	80
	592/3	0	14	94
	592/1	0	06	62
	592/2	0	14	02
	623	0	13	49
	624	0	43	13
	625	0	51	28
	626	0	10	11
Canal		0	07	87
	693	0	66	68
	687	0	5	78
	692	0	41	13
	688	0	04	05
	680	0	04	15
	690	0	01	05
	691	0	19	74
	648	0	07	94
	707	0	33	34
	707/2	0	06	88

[No. O-14016/342/85-GP]

वा०अ० 2137-—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मोरारजी में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म०प्र०)

से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पार्श्व लाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयत्न के लिये एम्प्लाय्ड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः जब पेट्रोलियम और क्लिज पार्श्व लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एम्प्लाय्ड घोषित किया है।

बतल कि उक्त भूमि में विनियम कोई व्यक्ति, उस भूमि के मोक्ष पार्श्व लाईन बिछाने के लिये आशेष गजम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० एम्प्लाय्ड गैस पार्श्व लाईन परियोजना, 49 इन्ड्रा कॉलोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिवचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सूनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विजयपुर (म०प्र०) से सवाई माधोपुर (राज०) तक पार्श्व लाईन बिछाने के लिये राज्य राजस्थान जिला कोटा तत्समीय छप्पटा

गाँव	खसरा नं०	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4	5
चाँबोडा	2	1	43	75
	41	0	12	18
	40	0	08	46
	39	0	47	07
	42	0	25	70
	44	0	17	05
	43	0	05	82
	46	0	00	78
	555	0	22	69
	534	0	01	18
	561	0	13	23
	562	0	13	36
	563	0	05	56
	564	0	02	27
	565	0	01	65
	566	0	11	62
	567	0	08	18
	570	0	01	70
	573	0	00	70
	531	0	05	15
	528	0	22	49
	527	0	07	70
	526	0	09	36
	525	0	01	75
	524	0	00	88
	517	0	02	23
	515	0	04	22
	516	0	04	56
	518	0	05	25
	513	0	04	31

‘SCHEDULE

चाचोडा	506	0	10	81
	504	0	15	32
	507	0	00	88
	503	0	07	87
	502	0	20	70
	901	0	10	69
	883	0	09	80
	898	0	08	91
	899	0	10	78
	900	0	02	59
	895	0	01	66
	926	0	30	44
	925	0	00	02
	927	0	50	02
	930	0	00	47
	933	0	47	82
	935	0	33	56
	936	0	18	41
	937	0	17	23
	948	0	06	53
	951	0	66	78
	950	0	00	35
	1005	0	19	60
	1006	0	23	46
	1015	0	81	23
	1016	0	17	52
	1025	0	50	04
	1024	0	31	19
	1028	0	29	11
	952	0	03	56
	500	0	00	53
	505	0	00	78
	591	0	00	78
	514	0	00	69
	314/1063	0	00	29
	582	0	01	08

[सं. ओ-14016/343/85-जी पी]

S.O. 2327.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, H.B.J. Gas Pipeline Project 49, Indra Colony, Sawai Madhopur,

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chabra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
CHANCHODA	2	1	43	75
	41	0	12	18
	40	0	08	46
	39	0	47	07
	43	0	25	70
	44	0	17	05
	43	0	05	82
	46	0	00	78
	555	0	22	68
	554	0	01	18
	561	0	13	22
	562	0	13	36
	563	0	05	56
	564	0	02	37
	565	0	01	65
	566	0	11	61
	567	0	08	18
	570	0	03	70
	573	0	00	70
	531	0	05	15
	528	0	22	49
	527	0	07	70
	526	0	09	36
	525	0	04	75
	524	0	00	88
	517	0	02	23
	515	0	04	22
	516	0	04	56
	518	0	05	25
	513	0	04	31
	506	0	10	81
	504	0	15	32
	507	0	00	88
	503	0	07	87
	502	0	26	30
	901	0	10	69
	883	0	09	80
	898	0	08	91
	899	0	10	78
	900	0	02	59
	895	0	04	66
	926	0	30	44
	925	0	00	02
	927	0	50	02
	930	0	00	47
	933	0	47	82
	935	0	33	56
	936	0	18	41
	937	0	17	23
	948	0	06	53
	951	0	66	78
	950	0	00	35
	1005	0	19	60
	1006	0	23	46
	1015	0	81	23
	1016	0	17	52
	1025	0	50	04
	1024	0	31	19
	1028	0	29	11

1	2	3	4	5
Chanchoda	952	0	03	56
	500	0	00	53
	505	0	00	78
	591	0	00	78
	514	0	00	69
	514/1063	0	00	29
	582	0	01	08

[No. O-14016/343/85-GP]

कां० प्र० 2328—यह केन्द्र य सरकार को यह प्रत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजारा-बरेली-जगद-शपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारत य गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जाना चाहिए।

और यह प्रत होता है कि ऐसा लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एन० पाइप अनुसूचा में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) का धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एन० द्वारा घोषित किया है।

बताते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नए पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार, भारत य गैस प्राधिकरण लि० बं-58 बं, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू० पी० को इस अधिसूचना का तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित, यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसका सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी निधि व्यवसाय, का मार्फत।

अनुसूची

हजारा-बरेली-जगद-शपुर तक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

श्रिता सहकाल परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल	संख्या	विवरण
1	2	3
4	5	6
7	8	9
हजारा-बरेली-जगद-शपुर	154	11
पट्टा	154	7
	527	2
	528	5
	529	1
	530	10
	531	12
	532	2
	553	10
	554	17
	557	1
	558	6
	559	15
	565	10
	572	12
	573	1
	575	2
	576	6

1	2	3	4	5	6
हजारा-बरेली-जगद-शपुर	577	--	2	--	--
पट्टा	584	1	4	--	--
	585	--	1	--	--
	586	--	1	10	--
	496	--	10	--	--
	491	1	16	--	--
	492	--	1	10	--
	493	1	4	--	--
	294	--	8	--	--
	397	--	1	--	--
	498	--	1	10	--
	496	--	1	--	--
	401	--	1	10	--
	402	--	10	--	--
	403	--	16	--	--
	412	--	2	10	--
	413	--	8	10	--
	514	--	5	--	--
	415	--	2	10	--
	416	--	6	--	--
	417	--	5	--	--
	452	--	7	--	--
	453	--	8	10	--
	454	--	8	10	--
	456	--	7	--	--
	457	--	5	--	--
	460	--	5	--	--
	458	--	1	--	--

[सं O-14016/344/85-ज प]

S O 2328—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bhanpur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd H. B. J. Gas Pipeline Project 49, Indra Colony Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Gas Pipeline from HAJIRA-BARLILLY-JAGDISHPUR Project

Dis- trict	Tehsil	Par- gana	Village	Plot No.	AREA Bigha Biswa Bis- wansi	Re- mark
1	2	3	4	5	6	7
Hardoi	Shahabad	Pachhoha	Nagla-ptiu	153	11	—
				154	7	—
				527	2	—
				528	5	—
				529	3	10
				530	—	10
				531	12	—
				532	2	10
				553	10	10
				554	1	17 10
				557	3	—
				558	6	10
				559	15	10
				565	—	10
				572	12	—
				573	1	—
				575	2	10
				576	6	—
				577	2	—
				584	1	4 —
				585	1	—
				586	1	10
				496	10	—
				391	1	16 —
				392	1	10
				393	1	4 —
				394	8	—
				397	1	—
				398	1	10
				396	1	—
				401	1	10
				402	10	—
				403	16	—
				412	2	10
				413	8	10
				414	5	—
				415	2	10
				416	6	—
				417	5	—
				452	7	—
				453	8	10
				454	8	10
				456	7	—
				457	5	—
				460	5	—
				458	1	—

[No. O-14016/344/85-GP]

कॉ.प्रां. 2329.—यन: केन्द्रिय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हर्जोग-बरेल-जगदीशपुर ... तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारत, य गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जान। चाहिए।

और यन प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन

के लिए एतद्ग्रावद्ध अनुसूच: में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) का धारा 3 का उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्षों कि उक्त भूमि में हितवाद् कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि० व - 58 बा, अल गंज, लखनऊ- 226020 यू०पी० को इस अधिसूचना का तारख से 21 दिन के अंतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि वह चाहता है कि उसका मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसाय: को माफत।

अनुसूचा

हाजिरा-बरेल-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा	क्षेत्रफल	विवरण
				संख्या	-----	
					बोधा विस्वा विस्वासा	
1	2	3	4	5	6	7
हरदोई	खिलग्राम	कटियारा	ठकपुरा	20	--	14 10
				19	--	17 --
				29	--	2 --
				30	--	19 --
				31	--	4 --
				32	--	14 --
				73	--	14 --
				74	--	7 --
				75	--	8 --
				76	--	7 --
				116	--	2 10
				117	--	18 --
				122	--	14 10
				167	--	6 --
				132	--	18 --
				173	--	12 10
				174	--	2 --
				175	--	11 --
				183	--	5 --
				184	--	12 --
				185	--	1 --
244	--	5 --				
245	--	4 10				
246	--	3 --				
247	--	2 10				
248	--	3 10				
251	--	3 --				
252	--	3 --				
256	--	5 --				
257	--	9 --				
258	--	13 --				
281	--	2 10				
318	--	2 10				

1	2	3	4	5	6
रबोई	विलग्राम	कटियारी	ढकपुरा	319	-- 6 --
				320	-- 4 --
				321	-- 2 10
				322	-- 6 --
				323	-- 3 10
				324	-- 3 --
				325	5 5 --
				328	-- 1 --
				329	-- 19 --
				253	-- -- 10
				330	-- 19 10
				331	-- 12 10
				348	-- 8 --
				349	-- -- 10
				350	-- 7 --
				352	-- -- 10
				467	-- 6 --
				468	-- 7 --
				492	-- 5 --
				493	-- 9 --
				499	-- 3 10
				500	-- 5 --
				501	-- -- 10
				601	-- 4 --
				602	-- 9 --
				498	-- 4 --
				604	-- 5 --
				642	-- 6 --
				644	-- 8 10
				645	-- 11 10
				646	-- 7 --
				648	-- 1 --
				647	-- 13 --
				707	-- 18 --
				708	-- 13 --
				709	-- 3 --
				710	-- 11 --
				711	-- 1 --
				712	-- 7 --
				814	-- 13 --
				118	-- 2 --
				121	-- 1 --
				133	-- 1 --
				326	-- -- 5
				327	-- -- 5
				603	-- 2 --
				491	-- 2 --
				497	-- 1 --
				469	-- 2 --
				488	-- -- 10

[सं० O-14016/345/85-जी०पी०]

And whereas it appears, that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Gas Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	AREA			Remarks
					Bigha	Biswa	Biswansi	
1	2	3	4	5	6			7
Har-doi	Bil-gram	Kati-yari	Dhak-pura	20	1	14	10	
				19	17	17	—	
				29	—	2	—	
				30	—	19	—	
				31	—	4	—	
				32	—	14	—	
				73	—	14	—	
				74	—	7	—	
				75	—	8	—	
				76	—	7	—	
				116	—	2	10	
				117	—	18	—	
				122	—	14	10	
				167	—	6	—	
				132	—	18	—	
				173	—	12	10	
				174	—	2	—	
				175	—	11	—	
				183	—	5	—	
				184	—	12	—	
				185	—	1	—	
				244	—	5	—	
				245	4	4	10	
				246	—	3	—	
				247	—	2	10	
				248	—	3	10	
				251	—	3	—	
				252	—	3	—	
				253	3	2	10	
				256	—	5	—	
				257	—	9	—	
				258	—	13	—	
				281	—	2	10	
				318	—	2	10	
				319	—	6	—	
				320	—	4	—	
321	—	2	10					
322	—	6	—					
323	—	3	10					
324	—	3	—					
325	—	5	—					
328	—	1	—					

S.O. 2329.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hujira-Bareilly-Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

1	2	3	4	5	6	7
Har-	Bil-	Kati-	Dhak-	329	—	17
doi	gram	yari	pura	253	—	10
				330	—	19
				331	—	10
				348	—	8
				349	—	10
				350	—	7
				352	—	10
				467	—	6
				468	—	7
				492	—	5
				493	—	9
				499	—	3
				500	—	5
				501	—	10
				601	—	4
				602	—	9
				498	—	4
				604	—	5
				642	—	6
				644	—	8
				645	—	11
				646	—	7
				648	—	1
				647	—	13
				707	—	18
				708	—	13
				709	—	3
				710	—	11
				711	—	1
				712	—	7
				814	—	13
				118	—	2
				121	—	1
				133	—	1
				326	—	5
				327	—	5
				603	—	2
				491	—	2
				497	—	1
				469	—	2
				488	—	10

[No. O-14016/345/85-GP]

कां०आ० 2340 अतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एन०पाव० अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जन करने का अपना आशय एन०पाव० घोषित किया है।

वर्णन कि उक्त भूमि में गिबबड फोर्ड व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आशय मध्यम प्राधिकार, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयाग, ए०बी०जे० पाइप लाइन 45, सुभाष नगर मार्बल राड,

उज्जैन (म०प्र०) 456001 का इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशय करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ए०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्राजेक्ट

ग्राम—रायगा नरमोन—पिछोर जिला—शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु०का० खसरा न०		उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	480	0.136
2.	479	0.240
3.	455	0.031
4.	456	0.031
5.	478	0.356
6.	177	0.010
7.	483	0.031
8.	473	0.021
9.	474	0.031
10.	475	0.105
11.	476	0.178
12.	600	0.240
13.	601	0.167
14.	603	0.345
15.	604	0.021
16.	610	0.147
17.	616	0.220
18.	617	0.260
19.	618	0.188
20.	620	0.010
21.	581	0.377
22.	582	0.021
23.	1363	0.095
24.	1364	0.157
25.	1365	0.105
26.	1368	0.073
27.	947/1460	0.042
28.	947	0.178
29.	949	0.126
30.	943	0.021
31.	946	0.272
32.	659	0.021
33.	950	0.021
34.	964	0.198
35.	965	0.052
36.	966	0.021
37.	976	0.010
38.	977	0.052
39.	957	0.010
40.	958	0.010
41.	962	0.251
42.	1010	0.021

1	2	3
43	1011	0 021
44	1012	0 010
45	1013	0 021
46	1038	0 010
47	1039	0 073
48	1040	0 031
49	1044	0 021
50	1045	0 084
51	1047	0 021
52	1046	0 062
53	1034	0 021
54	1048	0 073
55	905	0 010
56	906	0 010
57	907	0 010
58	908	0 073
59	909	0 010
60	894	0 031
61	896	0 031
62	1066	0 021
63	1068	0 042
64	1069	0 021
65	890	0 073
66	891	0 010
67	892	0 010
68	893	0 010
69	872	0 021
70	1070	0 021
71	1071	0 063
72	1072	0 010
73	1073	0 021
74	1163	0 021
75	1164	0 021
76	1101	0 053
77	1102	0 042
78	1103	0 042
79	1093	0 021
80	1094	0 073
81	1095	0 010
82	1096	0 062
83	1097	0 105
84	1099	0 021
85	1117	0 021
86	978	0 010
87	1041	0 021
88	1067	0 062
89	918	0 136
90	916	0 021
91	919	0 147
92	917	0 083
93	963	0 147
94	1015	0 021
95	1016	0 010
योग-कुल क्षेत्रफल		6 998

S O 2330—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajia Bareilly to Jagdhpur in Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Villago Payaga Tehsil Pichhore Distt—Shivpuri

SCHEDULE

S No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U in Hectar
1.	480	0 136
2	479	0 240
3.	455	0 031
4	456	0 031
5	478	0 356
6	477	0 010
7	483	0 031
8	473	0 021
9	474	0 031
10	475	0 105
11	476	0 178
12	600	0 240
13	601	0 167
14.	603	0 345
15	604	0 021
16	610	0 147
17.	616	0 220
18	617	0 260
19.	618	0 188
20.	620	0
21.	581	0 377
22.	582	0 021
23.	1363	0 095
24	1364	0 157
25.	1365	0 105
26	1368	0 073
27.	947/1460	0 042
28.	947	0 178
29	949	0 126
30.	943	0 021
31.	946	0 272
32	659	0 021
33.	950	0 021
34	964	0 198
35	965	0 052
36.	966	0 021
37	976	0 010
38.	977	0 052
39	957	0 010
40	958	0 010

1	2	3
41.	962	0.251
42.	1010	0.021
43.	1011	0.021
44.	1012	0.010
45.	1013	0.021
46.	1038	0.010
47.	1039	0.073
48.	1040	0.031
49.	1044	0.021
50.	1045	0.084
51.	1047	0.021
52.	1046	0.062
53.	1034	0.021
54.	1048	0.073
55.	905	0.010
56.	906	0.010
57.	907	0.010
58.	908	0.073
59.	909	0.010
60.	894	0.031
61.	896	0.031
62.	1066	0.021
63.	1068	0.042
64.	1069	0.021
65.	890	0.073
66.	891	0.010
67.	892	0.010
68.	893	0.010
69.	872	0.021
70.	1070	0.021
71.	1071	0.063
72.	1072	0.010
73.	1073	0.021
74.	1163	0.021
75.	1164	
76.	1101	0.053
77.	1102	0.042
78.	1103	0.042
79.	1093	0.021
80.	1094	0.073
81.	1095	0.010
82.	1096	0.062
83.	1097	0.105
84.	1099	0.021
85.	1117	0.021
86.	978	0.010
87.	1041	0.021
88.	1067	0.062
89.	918	0.136
90.	916	0.021
91.	919	0.147
92.	917	0.083
93.	963	0.147
94.	1015	0.021
95.	1016	0.010
Total area		6.998

[No. O-14016/346/85-GP]

का.भा. 2341:- यत्. केन्द्रिय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजौरा में बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के पश्चिमत के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जाना चाहिये।

और यत् यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्प्रादेश अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की द्वारा 3 क उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रिय सरकार न उभरे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का शपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बतते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच०बी०जे० पाईप लाइन 45, मुम्बई नगर, मांवेर रोड, उज्जैन (म०प्र०) 456001 को इस अधिसूचना को तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

आगे ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिवृष्टत. यह भी कथन करने कि क्या यह वाहता है कि उसका मुतवाई व्यक्तिगत रूप में नो या किम। विधि व्यवसाय। का मार्फत।

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम—छिन्नाहा तहसील— पिछोर जिला—शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)
अनुसूची

अनु० क्र.	खगरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर में)
1	2	3
1.	2243	0.167
2.	2258	0.031
3.	2252	0.606
4.	2215	0.031
5.	2164	0.010
6.	2163	0.031
7.	2162	0.021
8.	2143	0.490
9.	576	0.053
10.	2051	0.261
11.	2052	0.021
12.	2053	0.178
13.	2054	0.010
14.	547	0.115
15.	554	0.031
16.	2055	0.010
17.	553	0.105
18.	2064	0.021
19.	2048	0.167
20.	2049	0.188
21.	2046	0.010
22.	551	0.010
23.	801	0.126
24.	2015	0.021
25.	546	0.010
26.	2043	0.136
27.	2042	0.167
28.	2044	0.084
29.	2041	0.021
30.	2040	0.012
31.	1961	0.031
32.	1962	0.010
33.	548	0.021

1	2	3	1	2	3
34.	1963	0.010	90.	831	0.105
35.	539	0.147	91.	833	0.304
36.	532	0.156	92.	839	0.136
37.	533	0.095	93.	840	0.126
38.	536	0.084	94.	320/3158	0.010
39.	537	0.105	95.	571	0.188
40.	538	0.010	96.	322	0.010
41.	540	0.137	97.	321 मी०	0.010
42.	549	0.031	98.	803/3145	0.021
43.	555	0.031	99.	2137	0.188
44.	582	0.157	100.	2159	0.261
45.	583	0.021	101.	2165	0.083
46.	607	0.010	102.	2196	0.031
47.	579	0.199	103.	2137/31/56	0.199
48.	793	0.010	104.	2139	0.304
49.	800	0.126	105.	2140	0.230
50.	810	0.209	106.	2195	0.325
51.	809	0.115	107.	2241	0.220
52.	808	0.010	108.	2242	0.021
53.	580	0.010	109.	2256	0.387
54.	581	0.010	110.	2141	0.220
55.	577	0.010	111.	2197	0.157
56.	578	0.021	112.	2199	0.010
57.	572	0.021	113.	832	0.073
58.	608	0.042	114.	841	0.063
59.	612	0.031			
60.	613	0.010			
61.	753	0.084			
62.	755	0.010			
63.	756	0.010			
64.	748	0.084			
65.	811	0.052			
66.	744	0.073			
67.	742	0.063			
68.	841	0.084			
69.	736	0.084			
70.	735	0.105			
71.	807	0.042			
72.	734	0.010			
73.	733	0.010			
74.	819	0.272			
75.	752	0.021			
76.	737.	0.021			
77.	723	0.095			
78.	724	0.178			
79.	725	0.010			
80.	726	0.052			
81.	728	0.010			
82.	713	0.010			
83.	806	0.021			
84.	823	0.010			
85.	822	0.010			
86.	824	0.209			
87.	826	0.219			
88.	830	0.304			
89.	828	0.010			

योग कुल क्षेत्रफल

10.899

[सं० O-14016/347/85-जं० पी]

S.O. 2331.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from HAZIRA-BARILLY to JAGADISHPUR in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil Natural Gas Commission, HBJ Gas PipeLine 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT		
Village : Chhirwaha Tehsil : Pichhore Distt. : Shivpuri		
SCHEDULE		
S No.	Survey No.	Area to be acquired R.O.U. in Hecter
1.	2243	0.167
2.	2258	0.031
3.	2252	0.606
4.	2215	0.031
5.	2164	0.010
6.	2163	0.031
7.	2162	0.021
8.	2143	0.490
9.	576	0.053
10.	2051	0.261
11.	2052	0.021
12.	2053	0.178
13.	2054	0.010
14.	547	0.115
15.	554	0.031
16.	2055	0.010
17.	553	0.105
18.	2064	0.021
19.	2048	0.167
20.	2049	0.188
21.	2046	0.010
22.	551	0.010
23.	801	0.126
24.	2045	0.021
25.	546	0.010
26.	2043	0.136
27.	2042	0.167
28.	2044	0.084
29.	2041	0.021
30.	2040	0.042
31.	1961	0.031
32.	1962	0.010
33.	548	0.021
34.	1963	0.010
35.	539	0.147
36.	532	0.156
37.	533	0.095
38.	536	0.084
39.	537	0.105
40.	538	0.010
41.	540	0.137
42.	549	0.031
43.	555	0.031
44.	582	0.157
45.	583	0.021
46.	607	0.010
47.	579	0.199
48.	793	0.010
49.	800	0.126
50.	810	0.209
51.	809	0.115
52.	808	0.010
53.	580	0.010
54.	581	0.010
55.	577	0.010
56.	578	0.021
57.	572	0.021
58.	608	0.042
59.	612	0.031
60.	613	0.010
61.	753	0.084

1	2	2
62.	755	0.010
63.	756	0.010
64.	748	0.084
65.	811	0.052
66.	744	0.073
67.	742	0.063
68.	741	0.084
69.	736	0.084
70.	735	0.105
71.	807	0.042
72.	734	0.010
73.	733	0.010
74.	819	0.272
75.	752	0.021
76.	737	0.021
77.	723	0.095
78.	724	0.178
79.	725	0.010
80.	726	0.052
81.	728	0.010
82.	713	0.010
83.	806	0.021
84.	823	0.010
85.	822	0.010
86.	824	0.209
87.	826	0.219
88.	830	0.304
89.	828	0.010
90.	831	0.105
91.	833	0.304
92.	839	0.136
93.	840	0.126
94.	320/3158	0.010
95.	571	0.188
96.	322	0.010
97.	321 M.	0.010
98.	803/3145	0.021
99.	2137	0.188
100.	2159	0.261
101.	2165	0.083
102.	2196	0.031
103.	2137/3156	0.199
104.	2139	0.304
105.	2140	0.230
106.	2195	0.325
107.	2241	0.220
108.	2242	0.021
109.	2256	0.387
110.	2141	0.220
111.	2197	0.157
112.	2199	0.010
113.	832	0.073
114.	841	0.063
TOTAL AREA		10.899

[No. O-140016/347/85-GP]

का० प्रा० 2332—केन्द्रिय सरकार को यह प्रस्ताव होता है कि लोकहित यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में नजरा से बरेली से जगयाश-पुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राप्ति-करण लि० द्वारा बिछाई जाना चाहिये।

और यतः यह प्रस्ताव होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूचा में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अन्य प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के धारा 3 के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राण्य एतद्वारा घोषित किया है।

बनते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के तत्वे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार, तैयार तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एन.ए.ओ. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर सावर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना के तारखे से 21 दिनों के अन्दर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसका, सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किमं विधि व्यवसाय का मार्फत।

एन.ए.ओ. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम ककरोबा उर्फ टूत, तहसील पिछोर जिला-शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र०	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
1	2	3
1.	1641	0.108
2.	1642	0.390
3.	1643	0.119
4.	1646	0.504
5.	1645	0.314
6.	1649	0.231
7.	1766	0.243
8.	1767/1984	0.564
9.	1782	0.564
10.	1788	0.214
11.	1789	0.282
12.	1792	0.593
13.	1873	0.131
14.	1878	0.105
15.	1627	0.010
16.	1626	0.010
17.	1875	0.174
18.	1790	0.081
19.	1639	0.020
20.	1628	0.021
21.	1764	0.021
22.	1881	0.021
23.	1882	0.197
24.	1877/2	0.200
25.	1876	0.280
26.	1871	0.105
27.	1640	0.062
योग-कुल क्षेत्रफल		5.621

[म.प्र. O-11016/348/85-जी पी]

S.O. 2332.--Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil Natural Gas Commission, HBI Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBI GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Karkowa URF Thuni; Tehsil Pichhore Distt. : Shivpuri

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1	2	3
1.	1641	0.108
2.	1642	0.390
3.	1643	0.119
4.	1646	0.504
5.	1645	0.314
6.	1649	0.231
7.	1766	0.243
8.	1767/1984	0.564
9.	1782	0.684
10.	1788	0.214
11.	1789	0.282
12.	1792	0.593
13.	1873	0.131
14.	1878	0.105
15.	1627	0.010
16.	1626	0.010
17.	1875	0.174
18.	1790	0.081
19.	1639	0.020
20.	1628	0.021
21.	1764	0.021
22.	1881	0.021
23.	1882	0.197
24.	1877/2	0.200
25.	1876	0.280
26.	1871	0.105
27.	1640	0.062
Total Area		5.621

[No. O-14016/348/85-GP]

का.प्रा. 2334 --यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजिरा-बरेली-जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसा लाइनों को बिछाने का प्रयाजन के लिए, एतदुपायक अधिसूचना में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) का धारा 3 के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राण्य एतद्वारा घोषित किया है।

बनते कि, उस भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के तत्वे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार, भारतीय गैस प्राधिकरण

वि. बी-58/बी अलिगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना को पाराख में 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजिरा-बरेल्ल-जगद शपुर तक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल बीघा-बिसवा-बिस्वा में	
1	2	3	4	5	6	
हरदोई	शाहाबाद	पछाहा	पचरैया	422	--	1 8
				423	1	0 10
				424	0	0 9
				425	--	9 18
				426	--	11 11
				436	0	0 4
				437	--	1 10
				438	--	4 --
				439	--	10 --
				440	--	3 6
				442	1	-- 7

[स. O-14016/349/85-जी०]

S.O. 2333.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. (H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Gas Pipe Line From Hazira-Bareilly-Jagdishpur Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area	
					Bigha	Biswa Biswansi
1	2	3	4	5	6	
Hardoi	Shahabad	Pachaha	Pacharaya	422	--	4 8
				423	1	0 10
				424	0	0 9
				425	--	9 18
				426	--	11 11
				436	0	0 4
				437	--	1 10
				438	--	4 --
				439	--	10 --
				440	--	3 6
				442	1	-- 7

[स. O-14016/349/85-GP]

का प्रा. 2333—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लाईन में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजिरा से बरेली में जगद शपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारत गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यहाँ पर प्रतीत होता है ऐसी लाइनों को रखाने के परोक्ष के लिये एतद्पाइपलाइन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बताने कि उस भूमि में हितवश कोई व्यक्ति उस भूमि के लिये पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाइप लाइन 45, मुम्बई नगर, सावित्री रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना के पाराख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

अनु. क्र.	खसरा न.	उपयोग	अधिकार	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	23			0.231
2	24			0.188
3	25			0.063
4	32/1			0.736
5	78/2			0.449
6	52/4			0.136
7	56			0.369
8	72/2			1.415
9	73/1			0.649
10	174			0.125
11	188			0.052
12	189			0.063
13	190			0.052
14	197			0.073
15	198			0.125
16	230			0.010
17	231			0.063
18	232			0.071
19	233			0.063
20	234			0.073
21	236			0.052
22	237			0.052
23	238			0.052
24	270			0.021
25	271			0.051
26	268			0.081

1	2	3
27	253	0 105
28	285	0 031
29	201	0 126
30	221	0 115
31	227	0 021
32	60	0 136
33	49	0 005
34	46	0 063
35	282	0 010
36	315	0 125
37	1	0 010
38	15	0 051
39	22	0 012
40	2/2	0 010
41	46	0 063
42	49	0 063
43	74	0 073
44	81	0 031
45	200	0 010
46	204	0 021
47	213	0 010
48	256	0 010
49	257	0 010
50	259	0 010
51	260	0 021
52	261	0 010
53	262	0 010
54	263	0 031
55	264	0 021
56	265	0 072
57	269	0 010
58	277	0 031
59	319	0 031
60	324	0 021
61	339	0 052
62	342	0 021
63	343	0 052
64	61	0 042
65	235/740	0 125
66	235	0 012
67	317	0 031
68	288	0 147
69	309	0 021
70	310	0 052
71	311	0 157
72	312	0 177
73	313	0 073
74	335	0 197
75	336	0 115
76	337	0 051
77	338	0 157
78	338/741	0 012
79	334/74	0 251
योग—कुल क्षेत्रफल		8 640

SO 2234—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazira Baitilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipeline 45 Subhash Nagar Sanwer Road Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village—Budhonrajpur		Tehsil Pitchhore Distt—Shivpuri	
S No	Survey No	Area to be Acquired for R O U in Hectare	
1	23	0 231	
2	24	0 188	
3	25	0 063	
4	32 1	0 736	
5	78 2	0 449	
6	52/1	0 136	
7	56	0 369	
8	72/2	1 415	
9	73/1	0 649	
10	178	0 125	
11	188	0 052	
12	189	0 063	
13	190	0 052	
14	197	0 073	
15	198	0 125	
16	230	0 010	
17	231	0 062	
18	232	0 074	
19	233	0 063	
20	234	0 073	
21	236	0 052	
22	237	0 052	
23	238	0 052	
24	270	0 021	
25	271	0 081	
26	265	0 081	
27	283	0 105	
28	285	0 031	
29	284	0 136	
30	286	0 115	
31	287	0 021	
32	60	0 136	
33	42	0 063	
34	46	0 063	
35	28	0 010	
36	315	0 125	
37	338	0 010	
38	318	0 031	
39	22	0 04	
40	32 2	0 010	
41	46	0 063	

42	49	0 063
43	74	0 073
44	51	0 031
45	00	0 010
46	204	0 021
47	243	0 010
48	256	0 010
49	257	0 010
50	59	0 010
51	260	0 021
52	261	0 010
53	262	0 010
54	263	0 031
55	264	0 021
56	265	0 072
57	269	0 010
58	277	0 031
59	319	0 031
60	324	0 021
61	339	0 052
62	342	0 022
63	343	0 052
64	61	0 042
65	235 740	0 125
66	235	0 042
67	312	0 031
68	288	0 147
69	309	0 021
70.	310	0 052
71	311	0 157
72	312	0 177
73.	313	0 073
74	335	0 197
75	336	0 115
76	337	0 081
77	338	0 157
78.	238 74	0 042
79	334 743	0 251
Total Area		8 640

[No. O-14016/350/85 G P]

का आ १३१५—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग व अधिकार वा अर्जन) अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५०) की धारा ३ की उपधारा (१) व अश्वीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ म १३१५ तारीख १२.७.८४ द्वारा कन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना में सलन अनुसूची में निम्नलिखित भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाठ्य लाहना की विधान के विरुद्ध अर्जित करने का अपना आशय वाचिन कर दिया था।

आर.एस. मन्थन प्रा. रसिणी न. उमन सधितियन का भाग (५) का
उपभाग (१) क अधीन गन्तव्य का गिपिट द. का है।

और आगे यत संशोधन संस्कार व उका रिपोर्ट पर विचार करने से पश्चात हम प्रशिक्षण से रास्ता प्रवृत्त व विनिर्दिष्ट भूमिका में उपयोग का अधिकार सज्जित करने का विनिश्चय लिया है।

अब आ उत्तर अधिनियम का प्राग (१) की धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्ति से प्राग राज्य हण के साथ संलग्न एकराया घोषित करना है कि हम अधिसूचना न संख्या अन्वुता ग विविधित उक्त सूचिया म उपयोग में लीएंग सांस्कृतिक विद्या के पठान के लिए एकराया प्रतिष्ठित करेगा ।

प्रयोग करत ह्या नेटवर्क सरकार मे निहित जते ते प्रजाप भागीप गैस

प्रतिष्ठापन नि. स. मशी बाध्याग्री से मुक्त हो स. पाठना के पक्षाशन को
इस तारीख का निर्दिष्ट जगा ।

प्र र म्या

हजाग प्रेमनाथ। दीक्षापुर लक्ष पाछर ताहिन विश्वास क रीति।

राज्य गजगत जिला यमुना बावका उमार्ह

गॉथ	सब न	हेक्सेयर	गप्ररई	मेल्पीयर
जोया जना वरा	कर्ट २८	०	०३	५६
	२४३	०	२७	२०
	२४१	०	०१	७६
	२५०	०	००	३३
	२५२	०	२४	१८
	२४१	०	०९	५३
	२८०	०	०९	१२
	२७७	०	२५	६०
	२७३	०	११	२०
	२७३	०	११	२०
	२७४	०	०४	००
	२६५	०	०४	६४
	२५७	०	००	५६
	२७५	०	२२	००
	२६४/१	०	०४	४८
	२६४/२	०	०६	४०
	२६२	०	०९	४४
	२६१	०	१२	६३
	२६३/१	०	०७	२०
	२६४/२	०	०३	५२
	१५	०	१४	५०
खारावा		०	०३	५०

[મ ઓ-12016/61/84-ગ્રાન્ટ જો-ડી]

S.O. 2335.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2395 dated 12.7.1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline,

And where as the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (1) of that section the Central Government directs that the right of alienation in such lands shall instead of vesting in Central Government vest on the date of the notification of alienation in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

[No. 0-120] 6-61-84 OREGON IV]

SCHEDULE				
Pipeline from Hujira—Barcilly—Jagdishpur				
State : Gujarat	District : Vadodara	Taluka : Dahhoi		
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Jivatalavadi	Cart Track	0	03	96
	283	0	27	20
	284	0	01	76
	290	0	00	32
	282	0	24	48
	281	0	09	92
	280	0	09	12
	277	0	25	60
	272	0	11	20
	273	0	11	20
	274	0	04	00
	268	0	04	64
	257	0	00	96
	275	0	22	00
	264/1	0	04	48
	264/2	0	06	40
	262	0	09	44
	261	0	12	62
	263/1	0	07	20
	263/2	0	03	52
	95	0	14	50
	Kharabo	0	03	50

[No. O-12016/61/84-ONG-D4]

का. प्रा. 2336.—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का प्रा. सं. 4105 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था,

और यत् सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और प्रागे, यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है;

और प्रागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में वायु का प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हुजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : अकलेश्वर

गांव	सर्वे नं	हैक्टर	आर	सन्टीयर
1	2	3	4	5
मोडवा बुजर्गे	636	0	26	88
	637	0	41	20
	638	0	36	00
	4	0	20	00

1	2	3	4	5
	गमनाल	0	71	78
	99	0	01	92
	100	0	06	40
	101	0	12	00
	103	0	03	20
	101	0	20	29
	105	0	02	40
	कादें ट्रेक	0	01	50
	179	0	07	20
	178	0	07	20
	177	0	08	80
	173	0	11	52
	174	0	13	15
	175	0	01	92
	160	0	09	60
	159	0	10	72
	158	0	09	60
	154	0	26	40
	152	0	18	40
	150	0	14	40
	149	0	20	00
	148	0	45	60
	273	0	19	20
	274	0	04	00
	276	0	27	20
	277	0	06	40
	297	0	18	88
	295	0	20	80
	296	0	01	92
	362	0	23	20
	361	0	25	92
	359	0	16	80
	354	0	09	12
	355	0	06	88

[स. O-14016/66-ए/84 की फी]

S.O. 2336.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S. O. 4105 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM HAJIRA-BAREILLY-JAGDISHPUR
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Centiare
Mandva Buzarg	636	0	26	88
	637	0	31	20
	638	0	36	00
	4	0	20	00
	Gamtal	0	71	78
	99	0	01	92
	100	0	06	40
	101	0	12	00
	103	0	03	20
	104	0	20	29
	105	0	02	40
	Cart Track	0	04	50
	179	0	07	20
	178	0	07	20
	177	0	08	80
	173	0	11	52
	174	0	13	15
	175	0	01	92
	160	0	09	60
	159	9	10	72
	158	0	09	60
	154	0	26	40
	152	0	18	40
	150	0	14	40
	149	0	20	00
	148	0	45	60
	273	0	19	20
	274	0	04	00
	276	0	27	20
	277	0	06	40
	297	0	18	88
	295	0	20	80
	296	0	01	92
	362	0	23	20
	361	0	25	92
	359	0	16	80
	354	0	09	12
	355	0	06	88

[No. O-14016/66-A/84-GP]

का.प्रा. 2337—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का आ. म. 3473 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मलमल अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आणख घोषित कर दिया था ;

और यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में मलमल अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मलमल अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के पक्ष में अर्जित करने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निम्नित्त ज्ञान के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से, धारणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

गुज. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम	सीगबामा	तहसील	गुना	जिला	गुना	राज्य (म.प्र.)
अनुक्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)				
1.	276	0-679				
2.	274	0-042				
3.	287	0-261				
4.	288	0-157				
5.	273	0-470				
6.	289	0-031				
7.	270	0-105				
8.	290	0-010				
9.	272	0-209				
10.	292	0-105				
11.	231	0-050				
12.	253/2	0-200				
13.	241	0-146				
14.	219	0-052				
15.	240	0-157				
16.	239	0-188				
17.	212	0-105				
18.	220	0-523				
19.	222	0-177				
20.	221	0-314				
21.	218/2	0-300				
22.	238	0-418				
23.	237/1/1	0-470				
24.	237/2	0-470				
25.	401/1/2	0-261				
26.	400	0-076				
27.	402	0-031				
28.	403/1	0-105				
29.	232	0-470				
30.	230	0-345				
31.	218/1	0-300				
32.	251	0-052				
33.	252	0-010				
34.	66/1	0-021				
35.	213	0-031				
36.	234/1	0-052				
37.	256	0-010				

कुल क्षेत्रफल :— 6-933

[म० O-14016/73/8-जोड़ें]

S.O. 2337.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3473 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPELINE PROJECT

VILLAGE : SINGWASA TEHSIL : GUNA DISTT. GUNA

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	276	0.679
2.	274	0.042
3.	287	0.261
4.	288	0.157
5.	273	0.470
6.	289	0.031
7.	270	0.105
8.	290	0.010
9.	272	0.209
10.	292	0.105
11.	231	0.050
12.	253/2	0.200
13.	241	0.146
14.	219	0.052
15.	240	0.157
16.	239	0.188
17.	212	0.105
18.	220	0.523
19.	222	0.177
20.	221	0.314
21.	218/2	0.300
22.	238	0.418
23.	237/1/1	0.470
24.	237/2	
25.	401/1/2	0.261
26.	400	0.076
27.	402	0.031
28.	403/1	0.105
29.	232	0.470
30.	230	0.345
31.	218/1	0.300
32.	251	0.052
33.	252	0.010
34.	66/4	0.021
35.	213	0.031
36.	234/1	0.052
37.	256	0.010
Total Area		6.933

[No. O-14016/73/81-GP]

का आ 2338--यत वेदालियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के पतापर या पर्वत) पत्रिका, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 में प्रमाण (1) के तहत भारत सरकार में वेदालियम मन्त्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1474 तारीख 3-11-81 द्वारा

केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मन्त्र अतुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना अधिकार घोषित कर दिया था,

और यत मन्त्र अधिकांश ने उक्त अधिनियम की धारा 6 का उपधारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट द दी है ;

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में मन्त्र अतुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ,

अब जत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान शक्ति का प्रयोग करत हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मन्त्र अतुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमिया में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदान शक्तिया का प्रयोग करत हुए केन्द्रीय सरकार में निम्न ज्ञात के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइपलाइन प्राजेक्ट

ग्राम : मंदला तहसील, बदनाबर जिला : धार राज्य (म.प्र.)

अनु. क्र. खसरा न. उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)

1.	92/1	1-126
2.	107	0-013
3.	126/1	0-506
4.	91/1/1	0-746
5.	91/1/2	0-557
6.	91/1/3	1-556
7.	241/1	0-278
8.	595/1	0-721
9.	591/1	0-584
10.	590	0-240
11.	589/2	0-114
12.	585/4	0-091
13.	385/5	0-226
14.	584	0-331
15.	583	0-065
16.	559/1/1	0-455
17.	576	0-078
18.	575	0-292
19.	571	0-278
20.	573	0-315
21.	579/1	0-013
22.	579/1/2	0-126
23.	572	0-018
24.	571	0-506
25.	570/1	0-734
26.	608/2	0-039
27.	569	0-089
28.	568	0-099
29.	709/1/1	1-517
30.	566	0-075

1	2	3
31	558/1	0-152
32	731	0-157
33	731/1	0-031
34	770	0-009
35	771	0-116
36	771	0-157
37	777	0-114
38	780	0-392
39	791	0-039
40	791	0-025
41	791	0-126
42	799	0-025
43	961	0-113
44	951	0-126
45	960	0-078
46	962	0-189
47	956/2 } 951/2 }	0-206
48	983	0-078
49	982	0-130
50	978	0-065
51	984	0-039
52	985	0-051
53	986	0-114
54	991/2	0-066
55	995	0-025
56	1010	0-253
57	1036/2 } 1011/1 }	0-051
58	1017/1	0-114
59	1017/2	0-304
60	1051	0-165
61	1051	0-099
62	1051	0-025
63	1017	0-304
64	1058	0-139
65	1061	0-139
66	1145	0-139
67	1146	0-139
68	1147	0-139
69	1147	0-089
70	1149	0-367
71	1151/1	0-266
72	1152	0-089
73	1153	0-031
74	1151/2	0-0
कुल क्षेत्रफल		17-957

[सं O-14016/76/84 जीपी]

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Governments on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from all encumbrances

SCHEDULE

H B I Gas Pipeline Project

VILLAGE : SANDALA : TEHSIL : BADNAWAR,

DISTT DHAR

S. No	Survey No	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	92/1	1.126
2.	107	0.013
3.	126/1	0.506
4.	91/1/1	0.746
5.	91/1/2	0.557
6.	91/1/3	1.556
7.	241/1	0.278
8.	595/1	0.721
9.	591/1	0.584
10.	590	0.240
11.	589/2	0.114
12.	585/4	0.091
13.	385/5	0.226
14.	584	0.331
15.	583	0.065
16.	559/1/1	0.455
17.	576	0.078
18.	575	0.292
19.	574	0.278
20.	573	0.318
21.	579/1	0.013
22.	579/1/2	0.126
23.	572	0.013
24.	571	0.506
25.	570/1	0.734
26.	608/2	0.039
27.	569	0.039
28.	568	0.089
29.	709/1/1	1.517
30.	566	0.075
31.	556/1	0.152
32.	751	0.152
33.	798/1	0.039
34.	770	0.202
35.	774	0.126
36.	776	0.187
37.	777	0.114
38.	780	0.322
39.	791	0.039
40.	792	0.075
41.	794	0.126
42.	949	0.025
43.	961	0.113
44.	952	0.176
45.	960	0.078
46.	96	0.189

S.O. 2338 -Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3474 Date 31.11.84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline

1	2	3	अनुसूची
47.	956/2 981/2 }	0.266	पञ्च. कां. जे. गैस पाइपलाइन प्राजेक्ट
48.	983	0.078	ग्राम : बखतपुरा तहसील, बरनाहर जिला, पंजाब राज्य (मध्य-प्रदेश)
49.	987	0.130	पञ्च. क. स्वराज, उपयोग अधिकार यार्जन का क्षेत्र (ट्रैक्टमेंट में)
50.	978	0.065	1 2 3
51.	984	0.039	1. 72 0-076
52.	985	0.051	2. 68 0-379
53.	986	0.114	3. 61/2 0-063
54.	994/2	0.266	4. 61/3 0-089
55.	995	0.025	5. 61/1 0-177
56.	1040	9.253	6. 61/4 0-126
57.	1036/2 1041/1	0.051 0.114	7. 55 0-266
58.	1047/1	0.304	8. 56 0-139
59.	1047/2	0.165	9. 54 0-038
60.	1059	0.089	10. 48 0-721
61.	1056	0.025	11. 237/1 0-316
62.	1057	0.304	12. 239 0-013
63.	1058	0.139	13. 246 0-139
64.	1064	0.331	14. 247 0-025
65.	1145	0.139	15. 248 0-089
66.	1146	0.126	16. 249 0-114
67.	1147	0.089	17. 293/1/2 0-367
68.	1149	0.367	18. 294 0-038
69.	1151/1	0.266	19. 381/1 0-203
70.	1152	0.089	20. 474 0-038
71.	1153	0.039	21. 473 0-063
72.	1151/2	0.202	22. 383 0-025
Total Area		17.987	23. 470 0-126
[No. O-14016/76/84-GP]			24. 384 0-342

का. आ. 2319. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) क. धारा 3 क. उपधारा (1) के अधिन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का अधिसूचना का. आ. सं. उप 80 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रिय सरकार ने उस अधिसूचना से सम्बन्धित अनुसूच में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जन करने का अर्पण आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम का धारा 6 की उपधारा (1) के अधिन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रिय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सम्बन्धित अनुसूच में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम क. धारा 6 क. उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार एतद्वारा घोषित करत है कि इस अधिसूचना में सम्बन्धित अनुसूच में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जन किया जाता है ;

और आगे उस धारा क. उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार में निहित होने के बजाय भारत में गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं में मुक्त रूप से धोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा ।

कुल क्षेत्रफल :- 4-549

[म. O-14016/88/84-जोषी]

S.O. 2339.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry Petroleum S.O. 3480 Date 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Bakhtpur Tehsil : Badnawar Distt. Dhar

S.No.	Survey No	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	77	0.076
2.	68	0.379
3.	61/7	0.063
4.	61/3	0.089
5.	61/1	0.177
6.	61/4	0.126
7.	55	0.266
8.	56	0.139
9.	54	0.038
10.	48	0.721
11.	237 1	0.316
12.	239	0.013
13.	246	0.139
14.	247	0.025
15.	248	0.089
16.	249	0.114
17.	293/1/2	0.367
18.	294	0.038
19.	381/1	0.203
20.	474	0.038
21.	473	0.063
22.	383	0.025
23.	470	0.126
24.	384	0.342
25.	398/2	0.089
26.	398/1/1	0.051
27.	399/1	0.063
28.	399/2	0.089
29.	400	
30.	406	0.126
31.	401	0.114
32.	403	0.038
33.	404	0.063
34.	407	0.101
35.	403	0.126
36.	468/1 1	0.051

1	2	3
36.	412	0.038
37.	413/2	0.013
38.	413/3	0.025
39.	467/2	0.051
40.	760/412	0.063
41.	464/1	0.038
42.	465	0.266
43.	69	0.008
44.	293/2	0.025
45.	471	0.025
46.	411	0.010
47.	413/1	0.025
Total Area		4 549

[No. O-14016/88/84—GP]

का आ 2340—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना कां. आ. सं. 3755 तारीख 6-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आणख घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से निश्चित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निश्चित होगा।

अनुसूची

हजीरा में बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य : गुजरात जिला : व तालुका : भरुच

गांव	सर्वे. न.	ह. आ. से.
1	2	3
मानोरा	411	0-27-75
	410	0-16-00
	409	0-05-06
	407	0-41-21
	408	0-16-34
	404	0-47-25
	Cart track	0-05-70
	393	0-33-60
	392	0-12-30
	388	0-55-34

1	2	3
झानौर—जारी	354	0-14-77
	387	0-09-00
	355	0-36-50
	353	0-01-35
	358	0-02-10
	331	0-21-90
	330	0-23-70
	327	0-02-10
	328	0-32-88
	329	0-07-69
	325	0-30-30
	Cart track	0-04-30
	220	0-31-80
	221	0-02-88
	225	0-24-52
	224	0-13-20
	181	0-38-75
	226	0-00-05
	230	0-71-55
	235	0-10-09
	236	0-00-86
	234	0-03-15
	Cart track	0-03-20
	143	0-00-60
	141	0-53-10
	140	0-34-40
	136	0-26-52
	113	0-27-90
	115	0-09-94
	114	0-39-14
	122	0-03-51
	121	0-39-00

[सं. O-1401/105/84-जीपी]

S.O. 2340.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3755 dated 6-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE				
Pipeline from Hajira—Baradilly—Jagdishpur				
State : Gujarat District & Taluka : Bharuch				
Village	Survey No.	H.	A.	CA.
Zanor	411	0	27	75
	410	0	16	00
	409	0	05	06
	407	0	41	21
	408	0	16	34
	404	0	47	25
	Cart track	0	05	70
	393	0	33	60
	392	0	12	30
	388	0	55	34
	354	0	14	77
	387	0	09	00
	355	0	36	50
	353	0	01	35
	358	0	02	10
	331	0	21	90
	330	0	23	70
	327	0	02	10
	328	0	32	88
	329	0	07	69
	325	0	30	30
	Cart track	0	04	30
	220	0	31	80
	221	0	02	88
	225	0	24	52
	224	0	13	20
	181	0	38	75
	226	0	00	05
	230	0	71	55
	235	0	15	09
	236	0	00	86
	234	0	03	15
	Cart Track	0	03	20
	143	0	00	60
	141	0	53	10
	140	0	34	40
	136	0	26	52
	113	0	27	90
	115	0	09	94
	114	0	39	14
	122	0	03	51
	121	0	39	00

[No. O-14016/105/84-GP]

का. आ. 2341.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3756 तारीख 6-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जन करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है।

और अतः, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा प्रजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली में जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : अक्लेश्वर

गांव	सर्वे नं.	हे. आ. से.
कांसीया	18/पी	0-24-00
	95/13	0-25-60
	95/15	0-03-20
	96/7	0-44-00
	96/6	0-01-76
	97/24	0-36-00
	97/22	0-62-52
	97/21	0-01-28
	97/20	0-21-60
	97/17	0-01-76
	97/23	0-26-40
	97/28	0-08-40
	97/25	0-00-24
	98	0-12-00

[सं. O-14016/107/84-जीपा]

S.O. 2341.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3756 dated 6-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Survey No.	H.	A.	CA.
1	2	3		
Kansiya	16/P	0	24	00
	95/13	0	25	60
	95/15	0	03	20
	96/7	0	44	00

1	2	3
	96/6	0 01 76
	97/24	0 36 00
	97/22	0 62 52
	97/21	0 01 28
	97/20	0 21 60
	97/17	0 01 76
	97/23	0 26 40
	97/28	0 06 40
	97/25	0 00 24
	98	0 12 00

[No. O-14016/107/84-GP]

का. मा. 2341.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. मा. सं. 3757 तारीख 6-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है।

अथ, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 [की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा प्रजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : अक्लेश्वर

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	एचआरई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कांसी	197	0	05	60
	188	0	68	48
	194	0	24	00
	193	0	12	00
	192	0	43	20
	260/ए+बी	0	13	62
	203	0	19	20
	202	0	30	40
	219	0	40	80
	222	0	44	00
	223	0	00	64
	224	0	40	00
	214	0	50	40

1	2	3	4	5
	213	0	17	60
	76	0	61	60
	कार्ट ट्रैक	0	03	52
	70	0	42	40
	51	0	56	00
	52	0	38	08
	53	0	16	00
	54	0	22	20
	55	0	17	85
	260	0	24	75
	261	0	10	27
	262	0	50	00
	263	0	10	08
	350	0	74	41
	313	0	07	12
	312	0	54	45
	311	0	05	17
	310	0	12	70
	296	0	85	90
	300	0	01	75
	298	0	37	33
	297	0	34	02

[सं. O-14016/108/84-जी पी]

S.O. 2342.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3757 dated 6-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in and) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section Central Government directs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Bareilly to Jagdishpur
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshmar

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Cent tiare
1	2	3	4	5
Bhadi	197	0	05	60
	188	0	68	48
	194	0	24	90
	193	0	12	00

1	2	3	4	5
	192	0	43	20
	200/A+B	0	13	92
	203	0	19	20
	202	0	30	40
	219	0	40	80
	222	0	44	00
	223	0	00	64
	224	0	40	80
	214	0	50	40
	213	0	17	60
	76	0	61	60
	Cart track	0	03	52
	70	0	42	40
	51	0	56	00
	52	0	38	80
	53	0	16	00
	54	0	22	20
	55	0	17	85
	260	0	24	75
	261	0	10	27
	262	0	50	00
	263	0	10	08
	350	0	74	41
	313	0	07	12
	312	0	54	45
	311	0	05	17
	310	0	12	70
	296	0	85	90
	300	0	01	75
	298	0	37	33
	297	0	34	02

[No. O-14016/108/84-GP]

का.आ. 2343—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० अ० सं० 3681 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवम् द्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में बाधना के प्रशासन की इस तारीख की निर्दिष्ट होगी।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—अंकलेश्वर

गांव	सर्वे न.	हे. अ. फ.
सामोर	337	0-06-15
	338	0-72-45
	340	0-21-31

[मं. O-14016/118/84 जी पी]

S.O. 2343.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3681 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Survey No.	H.	A.	CA
Samor	337	0	06	15
	338	0	72	45
	340	0	21	31

[No. O-14016/118/84-GP]

का. आ. 3144—यह पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3761 तारीख 6-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यह महत्व प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यह केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवम्वादा घोषित करती

है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एवम्वादा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—अंकलेश्वर

गांव	सर्वे नं.	हे. अ. फ.	अ. फ.
अमृतपुरा	18	0	36
	26	0	25
	31	0	26
	25	0	01
	36	0	00
	32	0	27
	33	0	02
	34	0	35
	49	0	13
	48	0	37
	39/6	0	13
	46	0	16
	44/1	0	61
	15	0	08

[मं. सं-14016 118/84-जी पी]

S.O. 2344.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3761 dated 6-11-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And Whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jugdishpur
State : Gujarat . District : Bharuch, Taluka . Ankleshwar

Village	Block No.	Hec- tare	Acre	Cen- tiare
Amaratpura	18	0	36	00
	26	0	25	65
	31	0	26	19
	25	0	01	42
	36	0	00	90
	32	0	27	00
	33	0	02	32
	34	0	35	39
	49	0	13	20
	48	0	37	20
	39/6	0	13	95
	46	0	16	05
	44/1	0	64	75
	15	0	08	15

[No. O-14016/121/84 GP]

भा. प्रा. 3345—यस पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का वर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 का उपधारा (1) के अंतर्गत भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ सं. 3762 तारीख 6-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रजित करने का अपना अधिकार घोषित कर दिया था।

और यह सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यह केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने में परन्तु इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यह उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन.ए. द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोग के लिए एन.ए. द्वारा प्रजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निम्न होने के अन्तर्गत भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी जाधायों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निम्न होगा।

अनुसूची

हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात, जिला—धरम, तालुका—अंकलेश्वर

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेर	आरे	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कोसवडी	302	0	02	00
	299	0	48	82
	300	0	21	42
	301	0	24	38
	291	0	41	80
	289	0	16	08
	288	0	40	00

2	3	4	5
287	0	24	00
काटेदूक	0	06	40
255	0	02	40
256	0	71	20
257	0	27	25
258	0	20	10
259	0	02	88
261	0	05	90
262	0	07	20
264	0	00	86
जावो	0	16	00
222	0	01	80
221	0	23	20
219	0	44	89
179	0	67	05
184	0	37	60
164	0	21	65
165	0	06	24
162	0	32	80
161	0	00	52
काटेदूक	0	03	20
131	0	21	60
132	0	28	80
97	0	44	00
795	0	03	20
794	0	45	92
काटेदूक	0	03	60
133	0	00	16
753	0	38	40
754	0	11	20
757	0	02	88
96	0	02	88
95	0	18	08
124	0	69	92
125	0	04	00
136	0	09	80
134	0	30	56
756	0	24	00
759	0	22	72
755	0	14	36
750	0	20	00
749	0	33	39
763	0	12	80
748	0	23	20
747	0	63	20
743	0	04	00
744	0	52	00

[सं. O-14016/121/84-जोपी]

S.O. 2345.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3762 dated 6-11-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And Whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat, District : Baruch, Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Kosamadi	303	0	02	00
	299	0	48	62
	300	0	21	42
	301	0	24	38
	291	0	41	98
	289	0	16	08
	288	0	40	00
	287	0	24	00
Cart track		0	06	40
	255	0	02	40
	256	0	71	20
	257	0	23	25
	258	0	20	10
	259	0	02	88
	261	0	05	90
	262	0	07	20
	264	0	00	96
Khadi		0	16	00
	222	0	01	60
	221	0	23	20
	219	0	44	88
	179	0	67	05
	184	0	37	60
	164	0	23	65
	165	0	06	24
	162	0	32	80
	161	0	00	32
Cart track		0	03	20
	131	0	21	60
	132	0	28	80
	97	0	44	00
	795	0	03	20
	794	0	45	92
Cart track		0	03	60
	133	0	00	16
	753	0	38	40
	754	0	11	20
	757	0	02	88
	96	0	02	88
	95	0	38	08
	124	0	69	92

1	2	3	4	5
Kosamaddin	125	0	04	00
Contd.	135	0	09	60
	134	0	30	56
	756	0	24	00
	759	0	22	72
	755	0	14	56
	750	0	20	00
	749	0	33	39
	763	0	12	80
	748	0	22	20
	747	0	63	20
	743	0	04	00
	744	0	52	00

[No. O-14016/122/84-GP]

का. आ. 2346--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1982 (1982 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्जन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. नं. 3763 तारीख 0-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जन करने का अपना अधिकार घोषित कर दिया था।

और यतः मन्त्र प्रधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्जन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जन किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्रधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से, मोड़ना के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजारा से बरेली में जयविभापुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए राज्य: गुजरात, जिला: मरुज, तालुका: अन्कलेश्वर

गाँव	ब्लॉक नं०	हे.	आ.	से.
1	2	3	4	5
अजिनाली	12/1	0	22	40
	43	0	34	40
	42/2	0	07	60
	46	0	04	56
	45	0	18	61
	47	0	18	20
	49	0	41	70
	काई ट्रैक	0	03	45
	114	0	18	80
	113	0	06	30
	134	0	12	25
	122	0	09	75
	125	0	41	10
	240	0	20	55
	239/B	0	22	80

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
जीतामी—बरी	249	0	12	96	Jitali-Cent	47	0	16	20
	250	0	44	25		49	0	41	70
	251	0	03	52		Cart track	0	03	45
	252	0	12	80		114	0	16	80
936		0	00	14		113	0	06	30
257		0	46	20		124	0	12	25
259		0	50	10		123	0	09	75
कार्ट ट्रैक		0	02	70		125	0	41	10
393		0	18	45		240	0	29	85
261		0	39	60		239/B	0	12	80
खराबो		0	01	75		249	0	12	96
307		0	01	15		250	0	44	25
308		0	30	70		251	0	03	52
333		0	40	50		252	0	12	80
312		0	23	70		836	0	00	14
खराबी		0	25	75		257	0	46	20
311		0	77	64		259	0	50	10
337		0	10	65		Cart Track	0	02	70
326		0	32	20		393	0	18	45
327		0	19	80		261	0	39	60
319		0	00	16		Kharabo	0	01	75
320		0	27	30		307	0	01	15
						308	0	30	70
						333	0	40	50
						332	0	23	70
						Kharabo	0	25	75
						331	0	77	64
						337	0	10	65
						326	0	32	20
						327	0	19	80
						319	0	00	16
						320	0	27	30

[सं. O-14016/123/84-जं. फं.]

S.O. 2346.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3763 dated 6-11-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And Whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat.	District	Bharuch, Taluka	: Ankleshwar
Village	Block No.	H	A CA
1	2	3	
Jitali	42/1	0	27 60
	43	0	34 40
	42/2	0	07 60
	46	0	04 56
	45	0	16 61

कांसां 2347—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना कांसां 3766 तारीख 17-11-84 द्वारा केंद्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत् मंत्रालय प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट द दी है।

और आगे, यत् केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के अर्जित के लिए अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने निहित होन के अन्तर्गत भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में समस्त अधिकारों में सलग्न रूप में घोषणा के पश्चात्तः का निर्णय को निहित होगा।

[No. O-14016/123/84-GP]

अनुसूची		
एचबीजे गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट		
ग्राम : तिलगारा, तहसील बदनावार, जिला धार, राज्य (म.प्र.)		
अनु.क्र०। खमरा न०	उपयोग अधिकार प्रजनन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)	
1. 1112	0-051	
2. 3191	0-013	
3. 3190	0-190	
4. 3192/1/2	0-202	
5. 3192/1/1	0-190	
6. 3192/2	0-126	
7. 3192/3	0-051	
8. 3189/2	0-076	
9. 3193/2	0-063	
10. 3195	0-126	
11. 3194/1	0-159	
12. 3197/1	0-038	
13. 3199/2	0-063	
14. 3199/1/1	0-126	
15. 3197/2 } 3194/2/1 }	0-063 0-013	
16. 3198	0-126	
17. 3200	0-038	
18. 3201	0-076	
19. 3179/1	0-190	
20. 1185	0-190	
21. 1186	0-038	
22. 1190	0-253	
23. 1189	0-126	
24. 3151	0-151	
25. 3151/1	0-151	
26. 3172	0-126	
27. 3169	0-025	
28. 3170	0-013	
29. 3171	0-189	
30. 3124	0-217	
31. 2126	0-076	
32. 3127	0-101	
33. 3116	0-126	
34. 3129	0-101	
35. 3103	0-076	
36. 3114 } 3115 }	0-076 0-013	
37. 3072	0-076	
38. 3039	0-176	
39. 3040	0-126	
40. 3042	0-076	
41. 3047	0-126	
42. 3048	0-141	
43. 3031	0-051	
44. 3030	0-013	
45. 3033	0-126	
46. 3034 } 3033 } 2047 }	0-266 0-013	3047

1	2	3
47.	3021/1	0.089
48.	3021/2	0.089
49.	3022/1	0.038
50.	3022/2	0.038
51.	3023/1	0.038
52.	3023/2	0.038
53.	3128/1	0.003
54.	3128/2	0.003
55.	2896	0.126
कुल रकबा		5.680

[सं. O-14016/126/84-जीपी]

S.O. 2347.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S. O. 3766 dated 17-11-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And Whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

Village : Tilgara Tehsil Badnawar Distt. : Dhar

S. Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare	
No.		
1	2	3
1.	1112	0.051
2.	3191	0.013
3.	3190	0.190
4.	3192/1/2	0.202
5.	3192/1/1	0.190
6.	3192/2	0.126
7.	3192/3	0.051
8.	3189/2	0.076
9.	3193/2	0.063
10.	3195	0.126
11.	3194/1	0.159
12.	3197/1	0.038
13.	3499/2	0.063
14.	3199/1/1	0.126
15.	3197/2 } 3194/2/1 }	0.063 0.013
16.	3198	0.126

1	2	3
17. 3200		0.038
18. 3201		0.076
19. 3179/1		0.190
20. 1185		0.190
21. 1186		0.030
22. 1190		0.253
23. 1189		0.126
24. 3151		0.151
25. 3152/1		0.151
26. 3172		0.126
27. 3169		0.025
28. 3170		0.013
29. 3171		0.189
30. 2124		0.27
31. 3126		0.076
32. 3127		0.101
33. 3116		0.126
34. 3129		0.101
35. 3130		0.076
36. 3114 } 3115 }		0.076 } 0.13 }
37. 3072		0.75
38. 3039		0.076
39. 3040		0.126
40. 3042		0.076
41. 3047		0.126
42. 3048		0.141
43. 3031		0.051
44. 3030		0.013
45. 3033		0.126
46. 3034 } 3233 }	3047	0.266 } 0.013 }
47. 3021/1		0.089
48. 3021/2		0.089
49. 3022/1		0.038
50. 3222/2		0.038
51. 3023/1		0.038
52. 3023/2		0.038
53. 3128/1		0.003
54. 2128/2		0.003
55. 2896		0.126
Total Area		5.680

[No. O-14016/126/84-GP]

का.प्र. 2348.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.प्र.सं. 3767 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अर्पण घोषित कर दिया था।

और यतः मन्त्रम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्राजेक्ट

ग्राम: महानपुर, तहसील: गुना जिला-गुना: राज्य(म.प्र.)		
अनु क्रमांक	खसरा नंबर	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1.	52	0.398
2	58	0.027
3	49	0.105
4.	51	0.021
5	50	0.099
6	38	0.157
7.	37/1	0.099
8.	37/2	0.230
9.	36	0.146
10.	35	0.105
11.	40	0.021
12.	12/2	0.219
13.	10/1	0.260
14.	11	0.099
15.	10/2	0.146
16	29	0.105
कुल रकबा		2.231

[सं. O-14016/129/84-जीपी]

S.O. 2348.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3767 dated 17-11-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And Whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Muhalpur Tehsil Guna Distt. : Guna

S. Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1. 52	0.398
2. 58	0.021
3. 49	0.105
4. 51	0.021
5. 50	0.099
6. 38	0.157
7. 37/1	0.099
8. 37/2	0.230
9. 36	0.146
10. 35	0.105
11. 40	0.021
12. 12/2	0.219
13. 10/1	0.260
14. 11	0.099
15. 10/2	0.146
16. 29	0.105
Total Area	2.231

[No. O-14016/129/84-GP]

कां०आ० 2349.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना कां०आ० सं० 3805 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अथ, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय रीस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजारा बरेली जायसपुर पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	मिया गा. क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर	अकबर	अकबर	बिवाइन	1209 मि.	1-3-2	
देहात	पुर	पुर		1209 मि.	0-6-15	
				1209 मि.	3-4-3	

[सं. O-14016/197/84-भौ.पी.]

S.O. 2349.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3805 dated 17-11-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And Whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira : Bareilly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur	Akbar-	Akbar-	Verine	1209 min	1-3-2	
Dehat	pur	pur		1209 min	0-6-15	
				1209 min	3-4-3	

[No. O-14016/197/84-GP]

का. आ. 2350.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3806 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अथ, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय रीस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची						
हजिरा बरेली जगदीशपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट						
जिला	तहसील	परगना	ग्राम	माफ़िस.	अर्जित क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर	अकबर	अकबर	चिरौरा	891	0-13-0	
देहात	पुर	पुर		902	0-11-0	
				903	0-1-0	
				904	0-4-0	
				905	0-12-0	
				906	0-2-0	
				907	0-8-0	
				908	0-7-0	
				911	1-13-0	
				910	0-2-0	
				817	0-1-0	
				815	0-0-10	
				812	0-8-0	
				811	0-3-0	
				810	0-3-0	
				804	0-4-0	
				805	0-3-0	
				809	0-16-0	
				808	0-0-10	
				912	0-11-0	
				913	0-2-0	

[सं. O-14016/198/84-जी.पी.]

S.O. 2350.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3806 dated 17-11-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And Whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira—Barielly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-mark
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur	Akbar-	Akbar-	Chiro-	891	0-13-0	
Dehat	pur	pur	ura	902	0-11-0	
				903	0-1-0	

1	2	3	4	5	6	7
				904	0-4-0	
				905	0-12-0	
				906	0-2-0	
				907	0-8-0	
				908	0-7-0	
				911	1-13-0	
				910	0-2-0	
				817	0-1-0	
				815	0-0-10	
				812	0-8-0	
				811	0-3-0	
				810	0-3-0	
				804	0-4-0	
				805	0-3-0	
				809	0-16-0	
				808	0-0-10	
				912	0-11-0	
				913	0-2-0	

[No. O-14016/198/84-GP]

का. आ. 3351.—यह पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3731 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था।

और यह सूक्ष्म प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यह केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाना है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी भाषाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच. जी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम . टी टी पाडा तहसील : अदनाबर जिला धार राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु क्र खसरा नं. 1

उपयोग अधिकार
अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)

1	2	3
1.	258	0.354
2.	248/4	0.342
3.	220	0.025
4.	170	0.051
5.	171	0.126
6.	172	0.190

1	2	3
7.	169	0.025
8.	175	0.039
9.	177	0.051
10.	178	0.038
11.	179	0.405
12.	381/180	0.025
13.	183	0.063
14.	184	0.101
15.	145/2	0.214
16.	145/3	0.164
17.	144	0.152
18.	146	0.063
19.	140/1	0.190
20.	140/2	0.240
21.	141/1	0.076
22.	135	0.038
23.	302	0.076
24.	303	0.304
25.	304	0.025
26.	305/2	0.215
27.	306/2	0.038
28.	307	0.038
29.	128	0.379
30.	129	0.025
31.	130	0.025
32.	131	0.025
33.	125/1 } 125/2 }	0.051
34.	126/1 } 126/2 }	0.063
35.	127	0.051
36.	19	0.038
37.	27	0.051
38.	29	0.240
39.	32	0.051
40.	39	0.089
41.	38	0.076
42.	37	0.025
43.	36	0.152
44.	41	0.089
45.	42	0.025
46.	43	0.038
47.	44	0.089
48.	45	0.089
49.	46	0.038
50.	50	0.126
51.	51	0.164
52.	79	0.076
53.	49	0.038
54.	80	0.101
55.	384/81	0.037
56.	82	0.151
57.	83	0.013
58.	84	0.013
59.	48, 5	0.632

1	2	3
60.	86	0.038
61.	91	0.063
62.	184	0.006
63.	81	0.025
64.	85	0.013
65.	295/1	0.038
कुल क्षेत्रफल		6.961

[मं. O 14016/223 / 34 जी. पी.]

S.O. 2351.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3761 dated 17-11-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And Whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Titirada Tehsil : Badnawar Distt. : Dhar

S. Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1. 258	0.354
2. 248/4	0.342
3. 220	0.025
4. 170	0.051
5. 171	0.126
6. 172	0.190
7. 169	0.025
8. 175	0.089
9. 177	0.051
10. 178	0.038
11. 179	0.005
12. 381/180	0.025
13. 183	0.063
14. 184	0.101
15. 145/2	0.214
16. 145/3	0.164
17. 144	0.152
18. 146	0.063
19. 140/1	0.190
20. 140/2	0.240

1	2	3
21.	141/1	0.076
22.	135	0.038
23.	302	0.076
24.	303	0.304
25.	304	0.025
26.	305/2	0.215
27.	306/2	0.038
28.	307	0.038
29.	128	0.379
30.	129	0.025
31.	130	0.025
32.	131	0.025
33.	125/1	0.051
	125/2	
34.	126/1	0.063
	126/2	
35.	127	0.051
36.	19	0.038
37.	27	0.051
38.	29	0.240
39.	32	0.063
40.	39	0.089
41.	38	0.076
42.	37	0.025
43.	36	0.152
44.	41	0.089
45.	42	0.025
46.	43	0.038
47.	44	0.089
48.	45	0.089
49.	46	0.038
50.	50	0.126
51.	51	0.164
52.	78	0.076
53.	49	0.038
54.	80	0.101
55.	384/81	0.037
56.	82	0.151
57.	83	0.013
58.	84	0.013
59.	48/5	0.632
60.	86	0.03
61.	91	0.063
62.	182	0.006
63.	81	0.025
64.	85	0.013
65.	295/1	0.038
Total Area		6.973

[No. O-14016/223/84-GP]

का या 1352—यस पेट्रोलियम और खनिज पार्श्व लाईन (भूमि से उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) का धारा 3 का उपधारा (1) के अर्जन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय को अधिसूचना का. आ. स. 3733 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पारस्परिकता को विछाने के लिए अर्जन करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यह : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यह : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अब अब : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पारस्परिकता को विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जन किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय शीश प्राधिकरण निमित्त में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा :

अनुसूची

एच. बी. जे. शीस पार्श्व लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम अलमिया खेडी तहसील पेटलावद जिला भाबुआ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु. क्र. खसरा नं.	उपयोग अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
--------------------	--

1	2	3
1	294	0.235
2	298	0.056
3	429	0.170
4	299	0.136
5	426	0.154
6	301	0.267
7	307	0.316
8	138	0.162
9	140	0.142
10	308	0.202
11	163	0.210
12	161	0.140
13	162	0.125
14	166	0.243
15	168	0.010
16	154	0.364
17	383	0.101
18	117	0.020
19	118	0.101
20	131	0.251
21	133	0.040
22	137	0.016
23	139	0.024
24	309	0.024
25	384	0.002
26	383	0.105
27	385	0.243
28	456/1	0.202
29	454/1	0.101
30	454/3	0.016
31	450/1	0.134
32	451/2	0.036
33	441	0.008
34	442	0.324
35	439	0.214
36	438	0.073

SCHEDULE		
HBJ GAS PIPE LINE PROJECT		
1	2	3
37	425	0.129
38	496	0.016
39	454/2	0.061
40	456/2	0.016
41	499/1	0.364
42	451/1	0.105
43	132	0.049
44	141	0.016
45	153	0.015
46	167	0.016
47	292	0.142
48	296	0.040
49	378	0.040
50	381	0.016
51	430	0.081
52	41	0.020
53	434	0.181
54	443	0.032
55	447	0.061
56	448	0.040
57	452	0.032
58	165	0.032
59	120	0.016
60	453	0.040
61	455	0.016
62	437	0.016
63	119	0.243
64	446	0.016
योग कुल क्षेत्रफल		7.078

[नं० 14016 / 225 / 84-जी.पं.]

S.O. 2352—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3733 dated 17-11-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

Villages : Alasya Khedi Tehsil : Petawad Distt. : Zabua

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
---------	------------	---

1	2	3
1.	294	0.235
2.	298	0.056
3.	479	0.170
4.	299	0.136
5.	426	0.154
6.	301	0.267
7.	307	0.316
8.	138	0.162
9.	140	0.142
10.	308	0.202
11.	163	0.210
12.	161	0.149
13.	162	0.125
14.	166	0.243
15.	168	0.040
16.	154	0.364
17.	383	0.101
18.	117	0.020
19.	118	0.101
20.	131	0.251
21.	133	0.040
22.	137	0.016
23.	139	0.240
24.	309	0.024
25.	384	0.202
26.	382	0.105
27.	385	0.243
28.	456/1	0.207
29.	454/1	0.101
30.	454/3	0.016
31.	450/1	0.134
32.	451/2	0.036
33.	441	0.008
34.	442	0.324
35.	439	0.214
36.	438	0.073
37.	425	0.129
38.	426	0.016
39.	454/2	0.061
40.	456/2	0.016
41.	499/1	0.364
42.	451/1	0.105
43.	132	0.049
44.	141	0.016
45.	153	0.045
46.	167	0.016
47.	292	0.142
48.	296	0.040
49.	378	0.040
50.	381	0.016
51.	430	0.081
52.	431	0.020
53.	434	0.781
54.	443	0.032
55.	447	0.061

1	2	3
56.	448	0.040
57.	452	0.032
58.	165	0.032
59.	120	0.016
60.	453	0.040
61.	455	0.016
62.	437	0.016
63.	119	0.243
64.	446	0.016
TOTAL AREA		7.078

[No. O-14016/225/84-G.P.]

का० आ० 2353 यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 3907 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना के सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत्: सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम का धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होत के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी वाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : पाड़ल घाटी तहसील : झाड़ुआ जिला : झाड़ुआ राज्य : (मध्य प्रदेश)

अनु० क्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर में)
1	2	3
1.	123	0.568
2.	163	0.208
3.	167	0.320
4.	114	0.360
5.	116	0.240
6.	124/1	0.336
7.	119	0.008
8.	127	0.132
9.	115	0.405
10.	41	1.240
11.	39	1.200
12.	40	0.080

1	2	3
13.	82	0.240
14.	88	0.280
15.	117	0.008
16.	43	0.008
17.	118	0.040
18.	113	0.036
19.	109	0.140
20.	157मी०	0.405
21.	136	0.020
22.	89	0.120
23.	83मी०	1.800
24.	126	0.096
कुल योग:		8.290

[म० O-14016/245/84-जी०पी०]

S.O. 2353.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3907 dated 24-11-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBI GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Padal Ghati Tehsil : Zabua Distt. : Zabua
State : Madhya Pradesh

S No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	123	0.568
2.	163	0.208
3.	167	0.320
4.	114	0.360
5.	116	0.240
6.	124/1	0.336
7.	119	0.008
8.	127	0.132
9.	115	0.405

1	2	3
10.	41	1.240
11.	39	1.200
12.	40	0.080
13.	82	0.240
14.	88	0.280
15.	117	0.008
16.	43	0.008
17.	118	0.040
18.	113	0.036
19.	109	0.140
20.	157 M.	0.405
21.	136	0.020
22.	89	0.120
23.	83 M.	1.800
24.	126	0.096
TOTAL AREA		8.290

[No. O-14016/245/84-GP]

कां०आ० 2354.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना कां०आ० सं० 3933 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों का बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह वांछित कर दिया था।

और यतः महम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने के निमित्त अज्ञात किया है।

अब अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइनों के बिछाने के लिए अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सारी प्राप्ति में संपूर्ण रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

पञ्च०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम—शावही नरसीन—पेटलावद जिला—प्रायद्वीप राज्य—मध्य प्रदेश

अनुसूची

अनुसूची संख्या		उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
1	2	3
1.	49	0.080
2.	48	0.220
3.	36	0.440
4.	34	0.110
5.	35	0.010

D.I.G./35—9

1	2	3
6.	46	0.230
7.	45	0.110
8.	37	0.100
9.	38	0.008
10.	78	0.220
11.	79	0.420
12.	84	0.032
13.	32	0.005
14.	47	0.085
15.	39	0.032
16.	76	0.006
17.	44	0.010
18.	77	0.072
19.	30	0.008
20.	15	0.020
योग कुल क्षेत्रफल		2.218

[सं० O-14016/276/84-जी पी]

S.O. 2354.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3933 dated 24-11-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Dabadi Tehsil : Petlawad Distt. : Zabua

SCHEDULE

S No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	49	0.080
2.	48	0.220
3.	36	0.440
4.	34	0.110
5.	33	0.010
6.	46	0.230
7.	45	0.110

1	2	3
8.	37	0.100
9.	38	0.008
10.	78	0.220
11.	79	0.420
12.	84	0.032
13.	32	0.005
14.	47	0.085
15.	39	0.032
16.	76	0.006
17.	44	0.010
18.	77	0.072
19.	30	0.008
20.	15	0.020
TOTAL AREA		2.218

[No. O-14016/276/84-G.P.]

कांआ० 2355:--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना कांआ०सं० 3939 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः महाम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एचबीजे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम-धमाना तहसील-बदनावर जिला-धार राज्य-मध्य प्रदेश

अनुसूची

अनु० क्र०	खसरा न०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1	99	0.070
2	44	0.385
3	45	0.325
4	43	0.140
5	49	0.013
6	5	0.150
7	7	0.160
8	3	0.289

1	2	3
9	14	0.470
10	15/1	0.290
11	15/2	0.330
12	1	0.150
13	4	0.013
14	46/1	0.101
15	41	0.025
कुल योग--क्षेत्रफल		3.911

[सं O-14016/282/84-डो०पी०]

S.O. 2355.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3939 dated 24-11-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village—Dhamana Tehsil—Badnawar Distt. Dhar

SCHEDULE

S No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1	99	0.070
2	44	0.385
3	45	0.325
4	43	0.140
5	49	0.013
6	5	0.150
7	7	0.160
8	3	0.289
9	14	0.470
10	15/1	0.290
11	15/2	0.330
12	1	0.150
13	4	0.013
14	46/1	0.101
15	41	0.025
Total area		3.911

[No O-14016/232/84-G.P.]

या आ 2355—यह पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय के अधिनियम का आ स 1940 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मसलन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यह सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यह केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में मसलन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मसलन अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों के उपयोग का अधिकार पाइप लाइनों बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे यह धारा के उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित हान के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख का निहित होगा।

अनुसूची

एच बी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम बरबेह तहसील साबुआ जिला— साबुआ राज्य (मध्य प्रदेश)

क्र. सं.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
1	वन विभाग	0 324
योग — कुल क्षेत्रफल		0 324

[स O-14016/283/84—जी पी]

S.O. 2356—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3940 dated 24-11-1984 under subsection (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from all encumbrances

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village	Block	Tehsil	Zabua	Distt	Zabua
S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R O U (in Hectare)			
1	Forest Deptt	0 324			
TOTAL AREA		0 324			

[No O-14016/283/84 G P]

का आ 2357—यह पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का आ प 3913 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मसलन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यह सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है,

और आगे यह केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में मसलन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मसलन अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे यह धारा के उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित हान के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच बी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम बरबेह तहसील पेटलाबद जिला साबुआ राज्य (मध्य प्रदेश)

क्र. सं.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
1	2	3
1	29	0 340
2	34	0 146
3	47	0 761
4	49	0 081
5	48	0 004
6	32	0 008
7	33	0 012

योग — कुल क्षेत्रफल 1 352

[स O-14016/283/84—जी पी]

S.O. 2357.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3943 dated 24-11-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Brabat Tehsil : Petlawad Distt. : Zabua

SCHEDULE

Sl No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. (in Hectare)
1	2	3
1.	29	0.340
2.	34	0.146
3.	47	0.761
4.	49	0.081
5.	48	0.004
6.	32	0.008
7.	33	0.012
Total Area		1.352

[No. O-14016-286/84-GP]

का. भा. 2358.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 4062 तारीख 1.12.84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है;

और चाहे उस धारा की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में धारणा के प्रकाशन की इस तारीख 1 निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा- बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	स.	नियोजित रुकबा
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	पुरवा	मोरावी	जम्हूपुर	212	0-12-0
				233	1-1-0
				366	0-2-8
				364	0-1-4
				367	0-8-10
				369	1-4-5
				370	0-3-0
				372	0-3-0
				392	1-14-10
				393	0-5-10
				394	0-1-0
				388	0-0-5
				387	0-0-5
				389	0-1-4
				395	0-3-0
				396	0-3-12
				386	0-3-10
				397	0-4-15
				398	0-5-10
				383	0-2-8
				384	0-4-15
				399	0-3-8
				400	0-3-0
				401	0-2-10
				402	0-8-0
				411	0-13-10
				407	0-7-4
				408	0-3-0
				409	0-8-5
				445	0-0-0
				725	0-4-10
				726	0-1-5
				727	0-7-5
				728	1-8-0
				737	0-0-15
				738	0-2-5
				739	1-4-0
				740	0-0-15
				747	0-2-10
				410	1-0-10
				368	0-0-5
				378	0-0-5
				412	0-0-10
				735	0-2-0

[सं. O-14016/300/84-जी पी]

S.O. 2558.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4062 dated 1-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances,

SCHEDULE

Hajira-Barielly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Purva	Mara-van	Jam-burpur	212	012-0	
				233	1-1-0	
				366	0-2-8	
				364	0-1-4	
				367	1-8-10	
				369	1-4-5	
				370	0-3-0	
				372	0-3-0	
				392	1-14-10	
				393	0-5-10	
				394	0-1-0	
				388	0-0-5	
				387	0-0-5	
				389	0-1-4	
				395	0-3-0	
				396	0-3-12	
				386	0-3-10	
				397	0-4-15	
				398	0-5-10	
				383	0-2-8	
				384	0-4-15	
				399	0-3-8	
				400	0-3-0	
				401	0-2-10	
				402	0-8-0	
				411	0-13-10	
				407	0-7-4	
				408	0-3-0	
				409	0-8-5	
				445	0-6-0	
				725	0-4-10	
				726	0-1-5	
				727	0-7-5	

1	2	3	4	5	6	7
				728	1-6-0	
				727	0-0-15	
				738	0-2-5	
				739	1-4-0	
				740	0-0-15	
				747	0-2-10	
				410	1-0-10	
				368	0-0-5	
				378	0-0-5	
				412	0-0-10	
				735	0-2-0	

[No. O-14016/300/84-GP]

का. घा 2559.—यत्. पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962) (1962 का 50) क धारा 3 क उपधारा (1) के अधिन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिसूचना का. भा. म० 4073 तारीख 1.12.84 द्वारा केन्द्रिय सरकार ने उस अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यत्. सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम क धारा 6 क उपधारा (1) के अधिन सरकार को रिपोर्ट दे र है।

और आगे यत्. केन्द्रिय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, यत्. उक्त अधिनियम क धारा 6 क उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा क उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रिय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सर्व बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन के इस तारीख को निहित होगा;

अनुसूची

हाजिरा-बरेल-जगद शपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	लिया गया	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	पुरवा	मौरावा	खसपुर	53/1	1-11-15	
				54	0-7-4	
				59	0-10-8	
				60	0-3-0	
				61	0-3-12	
				62	0-7-0	
				64	0-4-10	
				120	0-14-0	
				122	0-9-12	
				123	0-8-8	
				127	0-18-3	
				131	0-14-0	
				135	0-7-0	

1	2	3	4	5	6	7
				136	0-10-9	
				140/2	2-6-15	
				141	0-9-4	
				290	0-1-15	
				292	0-1-18	
				293	0-15-0	
				294	0-7-0	
				295	0-8-6	
				296	0-2-14	
				299	0-13-16	
				305	0-1-0	
				306	0-3-12	
				369	0-2-10	
				370	0-3-10	
				371	0-5-10	
				373	0-1-12	
				372	0-5-3	
				374	0-2-0	
				375	0-17-10	
				143	0-2-10	
				63	0-0-10	

[N. O-14016/301/84-ज.प.०]

S.O. 2359.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4073 dated 1-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Purwa	Mau-ranva	Rasulpur	53/1	1-11-15	
				54	0-7-4	
				59	0-10-8	
				60	0-3-0	
				61	0-3-12	
				67	0-7-0	
				64	0-4-10	
				120	0-14-0	
				122	0-9-12	

1	2	3	4	5	6	7
				123	0-8-8	
				127	0-19-8	
				131	0-14-0	
				135	0-7-0	
				136	0-10-9	
				140/2	2-6-15	
				141	0-9-4	
				290	0-1-15	
				292	0-1-18	
				293	0-15-0	
				294	0-7-0	
				295	0-8-6	
				296	0-2-14	
				299	0-13-16	
				305	0-1-0	
				306	0-3-12	
				369	0-2-10	
				370	0-3-10	
				371	0-5-10	
				373	0-1-12	
				372	0-5-3	
				374	0-2-0	
				375	0-17-10	
				143	0-2-10	
				63	0-0-10	

[No. O-14016/301/84-GP]

का. मा. 1360—यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिसूचना का. मा. 4772 तारख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारों ने उक्त अधिनियम के धारा 6 के उपधारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे डाला है।

और तबसे केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम के धारा 6 के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा के उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारत गैस प्राधिकरण लि. में सभ बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेल-जगदधपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गांवा नं०	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झारख	आम	जाम	परबई	102	1-70	
				163	0-46	

1	2	3	4	5	6	7
				172	0-01	
				173	1-58	
				191	0-08	
				192	0-52	
				193	0-18	
				195	0-40	
				196	1-03	
				199	0-66	
				208	0-80	
				209	0-40	
				210	0-85	
				340	1-65	
				353	0-69	
				354	0-14	
				355	0-05	
				356	0-35	
				357	0-02	
				449	0-32	
				358	0-79	
				359	0-35	
				360	0-06	
				361	0-01	
				368	0-07	
				390	0-23	
				392	0-38	
				393	1-25	
				418	0-03	
				419	0-05	
				420	0-05	
				421	0-01	
				422	0-02	
				417	0-45	
				415	0-06	
				435	0-16	
				414	0-35	

[सं० O-14016/358/84-अ.प.०]

S.O. 2360.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4272 dated 24-11-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of

this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipe Line from Hajira-Bareilly-Jagdīshpur 10 jc.

Distt	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area in acres	Re-mark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Parwar	162	1-70	
				163	0-46	
				172	0-01	
				173	1-58	
				191	0-08	
				192	0-52	
				193	0-18	
				195	0-40	
				196	1-03	
				199	0-66	
				208	0-80	
				209	0-40	
				210	0-85	
				340	1-65	
				353	0-69	
				354	0-14	
				355	0-05	
				356	0-35	
				357	0-02	
				449	0-32	
				358	0-79	
				359	0-35	
				360	0-06	
				361	0-01	
				368	0-07	
				390	0-23	
				392	0-38	
				393	1-25	
				418	0-03	
				419	0-05	
				420	0-05	
				421	0-01	
				422	0-02	
				417	0-45	
				415	0-06	
				435	0-16	
				414	0-35	

[No. O-14016/358/84-GP]

का० प्रा० 2361.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) का धारा 3 के उपधारा (1) के अर्थ में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० सं० 4409 तारीख 3-12-84 द्वारा केन्द्रिय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को प्राप्त लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्थ में सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रिय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम क धारा 6 के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा क उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार ने निहित होने के बजाय भारत य गैस प्राधिकरण लि० में सभ बाधाओं से मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन क इस तारख को निहित होगा।

अनुसूची

हजारा से बरेल से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।
राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल ता० देवगढ़ बारीया

गांव	सर्वे न०	हेक्टेयर	भार	सेंटीयर
रानपुरा	115/1	0	20	48
	115/2	0	14	40
	116/1	0	37	76
	118/3	0	00	25
	117/4	0	51	12
	116/2	0	22	68
	123	0	38	70
	124	0	15	20
	125/प	0	30	19
	126	0	01	01
	147	0	21	60
	146	0	28	00
	145/1	0	00	80
	145/2	0	14	40
	144	0	19	20
	140	0	12	80
	143/1	0	32	64
	141	0	11	20
कोटार		0	12	00

[सं० O-14016/374/84-ज प]

S.O. 2361.—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4409 dated 3-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances,

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bardilly—Jogdispur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Devgad Bariya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Ranipura	115/1	0	20	48
	115/2	0	14	40
	116/1	0	37	76
	118/3	0	00	25
	117/P	0	51	12
	116/2	0	22	68
	123	0	38	70
	124	0	15	20
	125/P	0	30	19
	126	0	01	01
	147	0	21	60
	146	0	28	00
	145/1	0	00	80
	145/2	0	14	40
	144	0	19	20
	140	0	12	80
	143/1	0	32	64
	141	0	11	20
	KOTAR	0	12	00

[No. O-14016/374/84-G.P.]

का० प्रा० 2362—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के धारा 3 क उपधारा (1) के अधिन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का अधिसूचना का० प्रा० सं० 4489 तारख 10-12-84 द्वारा केन्द्रिय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम क धारा 6 क उपधारा (1) के अधिन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रिय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम क धारा 6 क उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा क उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार ने निहित होने के बजाय भारत य गैस प्राधिकरण लि० में सभ बाधाओं से मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन क इस तारख को निहित होगा।

अनुसूची

हजारा से बरेल से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य गुजरात ; जिला-पंचमहल , तालुका-देवगढ़ बारीया

गांव	सर्वे न०	हेक्टेयर	भार	सेंटीयर
देवगढ़	443	0	26	40
	442/1	0	39	00
	445	0	39	00

[सं० ओ-14016/377/84-ज प ०]

S.O. 2362.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4489 dated 10-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira Barcilly Jagdishpur
State : Gujarat District : Panchamahall Taluka : Dev gad h
Bariya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Devgad h	443	0	26	40
	422/1	0	39	00
	445	0	39	00

[No. O-14016/377/84-GP]

का० प्रा० सं० 2363 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिसूचना का० प्रा० सं० 4534 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्र सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राण्य घोषित कर दिया था।

और यतः मध्यम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्र सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा के उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने निहित होने के बजाय भारत की मध्यम प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं में मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन के इस तारीख को निहित होगा।

211GU/85-10

अनुसूची

हर्जरा से बरेल में जगदपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य-गुजरात जिला-पंचमहल तालुका-हानोल

गांव	सर्वे न.	हेक्टेयर	आर	सेंटेयर
1	2	3	4	5
गोर्प पुरा	203	0	55	00
	204	0	16	00
कोटार		0	07	00
	208	0	16	00
	209	0	01	00
	225	0	00	50
	221	0	18	00
	223	0	29	00
	222	0	24	00
	221	0	20	00
	220	0	24	00
	216	0	22	00
कोटार		0	09	00
54		0	47	00
53		0	25	00
काटें ट्रेक		0	03	00
27		0	17	00
28		0	29	00
294		0	17	00
कोटार		0	04	00
21		0	73	00
11		0	35	00
12		0	33	00
काटें ट्रेक		0	11	00
10		0	00	50
70		0	34	00

[सं० ओ-14016/436/84-जी.प.]

S.O. 2363.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4534 dated 10-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdish Pur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Kalar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Gopipura	203	0	55	00
	204	0	16	00
	Kotlar	0	07	00
	208	0	16	00
	209	0	01	00
	225	0	00	50
	224	0	18	00
	223	0	29	00
	222	0	24	00
	221	0	20	00
	220	0	24	00
	216	0	22	00
	Kotlar	0	09	00
	54	0	47	00
	53	0	25	00
	Cart Track	0	02	00
	27	0	17	00
	28	0	29	00
	294	0	17	00
	Kotlar	0	04	00
	21	0	73	00
	11	0	35	00
	12	0	33	00
	Cart Track	0	11	00
	10	0	00	50
	70	0	34	00

[No. O-14016/436/84-G.P.]

का. आ. 2364 यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार के पेट्रोलियम पत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4546 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था।

और यत् गवर्नर प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के वजह भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी।

अनुसूची

हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।
राज्य--गुजरात जिला--पंचमहल तालुका--कालो

गाँव	ब्लाक नं०	हेक्टर	आर	सेटीयर
1	2	3	4	5
बरवाडा	70	0	02	40
	68	0	34	00
	97	0	19	22
	57	0	08	00
	58	0	35	41
	66/3	"	20	00
	59/4	0	37	44
	60	0	12	00
	48	0	01	00
	47	0	06	00
	45		12	15
	43	0	09	60
	44	0	05	06
	42/4	0	20	25
	42/5	0	02	00
	168	0	32	00
	166	0	19	22
	165	0	44	52
	164	0	12	00
	163	0	37	00
	186	0	19	22
	187	0	38	80
	190	0	22	00
	189	0	13	00
	कोदार	0	32	40
	209	0	08	00
	211	0	24	00
	213	0	40	00
	214	0	00	50

[सं. ओ-14016/448/84-जी.पी.]

S.O. 2364.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4546 dated 10-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Kaloj

Village	Block No.	Hectare	Area	Centiare
1	2	3	4	
Varvada	70	0	02	40
	68	0	24	00
	67	0	19	22
	57	0	06	00
	53	0	35	41
	66/3	0	20	00
	59/4	0	37	44
	60	0	12	00
	48	0	01	00
	47	0	06	00
	45	0	12	15
	43	0	09	60
	44	0	05	06
	42/4	0	20	25
	42/5	0	02	00
	168	0	32	00
	166	0	19	22
	165	0	44	52
	164	0	12	00
	163	0	37	00
	186	0	19	22
	187	0	28	80
	190	0	22	00
	189	0	13	00
	Kotar	0	32	40
	209	0	08	00
	211	0	24	00
	213	0	40	00
	214	0	00	50

[No. O-14016/448/84-G P]

का. अ. 2165—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. सं. 4555 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः गलम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विश्वास करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में विनिश्चयित कि राजद्वारा भारत सरकार के प्राधिकरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निश्चित होगा।

अनुसूची

इन्डिया से बरेली से जगदिशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य- गुजरात जिला-पंचमहल तालुका-कालोज

गाँव	ब्लॉक नं.	हेक्टर	आर.	सेंटियर
माली आब	1:1	0	25	00
	1:10/1	0	12	00
	1:20/2	0	08	00
	1:20/4	0	10	00
	1:16	0	36	05
	1:15	0	38	00
	1:11	0	21	00
	1:14	0	08	00
	1:12/1	0	10	00
	1:12/2	0	00	16
	1:13/2	0	12	00
	7:7/1	0	19	00
	7:7/3	0	22	00
	7:7/4	0	01	00
	फाट ट्रेक	0	03	00
	10:5/1	0	18	00
	10:5/1	0	26	00
	10:5/3	0	30	00
	10:5/2	0	00	16
	10:5/4	0	07	00
	9:8/3	0	25	00
	फाट ट्रेक	0	05	00
	10:0/1	0	26	00
	9:9	0	09	00
	कोटार	0	09	00
	8:9/1	0	42	00
	8:9/2	0	01	00

[सं. O-14016/458/84-जीपी]

S.O. 2365.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4555 dated 10-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluak : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Saliav	121	0	25	00
	120/1	0	12	00
	120/2	0	08	00
	120/4	0	10	00
	116	0	36	00
	115	0	38	00
	111	0	21	00
	114	0	08	00
	112/1	0	10	00
	112/2	0	00	16
	113/2	0	12	00
	77/1	0	19	00
	77/3	0	22	00
	77/4	0	01	00
	Cart track	0	03	00
	106/1	0	18	00
	105/1	0	26	00
	105/3	0	30	00
	105/2	0	00	16
	105/4	0	07	00
	98/3	0	25	00
	Cart track	0	05	00
	100/P	0	26	00
	99	0	09	00
	Kotar	0	09	00
	89/1	0	42	00
	89/2	0	01	00

[No O-14016/458/84-G P]

का. आ. 2366 :—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4557 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत् सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति या प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी वाद्यार्थों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा से बरेली में जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात, जिला : पंचमहल, तालुका : हलोल

गाँव	सर्वे नं	हेक्टेयर	आर	संटीयर
घनवर	169	0	42	00
	163	6	23	87
	165	0	16	68
	173/पी	0	50	29
	179	0	18	95
	183	0	10	62
	187	0	04	80
	186	0	38	10
	188	9	13	50
	25/3	9	00	20
	25/2	0	20	90
	24	0	18	75
	25/1	9	16	05
	23	0	16	32
	26/2	0	15	10
	26/1,1	0	24	00
	21	0	22	20
	20	0	32	20
	14/2	0	10	56
	14/1	0	07	80
	14/3	0	12	44
	14/4	0	08	40
	6	0	53	65

[सं. O-14016/460/84-जीपी]

S.O. 2366.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4557 dated 10-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jalandhar

State : Gujarat Dist : Panchmahal Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Ac	Centiare
Dhansar	169	0	42	00
	168	0	28	87
	165	0	16	68
	178/P	0	50	29
	179	0	18	95
	183	0	10	62
	187	0	04	80
	186	0	38	10
	188	0	13	50
	25/3	0	00	20
	25/2	0	20	90
	24	0	18	75
	25/1	0	16	05
	23	0	16	32
	26/2	0	15	10
	26/1/1	0	24	00
	21	0	22	20
	20	0	32	20
	14/2	0	10	56
	14/1	0	07	80
	14/3	0	12	44
	14/4	0	08	40
	6	0	53	65

[No. O—14016/460/84-G P]

का. मा. 2367.—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, मंत्रालय की अधिसूचना का. मा. सं. 4562 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना से मेलन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यह, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और प्रायः, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मेलन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, इस उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना से मेलन अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और प्रायः उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के द्वारा भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजारा से वरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये राज्य—गुजरात जिला—पंचमहल तालुका—दाहोय

गांव	सर्वे न.	हेक्टर	आर	सेटोयर
1	2	3	4	5
नगरावा	144	0	46	00
	148	0	41	00
	149	0	00	50
	152	0	26	00
	154	0	49	00
	156	0	26	00
	137/1	0	02	00
	136/पी	0	57	00
	133/1	0	15	00
	135/2	0	15	00
	123/4	0	19	00
	123/2	0	27	00
	123/3	0	16	00
	124/1	0	11	00
	124/2	0	07	28
	129/7	0	06	00
	126/2/पी	0	26	00
	126/1/पी	0	13	70
	127/पी	0	37	00
	60/1	0	13	00
	60/2	0	04	00
	64	0	28	00
	63/1	0	03	00
	63/2	0	06	00
	65/1	0	22	00
	65/2	0	22	00
	60/8	0	31	00
	60/7	0	00	50
	60/4/ए } 60/4/बी }	0	25	00
	60/5	0	37	00
	53/ए	0	24	00
	52	0	16	50
	47/1	0	37	00
	47/2	0	29	00
	48	0	01	00

[सं O-14016/465/84-जी पी]

S.O. 2367.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S. O. 4562 dated 10-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Nagralla	144	0	46	00
	148	0	41	00
	149	0	00	50
	152	0	26	00
	154	0	49	00
	156	0	26	00
	137/1	0	02	00
	136/P	0	57	00
	135/1	0	15	00
	135/2	0	15	00
	123/4	0	19	00
	123/2	0	27	00
	123/3	0	16	00
	124/1	0	11	20
	124/2	0	07	28
	129/7	0	06	00
	126/2/P	0	26	00
	126/1/P	0	13	70
	127/P	0	37	00
	69/1	0	13	00
	69/2	0	04	00
	64	0	28	00
	63/1	0	03	00
	63/2	0	06	00
	65/1	0	22	00
	65/2	0	22	00
	60/8	0	31	00
	60/7	0	00	50
	60/4/A)	0	25	00
	60/4/B)	0	25	00
	60/5	0	37	00
	53/A	0	24	00
	52	0	16	50
	47/1	0	37	00
	47/2	0	29	00
	48	0	01	00

[N. O.—14016/465/84-GP]

का. आ. 2368.—यन: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परियोजना के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यन. यह प्रतीत होता है कि ऐसी जगहों का बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यन: जब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के

अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए केन्द्रीय सरकार ने उक्त उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा वाचित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के लिये पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कॉलोनी, सवाई माधोपुर को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के तहत का. आ. सं. 435 दिनांक 14-1-85 द्वारा भारत सरकार के गजट दिनांक 2-2-85 भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना एतद्वारा वाचिम ली जाती है।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान जिला—कोटा तहसील—छाबड़ा

गांव	खसरा न.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
केशोली	129	0	61	84
	131	0	14	26
	130	0	00	12
	132	0	00	41

[सं. O-14016/454/84-जी पी]

S.O. 2368.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur, (M.P. to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Swai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

The notification issued vide S.O. No. 435 dated 14-1-85 under Section 3(1) of the said Act and published in the Government Gazette of India Part II, Section 3(ii) dated 2-2-85 is hereby withdrawn.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chabra

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centi-are
Kasholi	129	0	61	84
	131	0	14	26
	130	0	00	12
	132	0	00	41

[No. O-14016/354/84-GP]

नई दिल्ली 23 मई, 1985

का आ 2369 यह पेट्रोलियम और लिजियम लाइन (यस में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) का धारा 3 का उपधारा (1) के अधिनियम भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का अधिसूचना का आ स नमिस्त्र 3151/13-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना में संलग्न अतसूचा में विनिर्दिष्ट भूमिया के उपयोग के अधिकार का पाक्ष लाइनों का बिछाने के लिए अर्जन करने का अर्जन आशय घोषित कर दिया था।

और यह अक्षय प्राधिकार न 2369 अधिनियम का धारा 6 की उपधारा (1) के अधिनियम सरकार का गिण्ट दे की है।

और आगे यह केन्द्रीय सरकार उक्त गिण्ट पर विचार करने के पश्चात् उक्त अधिसूचना में संलग्न अतसूचा में विनिर्दिष्ट भूमिया में उपयोग का अधिकार अर्जन करने के विनिर्दिष्ट किया है।

अब उक्त उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अतसूचा में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाक्ष लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए पदद्वारा अर्जन किया जाता है।

और आगे उक्त धारा का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बंधावा में मुक्त रूप में पापणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अतसूची

हजिरा-बरिली-जगदीशपुर पाक्ष लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	पगना	ग्राम	गाटा नं.	नियत गया रकबा (अक्षर में)	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	करी	578	0-35	
				579	0-43	
				580	0-02	
				581	0-04	
				586	0-76	
				604	0-02	
				645	0-39	
				646	0-04	
				647	0-98	
				648	0-05	
				649	0-80	
				655	0-02	
				657	1-78	
				660	0-04	
				661	0-10	
				662	0-03	
				687	0-06	
				688	0-56	
				692	0-02	
				693	0-04	
				694	0-20	
				697	1-03	
				698	2-01	
				703	0-04	
				885	1-59	

4

5

6

887

0-0

889

0-78

890

0-80

891

0-04

892

0-01

[स. O-14016/64/84 जा. ग.]

New Delhi the 23rd May, 1985

SO 2369—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum SO 3454 dated 13-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further, in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from encumbrances

SCHEDULE

Pipe line from Hajira-Barielly-Jagdishpur Project

Dist	Tahsil	Pargana	Village	Plot No	area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Kari	578	0-35	
				579	0-43	
				580	0-02	
				581	0-04	
				586	0-76	
				604	0-02	
				645	0-39	
				646	0-04	
				647	0-98	
				648	0-05	
				649	0-80	
				655	0-02	
				657	1-78	
				660	0-04	
				661	0-10	
				662	0-03	
				687	0-06	
				688	0-56	
				692	0-02	
				693	0-04	
				694	0-20	
				697	1-03	
				698	2-01	
				703	0-04	
				649	0-20	

5	6	2	3	4	5	6	7
697	0-03				114	0-40	
698	2-08				120/1	0-03	
703	0-03				121	0-70	
885	1-59				129	0-92	
887	0-02				138	0-37	
889	0-78				139	0-63	
890	0-80				140	0-08	
891	0-09				141	0-20	
892	0-04				141	0-20	

[No. O—14016/64,84-G.P.]

का. आ 2170—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. म. 3457 तारीख 16-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जन करने का अपना अधिकार घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आने यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जन किया जाता है।

और आने उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय रीस प्राधिकरण वि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदोलपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील-परगना	ग्राम	गाटांग	निचा गाँव	विवरण
				रकबा एकड़ में	

1	2	3	4	5	6	7
सं०	सं०	सं०	राजपुर	71	0-02	
				72	0-90	
				73	0-03	
				75	0-09	
				76	0-60	
				79	0-25	
				87/1	1-90	
				91	0-08	
				92	0-70	
				106	0-50	
				109	0-03	
				110	0-80	
				111	0-50	
				113	0-92	

[म. O—14016/67/84-जी. पा.]

S.O. 2370.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3457 dated 16-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Tahsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Raja Pur	71	0-02	
				72	0-90	
				73	0-03	
				75	0-09	
				76	0-60	
				79	0-25	
				87/1	1-90	
				91	0-08	
				92	0-70	
				106	0-50	
				109	0-03	
				110	0-80	
				111	0-50	
				113	0-92	
				114	0-40	
				120/1	0-03	
				121	0-70	
				129	0-92	
				138	0-37	
				139	0-63	
				140	0-08	
				141	0-20	
				327	0-30	
				328	0-75	
				329	0-75	
				330	0-80	
				432	0-88	
				433	0-05	
				434	1-03	
				435	0-50	
				469	0-50	
				485	0-30	
				486	0-02	
				487	0-80	
				488	0-40	
				489	0-40	
				83	0-02	
				468	0-03	
				430	0-15	
				382	0-50	
				380	0-50	
				484	0-11	
				29	0-01	
				307	0-05	
				378	0-08	
				379	0-01	
				431	0-20	
				74	0-05	
				84	0-03	
				133	0-03	
				490	0-01	

का. आ. 2371—यतः पेट्रोनियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोनियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3666 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट की है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने पर्याप्त इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन गोजेबट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा स.	लिया गया रकबा एकड़ में	बिबरण
1	2	3	4	5	6	7
मोती	मोठ	मोठ	रमिलिया	127	0-02	
			स्टेट	126	0-58	
				131	0-73	
				122	1-10	
				120	0-02	
				119	0-03	
				117	0-80	
				116	0-01	
				113	0-73	
				111	0-15	
				149	0-02	
				148	0-02	
				153	0-30	
				152	0-38	
				151	0-02	
				150	0-02	
				103	0-16	
				101	1-24	
				97	0-35	
				100	0-04	
				98	0-03	

S.O. 2371—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3666 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipeline from Hajira-Bargailly-Jagdishpur Project

Distt.	Tahsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Imiliya State	127	0-02	
				126	0-58	
				131	0-73	
				122	1-10	
				120	0-02	
				119	0-03	
				117	0-80	
				116	0-01	
				113	0-73	
				111	0-15	
				149	0-02	
				148	0-02	
				153	0-30	
				152	0-38	
				151	0-02	
				150	0-02	
				103	0-16	
				101	1-24	
				97	0-35	
				100	0-04	
				98	0-03	

[No. O—14016/68/84-GP]

क. अ. 2372—यत् पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ लाइन (भूमि से उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ. स. 4103 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत्: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत्: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन का इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा स.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	बिरगवां	132	0-68	
				133	0-03	
				134	1-33	
				135	0-05	
				136	0-48	
				299	0-10	
				322	0-25	
				323	0-30	
				325	1-70	
				326	1-06	
				328	0-98	
				330	0-06	
				331	0-01	
				332	0-24	
				334	0-22	
				352	1-04	
				354	0-54	
				356	0-04	
				358	1-02	
				360	1-34	
				363	0-05	
				364	0-01	
				378	0-18	
				377	0-38	
				380	0-10	
				381	0-10	
				382	0-57	
				391/4	0-02	
				392	0-06	
				399	1-10	
				400	0-11	

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
				412	0-27						326	1-06	
				413	0-06						328	0-98	
				114	0-54						330	0-06	
				425	0-04						331	0-01	
				419	0-80						332	0-24	
				1-0	0-22						334	0-22	
				422	2-23						352	1-04	
				429	0-68						354	0-54	
				430	0-83						356	0-04	
				431	0-40						358	1-02	
				432	0-04						360	1-34	
				434	0-01						363	0-05	
				435	0-02						364	0-01	
				469	0-04						378	0-18	
				480	0-30						377	0-38	
				471	0-05						380	0-10	
											381	0-10	
											382	0-57	
											391/4	0-02	
											392	0-06	
											399	1-10	
											400	0-11	
											412	0-27	
											413	0-06	
											414	0-54	
											425	0-04	
											419	0-80	
											420	0-22	
											422	0-23	
											429	0-68	
											430	0-83	
											431	0-40	
											432	0-04	
											434	0-01	
											435	0-02	
											469	0-04	
											480	0-30	
											471	0-05	

[स. O-14016/5/84-जी. पी.]

S.O. 2372.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4103 dated 12-11-84 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bar By Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area to Acquired in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Birga-wan	132	0-68	
				133	0-03	
				134	1-33	
				135	0-05	
				136	0-48	
				299	0-10	
				322	0-25	
				323	0-30	
				325	1-70	

[No. O 14016/5/84-GP]

का. आ. 2372—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. म. 4103 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला तहसील पर्यन्त ग्राम गाटा सं लिया गया विवरण
रकबा एकड़ में

1	2	3	4	5	6	7
झाँसी	मोठ	मोठ	सरसा	60	1-18	
				61	0-09	
				65	0-03	
				66	1-59	
				75	0-70	
				76	0-10	
				77	0-03	
				176	0-03	
				191	0-09	
				216	1-62	
				217	0-93	
				221	0-04	
				231	0-33	
				232	1-75	
				233	0-18	
				234	0-66	
				235	0-03	
				239	0-07	
				240	0-34	
				241	0-25	
				243	1-38	
				291	1-23	
				292	0-45	
				293	0-28	
				294	0-49	
				296	0-10	
				297	0-09	
				298	0-37	
				299	0-17	
				310	0-03	
				321	2-08	
				322	0-19	
				325	0-08	
				326	0-21	
				327	0-55	
				332	0-08	
				345	0-03	
				352	1-29	
				353	0-16	
				355	0-01	
				356	1-74	
				358	0-96	

1	2	3	4	5	6	7
				373	0-03	
				380	0-21	
				381	0-07	
				382	1-35	
				386	0-22	
				387	0-54	
				388	1-09	
				591	0-19	
				392	0-46	
				426	0-28	
				532	0-24	
				534	0-06	
				597	0-36	
				597/1779	0-11	
				598	0-28	
				599	0-03	
				602	0-98	
				603	0-05	
				604	0-34	
				605	0-03	

[सं. O-14016/5/84-जी पी]

S.O. 2373.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4103 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pur- gana	Village	Plot No.	Area Acquired (in acres)	Re- mark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Sersa	60	1-18	
				61	0-09	
				65	0-03	
				66	1-59	
				75	0-70	

1	2	3	4	5	6	7
				76	0-10	
				77	0-03	
				191	0-03	
				216	1-62	
				217	0-93	
				221	0-04	
				231	0-33	
				232	1-75	
				233	0-18	
				234	0-66	
				235	0-08	
				239	0-07	
				240	0-34	
				241	0-25	
				243	1-38	
				291	1-23	
				292	0-45	
				293	0-28	
				294	0-49	
				296	0-10	
				297	0-09	
				298	0-37	
				299	0-17	
				310	0-03	
				321	0-08	
				322	0-19	
				325	0-08	
				326	0-21	
				327	0-55	
				332	0-08	
				345	0-03	
				352	1-29	
				353	0-16	
				355	0-01	
				356	1-74	
				358	0-96	
				373	0-03	
				380	0-21	
				381	0-07	
				382	1-35	
				386	0-22	
				387	0-54	
				388	1-09	
				391	0-19	
				392	0-46	
				426	0-28	
				532	0-24	
				534	0-06	
				597	0-36	
				597/1779	0-11	
				598	0-28	
				599	0-03	
				602	0-98	
				603	0-05	
				604	0-34	
				605	0-03	

[No. O-14016/5/84-GP]

दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अब: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश होती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय रैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाश इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा--बरेली--जगदीशपुर रैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा नं.	अर्जित किया	विवरण
					एकड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
ब्रामी	मोठ	मोठ	खडौवा	10	0-03	
				11	0-01	
				12	0-13	
				16	2-00	
				24	0-25	
				25	0-51	
				68	0-96	
				92	0-48	
				102	0-04	
				105	0-02	
				106	1-22	
				108	0-05	
				111	0-08	
				112	0-56	
				115	0-05	
				116	0-56	
				117	0-45	
				119	0-04	
				120	0-02	
				125	1-00	
				127	0-10	
				136	0-02	
				152	0-05	
				153	1-80	
				154	0-18	
				155	0-68	
				181	0-04	
				182	0-16	
				183	1-05	
				184	0-04	
				190	1-12	

का. आ. 2374--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. स. 4103 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि-

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
				191	0-30						105	0-02	
				192	0-04						106	1-22	
				193	0-02						108	0-05	
				211	0-68						111	0-08	
				224	0-25						112	0-56	
				225	0-96						115	0-05	
				231	0-62						116	0-56	
				233	0-32						117	0-45	
				234	0-96						119	0-04	
				235	0-03						120	0-02	
				236	0-03						125	1-00	
				238	0-80						127	0-10	
				239	0-05						136	0-02	
				254	0-06						152	0-03	
				255	0-08						153	1-80	
				256	0-03						154	0-18	
				288	0-04						155	0-68	
				289	0-02						181	0-04	
											182	0-16	
											183	1-05	
											184	0-04	
											190	1-12	
											191	0-30	
											192	0-04	
											193	0-03	
											211	0-68	
											224	0-25	
											225	0-96	
											231	0-62	
											233	0-32	
											234	0-96	
											235	0-03	
											236	0-03	
											238	0-80	
											239	0-05	
											254	0-06	
											255	0-08	
											256	0-03	
											288	0-04	
											289	0-02	

[स. ओ-14016/5/84-जी पी]

S.O. 2374.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4103 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipe Line from Hajira—Barcilly—Jagdishpur Project

District	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Khana-uwa	10	0-03	
				11	0-01	
				12	0-13	
				16	2-00	
				24	0-25	
				25	0-51	
				68	0-96	
				92	0-48	
				102	0-04	

[No. O-14016/5/84-GP]

का. आ. 2375—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. स. 5779 तारीख 27-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः महम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) ले अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अथ, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का

अधिकार केन्द्रीय सरकार से निहित होने के बजाय भारतीय सैन्य प्राधिकरण वि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट						
जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाँव स.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झाँसी	झाँसी	झाँसी	खन्द करारी	75/4	0-75	
				75/3/2	0-54	
				75/4/1	0-65	
				77	0-22	
				77/175	0-05	
				79/1	0-09	
				79/2	0-09	
				80	0-39	
				83/1	0-14	
				83/2/1	0-14	
				83/2/2	0-13	
				92/1/1	0-05	
				92/1/2	0-05	
				92/1/3	0-05	
				92/1/4	0-06	
				92/2/2	0-06	
				92/2/3	0-06	
				92/2/4	0-06	
				92/2/5	0-06	
				93/1/1	0-06	
				93/1/2	0-06	
				93/1/3	0-06	
				93/2/1	0-06	
				93/2/2	0-06	
				93/2/3	0-06	
				93/2/4	0-05	
				108/1/1	0-60	
				108/1/2	0-72	
				108/4/1	0-39	
				108/4/2	0-37	
				110/1	0-10	
				110/2/1	0-10	
				110/2/2	0-10	
				110/2/3	0-09	
				111/1	0-09	
				111/2/1	0-09	
				111/2/2	0-09	
				111/2/3	0-08	
				111/2/4	0-08	
				112/1	0-11	
				112/2/1	0-10	
				112/2/2	0-10	
				112/2/3	0-10	
				115/1/1	0-20	
				115/1/2	0-20	

1	2	3	4	5	6	7
				115/1/3	0-19	
				115/2	0-19	
				118/1	0-09	
				118/2/1	0-09	
				118/2/2	0-09	
				118/2/3	0-10	

[सं. O-14016/169/84-जी पी]

S.O. 2375.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3779 dated 27-10-84 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-mark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Roond	75/4	0-75	
			Karari	75/3/2	0-54	
				75/4/1	0-65	
				77	0-22	
				77/175	0-05	
				79/1	0-09	
				79/2	0-09	
				80	0-39	
				83/1	0-14	
				83/2/1	0-14	
				83/2/2	0-13	
				92/1/1	0-05	
				92/1/2	0-05	
				92/1/3	0-05	
				92/1/4	0-06	
				92/2/2	0-06	
				92/2/3	0-06	

1	2	3	4	5	6	7
				92/2/4	0 06	
				92/2/5	0-06	
				93/1/1	0-06	
				93/1/2	0-05	
				93/1/3	0-05	
				93/2/1	0-06	
				93/2/2	0-06	
				93/2/3	0-06	
				93/2/4	0-05	
				108/1/1	0-60	
				108/1/2	0 72	
				108/4/1	0 39	
				108/4/2	0-37	
				110/1	0-10	
				110/2/1	0-10	
				110/2/2	0-10	
				110/2/3	0-09	
				111/1	0-09	
				111/2/1	0-09	
				111/2/2	0-09	
				111/2/3	0-08	
				111/2/4	0-08	
				112/1	0-11	
				112/2/1	0-10	
				112/2/2	0-10	
				112/2/3	0-10	
				115/1/1	0-20	
				115/1/2	0-20	
				115/1/3	0-19	
				115/2	0-19	
				118/1	0-09	
				118/2/1	0-09	
				118/2/2	0-09	
				118/2/3	0-10	

[No. O-14016/169/84-GP]

का आ 2476—यन पेट्रोलियम और खनिज पारंपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ. सं. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न भूमियों में विनिवृष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पारंप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यन सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट की है।

और आगे यन: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में विनिवृष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिवृष्ट किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न भूमियों में विनिवृष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पारंपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची
हाजिरा बरेली जगदीशपुर पारंपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटासं	रकबा	विवरण
का नाम						
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर	कानपुर-	कानपुर-	नगवा	49/6	0-5-10	
मिटी	मिटी	सिटी				
				52	2-15-0	
				53	0-16-16	
				61	0-7-0	
				62	0-9-0	
				60	0-17-0	
				63/1	0-5-0	
				63/2	0-5-0	
				63/3	0-5-0	
				64	0-10-0	
				104	0-17-0	
				111	0-11-0	
				114	0-13-0	
				122	0-0-10	
				137	0-5-0	
				162	0-6-10	
				169	0-11-0	
				168	0-3-0	
				138	1-15-0	
				167	1-4-0	
				216/5	1-15-0	
				217	0-17-0	
				218	0-4-10	
				192/4	1-7-0	
				222	0-10-0	
				224	0-16-0	
				223	0-12-0	
				225	0-6-0	
				226	0-10-0	
				231	0-4-0	
				233	1-8-0	
				246	0-18-10	
				242	0-8-0	
				247/2	0-9-0	
				248	0-1-0	
				397	0-1-0	
				398	0-6-0	
				401	0-4-0	
				402	0-2-0	
				404	0-0-10	
				406/1	0-8-0	
				542/1	2-3-0	
				542/2	1-0-0	

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
				542/1	0-5-0					167	1-4-0		
				562/1	1-5-0					216	1-15-0		
				190	0-8-0					217	0-17-0		
				37/1	0-12-0					218	0-4-10		
				37/2	0-12-0					192/4	1-7-0		
				114	0-4-0					222	0-10-0		
				120	0-2-0					224	0-16-0		
				103	0-3-0					223	0-12-0		
				112	0-6-0					225	0-6-0		
										226	0-10-0		
										231	0-4-0		
										233	1-8-0		
										246	0-18-10		
										242	0-8-0		
										247/2	0-9-0		
										248	0-1-0		
										397	0-1-0		
										398	0-6-0		
										401	0-4-0		
										402	0-2-0		
										404	0-0-10		
										406/1	0-8-0		
										542/1	2-3-0		
										542/2	1-0-0		
										543/4	0-5-0		
										562/1	1-5-0		
										190	0-8-0		
										37/1	0-12-0		
										37/2	0-12-0		
										114	0-4-0		
										120	0-2-0		
										103	0-3-0		
										112	0-6-0		

[सं. O-14016/6/84-जीपी]

S.O. 2376.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Per-gana	Tehsil	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur City	Kanpur City	Kanpur City	Nagwa	49/6	0-5-1 0	
				52	2-15-0	
				53	0-16-16	
				61	0-7-0	
				62	0-9-0	
				60	0-17-0	
				63/1	0-5-0	
				63/2	0-5-0	
				63/3	0-5-0	
				64	0-10-0	
				104	0-17-0	
				111	0-11 0	
				114	0-13-0	
				122	0-0-10	
				137	0-5-0	
				162	0-6-10	
				169	0-11-0	
				168	0-3-0	
				138	1-15-0	

[No. O-14016/6/84-GP]

का. आ. 2377:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय/पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राश्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चित किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उन धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस उपयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा म.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर	कानपुर	कानपुर	खडगपुर	18	1-13-10	
शहर	शहर	शहर	पुर	15	1-6-6	
				14	0-8-7	
				11	0-3-0	
				9	0-1-0	
				1	0-8-0	
				3	0-3-16	
				4	1-5-0	
				5m	0-18-17	

[सं. O-14016/6/84 जीपी]

S.O. 2377.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Per-gana	Tehsil	Village	Plot No	Area Acquired	Re-mak
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur	Kanpur	Kanpur	Kha-	18	1-13-10	
City	City	City	rgpur	15	1-6-6	
				14	0-8-7	
				11	0-3-0	
				9	0-1-0	
				1	0-8-0	
				3	0-3-16	
				4	1-5-0	
				5m	0-18-17	

[No. O-14016/6/84-GP]

का प्रा. 2378—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का प्रा. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः संश्लेष प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट द दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चित किया है।

अतः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस उपयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया गाटा म०	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर	कानपुर	कानपुर	परसौली	360	0-1-0	
				359	0-13-13	
				361	0-1-19	
				358	1-0-02	
				371	0-1-0	
				223	0-1-7	
				372	0-3-18	
				221	0-13-19	
				220	0-13-6	
				213	0-2-5	
				216	0-19-17	
				217	0-9-0	
				205	0-3-0	
				203	0-7-6	
				191	0-0-13	
				189	0-18-17	
				188	0-4-6	
				187	0-15-10	
				186	0-3-12	
				177	0-17-17	
				154	0-2-12	
				155	2-1-15	
				156	0-10-18	

158	1-0-03
146	0-16-5
135	0-0-1
134	0-1-6
145	0-3-5
133	1-2-12
222	0-0-2
218	0-0-7
214	0-0-5
193	0-0-13
190	0-0-6
182	0-0-16
144	0-0-10
143	0-1-0

[सं. O-14016/6/84-जीपी]

S.O. 2378.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act., 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Per-gana	Tehsil	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur City	Kanpur City	Kanpur City	Persoli	360	0-1-0	
				359	0-13-13	
				361	0-1-19	
				358	1-0-02	
				371	0-1-0	
				223	0-1-7	
				372	0-3-18	
				221	0-13-19	
				220	0-13-6	
				213	0-2-5	
				216	0-19-17	
				217	0-9-0	
				205	0-3-0	

203	0-7-6
191	0-0-13
189	0-18-17
188	0-4-6
187	0-15-10
186	0-3-12
177	0-17-17
154	0-2-12
155	2-1-15
156	0-10-18
158	1-0-03
146	0-16-5
135	0-0-1
134	0-1-6
145	0-3-5
133	1-2-12
222	0-0-2
218	0-0-7
214	0-0-5
193	0-0-13
190	0-0-6
182	0-0-16
144	0-0-10
143	0-1-0

[No. O-14016/6/84-GP]

का. भा. 2379 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. भा. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में विनिश्चित भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में विनिश्चित भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में विनिश्चित भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdeshpur Pipe Line Project

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
कानपुर	कानपुर	कानपुर	डांडे का पुरवा	7	1-2-4
				10	0-2-0
				11	0-1-0
				12	2-0-18
				14	0-1-16
				15	1-0-8
				16	0-7-16
				37	0-16-12
				49	0-15-08
				52	0-8-34
				53	0-0-12
				100	1-16-0
				103	0-1-3
				104	0-0-11
				105	0-13-6
				106	0-6-0
				107	0-1-6
				50	0-0-15

[सं. O-14016/6/84-जीपी]

S.O. 2379.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Distt.	Per-gana	Tehsil	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-mark
Kanpur City	Kanpur City	Kanpur City	Denda-yaka Purva	7	1-2-4	
				10	0-2-0	
				11	0-1-0	
				12	2-0-18	
				14	0-1-16	
				15	1-0-8	
				16	0-7-16	
				37	0-16-12	
				49	0-15-06	
				52	0-8-14	
				53	0-0-12	
				100	1-16-0	
				103	0-1-3	
				104	0-0-11	
				105	0-13-6	
				106	0-6-0	
				107	0-1-6	
				50	0-0-15	

[No. O-14016/6/84-GP]

का. भा. 2880:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का भा. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में आपणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा, बरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
कानपुर	कानपुर	कानपुर	श्रीरियारा मिटी	11	0-2-16
				15	0-12-0
				16	0-9-11

[सं. O-14016/6/84-जीपी]

S.O. 2380.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur-Pipe Line Project

Distt.	Per-gana	Tehsil	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-mark
Kanpur City	Kanpur City	Kanpur City	Oriya-na	11	0-2-16	
				15	0-12-0	
				16	0-9-11	

[No. O-14016/6/84-GP]

कां० प्रा० 2381.—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अधिनियम) अधिनियम 1962 (1962 का 50 का धारा) 3 के उपधारा (1) के अधिनियम भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिनियम कां० प्रा० 3789 तारीख 27.10.84 द्वारा केन्द्र सरकार ने उस अधिनियम से सलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था।

और यत्: सश्रम अधिकारों ने उक्त अधिनियम के धारा 6 के उपधारा (1) के अधिनियम सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और प्रागे यत्: केन्द्र सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिनियम से सलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम का धारा 6 के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिनियम से सलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और प्रागे उक्त धारा को उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्र सरकार निदेश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्र सरकार में निहित होने के बजाय भारत गैस प्राधिकरण लि. में महा बाधाओं में मान्यता से प्रयोग के लिये तैयार होना तैयार होना को निहित होगा।

अनुसूची						
हजिरा- बरेल्ल- जगदिशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट						
जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा नं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झाँसी	झाँसी	झाँसी	लकागा	36	0- 02	
				37	0- 01	
				38	2- 00	
				39	0- 45	
				40	0- 54	
				51	0- 31	
				52	0- 02	
				54	0- 05	
				55	0- 30	
				56	0- 30	
				57	0- 29	
				58	0- 02	
				62	1- 16	
				63	0- 01	
				64	1- 56	
				77	0- 40	
				87	0- 01	
				88	0- 32	
				90	1- 59	
				112	0- 31	
				116	0- 02	
				117	0- 01	
				118	0- 02	
				119	0- 40	
				120	1- 18	
				123	0- 10	
				124	0- 02	
				129	1- 23	
				131	0- 15	
				223	0- 19	
				224	0- 20	
				225	0- 13	
				227	0- 02	
				229	0- 40	
				230	0- 02	
				231	0- 66	
				233	0- 24	
				240	0- 02	
				244	0- 52	
				245	0- 60	
				248	0- 12	
				368	0- 72	
				382	0- 42	
				383	0- 01	
				384	0- 51	
				385	0- 01	
				387	0- 90	
				388	0- 01	

SCHEDULE

Hajira-Barcilly-Jagdishpur Pipeline Project

1	2	3	4	5	6	7
				389	0-02	
				390	1-12	
				391	0-93	
				392	0-01	
				393	0-12	
				398	0-15	
				399	0-03	
				430	0-02	
				431	0-66	
				433	0-14	
				436	0-18	
				437	0-01	
				438	0-01	
				439	0-23	
				440	0-09	
				457	1-50	
				459	0-52	
				460	0-40	
				461	0-01	
				462	0-75	
				463/1	0-12	
				474	0-03	
				482	3-03	
				488	0-66	
				491	0-51	
				492	0-42	
				504	0-32	
				723	0-75	

[सं. O-14016/179/84-जीपी]

S.O. 2381.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3788 dated 27-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Distt	Tohsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Lokara	36	0-02	
				37	0-01	
				38	2-00	
				39	0-45	
				40	0-54	
				51	0-31	
				52	0-02	
				54	0-05	
				55	0-30	
				56	0-30	
				57	0-29	
				58	0-02	
				62	1-16	
				63	0-01	
				64	1-56	
				77	0-40	
				87	0-01	
				88	0-32	
				90	1-59	
				112	0-31	
				116	0-02	
				117	0-01	
				118	0-02	
				119	0-40	
				120	1-18	
				123	0-10	
				124	0-02	
				129	1-23	
				131	0-15	
				223	0-19	
				224	0-20	
				225	0-13	
				227	0-02	
				229	0-40	
				230	0-02	
				231	0-66	
				233	0-24	
				240	0-02	
				244	0-52	
				245	0-60	
				248	0-12	
				368	0-72	
				382	0-42	
				383	0-01	
				384	0-51	
				385	0-01	
				387	0-90	
				388	0-01	
				389	0-02	
				390	1-12	
				391	0-93	
				392	0-01	
				393	0-12	
				398	0-15	
				399	0-03	

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
				430	0-02						132	0-02	
				431	0-66						123	0-01	
				433	0-14						122	0-45	
				436	0-18						121	0-02	
				437	0-01						119	0-02	
				438	0-01						118	0-02	
				439	0-23						117	0-03	
				440	0-09						116	0-02	
				457	1-50						115	0-22	
				459	0-52						114	0-75	
				460	0-40						111	0-02	
				461	0-01						110	1-25	
				462	0-75						108	0-02	
				463/1	0-12						107	0-03	
				474	0 03						106	0-15	
				483	0 03						105	0-55	
				488	0-66						104	0-10	
				491	0-51						103	0-32	
				492	0-42						102	0-08	
				504	0-32						179	0-17	
				723	0-75						339	0-27	

[No. O—14026/179/84-G.P.]

का.भा. 2182 : अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 3455 तारीख 16.10.84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यह सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यह केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय रीस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की हम तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा- बरेली- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिल्हा	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र— फल एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	झांसी	झांसी	कोटबेरा	131	1-65	
				131	0-36	

338	0-90
337	0-03
332	0-55
334	0-48
331	0-14
330	0-30
328	0-09
325	0-30
299	1-60
301	0-11
304	0-25
293	0-10
294	0-05
305	0-02
292	0-30
306	0-45
307	0-08
308	0-03
309	0-30
286	0-20
287	0-51
285	0-03
278	0-31
279	0-46
276	0-04
272	0-10
273	0-33
274	0-42
270	0-06
255	0-65
268	0-10
504	0-06

1	2	3	4	5	6	7	SCHEDULE						
				505	0-10		Hajipur-Bareilly-Jagdishpur Pipe line Project						
				506	0-08		Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
				507	0-11		1	2	3	4	5	6	7
				508	0-09		Jhonsi	Jhonsi	Jhonsi	Kot-khera	134	1-65	
				509	0-03						131	0-36	
				510	0-05						132	0-02	
				512	0-20						123	0-03	
				513	0-25						122	0-45	
				514	0-10						121	0-02	
				521	0-63						119	0-02	
				522	0-09						118	0-02	
				533	0-45						117	0-03	
				536	0-40						116	0-02	
				537	0-15						115	0-22	
				535	0-21						114	0-75	
				569	0-54						111	0-02	
				568	0-55						110	1-25	
				567	0-80						108	0-02	
				566	0-02						107	0-03	
				565	0-02						106	0-15	
				551	1-60						105	0-55	
				1	0-15						104	0-10	
				112	0-02						103	0-32	
				269	0-06						102	0-08	
				119	0-02						179	0-17	
											339	0-27	
											338	0-90	
											337	0-03	
											332	0-55	
											334	0-48	
											331	0-14	
											330	0-30	
											328	0-09	
											325	0-30	
											299	1-60	
											301	0-11	
											304	0-25	
											293	0-10	
											294	0-05	
											305	0-02	
											292	0-30	
											306	0-45	
											307	0-08	
											308	0-03	
											309	0-30	
											286	0-20	
											287	0-51	
											285	0-02	
											278	0-31	
											279	0-46	
											276	0-04	
											272	0-10	
											273	0-33	
											274	0-42	

[सं. O-14016/65/84-सं. १००]

S.O. 2382.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3455 dated 16-10-84 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1952), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

1	2	3	4	5	6	7
				270	0-06	
				255	0-65	
				268	0-10	
				504	0-06	
				505	0-10	
				506	0-08	
				507	0-14	
				508	0-09	
				509	0-03	
				510	0-05	
				512	0-20	
				513	0-25	
				514	0-10	
				521	0-63	
				522	0-09	
				533	0-45	
				536	0-40	
				537	0-15	
				535	0-21	
				569	0-54	
				568	0-55	
				567	0-80	
				566	0-02	
				565	0-02	
				551	1-60	
				1	0-15	
				112	0-02	
				269	0-06	

[No. O-14016/65/84 G-P.]

का.भा. 2383 —यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 3746 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यह सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यह केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन्यूट्रारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एन्यूट्रारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस सार्वजनिक को निहित होगा।

211 GI/85-1

अनुसूची						
हाजिरा- बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट						
जिला	खजूराल	परगना	ग्राम	खजूराल	लिया गया रकबा	विशेषण
1	2	3	4	5	6	7
जमी	जमी	मोठ	एरा	274	0-06	
				273	0-87	
				281	0-02½	
				275	1-59	
				282	0-50	
				279	0-28	
				280	0-54	
				285	0-04	
				300	1-46	
				302	0-02	
				303	0-02½	
				358	0-01	
				356	0-90	
				357	0-09	
				351	0-48	
				350	0-01½	
				346	0-83	
				345	0-03	
				312	0-02	
				337	0-86	
				341	0-32	
				335	0-41	
				338	0-01½	
				339	0-05	
				340	0-56	

[म. सं-14016/63/84- जी.पी.०]

S.O. 2383.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3746 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipe line from, Hajira —Bareilly—Jagdishpur Project

Distt[Tehasil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Aira	274	0-06	
				273	0-87	
				281	0-02-1/2	
				275	1-59	
				282	0-50	
				279	0-28	
				280	0-54	
				285	0-04	
				300	1-46	
				302	0-02	
				303	0-02-1/2	
				358	0-01	
				356	0-90	
				357	0-09	
				351	0-48	
				350	0-01-1/2	
				346	0-83	
				345	0-03	
				312	0-02	
				337	0-86	
				341	0-32	
				335	0-41-1/2	
				338	0-01-1/2	
				339	0-05	
				340	0-56	

[No. O—14016/63/84-G.P.]

का. आ. 2384.—यस: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (I) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4466 तारीख 14-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और जो यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और जो उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार से निहित होने के अन्तर्गत भारतीय नौ प्रधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में खोप्रा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची						
हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट						
जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिखा गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोथ	मोथ	करारी	243	0-04	
				265	0-17	
				266	1-16	
				267	0-27	
				268	0-51	
				269	1-35	
				287	0-40	
				288	0-68	
				290	0-57	
				291	0-01	
				380	0-17	
				381	0-10	
				382	0-08	
				409	0-12	
				410	0-03	
				411	0-06	
				412	0-04	
				413	0-08	
				451	0-70	
				453	0-24	
				454	0-03	
				458	0-60	
				459	0-04	
				456	0-54	
				577	0-08	
				576	0-04	
				575	0-09	
				567	0-75	
				563	0-01	
				565	0-07	
				566	0-75	
				1261	0-10	
				1277	0-59	
				1278	0-27	
				1290	0-26	
				1287	0-06	
				1286	0-00	
				1285	0-08	
				1294	0-55	
				1300	0-24	
				1262	0-09	
				1299	0-07	
				1302	0-14	
				1301	0-31	
				1304	0-12	
				1306	0-25	
				1307	0-03	
				1314	0-12	
				1315	0-08	

1	2	3	4	5	6	7
				1313	0-06	
				1312	0-10	
				1316	0-19	
				1317	0-09	
				1318	0-03	
				1056	0-18	
				1108	0-26	
				1107	0-20	
				1057	0-52	
				1059	0-08	
				1051	0-18	
				999	0-70	
				1049	0-04	
				1048	0-04	
				1000	0-08	
				1001	0-03	
				1002	0-10	
				1003	0-06	
				1006	0-01	
				991	0-08	
				986	0-17	
				987	0-01	
				935	0-20	
				934	0-10	
				933	0-04	
				909	0-32	
				910	0-41	
				911	0-35	
				921	0-05	
				920	0-21	
				922	0-13	
				924	0-20	
				925	0-13	
				958	0-12	
				918	0-01	
				801	0-83	
				802	0-62	
				820	0-02	
				379	0-49	

[सं. श्री-13016/485/84-जी.पी.]

S.O. 2384.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4666 dated 14-12-84 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Tehasil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Karari	243	0-04	
				265	0-17	
				266	1-16	
				267	0-27	
				268	0-51	
				269	1-35	
				287	0-40	
				288	0-68	
				290	0-57	
				291	0-01	
				380	0-17	
				381	0-10	
				382	0-08	
				409	0-12	
				410	0-03	
				411	0-06	
				412	0-04	
				413	0-08	
				451	0-70	
				453	0-24	
				454	0-23	
				458	0-60	
				459	0-04	
				456	0-54	
				577	0-08	
				576	0-04	
				575	0-09	
				567	0-75	
				563	0-01	
				565	0-07	
				566	0-75	
				261	0-10	
				1277	0-30	
				1278	0-27	
				1290	0-26	
				1287	0-06	
				1286	0-30	
				1285	0-08	
				1294	0-55	
				1300	0-24	
				1262	0-09	
				1299	0-07	
				1302	0-14	
				1301	0-31	
				1304	0-12	
				1306	0-25	
				1307	0-03	
				1314	0-12	
				1315	0-08	
				1313	0-06	
				1312	0-10	
				1316	0-19	
				1317	0-09	

1	2	3	4	5	6	7
				1318	0-03	
				1056	0-18	
				1108	0-26	
				1107	0-20	
				1057	0-52	
				1059	0-08	
				1051	0-18	
				999	0-70	
				1049	0-04	
				1048	0-04	
				1000	0-08	
				1001	0-03	
				1002	0-10	
				1003	0-06	
				1006	0-01	
				991	0-08	
				986	0-17	
				987	0-01	
				935	0-20	
				934	0-10	
				933	0-04	
				900	0-32	
				910	0-41	
				911	0-35	
				921	0-05	
				920	0-21	
				922	0-13	
				924	0-20	
				925	0-13	
				958	0-12	
				918	0-01	
				801	0-83	
				802	0-62	
				820	0-21	
				379	0-49	

[No. O—14016/485/84-G.P.]

का. प्र. 4385—यथा: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का का. 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्धन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. प्र. सं. 3440 तारख 16-10-84 द्वारा केन्द्रिय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचा में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्धन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और भागे यतः केन्द्रिय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचा में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रिय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचा में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रिय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूचा						
हाजिरा-बरेल-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट						
जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झाँस	झाँस	झाँस	डंगरबाहु	927/3	0-30	
				929	0-05	
				930/2	1-71	
				933	0-80	
				934/2	1-07	
				943	0-17	
				945/3	0-16	
				946/1	0-34	
				948	0-03	
				1108	0-02	
				1109/1	0-20	
				1109/3	0-60	
				1113	0-32	
				1114/2	0-15	
				1115/1	0-25	
				1118/2	0-58	
				1118	0-78	
				1119	0-03	
				1124/1	0-06	
				1135	0-30	
				1136/10	0-80	
				1137/1	0-30	
				1138/2	0-90	
				1139	0-12	
				1140	0-06	
				1141/1	0-80	
				1142/1	0-15	
				1143	0-70	
				1144/2	1-94	
				1146/1	0-02	
				1147/1	0-27	
				1369/2	0-10	
				1139/1	1-75	
				1442/2	0-60	
				1141	0-05	
				1445/2	0-01	
				1446	0-60	
				1448	0-25	
				1449	0-05	
				1450/1	0-45	
				1451/1	0-45	
				1462	0-02	
				1464/2	0-02	
				1515	0-47	
				1517	0-65	
				1535	1-90	
				1536	1-00	
				1537	0-08	

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
				1538	0-80						943	0-17	
				1539	0-18						915/3	0-16	
				1546	0-15						946/1	0-34	
				1547	0-75						948	0-03	
				1549/1	2-59						1108	0-02	
				1550/1	0-04						1109/1	0-20	
				1559	1-42						1109/3	0-60	
				1560/1	0-10						1113	0-32	
				1648/2	0-03						1114/2	0-15	
				1649/1	1-10						1115/1	0-25	
				1651	0-95						1116/2	0-58	
				1655	0-15						1118	0-78	
				1658	0-45						1119	0-03	
				1659	0-90						1124/1	0-06	
				1661	0-15						1135	0-30	
				1369/2	0-40						1136/10	0-80	
				1463	0-10						1137/1	0-30	
				1589/1	0-01						1138/2	0-90	
				1657/1	0-01						1139	0-12	
				1660	0-07						1140	0-06	
				1663/2	0-01						1141/1	0-60	
				1668	0-03						1142/1	0-15	

[स ओ-14016/37/84-ज.प.]

S.O. 2485—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3440 dated 16-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (30 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (1) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas pipe line from Haujra Bareilly Jagdish pur Project

Distt	Tehasil	Par-gana	Village	Plot No.	Area in acers.	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Thansi	Jhansi	Jhansi	Dangar	927/3	0-30	
				Baha 929	0-05	
				930/2	1-71	
				933	0-80	
				934/2	1-07	

[No. O-14016/37/84-G.P.]

का. आ. 4386 --यतः पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम) अधिनियम 1962 (1962 का 50) क धारा 3 की उपधारा (1) के अधिनियम भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय क अधिसूचना का आ. सं. 3456 तारख 16-10-84 द्वारा केन्द्रिय सरकार ने उस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों का बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना अधिकार घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम का धारा 6 का उपधारा (1) के अधिनियम सरकार को रिपोर्ट दे द है।

और आगे यतः केन्द्रिय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है और आगे उस धारा क उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रिय सरकार से निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन का इस सार्वजनिक को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	नियमा गता रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
आंसी	आंसी	आंसी	रस्ता	120	0-32	
				121	0-33	
				122	0-35	
				123	0-32	
				127	1-13	
				150	0-16	
				128	0-03	
				143	0-13	
				144	0-32	
				145	0-01	
				147	0-65	
				149	0-02	
				155	0-06	
				371	0-12	
				372	0-16	
				373	0-16	
				375	0-04	
				376	0-32	
				380	0-04	
				381	0-22	
				382	0-16	
				384	0-03	
				385	0-37	
				388	0-25	
				396	0-11	
				400	0-91	

1	2	3	4	5	6	7
				401	0-12	
				124	0-02	
				560	0-70	
				398	0-90	
				399	1-50	
				410	0-10	
				509	0-69	
				510	0-02	
				513	0-17	
				514	0-54	
				515	0-16	
				519	0-66	
				522	0-62	
				523	0-49	
				524	0-81	
				640	0-95	
				642	0-80	
				682	0-61	
				683	0-37	
				684	0-18	
				688	0-32	
				690	0-75	
				692	0-06	
				689	0-46	
				693	0-32	
				694	1-53	
				627	0-08	
				628	0-08	
				629	0-08	
				411	0-30	

[सं. O-14016/66/84-गोपी]

एम. एस. श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 2386.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3456 dated 16-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said land; shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

नई दिल्ली, 17 मई, 1985

Gas Pipe line from Hajira-Bareilly-Jagdishpur Project

Distt	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area in acres	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Raksa	120	0-32	
				121	0-33	
				122	0-35	
				123	0-32	
				127	1-15	
				150	0-16	
				123	0-03	
				143	0-13	
				144	0-32	
				145	0-01	
				147	0-65	
				149	0-02	
				155	0-06	
				371	0-12	
				372	0-16	
				373	0-16	
				375	0-04	
				376	0-32	
				380	0-04	
				381	0-22	
				382	0-16	
				384	0-09	
				385	0-37	
				388	0-25	
				396	0-11	
				400	0-91	
				401	0-12	
				124	0-02	
				560	0-70	
				398	0-90	
				399	1-50	
				410	0-40	
				509	0-69	
				510	0-07	
				513	0-17	
				514	0-54	
				515	0-16	
				519	0-66	
				522	0-62	
				523	0-49	
				524	0-81	
				640	0-95	
				642	0-80	
				682	0-61	
				683	0-37	
				684	0-18	
				688	0-32	
				690	0-75	
				692	0-06	
				689	0-46	
				693	0-32	
				694	1-53	
				627	0-08	
				628	0-08	
				629	0-08	
				411	0-30	

[No. O-14016/66/84-G.P.]

M.S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

का धा. 122 - 74 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन के 122 में जी.जी.एस-3 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तैयार प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जाना चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एल.पाव. अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अब अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना वाशय एतद्वारा घोषित किया है।

नहीं कि उक्त भूमि में निम्नलिखित कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आशेष मकाम प्रशिक्षण, तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर धर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट. यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफ़त।

अनुसूची

एन. के. 122 से जी.जी.एस. 3 तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य-गुजरात जिला व तालुका-मेहराणा

गाँव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	एअर ई गेंटीअर
धानपुरा	621	0	03 00
कार्ट ट्रैक		0	01 44

[मं. O-12016/58/85-ओ एन जी-डी 4]

New Delhi, the 17th May, 1985

S.O. 2387.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NK-122 to GGS III in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying, such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline from NK-122 to GGS III.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hect-are	Are Centi-are
Dhanpura	621	0	03 00
Cart track		0	01 44

[No. O-12016/58/85-ONG-D-4]

आ. आ. 2388.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एम. बी. डी. आर. में सीटोपम सामग्री तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस लाइनों बिछाई जानी चाहिए।

और यह: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाठ्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वर्णन कि उक्त भूमि में हितवद् कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप मजबूत प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिनियम की धारा 3 में 21 दिनों के भीतर कर सकता है।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट, यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मूलवादी व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एम. बी. डी. आर. से सीटोपम सामग्री तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला या तालुका—मेहसाणा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	एआरडी	सेन्टी-एअरडी
पुनवास	119	0	16	08
	118	0	08	76
	127	0	06	48
	126	0	02	04

[ग. ओ-12016/59/85-ओएनजीडी-4]

S.O. 2388.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SBDR to CTF Sobhasan in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SBDR to CTF SOB.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No	Hect-are	Are	Centi-are
Punasan	119	0	16	08
	118	0	08	76
	127	0	06	48
	126	0	02	04

[No. O-12016/59/85-ONG-D 4]

नई दिल्ली, 18 मई, 1985

आ. आ. 2389.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एम. बी. डी. आर. में सीटोपम सामग्री तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस लाइनों बिछाई जानी चाहिए।

और यह: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाठ्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वर्णन कि उक्त भूमि में हितवद् कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप मजबूत प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिनियम की धारा 3 में 21 दिनों के भीतर कर सकता है।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट, यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मूलवादी व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एम. बी. डी. आर. से सीटोपम सामग्री तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	सं. नं.	हेक्टेयर	एआरडी	सेन्टी-अर
सुजपुरा	76/पी	0	09	60
	82/1	0	03	84

[स. ओ-12016/60/85-आएनजीडी-4]

New Delhi, the 18th May, 1985

S.O. 2389.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKEV to NKEU in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NKEV to NKEU

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Sujpura	76/P	0	09	60
	82/1	0	03	84

[No. O-12016/60/85-ONG-D 4]

का आ. 2390—यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन. के. ड. एम. से एन. के. ड. एम. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मसम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

राज्य—गुजरात	जिला—मेहसाना	तालुका—कडी			
गांव	मं. न.	हेक्टेयर ड.आई.ई. सेंटीअर			
सुरज	654	0 08 88			
	655	0 05 52			
	कार्ट ट्रैक	0 01 44			
	716	0 09 36			
	715	0 07 68			
	714	0 04 08			
	707/पी	0 05 76			
	707/पी	0 07 80			
	708	0 06 72			
	700/2पी	0 07 44			
	700/1पी	9 07 56			
	700/1पी	0 12 72			
	693	0 06 48			
	694/1	0 06 12			

[मं. O—12016/61/85-ओ.एन.जी.-डी.4]

S.O. 2390.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKEL to NKEM in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009.)

211 GI/85—14

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline from NKEL to NKEM

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hect- are	Are	Centi- are
Suraj	654	0	08	88
	655	0	05	52
	Cart track	0	01	44
	716	0	09	36
	715	0	07	68
	714	0	04	08
	707/P	0	05	76
	707/P	0	07	80
	708	0	06	72
	700/2P	0	07	44
	700/1P	9	07	56
	700/1P	0	12	72
	693	0	06	48
	694/1	0	06	12

[No. O—12016/61/85-ONG-D 4]

का आ. 214—यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन. के. 141 से एन. के. जी. जी. एम. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मसम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

राज्य—गुजरात	जिला—तालुका—मेहसाना			
गांव	प्लॉट नं.	हेक्टेयर ए. आर. ई. सेंटीअर		
धानपुरा	297	0 04 56		
	कार्ट ट्रैक	0 01 08		

[मं. O—12016/62/85-ओ.एन.जी.-डी.4]

S.O. 2391.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NK-141 to NK. GGSIII in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And hereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NK-141 to NK. GGS III.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hect- are	Are C-nti- are
Dhanpura	297	0 04	56
	Cart track	0 01	08

[No. O—12016/62/85/ONG-D 4]

का. आ. 2392—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य एम. एन. ए. क्यू. से बमोल-3 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने समस्त उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अर्णों कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप राख प्रधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देशसात प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिवृत्ता की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत

अनुसूची

एस.एन.ए. क्यू. से बमोल—3 तक पाइप लाइन बिछाने के लिये
राज्य—गुजरात जिला ब तालुका—मेहसाणा

गांव	ब्लॉक नं.	हैक्टेयर ए.आर.आई.	सेन्टीअर
1	2	3	4
संधाल	551	0 05	52
	552	0 08	
	555	250 08	04

1	2	3	4	5
	557	0 09	18	
	593/पी	0 15	40	
	काटे ट्रैक	0 00	40	
	594/पी	0 20	52	
	595	0 04	68	
	काटे ट्रैक	0 00	48	
	313	0 09	10	
	312	0 08	12	
	311	0 01	92	
	काटे ट्रैक	0 02	40	
	622	0 02	16	
	623	0 04	68	
	624	0 09	72	
	काटे ट्रैक	0 01	44	
	58	0 00	66	
	57	0 10	80	
	56	0 10	56	
	55	0 08	28	
	54	0 00	60	
	45	0 02	52	
	46	0 08	23	
	47	0 11	52	
	काटे ट्रैक	0 01	20	
	77	0 05	54	
	78	0 04	02	
	81	0 08	60	
	82	0 09	74	
	काटे ट्रैक	0 01	50	
	20/2	0 02	34	
	20/3	0 09	66	
	20/5	0 11	83	
	20/6/पी	0 03	60	
	20/6/पी	0 04	36	

[सं. O—12016/63/85-मो एन जी डी-4]

S.O. 2392.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNAQ to Balal-3 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipe line from SNAQ to BALOL-3.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hect- are	Acre	Centi- are
1	2	3	4	5
Sarthal	551	0	05	52
	552	0	08	52
	555	0	08	34
	557	0	09	36
	593/P	0	15	48
	Cart track	0	00	48
	594/P	0	20	52
	595	0	04	68
	Cart track	0	00	48
	313	0	09	12
	312	0	08	22
	311	0	01	92
	Cart track	0	02	40
	622	0	02	16
	623	0	04	68
	624	0	09	72
	Cart track	0	01	44
	58	0	00	66
	57	0	10	80
	56	0	10	56
	55	0	08	28
	54	0	00	60
	45	0	02	52
	46	0	08	23
	47	0	11	52
	Cart track	0	01	20
	77	0	05	54
	78	0	04	02
	81	0	03	60
	82	0	03	74
	Cart track	0	01	50
	20/2	0	02	34
	20/3	0	09	66
	20/5	0	11	83
	20/6/P	0	03	60
	20/6/P	0	04	36

[No. O—12016/63/85-ONG-G 4]

नई दिल्ली, 20 मई, 1985

का. आ. 2393—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जे. एन. ए. सी. से जोटाणा जी जी एस. -1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वाचक अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज वाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) को धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जे. एन. ए. सी. से जोटाणा जी जी एस-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात	जिला व तालुका—मेहसाणा	गांव	सं. नं.	हैक्टर	ए. आर. ई.	सेन्टाभर
		मोदीपुर	182	0	26	04
			179	0	09	48
			177	0	09	12

[सं. O —12016/65/85-ओ एन. जी. बी-4]

New Delhi, the 20th May, 1985

S.O. 2393.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for transport of petroleum from JNAC to Jotana GGS 1 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission; And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Markarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from JNAC to JOTANA GGS I.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect- are	Acre	Centi- are
Modipura	182	0	26	04
	179	0	09	48
	177	0	09	12

[No. O—12016/65/85-ONGD4]

का. आ. 2394—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एम. एन. ए. जी. से एम. एन. ए. आई. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वाचक अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज वाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) को धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी बताना करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किमा विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एम् एन ए सड, से एम् एन ए आई, त्रु पाइप लाइन विधान के नियम ।

राज्य—गुजरात जिला व तालुका—मेहसाणा

गांव	सं न	हेक्टेअर	ए.आर.ई	वैदीअर
1	2	3	4	5
संथाल	448	0	17	70
	468	0	04	80
	469	0	13	80
	470	0	04	90

[स. O-12016/64/85-भा एन जी-ई-4]

पी क राजगोपालन, डेस्क अधिकारी

S O 2394 —Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest for the transport of petroleum from SNAZ to SNAI in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in schedule annexed hereto,

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission Construction & Maintenance Division Mak upura Road Vadodara (390009)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline from SNAZ to SNAI

State Gujarat District & Taluka Mehsana

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Santhal	448	0	17	70
	468	0	04	80
	469	0	13	80
	470	0	04	90

[No O—12016/64/85-ONG D 4]

P K RAJAGOPALAN, Desk Officer

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, 18 मई, 1985

का आ 2195—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए मन्त्र बंदरगाह विनिर्माणपूर्व सर्वेक्षण (ज्येष्ठ प्राथिक अन्वेषक) शर्ती नियम, 1983 का समाधान करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटीय मत्स्यन ईजीनियरी कन्द्रीय संस्थान (ज्येष्ठ प्राथिक अन्वेषक) शर्ती (समाधान) नियम, 1985 है।

(2) ये रजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे।

2 मत्स्य बंदरगाह विनिर्माणपूर्व सर्वेक्षण (ज्येष्ठ प्राथिक अन्वेषक) शर्ती नियम, 1983 की अनुसूची में, स्तम्भ 13 में निम्नलिखित प्रविष्टि को कोटि किया जाएगा, अर्थात्—

“5 संभव्य भूधनस्य कार्यालय का समुचित स्तर का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अधिकारी या ऐसा कोई जो उसी स्थान पर स्थित किसी दूसरे कार्यालय में कार्य कर रहा है—सदस्य”

[सं. 11-6/80-एफ आई (म)]

एस. बालकृष्णन, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

(Department of Agriculture & Coops)

New Delhi, the 18th May, 1985

S O 2395 —In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Pre-Investment Survey of Fishing Harbour (Senior Economic Investigator) Recruitment Rules 1983, namely —

1 (1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Senior Economic Investigator) Recruitment (Amendment) Rules, 1985

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Schedule to the Pre Investment Survey of Fishing Harbour (Senior Economic Investigator) Recruitment Rules, 1983, in column 13, the following entry shall be omitted namely —

Scheduled Caste Scheduled Tribe Officer of the appropriate Rank either belonging to the Attached/Subordinate Officer concerned or such an officer working in another office situated locally — Member”

[No 11-6/80-Fy(Admn)]

S BAI AKRISHNAN, Under Secy

संस्कृति विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, 18 मई, 1985

(पुरातत्व)

का आ 2196—प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और भवनोप नियमावली, 1959 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम् बी खन्, निदेशक (स्मारक) एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि तत्काल से उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा स्थित संरक्षित स्मारक जिसे ताजमहल के रूप में जाना जाता है, के मकबरे का भीतरी कक्ष पुरातत्व अधिकारी, उसके प्रतिनिधियों अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारी अथवा स्मारक में ह्यूटी पर तैनात किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को छोड़कर अगले आदेशों तक सुचारु रूप से बंद किसी व्यक्ति के लिए नहीं खोला जाएगा।

[सं 2/10/85-स्मारक]

ए. आ. खन् (ए. आ. खन्)

DEPARTMENT OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)
New Delhi, the 18th May, 1985
(ARCHAEOLOGY)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 मई, 1985

S.O. 2396.—In exercise of powers conferred by Rule 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, I, M. D. Khare, Director (Monuments) do hereby direct that with immediate effect the inner chamber of the mausoleum of the protected monument known as Taj Mahal located at Agra, Uttar Pradesh State shall not be open after sun-set to any person other than Archaeological Officer, his agents, subordinates and work men or any other Government Servant on duty at the monument until further orders.

[No. 2/10/85-M]
M. D. KHARE, Director (Monuments)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मई, 1985

का. आ. 2397 केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (सब के शासकाय प्रयाजना के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, फिल्म प्रभाग के शाखा कार्यालय, लखनऊ, का, जिसके कर्मचारी वृन्द न हिंदी का कार्यमाध्यम ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधि सूचित करता है।

[संख्या ई. 11011/35/83-हिंदी]
मुनि लाइ, उप निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
New Delhi, the 14th May, 1985

S.O. 2397.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Branch Office, Lucknow of Film Division, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. E. 11011/35/83-Hindi]
MUNI LAI, Dy. Director (O.L.)

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 15 मई, 1985

का. आ. 2398—स्थायी आदेश संख्या, 627, दिनांक 8 मार्च, 1980 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने कालाशेरि/माट्टोल/मुक्कोतुथारा टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-6-85 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-9/85-पी एच बी]
अजयम सिंह, सहायक महानिदेशक (पी.एच.बी.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(P&T Board)

New Delhi, the 15th May, 1985

S.O. 2398.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1980, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 1-6-1985 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Mattol/Kolasseri/Mukkoottuthara Telephone Exchanges Kerala Circle.

[No. 59/85-PHB]
B. R. SING, Asstt. Director General (PHB)

का.आ. 2399.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, पेन्च एरिया के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजका और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, बम्बई के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 8-5-1985 का प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR
New Delhi, the 16th May, 1985

S.O. 2399.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Pench Area, and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th May, 1985.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM LABOUR COURT NO. 2, BOMBAY
(CAMP AT JABALPUR)

Reference CGIT-2(12) of 1985 (Bombay)

Reference CGIT/LC(R) of 1983 Jabalpur

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Pench Area, P.O. Parasia, District Chhindwara and their workmen represented through the M.P. Rashtriya Koyala Khadan Mazdoor Sangh (INTUC) P.O. & District Chhindwara (M.P.)

APPEARANCES :

For Union—Shri S. K. Rao, Advocate.

For Management—Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Coal. DISTRICT : Chhindwara (M.P.)

AWARD

Dated, 19th March 1985

By their Order No. L-22011/5782-D.III(B) dated 1st July, 1983 [transferred vide Order No. S-11025 (I)/85-D.IV(B) dated 8th February] the Central Government has referred the following dispute for adjudication under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

“Whether the action of the management of WCL, Pench Area in relation to their G. M. Office in not regularising Shri Santosh Kumar as Water Mazdoor and paying him less than Cat. I wages as per recommendation of the Central Coal Wage Board followed by NCWI & II justified? If not, to what relief the workman is entitled for?”

2. The very nature of the dispute indicates that it centres round the question whether Shri Santosh Kumar was a contractor supplying the water on contract basis or was an employee in the regular service of the Western Coalfields Limited Parasia, District Chhindwara.

3. By their statement of claim the Union who is espousing the cause of the workman contends that the supply of water from the well was not on contractual basis but as an employee of the management of the industry.

4. Against this by their written statement the relationship is as already indicated has been denied and it stated that it is a job which requires hardly one and a half hours or two hours and therefore not a full time job.

5. To substantiate this contention the workman has examined himself where he has stated the facts that he has received no appointment order. In the absence of any appointment order and in the absence of payment as salary it would be difficult to hold the relationship established particularly when even at the time when Union intervened it merely resulted in the augmentation of the charges from Rs. 3.50 and Rs. 2/- to Rs. 4.40 and Rs. 2.50 P. respectively. It is, therefore, not possible to accept the plea of the workman or the Union.

6. This should normally dispose of the case, but having regard to the history as narrated by the workman and considering that consistently he is doing the work for the office since 1975, it is felt that it would be inhuman on the part of the management to continue the present arrangement and that it is not expected of a prudent employer like a Corporate Sector. Whatever may be the past there, the management should consider the appointment of the workman as a water supplier. By what designation he is employed is immaterial since the work is a noted work viz., supplying of water. There is a dispute as to whether the workman is working as a part time or full time. But if he is to be employed then the management is very likely to expect his services of regular hours, i.e. 8 hours for which the payment would be made as per the various award. In that case the workman cannot insist upon working as part time only since he is to get the benefit of full wages. I hope that the management pays heed to these observations and removes injustice which is being caused to the workman concerned. Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
[No. L-22011/57/82-D.III(B)|D.V]

Date : 19-3-1985.

का.अ. 2400 — औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्तर्गत में, केन्द्रीय सरकार में, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के उमरेर प्रोजेक्ट उमरेर, नागपुर के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोक्ता और उनके कर्मचारियों के बीच अन्तर्वेध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम नं. 2, 1947 के धारा 17 के अन्तर्गत में, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) के अन्तर्गत में, केन्द्रीय सरकार को 9.5.85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2400.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Umrer Project, Umrer of M/s. W.C. Ltd., Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th May, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande

Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/9 of 1985

Jabalpur No. CGIT/LC(R)(15) of 1983

PARTIES

Employers in relation to the Management of Umrer Project, Nagpur

AND

Their Workmen

APPEARANCES

For the Employers—Shri Rajendra Menon, Advocate

For the Workmen—Shri S. K. Rao, Advocate

INDUSTRY—Coal Mines STATE—M.P.

Bombay, dated the 10th April, 1985

AWARD

By their order No. L-22011/13/82-DIII(B) dated 11-5-1983 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, which was subsequently transferred to this Tribunal under Order No. S-11025 (1)/85-D.IV(B) dated 8-2-1985 :—

“Whether the action of the management of Umrer Project W.C. Ltd. Umrer not to treat Smt. Tewaribai, Smt. Rambai, Smt. Tanabai, Smt. Rajula Bai and Smt. Gangubai, Clay Cartridge makers at Umrer Colliery as their workmen is justified? If not, to what relief the workmen are entitled and from what date”.

2. The contention of the workmen who themselves are agitating the present dispute by their statement of claim is that they are working as Clay Cartridge makers since 1975 at Umrer Colliery, who were being paid Rs. 8/- per thousand of Clay Cartridges size 1 1/2" dia and 6" long for use of stemming material for short firing work. It is the contention of these workmen that although they are entitled to wages of Category No. 1 as defined and designated in N.W.A.I

for clay cartridgemarkers, the management is not paying accordingly and also not treating them their employees and hence the dispute.

3. By their written statement the W.C.Ltd are disputing the claim, they dispute the relationship of employer and employee between the parties and state that these ladies are in fact independent contractors who are being paid Rs. 10/- per thousand clay cartridges.

4. There are rejoinders on record where the same contention but made in details are advanced. On behalf of the employees it is contended that the work of these workmen is being supervised once or twice a week, that they work in Tinshed especially made for them, which shed is situated just above the pit-mouth, that the material is supplied by the management and this way it is alleged that there exists the relationship of employer-employee.

5. On the strength of these pleadings the following issues arise for determination and my findings thereon are :—

Issues	Findings
1. Whether the workmen stated namely Smt. Tewaribai and others were independent contractors or whether in service of the employer ?	In the service of the employer.
2. If they are working as independent contractors on contract basis have they any right to claim service rights ?	Does not arise.
3. If not, are they entitled to any relief?	They are entitled to relief.
4. What Award ?	As per order.

REASONS

6. Although the management has produced on record voluminous material to show that tenders are being invited and that only the contract is given to these workmen, certain facts are evident which ultimately would swing the balance one way or other. The oral evidence of the workman consists of statements of Smt. Rambai, Smt. Tewaribai, Smt. Rajula Bai, Smt. Tara Bai, Smt. Gangu Bai, and Rageshwar Mahadure from which evidence it is clear that the workmen are carrying out the work in the Tin-shed provided by the management, they are also supplied with raw material and that there is supervision. It is further evident that atleast since last 8 to 9 years the very ladies are performing the job. Not only that but the witnesses complain that they are required to do sundry jobs like taking the explosives, bringing the drinking water, cleaning the office, and lamm room and carrying earth from one place to another and loading them.

7. Against this evidence there are statements of Superintendent Manager Umrer Colliery and Asstt. Colliary Manager who have supported the stand of the management that the work is being performed by the female workmen on contract basis. The work is such that require minimum supervision but the fact remains that the right to reject the goods rested with the management.

8. Here is therefore a case where the management has supplied a shed in the mining area near the mouth of the pitch, has supplied raw material and engaged these workmen atleast for the last 8 to 9 years. In the light of this can it be said that these are not the employees of the Western Coalfields Ltd. In this connection In Silver Jubilee Tailoring House case reported in 1973 (II) LLJ, page 495 it has been held by the Supreme Court that during the last two decades the emphasis in the field has shifted and no longer rests so strongly upon the question of control. It is also held that it is wrong to say that in every case it is decisive. It is further held that the degree of supervision and control would be different in different types of business and that it an ultimate authority over the worker in the performance of his work resided in the employer than he was subject to latter's direction and that would be sufficient.

9. The workmen have also brought on record copy of arbitration Award where similarly placed Mud Pallet Makers were held to be employees of the company. This arbitration award is dated 31-3-1983 where the direction was that all such workers engaged by the management should be taken on company's rolls and be paid wages of category of piece rated workers with all the incidental benefits. In workmen of Food Corporation of India Vs Food Corporation of India in Civil Appeal No. 1055(NL) of 1981 when intermediary contractor was removed, and there was direct relationship between the workmen on one hand and the management on the other, the workmen were held to be workmen/employees on piece rated basis. In Special Leave Petition 1853 of 1978 the test to be applied in such cases was laid down and it was laid down by the Supreme Court that where a worker or group of workers labour to produce goods or services and these goods or services are for the business of another, that other is, in fact, the employer and he has economic control over the workers' subsistence, skill and continued employment.

10. The only effect of the arrangement would be that though the workmen are held to be in the employment of Western Coalfields Ltd., their employment is on piece rate basis a category even recognised in the Award All India Industrial Tribunal (Colliery Disputes) Vol II at page 75, category No. 29. These Clay Cartridge Makers are to be put in category No. 1 for whom wages are fixed. Since they are to be treated as piece rated neither daily rated nor monthly rated the management will have to fix daily quota in such a manner that within a span of eight hours they can complete the work and earn the wages fixed for Category 1 employees. Untill now the arrangement as was in vogue from the beginning but from the date of award the workmen shall be entitled to wages of category No. 1 employees under the award stated with all other benefits as the employees of the Colliery Award accordingly.

M A DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-2201/113/82 D III(B) D V]

का. आ. 2401.—औद्योगिक विधान अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 1 के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार को वेस्टर्न कोयल्फील्ड लिमिटेड, पेंसिल्वेनिया के प्रबंधन से सम्बन्धित नियोजकों और उनसे

कर्मकारों के बीच अनुव्यय में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 बम्बई के पंचाट का प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8.5.1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2401.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Pench Area, and their workmen which was received by the Central Government on the 8th May, 1985.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 2, BOMBAY (MAHARASHTRA) (CAMP AT JABALPUR)

Reference No. CGIT-2(11) of 1985 (Bombay)
Reference No. CGIT/LC(R) (26) 1983 (Jabalpur)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Pench Area, P.O. Parasfa, Distt. Chhindwara (M.P.) and their workmen represented through the Chhindwara Zila Koyala Khan Karamchari Sangh, P.O. Parasfa, District Chhindwara (M.P.).

APPEARANCES :

For Union—Shri S. S. Sharma.

For Management—Shri S. M. Singh.

INDUSTRY :

Coal—

DISTRICT :

Chhindwara (MP)

AWARD

Dated : 19-3-1985

By their Order No. L-22011(5)/82-D.III(B) Dated 1st July, 1983 (transferred vide Order No. S-11025 (1)/85-D.IV(B) Dated 8th February, 1985) following dispute has been referred by the Central Government for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act :—

“Whether the action of the management of Western Coalfields Limited, in relation to their Rawanwara Khan Colliery in not accepting the recommendations of the Distt. Medical Board Chhindwara and declaring Shri Paremdas, Compounder unfit for service and not regularising Shri Nazrul Hussan as Traffic Incharge and paying his difference of wages from 1-1-1981 is justified? If not, to what relief the workmen are entitled for?”

2. The Union who was espousing the cause of these two workmen viz., S/Shri Hazrul Hussan and Prem Das Compounder by the statement of claim has contended in the case of first named that he was working as a raising and loading mate initially when by an

order dated 1-1-1981 passed by the Manager, Rawanwara Khas Colliery Nazrul Hussan was appointed and authorised to work as Traffic Incharge and was made responsible for duties like setting the shifts, movement of tubs, and standard of loading etc. It is alleged that though from the said date onwards he continued to work as Traffic Incharge, he was not paid his wages of the said post namely as a workman Grade II, and it is therefore prayed that legal relief be granted and all the arrears including the annual increments etc. be ordered to be paid.

Regarding Prem Das Compounder the version of the Union is that he who was a permanent employee, was suffering from serious type of diseases and was completely disabled to perform his natural duties and therefore was sent to Barkui hospital for medical examination. It is contended that the Medical Officer demanded a sum of Rs. 1500 to declare him unfit, which amount was refused to be paid and, therefore, he was not declared unfit. The matter was, therefore, taken to the Collector, Chhindwara, who is a Director of Western Coalfields as a nominee of the M.P. Government, at whose instance the matter was referred to the District Medical Board with the Civil Surgeon of the Government Hospital as the Chairman of the Board which Board examined the workman and declared Prem Das unfit for normal duties. Despite these declarations the management refused to accept the certificate of the Board and declined to declare him unfit or to the appointment of his son in his place, as per the provisions in N.C.W.A. II. It is, therefore, prayed that the workman be declared unfit and suitable reliefs be awarded.

4. The contentions are opposed by the management by their written statement whereby the right of Chhindwara Zila Koyala Khan Karamchari Sangh, Parasfa to represent the cause of the workmen is itself being challenged on the ground that this Union has no membership in the Colliery and that individual workmen are not the members and therefore they have no right to espouse the cause. As to the facts the contentions of the management is that Nazrul Hussan acted as a Traffic Incharge only for 17 days and that thereafter he continued to work as a load mate and therefore disentitled to claim the wages of the post of Traffic Incharge.

5. Regarding the second workman the plea of the management is that when once the Medical Officer of the Barkui Hospital found the workman to be medically fit, the said certificate is binding on the workman and the management, and therefore the Civil Surgeon's Certificate was not acceptable to the employers. It, however, seems that on 28-3-1983 the workman was again referred to Barkui Hospital who declared him to be unfit and therefore in his place his dependent is absorbed in service.

6. There are also rejoinders on record reiterating the respective contentions, therefore requiring no further reference.

7. On the strength of these pleadings following

issues arise for determination and my findings thereon are as under :—

Issues	Findings
1. (a) Whether the Union espousing the cause of the workman has substantial following in the industry ?	Not proved
(b) If not, whether the present dispute becomes an industrial dispute ?	No
(c) If not, are the workmen or the Union entitled to any relief ?	No (Had the first two points gone in favour of Union, Nazrul Hussan would have been entitled to the relief as prayed for like payment of difference of wages from 1-1-1981)

Reasons :—

8. Since the right of the Union to espouse the cause of these workmen so as to convert the individual dispute into an industrial dispute was challenged, it was necessary for the Union to establish that they have substantial following in the industry and further that a decision was taken either by resolution or by other means supporting the espousal. In this regard mere sponsoring of dispute by the Union is not enough but it becomes necessary to enquire whether the Union which has sponsored the dispute can fairly claim a representative character in such a way that there would be a conversion of individual dispute into an industrial one. For the purpose of representative character, it can be gathered from the strength of the actual number of workers sponsoring the dispute and that the fact that the dispute is supported by the workmen or co-members will have to be established either in the form of resolution of the Union or of the workmen themselves who are supporting the same.

9. If we turn to the record for determining these factors, what the Union has done is that they have produced their registers of members for the years 1981-82 and 1983. It, however, seems that these registers do not bear the signatures of any of the members for having acknowledged the payment of membership fee. Absence of these signatures or thumb impressions therefore has attracted the criticism that these registers are fake one prepared for the purpose of record only and that they do not display the correct picture. The Union should have produced some authentic record whereby the proof of membership could have been accepted like verification by the competent authority which proof is lacking in the matter.

10. Not only that but there is absolutely nothing to indicate that the members, presuming them to be so had supported the cause of these workmen either by resolution or otherwise and therefore in the absence of vital proof on this material points, it is not possible to conclude that the dispute which is in the nature of individual dispute assumes the character of an industrial one.

11. But assuming that it is an industrial dispute still the question would be whether the facts as contended have been established. In the case of Nazrul Hussan the case of the Union is that he was appointed to work as a Traffic Incharge on 1-1-1981 and that since the said date he is continuously working in the said capacity. In this regard when examined Nazrul Hussan states that he was appointed as a Traffic Incharge in the vacancy of Hira Singh who was appointed as a Clerk and that one Suraj Narayan was posted in the vacancy of Bharatari Singh. It seems the case of the management is that when Hira Singh was promoted two persons were appointed on trial basis viz. Nazrul Hussan and Suraj Narayan and that Suraj Narayan was confirmed as Traffic Incharge but not Nazrul Hussan. In the cross-examination the witness admits that Bharatari Singh was a leading Superintendent working from previous to 1978 which post is a promotion post of Traffic Incharge and he wants to suggest that nobody was working in place of the said Bharatari Singh. When there were two vacancies namely one of Hira Singh who was admittedly promoted in the month of January 1981 and also a vacancy of Bharatari Singh, it is impossible to believe that in one vacancy there would be two postings and therefore the plea of the management and the witness V. K. Virthav on their behalf can never be accepted and the only conclusion possible is that in place of these two workmen viz. Hira Singh and Bharatari Singh there were two postings. Had the management's case been really true in the order itself dated 1-1-1981 we would have noticed the names of two incumbents but we find the name of Nazrul Hussan and not that of Suraj Narayan. Why the letter of appointment is worded accordingly is not at all explained.

12. In his evidence Nazrul Hussan says that he was continuously working, thereafter in his capacity as Traffic Incharge but was never paid the higher wages. This fact is disputed by the management. Now had the workman really worked for 17 days only as tried to be contended there would have been no occasion for Nazrul Hussan to submit applications dated 7-12-1981, 4-3-1983 and 2-2-1982 demanding the wages of the post of Traffic Incharge. Further more had the contention of the management that he worked for hardly 17 days and thereafter was repatriated to the original post, been really true, we would have immediately noticed the reaction of the superiors in the shape of rejection of these applications forthwith. On the application dated 7-12-1981 there is an endorsement "Please discuss" and there is also endorsement "Please check and report". What was the result of checking and discussion is not known. Second application bears no endorsement and might be because it was a copy of the original submitted to the management and the original remained with them. Third one bears an endorsement of "for comments". Now even assuming that these two applications namely first and third were returned back otherwise they would not have borne the endorsement of the colliery officers, still it does not mean that they were rejected. Some such reaction was essential and also its proof which is totally absent. Then as a leading mate there was no need for the workman to work in three shifts but it would have been restricted to his own shift only. The case of the workman

in this regard is that in all four Traffic Incharge were working at the relevant time, three were attached to the individual shifts while the fourth one Nazrul Hussan was looking after all the three shifts which he continued to do till 25-2-1983 when by a letter of even date this arrangement was ordered to be discontinued. Having regard to the letter of appointment, having regard to the vacancies/postings and having regard to the absence of the reaction which normally be there had the plea of the Union to be false. I am not prepared to accept the plea of the management and I am convinced that the workman just have worked as a Traffic Incharge from 1-1-1981 to 25-2-1983 at least. I cannot believe the statement in this regard by the management's witnesses. There is a corroboration to this conclusion from the report dated 2nd January 1979 of the Regional Labour Commissioner who has observed that the workmen are employed and assigned jobs of even higher categories and therefore he has referred to a decision take to regularise the post when a workman works in higher category for more than 190/240 days. Unless there was a practice of paying at the lower rate but extracting work in the higher category we would not have found a reference to the practice in the Labour Commissioner's Report. Concluding therefore I hold that the plea of the workman is established and had the dispute been held to be an industrial dispute the suitable relief could have been granted which, however, is not possible because of the adverse finding on the relevant issue.

13. In the case of the second workman the Medical Officer had declared Prem Das to be fit and in the absence of any circular or regulation making the decision of the Civil Surgeon binding on the management, merely because the Board differed from the decision of the Medical Officer, it cannot be said to be a malafide decision nor can it be said to be wrongly ignored. The record speaks that ultimately when Prem Das's case was again referred to the Medical Board he was declared unfit on 23-8-1983 and as per the rules his dependent was given employment in the industry. As the records stand there is nothing to hold that the first decision was malafide or that the action of the management in taking cognizance of the said decision to be wrong and therefore no relief is possible. Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.

[No. L-22011/5[82-D.III(B)]D.V]

नई दिल्ली, 17 मई 1985

का. आ. 2402.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार में, मैजरी कोल फील्ड लिमिटेड, केन्य मैजरी कोयलरी सब एरिया नं० 1 के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निहित औद्योगिक अधिव्यवस्था नं० 2 यम्बई के पंचाट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-5-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 17th May, 1985

S.O. 2402.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New Majri Colliery of Sub-area No.

1 of M/s. Western Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th May, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/31 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Coalfields Limited.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri Rajendra Menon Advocate.

For the workmen.—Shri S. R. Pendra, General Secretary, Lalzenda Coal Mines Mazdoor Union.

INDUSTRY : Coal Mines. STATE : Maharashtra. Bombay, the 12th April, 1985

AWARD

The following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, vide order No. L-22012(37)/84-D.V dated 14-2-1985, the conciliation proceedings having failed :—

‘Whether the action of the management of New Majri Colliery of Sub-Area No. 1, of WCL in terminating the services of Shri Mandala Kishya Mallaya Loader with effect from 23-3-1981 is justified? If not to what relief the workman is entitled to?’

2. The Union who is espousing the cause of the workman by the claim statement contends that Shri Mandala Kishya Mallaya the workman concerned was removed from service without holding any enquiry and without giving any notice, which rendered the termination void.

3. The management pleads that the workman was a underground Loader who was in the habit of remaining absent without leave and without permission and therefore he was charge-sheeted on 23-2-1980, whereafter a departmental enquiry was held in which the misconduct namely habitual absenteeism was proved. The workman by the letter dated 16-6-1980 admitted the mistake, sought opportunity of further chance giving an undertaking that in case he remained absent without leave in future his services may be straightaway terminated and therefore by letter dated 20-6-1980 he was permitted to join duty with a warning. It is complained that even thereafter the workman continued to remain absent without leave, that even in the entire year 1980 he worked only for eight days, in the year 1981 he did not work even for a day and therefore there was no option left but to terminate his services by order dated 18/23-3-1981. The management admits that 1.0

enquiry was held and sought permission to establish the misconduct before the Tribunal at the same time expressed apprehension even if the workman is reinstated he would not leave his habit of remaining absent.

4. Since no enquiry was held though according to the management the absence without leave amounts to misconduct, their request for opportunity to prove the misconduct was given and the evidence has been adduced in the matter.

5. In view of this development the following issues arise for determination and my findings are :—

Issues	Findings
(1) Whether the management prove the misconduct as alleged?	Yes
(2) If yes, is the order of termination justified?	Yes
(3) What Award?	As per award.

REASONS

6. Attendance Clerk Shri A. K. Naxne speaks of the absence of the workman from 4th July onwards till the time his services were terminated by order dated 18/23-3-1981, a fact further corroborated by Shri W. M. Kamgar a Clerk in the employment of the management. He says that in the month of July, 1980 because of less number of attendance no house rent was paid to the workman. Against this there is the statement of the workman who says that because he was sick, suffering from swelling of both ankles he could not attend the work but barring this oral testimony there is nothing to support the same. Here is a workman who in the past escaped the penalty because of his undertaking whereby he had agreed not to remain absent at any time and further agreed that in case he so remained absent he may be removed from service, but shortly thereafter for one reason or other indulged in the same misconduct despite the warning dated 19/20-6-1980 at the time of reinstatement and remained away from work from July, 1980 to March, 1981. Had he been really sick suffering from any ailment the workman certainly would have approached the Colliery Medical Officer and would have obtained a medical certificate on production of which the absence would have been easily explained. Why the workman failed to do so is not at all explained.

7. Had the direction been bad or illegal we would have immediately noticed the re-action but such re-action is conspicuously absent. There was no protest and on 26-10-1983 the workmen merely asked for payment of gratuity 10 months CDS etc. It seems that he was agreeable to the order of termination which amounted to dismissal and it might be after the arrival of the Union on the scene that we notice change in the stand. Whatever may be the reason one fact is certain that the workman remained continuously absent for latter part of 1980 and beginning of 1981, failed to explain the absence despite the previous undertaking and the history and although the dismissal is held to be severe punishment, such workman who does not work but constantly remained absent can never be foisted on the management

and the termination on account of misconduct in this particular case is held to be justified and legal.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.
[No. L-22012/37/84-D.V.]

का.आ. 2403.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 11) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, चुगुस कोलियरी (आर.आई.एच.बी.आई.) के वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के प्रबंधन में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबध्द में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, बम्बई का पचास को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8.5.1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2403.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chugus Colliery (RI & BI) of Western Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th May, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/30 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of
Chugus Colliery (RI & BI) of WCL.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the employers.—Shri Rajendra Menon, Advocate.

For the workmen.—Shri S. R. Pendre, General Secretary, Lalenda Coal Mines Mazdoor Union.

INDUSTRY : Coal Mines. STATE : Maharashtra.
Bombay, dated 11th April, 1985

AWARD

By their order No. L-22012(18)/84-D.III(B)/D.-V, dated 9-1-1985 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act on receipt of the failure of conciliation report from the Conciliation Officer:—

“Whether the action in demoting the workman, Shri Devendra Gopal Chatti, from the post of Trammer-cum-Loader to Badli workman with effect from 10-11-1983 taken by the Manager, Chugus Colliery (RI & BI), M.S. WCL., P.O. Chugus, District Chandrapur, is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?”

2. The contention of the Union who is espousing the cause of the workman is that the workman who was in the service of the Colliery from 9-4-1976 in the month of July, 1983 had proceeded on 10 days' leave and had returned to his village where he fell sick and therefore on return from his village he submitted medical certificate of the Doctor under whose treatment then he was. However, he was not allowed to work and subsequently by a letter dated 24-10-1983 a notice to show-cause was issued which was replied by him on 25-10-1983 but since the management was not satisfied with the said reply by order dated 19/20-11-1983 he was converted into a Badli workman. The grievance of the Union is that this action of the management is illegal as the action is taken without holding any enquiry therefore the workman is entitled to various reliefs.

3. The facts are not much in dispute but the contention of the management is that the action taken was in pursuance of clause 7F of the Standing Orders applicable to the establishment whereby when the workman remained absent beyond the period of leave he shall lose his lien on his appointment unless he returns within ten days of the expiry of his leave and explains to the satisfaction of the Manager, his inability to return in time. The standing order also speaks of the result namely on losing of lien on the appointment, the workman shall be entitled to be kept on the Badli list. It is alleged that the management could have chargesheeted the workman and taken disciplinary action for his absence particularly in the light of his habitual absenteeism but despite repeated absenteeism, a sympathetic attitude was taken and the action of converting his service into that of Badli was taken. It is further stated that although the order dated 20-11-1983 speaks of demotion in fact, it is stated, it does not amount to any demotion but the workman is performing the same duties.

4. The issues which arise for determination and my findings thereon are :—

Issues	Findings
(i) Whether the action of the management amounts to retrenchment?	Yes
(ii) If yes is it legal and justified	No
(iii) If not to what relief the workman is entitled ?	As per the order.

REASONS

As already stated the facts are not much in dispute. The records show that because the workman remained absent after he proceeded on leave from 6-10-1983. On 24-10-1983 a notice to show cause was issued which was replied on 25-10-1983 and ultimately order dated 19/20-11-1983 was passed converting the services into that of Badli. The order says that "keeping in view all the above, you are hereby kept on Badli for a period upto your satisfactory improvement in attendance i.e. completion of 190 days of attendance. This demotion is done as per the provisions of our certified standing order." Now when the workman was in the service from 1976 which fact is not denied. We had a

right to continue in the service and the effect of conversion into Badli service is that he will be appointed in case anybody is absent and if the post is vacant. In other words the guarantee of service is affected. For the said purpose reliance is placed on the Standing Order but as held in Naresh Chandra Das case reported in 1982 (II) LLJ, page 64 such automatic termination amounts to retrenchment and the management must follow the provisions of Section 25F of the Act. On page 70 it is held that even if the termination is effected not by any voluntary action on the part of the employer such termination also becomes retrenchment within the meaning of S. 2(oo). In view of the decision of the Calcutta High Court and similarly decision of the Andhra Pradesh High Court in Mohd. Abdul Khader case reported in 1984 LAB. I. C. 90, the order passed by the management is nothing but termination of permanent service although it is followed by an officer of Badli service, and since it amounts to retrenchment, the procedure under Section 25F of the Act must be followed which having not been done the termination is void and illegal and the workman is entitled to relief of reinstatement to his original post with all back wage less what is paid. In case during his subsequent service that is from 20-11-1983 the workman was found to be absent without leave he will not be entitled to wages for those days. This however, would not govern the days when because there was no vacancy on a particular day or days the workman could not be provided with work and on such days the workman shall be deemed to be on duty and all the back wages shall be payable.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.
[No. L-22012/18/84-D.III(B)/D.V.]

का.आ. 2404.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार में वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, पेन्च एरिया के प्रबंधन में सम्बद्ध नियोक्ता और उनके कर्मचारों के बीच अनुवध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 बम्बई के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8.5.1985 का पान हुआ था।

S.O. 2404—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Pench Area, and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th May, 1985.

**BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT NO. 2, BOMBAY
(CAMP AT JABALPUR)**

Reference No. CGIT-2(21) of 1985 (Bombay)
Reference No. CGIT/LC(R)(49) 1983 (Jabalpur)
PARTIES :

Employers in relation to the management of
Western Coalfields Limited, Pench Area,
District Chhindwara (M.P.) and their
workmen represented through the Chhind-
wara Zila Koyla Khan Karamchari Sangh,
P.O. Parasia, Chhindwara (M.P.).

APPEARANCES :

For Union,—Shri S. S. Sharma.

For Management,—Shri P. S. Nair, Advocate
and Shri Rajendra Menon, Advocate.

INDUSTRY : Coal. DISTRICT : Chhindwara (M.P.)

AWARD

Dated : March 19, 1985.

By their Order No. L-22011/88/82-D. III(B) dated 23rd August, 1983 (transferred vide Order No. S-11025(1)/85-D.IV(B) dated 8th February, 1985) following dispute has been referred by the Central Government for adjudication under Section 10(1)(d) of I.D. Act, 1947 on receipt of the failure report from the Labour Commissioner :—

“Whether the action of the management of WCL Pench Area in relation to their C. M. Stores in discharging the following 15 workmen in 1977 without giving any notice or compensation in lieu thereof is justified? If not, to what relief the workmen are entitled to?”

1. Shri Chatar Lal.
2. Shri Shiv Prasad.
3. Shri Man Singh.
4. Shri Somarlal.
5. Shri Gondu.
6. Shri Hari Prasad.
7. Shri Sarman.
8. Shri Basant.
9. Shri Rama.
10. Shri Ramdin.
11. Shri Bhaiyalal.
12. Shri Jhaonlal.
13. Shri Komal Prasad.
14. Shri Dhondou.
15. Shri Bhola.

2. The whole dispute centres round the question whether the 15 workmen named in the Schedule in fact were in service of the Western Coalfields Limited in Pench Area as averred by the workmen. The contention of the Union who has espoused the cause of these workmen is that these mazdoors were permanently employed by the management sometime in 1974-75 on the job of Timber loading in Western Coalfields Limited Trucks and then unloading the same in the collieries of W.C. Ltd., Pench Area

Parasia, on piece rate basis of Rs. 36 per truck per trip in a group of six persons. It is alleged that although these mazdoors are placed in Cat. I as per N.C.W.A. II and as such entitled to receive the wages of the said category, they were paid at the piece rate of Rs. 36 per truck per trip, as a result their earnings fell far below Rs. 6 per day and therefore they received much less than the minimum wage fixed for the concerned category. It is alleged that in this way they have worked from 1974 to December 1977 but sometime from 1st January 1978 when the work of transporting of timber was entrusted to the contractors, the services of these workmen were terminated without any notice or payment of compensation, in violation of the provisions of Section 25 of the I.D. Act. The said termination therefore is alleged to be illegal and the prayer is that these workmen should be reinstated in service without continuity, they should be paid full back wages from 1-1-1978, they should be paid the balance of wages for the period from 1974 to 1977 and such other relief as may be awarded.

3. The management by their written statement contest, the locus standi of the Union to raise the dispute on behalf of these individual workmen on the allegation that the said Union had neither any membership nor they have got any substantial backing and therefore cannot convert the individual dispute into an industrial one. The management further denies the relationship of employer and employee between the parties and their version is that these workmen were never in their service but in the service of the contractors and therefore there was no question of W.C. Ltd. terminating their services or paying any compensation in lieu of termination.

4. On the above pleadings, the following issues arise for determination :—

Issues	Findings
1. Whether the action of the management of W.C. Ltd. Pench Area in relation to their C.M. Stores in discharging the 15 workmen whose names are given in the Schedule in 1977 without giving any notice or compensation in lieu thereof is justified?	It is not proved to be the action of the management.
2. If not, relief and costs.	As per award.

REASONS

5. An objection has been raised that because the Union who had espoused the cause does not command substantial backing, any dispute raised by them cannot alter the nature of individual dispute into an industrial dispute. However, since the matter relates to the termination of service, normally if other factors are established, the proceeding would be governed by Section 2A of the Industrial Disputes Act, and when this is appreciated, the espousal by the Union may not be necessary nor other factors which are relevant while deciding the dispute not governed by Section 2A of the Act.

6. The espousal is by the aggrieved workmen themselves is evident from the three witnesses whose names are appearing in the list of employees facing termination. It is therefore, evident that the case cannot suffer any defect on this count.

7. But even finding that there is no difficulty from this corner and that espousal is legitimate one, still there is another hurdle in the path of the Union or the workman concerned before they can seek the relevant relief. The main question still remains whether the 15 workmen were in the employment of the management. For the said purpose there is the evidence of S/Shri Chatarlal Yadav, Shiv Prasad and Man Singh who have come forward to state that these workmen were the employees of the Western Coalfields Limited. They are also supported by Shri Sheo Murat Yadav a Driver in the service of the Western Coalfields Ltd., Colliery. Now the peculiar feature of this evidence is that admittedly before 1975 and subsequent to 1977 the work of transport of timber from the forest to the Colliery was entrusted to the contractors and it was never departmentally done by the Colliery. The question, therefore, remains as to what happened during the relevant years viz. 1974 to 1977 which required change in the mode of arrangement and there is no answer to that. Witnesses admitted that there were no fixed hours of work, that their attendance was not being marked, that they were not required to obtain any leave when they did not want to attend, that they were never treated by the Colliery Doctor and that no receipts were obtained for the payment made to them. Shri Chatarlal Yadav, however, further corrected when he stated that this thumb impressions were being taken on vouchers but no such voucher has been called from the management. Shiv Prasad stated that the employment in Western Coalfields Ltd. is through the Employment Exchange but no proof has been adduced to show that their names were sponsored by the said organisation. He made that when they absented nobody ever questioned about their absence and that during the period from 1975 to 1977, they had no occasion to meet any officer of the Colliery. The third witness namely Man Singh in the beginning stated that in the year 1975 he worked on Thekedari Trucks i.e. truck of contractor and corrected when he stated that such practice was before 1975. He is not in a position to state to whom the trucks belong and his assumption to this effect is because some employees of W.C. Ltd., were accompanying the truck. It was really necessary to prove the ownership of these trucks without which no conclusion one way or the other is possible. He then admits that even if absent without leave nobody was questioning or asking for examination and that even if the trip required more than two or three days no extra money was being paid. Absence of any record, absence of availability of normal facilities extended to the employees, absence of usual reconnection when somebody remained absent all go to indicate only one thing namely that these workers must not be in the employment of Western Coalfields Ltd., but in the employment of the contractors when whom they entered into the contract of payment of Rs. 36 per truck per trip, otherwise all these admissions cannot be explained.

8. Only one witness who is admittedly in the

employment of W. C. Ltd., has come forward to support the case of these workmen who says that he was working as a Driver but then reduced to the post of a Conductor. The statement of this witness, however, cannot be believed from his assertion that the contractors system prevailed after 1983 and that till 1973 to 1983 the work was done departmentally which statement is diagonally opposite to that of other witness. They admit that before 1974 and after 1977 the contract system was working. The witness namely Shri Sheo Murat Yadav speaks of the ownership of the truck of Western Coalfields Ltd. but in the cross-examination he admits that his assumption is based because the trucks were being unloaded at Rawanwarakhas. His version therefore in this regard cannot be accepted and the Union could have very well cited the record of R.T.O. to prove the colliery ownership which they failed to do. There is, therefore, no evidence that these trucks belonged to the management and not to the contractors. There is no proof that these workmen were engaged by the Colliery, there is no proof that they were in their service and when the very relationship of employer and employee stands not established, there is no question of any relief on the ground of wrongful termination. The termination if there be any must have been by the contractors with whom these workmen were working and therefore the relief can be claimed against them and not from the Western Coalfields Ltd. The result is that both the objections raised on behalf of the management prevailed. It seems that the workmen from the year 1980 started agitating and presented various applications but why they should remain quiet for three years when to their knowledge the termination had occurred at the end of the year 1977 has remained unexplained. I, therefore, hold that the action was not by the management though the order of reference presupposes the same.

9. When the action is not by the management, then the workmen were never in the service of the Western Coalfields Ltd. there cannot be any relief much less the relief of reinstatement, back wages etc.

10. Considering, therefore, the case from any point no relief is permissible. Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.

[No. L-22011/88/82-D.II(B)]D.V]

का. आ. 2405—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, खननार्ग कौमलरी 11, 12 इन्क्लाइन के स. वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, पेंच एरिया के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण न. 2, बम्बई के पंचाद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9.5.1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2405.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial No. 2, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rawanwara Colliery, 11, 12 Incline of Western Coalfields Limited, Pench Area and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th June, 1985.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY**

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande,
Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/14 of 1985 (Jabalpur No.
CGI/LC(R) (32) of 1983)

PARTIES

Employers in Relation to the Management of WCL,
Pench Area in relation to their Rawanwara Colliery

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri S. M. Singh, Dy. Chief
Personnel Manager,

2. Shri C. L. Jaiswal,
Sr. Personnel Officer.

For the Workmen—Shri S. S. Sharma,
President,

Chhindwara Zilla Koyala Khan Karmachari
Sangh.

STATE : M.P.

INDUSTRY : Coal Mines

Bombay, dated the 19th April, 1985

AWARD

By their order No. L-22011/9/82-D.III(B) dated 28-6-1983 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, on receipt of the failure of conciliation report from the Conciliation Officer. This reference was originally referred to the Central Govt. Industrial Tribunal at Jabalpur but subsequently transferred to this Tribunal vide Ministry's order No S-11025(1)/85-D.IV(B) dated 8-2-1985 :—

“Whether the action of the management of WCL, Pench Area in relation to the 11-12 incline of Rawanwara Colliery in not regularising Shri Munshi Shah tub loader as a Loading mate on the basis of more than 100 days attendances put by him on the job during the year 1980, with protection of Wages of Rs. 24.14 per day is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”

2. The grievance of the Union who is espousing the cause of the workman is that Munshi Shah who was permanently employed as a Tub Loader in No. 11/12 incline of Rawanwara Colliery was classified in the category of piece rated workers and was paid group VA wages minimum of Rs. 24.14 per day. It is alleged that the workman has completed primary education and can read and write Hindi and is capable of maintaining tub loading account and therefore he was selected as a loading mate with effect from January, 1980 as there was a shortage of educated loading mates in the colliery, but even on selection as loading mate the management continued to pay piece rated group V A wages of Rs. 24.14 per day

although for the new category which falls in Category IV the basic wages are Rs. 17.75 per day and it is a time rated job. It is alleged that this change from Tub Loader to Loading Mate was without the consent of the workman therefore violated section 9A of the Industrial Disputes Act. It is complained that on appointment as Loading mate where the workman worked for more than 190 days his pay should have been protected but here again the management declined to do so. It is alleged that similarly placed two workmen Shri Suraj Deo and Ballister appointed as Loading Mates were still being paid the earlier wages of Tub-Loaders though they are placed in Category V A. It is therefore urged that the workman be deposed as Loading Mate and his higher pay be protected.

3. The claim is being contested firstly on the ground that the Union concerned has no substantial standing in the colliery and they have no locus standi in the matter and therefore the dispute which is an individual dispute cannot be converted into an industrial dispute. It is then contended that Shri Munshi Shah was appointed as Loading Mate at this request on trial basis and at the time of regularisation when he was not prepared to accept the wages of the said post, he preferred to go back to the original category. It is stated that the management is prepared to regularise the workman as Loading Mate provided he accepts the wages of the post.

4. The fact that the Union has no locus standi is contested by the Union in their rejoinder, so also the contention that the change was done at the request of the workman.

5. By their rejoinder the management has reiterated the earlier stand and further stated that the cases of Suraj Deo and Ballister were totally different on facts and circumstances.

6. On these pleadings the following issues were framed by my learned predecessor for determination. My findings thereon are:—

Issues	Findings
1. Whether the action of the management of W.C.L. Pench Area in relation to 11-12 incline of Rawanwara Colliery in not regularising Shri Munshi Shah tub loader as Loading Mate, on the basis of more than 100 days attendances put by him on the job during the year 1980, with protection of wages of Rs. 24.14 per day is justified?	The action is unjustified but dispute being not an industrial dispute the reference fails
2. If not, relief and costs?	Does not arise.

REASONS

7. The main question in this case is whether the dispute which is in the nature of individual dispute has been converted into an industrial dispute. For the said purpose it is the contention of the Union that when the cause has been espoused by a trade union registered under the Trade Union Act, even though it is a minority Trade Union and not a recog-

used one, still the dispute would be an industrial dispute. Such trade union may not be recognised nor need it be a majority union. At the same time it is the duty of the Union to prove that it has got significant backing. For the said purpose besides the oral evidence of Shri Munshi Shah the Union has brought on record a register said to be the membership register of 1982 where the names of certain persons are shown. No thumb impressions or signatures are taken in the register and the management seriously challenges the veracity of the same. It is the case of the Management's witness that only two unions are functioning namely B.M.S. and INTUC who have got a membership of 670 each and that the total strength of the workers including the officers and staff is 1565. In view of this assertion therefore it was necessary for the union to adduce the proof of verification of membership by some authority having right to do so which the Union failed to do. Since the register does not bear any thumb impression or the signature, it is not known from the list prepared whether in fact the persons concerned are members of the Union and therefore since there is no proof that the Union has significant backing the espousal of the cause by such a Union cannot convert the dispute into an industrial one.

But had there been no hurdle on this count in my view the workman deserves the relief. He was in the service of the same Colliery although being a Tub Loader and when he was promoted to the post of Loading Mate, where he worked for more than 229 days as stated by the witness, whether there was promotion or no promotion it was the duty of the management to protect the wages. It was not a new appointment but on promotion of the workman working in the same Colliery. Consequently on promotion of the workman the management could not have asked him to accept something less than what he was getting though there was a change in the nature of rating. It is not that the workman was asking something which was not known to the company. On 6-2-1981 by office order the two workmen whose cases were similar namely Suraj Deo and Balister appear to have been paid the same wages as they were drawing as Tub Loader. Merely because the case was sponsored by another Union there could not have been any difference made and this is nothing but discrimination. An attempt was made to suggest that the cases of those two workmen were different but what is the difference is not at all made known. The witness of the management namely the Colliery Manager tried to state that the wages are protected when the vacancy of Loading Mate is temporary but when it becomes permanent the promotee gets the wages of the post and not his earlier wages. For the said purpose my attention was drawn to the notice dated 13-10-1980 but had this rule been strictly followed, the cases of Suraj Deo and Balister would not have been treated differently but this is not being done. The observance of the rules cannot be left to the fancy of the supervisory staff but if they want to follow they must follow in all similar cases.

9. It was tried to be suggested that Shri Munshi Shah does not possess knowledge of Hindi but had this been really true he would not have been allowed to work even for a day but the record speaks that he continued in the post of Loading Mate for more

than 200 days which itself would negative the plea of the management.

10. The result however is that had the dispute been an industrial dispute the workmen in my view would have got the relief which he failed to do so because of invalidity of the reference.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.

[No. L-22011/9182-D.II(B) D.V.]

A. V. S. SARMA, Desk Officer.

नई दिल्ली, 17 मई, 1985

का आ 2406.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में केंद्रीय सरकार सिंडिकेट बैंक के प्रबंधन में सम्बद्ध निष्ठाओं और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निष्ठाओं और औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण बंगलूर के पत्रों को प्रकाशित करती है, जो केंद्रीय सरकार का 8 5 95 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 17th May, 1985

S.O. 2406.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of Central Government Industrial Tribunal; Bangalore, as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the Syndicate Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th May, 1985.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN
KARNATAKA, BANGALORE

Dated this the 22nd day of April 1985

PRESENT :

Sri R. Ramakrishna, B.A., B.L., :— Presiding
Officer

Central Reference No. 3 of 1984.

I PARTY.

The General Secretary, Syndicate Bank Staff
Union, 5, Muran Sahib Street, Mount
Road, Madras-600002.

Vs.

I PARTY

The Chairman-cum-Managing Director, Syndi-
cate Bank Head Office, Manipal-576115.

APPEARANCES :

For the I Party :—Sri M.S.N. Rao, General
Secretary, Syndicate Bank Staff Union,
Madras.

For the II Party :—Sri S. Manohar, Autho-
rised Representative, Syndicate Bank,
Manipal.

REFERENCE

[Government Order No. L-12012 (51)/83-D.

II(A) dated Nov. 1983]

AWARD

The Central Government after forming an opinion that an industrial dispute exists between the above parties has referred this dispute for adjudication

under Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 on the following Schedule :-

THE SCHEDULE

Whether the action of the management of Syndicate Bank in relation to their Data Processing Department, Head Office, Manipal in withdrawing the payment of special allowance to Shri Ranga Poojari, Machine Operator, with effect from 5th June, 1981 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

2. Consequent to this reference this Tribunal has issued notices to both the parties and they have failed their claim statement, counter statement and rejoinder. Before adverting to the stands taken by the above parties in support of their actions it is necessary to advert to some of the undisputed facts in this dispute.

3. Sri Ranga Poojari, hereinafter referred to as workman, has joined the services of the II Party, hereinafter referred to as Bank, as a probationary clerk on 12-7-1969 and after about six months his post was confirmed and he has been asked to work as Punch Card Operator with effect from 1-3-1970 thereby allowing him to draw a special allowance of Rs. 23/- per month. The workman has continued to do the work entrusted to him until 27-5-81, as from that date he has been transferred to West Coast Zonal Office, Manipal and by a letter dated 4-6-81 he has been informed that the machine operator's duty entrusted to him was withdrawn with effect from 5-6-81. Before this transfer, the workman has been deputed to attend the training programme on unit record system from 11-6-79 at Madras. This special allowance which was started from Rs. 23/- per month was increased from time to time due to several bi-partite settlements and at the time of his transfer he was getting a sum of Rs. 249/- per month. Due to this transfer, the workman has suffered the monetary loss to this extent, hence this reference has been made to give adjudication on this point.

4. In the Claim Statement the workman has contended that after his selection he was posted to the Accounts Department (Data Processing) Department since he had acquired certain technical qualifications having under-gone IBM Card Punching Training Course, the punch card operator work was entrusted and in fact this selection was made taking into consideration his IBM qualifications. Hence he contended that he did not undergo any industrial training course which the Bank used to conduct at that time hence his appointment was made on the basis of his technical qualifications. He has further contended that he continued to discharge the duty of the machine operator for over 11 years and 3 months and also undergone training course and therefore his functions and duties with them had become an integral part and parcel of the service conditions and hence his transfer and withdrawing the entrustment as a machine operator and the non payment of the special allowance is not legally sustainable.

211 GI/85-16

5. He has further contended that the previous awards, namely; Sen Award and Sastri Tribunal Award were not recognised the special allowance for machine operator as at that time it was unknown in the banking industry hence on the direction of the Desai Award this case to be implemented. He has further contended that the Sastri Tribunal in dealing with transfer gave direction that an employee transferred from higher area to a lower area would continue to get the benefit of the higher scale even though he is transferred to a lower area might have resulted and some advantage in terms of cheaper living. The underlying reason was to protect the employee from victimisation under the guise of transfers. The protection of emoluments of a workman transferred from a higher area to a lower area acted as a check and dampener against the possible mis-use or abuse of power by the management of the Bank. The similar protective clauses have been built in the provisions of the Desai Award in the matter of special allowance payable to certain employees entrusted certain types of duties and responsible duties. He has further contended that in fixing the special allowance for the workmen operating accounting machines the Desai Tribunal took note of the demand that the special allowance fixed by the Tribunal should relate only to such period during which the workman was required to perform such duties which ceased to be payable when the employee ceased to perform the special duties for any reason. The special allowances were not intended to be paid for casual or occasional performance of such duties or discharge such functions whole time. clear and mandatory direction that it was not necessary that a person should continue to perform such duties or discharge such functions whole time. He has further contended that when a person can be asked to cease to do such work or cease to discharge such duties depend on the terms of his employment, and person who is employed permanently as a head clerk or stenographer cannot be deprived of such allowance at the sweet will and pleasures of the bank by asking him to work as an ordinary clerk and the Desai Tribunal gave further direction that a special allowance could continue to be drawn by a permanent incumbent while he is on leave also.

6. He has further contended that even though the order of appointment stated as a probationary clerk, it was not the nomenclature which really matters but on the other hand the duties of the employee was required to perform. The real nature of employment was attached to the accounting machine and the special allowance being a functional allowance it is directly related to the duties of a workman which become an integral part of the service conditions as he performed the duties for 11 years and 3 months and hence he is entitled to the same as a matter of customs, usage and practice.

7. He has further contended that the special allowances can be withdrawn if the workman refuse to perform the duties entailing the special allowance or he is requested to be relieved of such duties or as a consequent of disciplinary action and all the three things not being present in this case it is victimisation on the part of the management. He has

further contended that the Bi-partite Settlement dated 19-10-66 did not list out the duties and performance by the workman entitled to the special allowance and also depend upon the scope of temporary employment and he being a permanent employee should continue to draw the special allowance even if he is transferred to some other job. The bank awards and the settlement for the purpose of securing benefits to the bank employees which have stated beyond the shadow of doubt that a workman did not perform the duties attractive special allowance all the time are continued. The action of the management in transferring him was only an act of colourable exercise of power with a view to deprive him of the special allowance, hence the bank is bound to restore the special allowance retrospectively with effect from 5-6-81 together with all other attendant and consequential benefits. This withdrawal of special allowance amounts to a measure of punishment for misconduct which is not applicable in the case of this workman as he has not committed any misconduct.

8. He has further contended that the contract of employment as represented in the order of initial appointment does not refer to the contract of service throughout his service. The contract of employment gets modified through subsequent collective contracts and the sum total of all these which represents the contract of service. Thus the workman is entitled to the post of a permanent machine operator and he cannot be disturbed from that position and this withdrawal of special allowance amounts to a change in the conditions of service applicable to him and attracts the provisions of Section 94 of the Industrial Disputes Act.

9. He has prayed for an order directing the II Party to release the special allowance together with all attendant and consequential benefits with effect from 5-6-1981 with a further direction that the said special allowance shall continue to be paid to the workman with such modification as may be brought about in any subsequent collective contracts with costs of this petition.

10. The II Party after denying all the allegations made in the claim petition have initially contended that the reference made is not in accordance with law and does not constitute an industrial dispute and therefore liable to be rejected. They have further contended that the workman was appointed as a clerk and subsequently directed to perform the duties of punch card operator and was given special allowance in accordance with Bi-partite Settlement. It is further contended that the entrustment of said duty was only till further orders when the questions of paying emolument as having been applicable to the machine operator does not arise. The special allowance was continued as he has discharging the duties of machine operator and the fact that he had continued for more than 12 years does not clothe him with a right to claim the same even after he was relieved of the said additional duties of the machine operator. It is further contended that the circumstances under which the management cannot under the guise of transfer disallow the payment of special allowance is restricted to the categories, such as, head clerk, cashier, etc., and it is not appli-

cable to the entrustment of temporary nature and that to the category which is no enumerated such as machine operator, etc. It is further contended that if the contention of the workman is accepted it will be a great burden on the management hence the Bank will have to go on paying the special allowance to all the employees who have put in charge of the duties of machine operator temporarily or otherwise for a fixed period and subsequently who are transferred to other places which clearly show that the management will be obliged to pay the special allowance even for a person who is not actually working as a machine operator and the same cannot be the intention of any settlement or award. The special allowance being a functional allowance is directly related to the function of the duties is baseless and untenable. The said Ranga Poojari was appointed only as a clerk and the management have all the authority to transfer him to the said post which will in no way amounts to arbitrary, capricious and vindictive action on the part of the management. Sri Ranga Poojari was transferred from Accounts Department to Premises and Maintenance Department on 13-6-1981. Consequent to his transfer from Accounts Department, the duties of machine operator entrusted to him in terms of clause 5.2 and 5.11 of bipartite settlement was withdrawn. It is further contended that whether a workman can be asked to cease to do such work or discharge such duties and consequently ceased to draw such allowance will depend upon the terms of his employment and for instance a workman who is employed permanently as a head clerk or stenographer cannot be deprived of such special allowance by directing him to work as an ordinary clerk or asking him not to work as a Head Clerk or Stenographer which clearly shows that in other cases wherein the assigning of other duties was of a temporary nature, the bank has right of discontinue the payment of allowance if once an employee ceased to do the said work either by transfer or on account of posting some other person to do the said job.

11. It is further contended that the entrustment of the duties of machine operator to Ranga Poojari was made until further orders and it was also made known to him. His continued service for more than 11 years does not clothe him with any right to continue to receive the same allowance even after his transfer to his original appointment as a clerk even he is not doing the duty of a machine operator. The payment of allowance is in respect of the post concerned and the duties actually discharged and not attached to the person. Hence the allowance could be paid only to the person who is actually doing as a machine operator and hence there is no merits or claim made by the workman and the reference is liable to be rejected.

12. In view of the above pleadings, the following additional issues have been framed for consideration along with the points of disputes :—

- (1) Whether the II Party proves that performing the functions and duties of a Machine Operator is not an integral part and parcel of the service conditions of the service conditions of the I Party-workman?

- (2) Whether the II Party further proves that the work of the I Party workman was an entrustment of a temporary nature and hence he is not entitled to pay special allowance after his transfer ?
- (3) Whether the I Party proves that his work as a Machine Operator for 11 years and 3 months made the nature of his employment as a Machine Operator ?
- (4) Whether he further proves that depriving him of special allowance to do another job when the Data Processing Department continue in the Head Office amounts to victimisation and cannot be sustained ?
- (5) What order ?

13. FINDINGS :

- (2) Issue No. 2—No
- (1) Issue No. 1—No
- (3) Issue No. 3—Yes
- (4) Issue No. 4—Yes
- (5) Issue No. 5—As per final Award.

14. REASONS :—

Issues Nos. 1 to 4.—To prove the above issues the parties have placed both oral and documentary evidence. The II Party Bank have examined one Deputy Personnel Manager to show that the duties which have been performed by the I Party workman was only an entrustment with a right to the management to withdraw such entrustment when it is felt to do so thereby discontinuance of special allowance which was being paid all these years to the workman. Their main contention is payment/withdrawal of the special allowance mainly depends on the conditions of service in which a particular employee is appointed in the Bank.

15. The witness A. S. Kanak, the Deputy Personnel Manager has deposed that his functions are mainly relating to the Personnel Administration in respect of officers and employees working in Bombay, West Coast Zone and their Head Office. He has further deposed that Mr. Ranga Poojary was appointed as a probationary clerk in the year 1969 as per Exts. M-1 and M-2 is a condition of appointment order. It is his further evidence that Ranga Poojary was not appointed as a specialist and a specialist means any person requiring to perform and possessing technical skill, such as, punch operator, stenographer, etc. For the appointment of the specialist some norms have been prescribed, such as conducting the test etc., and such norms had not been applied in the selection of Mr. Ranga Poojary. He has further deposed that if not specialist is available to do the technical job, a clerk will be assigned to do the work and he will be paid special allowance and such procedure does not conform to such workman to claim that he is specialist and thereby to make a claim that he cannot be transferred to other department. This special allowance will be withdrawn when a particular person ceased to do the job in view of entrusting him other type of job and special allowance was withdrawn in view of the change of the nature of work. He has further deposed that there are instances where persons worked in technical work drawing special allowance being transferred to other departments withdrawing the special allow-

ance and there are instances that such transfers were made even in case of persons working upto 7 years and drawing special allowance in technical work. Sri Ranga Poojary is not entitled to claim that he is specialist hence he should not be transferred to other departments where special allowance facilities are not available.

16. It is elicited in the cross-examination that at the time of his transfer there are 4 to 5 persons working as punch card operators and Mr. Ranga Poojary may not be the junior most out of that 4 to 5 persons. At the time of transfer of Ranga Poojary the other punching card operators have not been transferred from that place and the Ranga Poojary has been entrusted to work from 1-3-70 and he has also been sent to have the training at Madras. It is further elicited that the transfers from special duties to other departments were made sometimes on request and sometimes due to exigencies of work. Mr. Ranga Poojary worked about 12 years as a punch card operator drawing special allowance and no notice was issued before his transfer order as it does not amount to alteration of service. He has further stated that according to them the punch card operator's work was temporarily entrusted which was withdrawn and the special allowance in case of stenographers, drivers cannot be withdrawn when they have been entrusted to do the duties other than what they were performing as they have been appointed or entrusted on fulfilment of qualifying norms. It is further elicited that there was no complaint against Ranga Poojary with regard to work and his behaviour, and he has denied that as vindictive attitude Mr. Ranga Poojary was transferred. He has further deposed that since Ranga Poojary was appointed as a clerk and as per the terms and conditions of appointment he was liable for transfer to any other department and the work of machine operator was only an entrustment and he has denied the suggestion to accommodate somebody to have the benefit of special allowance when Mr. Ranga Poojary was transferred to a section where special allowance is not available.

17. Against this evidence Mr. Ranga Poojary deposed that he joined the Bank as a probationary clerk on 16-7-69 which was confirmed after 6 months and soon after he has been asked to do the work as punch card operator and at the time of his appointment officials of the Bank conducted the test of a machine operator then appointed him. Before joining he has undergone training in IBM and obtained a certificate and he has worked as a punch card operator and machine operator without any break, from 1970 upto June 1981 and he has undergone training at Madras having sent by the Bank.

18. He has further deposed that he has been transferred from the post of machine operator to the post of a clerk from June 1981 due to which he has been deprived of a sum of Rs. 152/- per month which he was getting as a machine operator and at present the special allowance is enhanced from Rs. 249/- per month. He has further deposed that since he was not knowing the reasons for his transfer from the post of machine operator, he asked for a reason and no sufficient reason was given and he is not in a position to understand the reasons for his transfer as he was doing his duties efficiently. Due to his transfer he sustained a monetary loss of special allowance which he was

continuously getting for a period of 11 years and hence he raised a dispute through the union.

19. It is elicited in the cross-examination that prior to joining the work he has not worked as punch card operator in any place and he has not applied specifically for the post of machine operator. He has further stated that the Bank has conducted a test in the machine operation then he has been appointed as a clerk and he does not remember having received a letter Ext.M-7 intimating that he has not succeeded in the test of machine operator.

20. Ext. M-1 is an appointment order dated 12-7-69 appointing Mr. Ranga Poojary as a probationary clerk as per the terms and conditions Ext. M-2. Ext. M-2 contains several conditions and for the purpose of this case Condition No. 7 is relevant, according to which the Bank is liable to transfer the candidate from one department or office of the Bank to another. Ext. M-3 is an order dated 25-2-70 addressed to Mr. Ranga Poojary requiring him to perform duties of punch card operator with effect from 1-3-70 and to draw a special allowance of Rs. 23/- per month and the duties are in addition to any other duties that may be entrusted to him. Ext. M-4 dated 27-5-81 is a transfer order to West Coast Zone Office, Manipal, to work there until further orders. Ext. M-5 is a letter addressed to the workman dated 4-6-81 intimating him that the machine operator's duty entrusted to him is withdrawn with effect from 5-6-81. Ext. M-6 is a letter dated 8-2-82 calling upon Ranga Poojary to attend Refresher Course for experienced clerks at Staff Training College, Udupi from 18-2-82 to 3-3-82. Ext. M-7 is a letter addressed to Ranga Poojary dated 12-6-69 informing him that they are unable to consider his application dated 7-4-69 favourably after a test conducted at the head office, Manipal.

21. On the material available on record, the learned authorised representative for Mr. Ranga Poojary has submitted that the II Party have failed to justify the action taken by them in transferring Ranga Poojary, thereby depriving the monthly benefit the workman was getting for a period of 135 months and under the guise of transfer they cannot deprive the monthly benefit and though the work was entrusted the workman has acquired a right to continue to get the special allowance in view of his long service he has put in as a punch card operator and he has also acquired a special knowledge and undergone training in that particular branch hence the management are not justified in depriving such a benefit in the guise of a transfer to a place where there is no scope for the workman to perform the special skill acquired by him which was entitled for drawing a special allowance throughout. The learned representative has further submitted the term used until further orders applies in case of the nature of work which was given on a rotation basis, such as cashier and it is not applicable in case of Mr. Ranga Poojary. The learned representative further submitted that transfer and withdrawal of special allowance is violative of Section 9A of the Industrial Disputes Act and no notice has been served on him when the management wanted to effect a change in the work which resulted in deprivation of drawing special allowance every month which form part of the wages of Mr. Ranga

Poojary. He has further submitted that this act of the management amounts to unfair labour practice and further it is evident that there was no allegation against Ranga Poojary about any misconduct or inefficiency and the transfer depriving him the special allowance is a colourable exercise on the part of the management and though his juniors have been retained to continue their work as machine operator, it is a clear case of deprivation of special allowance when they have transferred Ranga Poojary to a department where there is no Data Processing Unit.

22. Against this submission, the learned representative for the II Party Bank has submitted that the manner of employment and the conditions of service is the chief criteria that has to be taken into consideration by this Tribunal to decide the points at issue and Ranga Poojary has having appointed as a probationary clerk cannot claim it is a right to a duty entrusted to him which is meant for specialist groups to claim special allowance. The learned representative further submitted that it is the right of the management to transfer its employees to any other branch depending upon the exigencies of work and if any interference is made to their discretion it will become difficult for the Bank to perform their duties and hence the reference is liable to be rejected on this score alone. He has further submitted that the cases of stenographers, drivers and machine operators directly appointed to that posts cannot be equated to the case of Ranga Poojary as it is a clear case of entrustment and subsequent withdrawal depending upon the exigencies of work of the Bank. The learned representative has filed a written arguments reiterating the stand taken by them in their statements filed in this dispute.

23. On a perusal of the document it can be seen that Mr. Ranga Poojary was appointed as a probationary clerk and his services are confirmed within 6 months and immediately afterwards he has been asked to perform the duties of punch card operator with effect from 1-3-70 allowing him to draw special allowance from that date. It was specifically stated in that latter that these duties are in addition to any other duty that may be entrusted to him. It is also in evidence that Mr. Ranga Poojary had acquired a special knowledge having undergone training in IBM and obtained a certificate before his appointment as a probationary clerk which has not been disputed by the II Party. It is also not in dispute that at the time of this entrustment Mr. Ranga Poojary was working in Data Processing Department which is evident in Ext. M-3 in the address of Ranga Poojary. The II Party have not placed any material that immediately after the appointment of Ranga Poojary under Ext. M-1 until completion of the probationary period what type of work was entrusted to him. Looking at these backgrounds it is quite evident and crystal clear that though Mr. Ranga Poojary was appointed as a clerk, the clerical duties are not entrusted to him and on the contrary he has been working in the Data Processing Department during his probationary period. Hence the contention of the Bank that his service conditions are governed by the appointment order Ext. M-1 will not strictly be applicable in view of entrustment of a duty other than clerical duty given to Ranga Poojary from the date of his joining the service. With

regard to the power of management to transfer its employees from one place to another and from the department to another department depending upon the exigencies of work and allotment of work this Tribunal cannot interfere with their power to transfer but it should be distinctly understood that there should not be any scope in reduction of their emoluments due to their transfer. In the case of Mr. Ranga Poojary there is unequivocal evidence to show that the workman was doing his duty efficiently all these years and his transfer is not due to abolition of a post in which he was working and it is admitted by the witness for the Bank that his juniors have been allowed to continue the work that was entrusted to them as machine operators and it is a clear case of unfair labour practice committed by the Bank.

24. But if we peruse the history of the various settlements and awards passed from time to time the special allowance is adopted in the Desai Award which was reconsidered in Bipartite Settlement arrived on 19-10-1976. Chapter V deals with the categories of workmen who are entitled for special allowances.

25. The learned representative for the II Party drew the attention of this Tribunal to para 5.9 of the Bipartite Settlement and submitted that the workman being entrusted to do a specialised job which entitled for special allowance the management is at liberty to withdraw the special allowance when the workman has ceased to do the works specified in Appendix in the said settlement. For proper depreciation para 5.9 reads as follows :—

5.9 A workman will be entitled to a special allowance only so long as he is incharge of such work or the performance of such duties which attract such allowance. Whether a workman can be asked to cease to do such work or discharge such duties and consequently cease to draw such allowance, will depend upon the terms of his employment. For instance a workman who is employed permanently as a Head Clerk or Stenographer cannot be deprived of him special allowance by asking him to work as an ordinary clerk or asking him not to work as a Head Clerk or stenographer. It, however, a recipient of a special allowance wants to give up the work or duties which entitle him to the special allowance, he shall if his request is granted, cease to draw the special allowance.

26. On a plain reading of the above, a workman can be asked to do such duties which attract special allowance will depend upon the terms of his employment. However, a Head Clerk or Stenographer who has been employed permanently cannot be deprived of his special allowance by asking him to work as an ordinary clerk or not to work as a Head Clerk or Stenographer. The cession of withdrawal is mainly depended upon the terms of the employment. Admittedly, Mr. Ranga Poojary has been appointed as a clerk as per Ext. M-1 enjoining to do the duties of a clerk as per the conditions of service Ext. M-2. Obviously, this leads to draw a conclusion

that Mr. Ranga Poojary was not appointed as a specialist to do the work as a punch card operator. But the facts and circumstances of this case will fall on a different footing as it is not the case of the management that a specialist was not available thereby they entrusted this special work to Mr. Ranga Poojary. The nature of work entrusted to him itself show that he had a specialised qualification to do the work of a punch card operator when he has been asked to do the said work though he has not been appointed in that category. The evidence of the workman shows that before his appointment he has undergone training in IBM which fact is corroborated by Ext. M-7 when the management has not selected him for specialist post. But he had specialised qualification when he was entrusted with this specialised duty hence the terms of his employment should be governed to the conditions prescribed for specialist group and not for the ordinary group. Added to this, the workman has did this specialist duty without any interruption for a period of 135 months wherein he was enjoying the special allowance as part of his wages and the management, under equity, was not justified in depriving the said special allowance under the guise of terms of employment.

27. The Bipartite Settlement para 5.6 prescribes that the special allowance is payable for additional duties and functions requiring greater skill or responsibility which constitute the normal part of the duties and functions and the special allowance are not intended to be paid for casual or occasional performance or discharge of such duties/functions. This makes it clear that if a person continuously discharge a specialist work requiring a greater skill the special allowance should not be withdrawn.

28. The learned representative for the I Party nextly submitted that there is violation of Section 9A of the Industrial Disputes Act by the management as the transfer of Mr. Ranga Poojary to a place withdrawing the special allowance and preventing him from doing the specialist work amounts to a change in the conditions of service which affected the wages of the workman and hence this transfer as contravened the above section and not legally sustainable. Against this submission, the learned representative for the II Party has submitted that Mr. Ranga Poojary has been transferred in a normal atmosphere in accordance with his terms of employment hence there is absolutely no violatice of Section 9 A of the Act. Section 9A reads as follows :—

9-A. Notice of change.—No employer, who proposes to effect any change in the conditions of service applicable to any workman in respect of any matter specified in the Fourth Schedule, shall effect such change :

(a) Without giving to the workmen likely to be affected by such change a notice in the prescribed manner of the change proposed to be effected ; or

(b) within twenty-one days of giving such notice.

29. It is undisputed that Mr. Ranga Poojary has worked as a specialist due to an entrustment as a punch card operator for a period of 135 months and this transfer to work as an ordinary clerk in view of

the service rendered by him as a punch card operator amounts to change in the conditions of service as it is obviously deprived him the special allowance which he was drawing for such a length of period. It is also in evidence that there are 4 to 5 punch card operators who are junior to him and they have not been transferred to do any clerical jobs or there is evidence that they have been appointed as specialist to work in that category. Though MW-1 has stated in his evidence that they have withdrawn this special allowance in case of employees who have put up in that category, he has not substantiated the same by giving the names and other particulars of such category of employees who have been deprived of the special allowance after such a long period of service. At this juncture, it is pertinent to note a decision reported in 1962 II L.L.J. 136 (Tamilnad Electricity Workers' Federation vs. Madras State Electricity Board) wherein His Lordship Sri Veerawami J, as he then was, speaking about the scope of Section 9A sub-clause (a) held as follows :—

"It is clear from Clause (a) of Sec. 9A of the Act that the requirement of a notice to workmen would arise only if they are likely to be affected prejudicially. A change in the conditions of service contemplated by the section should be understood in that sense. It is intended to cover a case where the proposal is, for instance, to enhance the pay scales or to better the other terms by a unilateral decision of the employer. The whole object of the section is apparently to prevent a unilateral action on the part of the employer changing the conditions of the service to the prejudice of the workmen. Further when the change becomes only effective by the concerned workmen agreeing to the same or opting for the same, the provisions of S. 9A of the Act could not have any application. Any proposed alteration by an employer in the conditions of service which does not automatically come into effect after 21 days, does not fall within the ambit of S. 9A. What it prohibits is the unilateral action on the part of the employer changing the conditions of service affecting the workmen concerned."

In the instant case this change of conditions of service has prejudicially affected the workman. Hence there is a clear contravention of Section 9A of the Act by the management. Hence I hold the Issues Nos. 1 and 2 in the negative and Issues Nos. 3 and 4 in the affirmative.

30. In the result, the following award is passed:—

AWARD

The Management of Syndicate Bank are not justified in withdrawing the payment of special allowance to Sri Ranga Poojari, Machine Operator, with effect from 5th June 1981. It is directed that the management shall pay to Sri Ranga Poojari the special allowance and all other consequential benefits retrospectively from June 1981 and to continue to pay the same to him until such time he is entrusted with

duties carrying higher special allowance or until such time he is promoted to the next higher cadre. The Management is at liberty to transfer him within that area where there are facilities to do the specialised work to Sri Ranga Poojari. Parties shall bear their own costs.

(Directed to the Stenographer, transcribed and typed by him and corrected by me).

R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer
[No. L-12012/51/83-D.II(A)]

का ५१ २१०७ - औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) की धारा १७ के अनुसार में केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजन और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पत्राद का प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को ६-५-८५ को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2407.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th May, 1985.

BEFORE SHRI J. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I. D. 115 of 1981 (DELHI); 26 of 1983 (CHANDIGARH)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Bank of India

AND

Their Workman—K L. Jain

APPEARANCES :

For the Employers—S. Sh. D. D. Kapoor and S. B. Kapoor

For the Workman—Sh. Mangat Sharma.

ACTIVITY : Banking STATE : Haryana

AWARD

Dated the 1st of May, 1985

The Central Govt., Minister of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. L-12012/181/80 D.II.A dated the 10th of August, 1981 read with S.O. No. S-11025(2)/83, dated the 8th of June, 1983 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication : -

"Whether the action of the management of Central Bank of India in not treating Shri K. L. Jain, in service with effect from 6-3-69 for the purpose of total length of his service is justified? If not, to what re-

lief is the said workman concerned entitled?

2. Brief facts of the case according to the petitioner workman are that he joined service against a permanent vacancy, though as a temporary hand, under the Respd. Bank at their Karnal branch in the clerical cadre on 6-3-1969 and even though it was a fixed tenure appointment, he was allowed to continue from time to time upto 14-6-1969, it is besides the point that during the meanwhile the Management manipulated a fictitious break of 2 days i.e. 6th and 7th of May 1969. It was pleaded that on 14-6-1969 he was asked by the concerned Branch Manager, to proceed to Rohtak office for collection of his probation letter, and thus after obtaining the necessary orders from there he returned to his parent branch at Karnal and resumed duty on 20-6-69; obviously there after he continued serving the Respd. Bank on various assignments and was ultimately confirmed in due course of time.

3. The petitioner's grouse was that the Management had introduced some fictitious breaks in his service before he was placed on probation and in this manner they deprived him of claiming continuity of service from the initial date of recruitment i.e. 6th of March, 1969 which adversely effected his service prospects on the point of gaining increments, seniority and other attendant benefits. He, therefore, tried to impress upon them the desirability of treating him in service w.e.f. 6-3-69 for all intents and purposes. But his demand and entreaties fell on deaf ears despite the intervention of the ALC(C) during the Conciliation stage, hence the Reference.

4. Resisting the proceedings on all counts the Management pleaded that initial appointment of the petitioner was for a limited temporary tenure which came to an end with the afflux of time and there after he was casually engaged from time to time to meet the fluctuating work load.

Allegation of manipulating or introducing any fictitious service-breaks was vehemently denied. It was, however, admitted that he was placed on probation w.e.f. 20-6-69 and then confirmed against a permanent post in due course of time. In the same sequence they questioned the validity of the reference on the ground that the petitioner was neither a workman nor his cause properly espoused and that otherwise also his claim was quite stale.

5. The parties were taken to trial on the following issues frame over and above the terms of reference :—

- (i) Whether the petitioner workman has locus-standi to invoke the jurisdiction of this Tribunal? OPP.
- (ii) Whether the cause of the petitioner is not properly espoused? OPR.
- (iii) Whether the alleged delay has any bearing on the case of the petitioner, if so what? OPR

6. In support of their respective versions the parties adduced verbal as well as documentary evidence which I have carefully perused and heard them at length. My issue-wise discussion and findings are as follows :—

ISSUE NO. 1

7. On behalf of the Management it was argued that since, even on his own admission, the petitioner has now been promoted to the Officer Cadre w.e.f. 28-2-81, therefore, he was no longer a "workman" to seek adjudication of his alleged rights in the instant proceedings. I am not impressed with the effort to knock out the petitioner on the mere technicalities of law because at the crucial moment he was a workman as defined by the Section 2(s) of the Act i.e. when he joined service at the lowest level in the clerical cadre. And it hardly requires any repetition that the controversy revolves around the service tenure of the petitioner from 6-3-69 upto 19-6-69 when he was still placed as such; it is an entirely different matter that the determination of his vested rights at that stage may have some bearing on his future career. Hence, on sustaining the petitioner's "locus-standi" I answer the issue in his favour.

ISSUE NO. 2.

8. In all fairness to them the learned representatives of the Management did not seriously contest the proposition that regardless of the merits of the controversy involved, the petitioner's cause was espoused by a Regd and recognised Union of the Bank-employees on a point concerning his service conditions which could be adjudicated upon by the Tribunal. In view thereof I return the issue against them.

ISSUE NO. 3.

9. It was argued that the cause of action accrued to the petitioner in the year 1969 when the Management declined him the so called benefit of his temporary tenure, and hence the very fact of his sleeping over the issue for all this while should be indicative of his lack of enthusiasm to pursue a stale, if not altogether lost, cause.

10. The submission deserves summary rejection because it is neither based on facts nor is supported by any judicial precedent or specific provision of law. On the other hand a bare perusal of the parties' correspondence consisting of the letters Ex. M4, M7, M8, W4 and W5 would leave no manner of doubt that right from August 1970 the petitioner was agitating his view point for the inclusion of temporary tenure in regular service for all intents and purposes. I, therefore, answer the issue in his favour.

TERMS OF REFERENCE

11. For the proper appreciation of the point in issue it would be in the fitness of things to reproduce the relevant provisions of the Bipartite Settlement Agreement dated 23-12-71 relied upon by the petitioner. It goes without saying that it was his Magna Carta and as such the very foundation of the case. It is incorporated, in Part-II of the document Exb. M13 and reads as below :—

"TERMS OF AGREEMENT"

(1) The employees who have been appointed in the Bank's service originally on or after 1-7-1966 and were given break in the service not exceeding three days excluding Sundays and Bank Holidays, will be considered as having been confirmed on the permanent staff after six months from the date of

their original appointments. Such members of the clerical and sub-ordinate staff will also be entitled to contribute towards provident fund from the date of their confirmation as per this agreement, and the due dates of their graded increments will be adjusted accordingly. (Emphasis supplied)

(2) In the cases of such members of the clerical and sub-ordinate staff who were continued to be temporary beyond the period of six months prior to 1-7-1969 and not earlier than 1-1-1959 without any break will also be allowed to contribute towards provident fund, six months after the date of their original appointment and they would be treated as confirmed from the end date.

(3) It is also agreed that the cases of the employees who were taken on temporary basis prior to 1-7-1966 and not earlier than 1-1-1959 but continued to work against permanent vacancies for more than six months will also be confirmed in service, six months after the date of their original appointment and will be allowed to contribute towards provident fund as per para (2) above".

12. From our angle clause 2 and 3 of the aforesaid Agreement are irrelevant since it is only clause 1 which regulates the fate of the clerical staff joining service after 1st July, 1966, and surely the petitioner's initial appointment started w.e.f. 6-3-69. On behalf of the Management it was rightly pointed out that only such employees who had suffered service breaks only upto 3 days excluding Sunday and Bank holidays could claim the benefit of temporary tenure whereas in our case there was a total break of as many as 7 days before the acceptance of the regular appointment by the petitioner.

13. At this stage it may also be worthwhile to have a glance into some of the admitted facts and documents of the Case Exb. M3 relates to the initial appointment granted to the petitioner for a fixed tenure of one month from 6-3-1969 to 5-4-1969. It was accepted by him under his own endorsement followed by the formal order Exb. M2; then he was granted extension for one month per Order Exb. W2. After that there was no renewal of service for 2 days i.e. 6th and 7th of May, 1969 but on his prayer another tenure of one month was granted w.e.f. 8-5-69 per Order Exb. W3 M15; obviously this tenure ended on 7-6-69. There is yet another material document on record consisting of the petitioner's own letter Exb. M4 which contains the entire history of his service, it reveals that even though no formal orders were issued to him yet he continued working in the Bank upto 14-6-69 inclusive, and it was only on that day, that he was asked by the Local Branch Manager to go to their Rohtak Office for bringing his probation letter as meanwhile some permanent vacancy was found available. Accordingly, on 18-6-69 the petitioner went to Rohtak and brought the appointment Order Exb. M1. Its closing part would show that the petitioner was given an option to accept the vacancy on reporting for duty at Karnal on 20-6-69 and on his such acceptance the formal order Exb. M1A was transmitted to the Karnal Office.

14. From the above data it surely emerges that there was a continuous break of at least 5 clear days between the termination of the petitioner's temporary

assignment by afflux of time and absorption into regular cadre by way of probation; it is besides the point that there had been another break of two days at the time of renewal of the temporary assignments between 5th and 8th May, 1969. Thus, in all the petitioner had 7 days break in his temporary tenure and, as such, was beyond the protective umbrella of clause (1) of the above quoted Bipartite Settlement Agreement.

15. On his behalf it was argued that in two similar cases the Management had condoned 6 days break and allowed retrospective confirmation to Sh. Brij Mohan Gupta and T. P. Singh. Brij Mohan Gupta was examined before the Tribunal as a witness whereas the matter of T. P. Singh was high lighted with the production of Exb. W6 containing the minutes of the relevant Joint Discussion Meeting dated 8th/9th Sept. 1980.

16. In my considered opinion the effort to invoke the precedents of Brij Mohan Gupta and T. P. Singh is mis-conceived because the very opening part of the Minutes Exb. W6 clearly establishes that before suffering any break in his temporary tenure, T. P. Singh had put in a continuous service of more than six months at a stretch; and it was precisely for this reason that his precedent was applied to the case of Brij Mohan Gupta, who under the weight of cross-examination stated that he had continuously worked from 24-7-67 to 23-1-68 before going through a break upto 30-1-68. To put in plain words, both these gentlemen had, at one stage, put in a continuous service of six months and had thus become entitled for including their temporary service in their permanent tenure for all intents and purposes.

17. Against this back drop, I cannot possibly resist the conclusion that if an employee attains the minimum standard of eligibility on putting in the requisite service of six months uninterruptedly and is ultimately absorbed in the regular cadre even after suffering a bit larger break he can legitimately claim the benefit of the aforesaid agreement. Of course the intervening break has to be kept up within a reasonable proximity of time; say around a fortnight or so, but since our petitioner had not attained the requisite qualification, therefore, he could not complain of any impropriety, irregularity or illegality in the Management's action. Accordingly, I return my Award against him.

Chandigarh

Dated 1-5-1985.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-12012/181/80-TJJA]

का आ 2408—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वये में केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धसूत्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अन्तर्विध में निश्चित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के फोरम को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को ९-५-९५ पास हुआ था।

S.O. 2408.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in

the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th May, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL CUM LABOUR COURT
KANPUR

Industrial Dispute No. 21 of 1984

In the matter of dispute between

Shri Ashok, S/o Shri Baboo Lal, C/o Shri O. P.
Nigam, 295/387 Din Dayal Road, Lucknow.

AND

The District Manager, State Bank of India. Near
Stadium Hazrat Ganj, Lucknow.

Shri O. P. Nigam, representative—for the work-
man.

Shri Mahesh Chand—a representative for the
management.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide its order no. L-12012/277/83-D.II(a) dated 25th February, 1984, has referred the following dispute for adjudication :

“Whether the action of the management of State Bank of India in relation to their Chowk Branch, Lucknow, in terminating the services of Shri Ashok Kumar, Part time Sweeper with effect from 23-3-80 is justified ? If not to what relief is the workman concerned entitled ?”

It is common ground that the applicant was appointed in Chowk Branch in the bank management as part time sweeper in the month of February, 1976 and remained serving the bank upto 23-3-80. According to the workman he was working on permanent post of Part time Sweeper and was getting privilege as medical leave, uniform, bonus etc. The management called the workman as temporary part time sweeper against purely temporary/ad-hoc requirements. According to the management the workman left the services of the management of his own accord on 31-12-78 after settling his dues by way of full and final settlement. The management further averred that on 19-1-79 the workman again approached the management for fresh temporary appointment and the management keeping in view his past services reappointed him a fresh as temporary part time sweeper w.e.f. 19-1-79, and worked till 23-3-80 when his services were terminated as no longer required.

In the claim statement it is averred on behalf of the workman that in the year 1979 and January, 1980, the workman remained ill and submitted medical certificate but he was not paid any salary for the period nor leave was sanctioned in spite of the fact that he has put in more than 3 years service and was entitled to privilege of medical leave and that during his absence his wife was working at his place as his substitute but she was paid only 1/3 salary. That after the

termination of the service of the workman a new hand was appointed and made permanent. That the services of the workman were terminated without notice or retrenchment compensation. That no appointment or termination letter was issued to him. That no retrenchment compensation was paid to him.

The management on the other hand has averred that the past services and work of the workman concerned was unsatisfactory and he habitually absented himself unauthorisedly without prior permission and thereby causing dislocation in the work and has been wrongly marking in the attendance register. On 12-5-79, the workman gave an apology letter and again on 1-7-79 an apology letter was given to the management by the workman. It is further averred that on 22-3-80 a 10 rupee currency note of the bank while in the custody of Cashier accidentally slipped out and fell down in the banking hall. The branch manager circulated a notice that in case any of them have found the said currency note he may deposit the same with the branch manager. Sri Asok admittedly had got it but avoided to deposit the same with the branch manager. Individually a search was made of the workman in the presence of all staff members of the bank and the said currency note was recovered from the pocket of the workman. The workman admitted his guilt in presence of all the staff members which clearly established his mala fide intention and attempt to misappropriate the same. The workman ultimately admitted his guilt and returned the said currency note to the branch manager. All this goes great doubt about his integrity and the management lost confidence in him and in view of lost of confidence his services were terminated w.e.f. 23-3-80.

The management has filed an apology letter of the workman dated 12-5-79 wherein he admitted that he did not come for duty from 1-1-79 to 12-5-79 with breaks without information and without previous sanction of the leave which was unauthorised absence. In the month of January, 80 he again absented himself from 4, 8, 14, 15, 20, 21 and 23rd January to 31st January, 1980. He has expressed regret for the same and assured not to absent himself in future. There is another regret letter dt. 1-7-76 in which he regretted his behaviour with the members of the staff. The management has filed an office order issued by the branch manager on 22-3-80, mentioning that a 10/- rupee currency note had fallen somewhere in the banking hall and that whoso amongst the staff happens to get it may deposit it immediately with the branch manager. This office order was circulated and it is signed by the workman also. On the back of that office order there is an endorsement signed by several staff which reads to the effect that at about 12 in the noon workman was called in the cabin of the branch manager and was enquired if he got a ten rupee note in the bank premises on which the workman replied in negative and on being told by Mr. Gupta that the note was duly signed and its number was noted by me, the workman blurted and produced the ten rupee note stating that he committed a mistake. In this way the workman first denied having got note and later realising that he may get implicated admitted having got it and returned the same. It was on this that the branch manager issued him a memo that very day charging him that he did not deposit a ten rupee note which the workman found in the bank premises and when his pocket was searched the said

ten rupee note was recovered from his pocket. Before the members of the staff he admitted that he got it lying in the banking hall. This shows that he was not honest towards bank and in that connection he should submit his explanation to the branch manager by 5 p.m. failing which it will be deemed that he has nothing to say and that his temporary services would be deemed to be terminated after the close of the banking hours that day.

The workman has filed 4 documents which show total number of days of the work done by the workman in the bank. The workman has also filed his medical certificate dt. 10-8-79 and copy his original appointment application dt. 22-1-76 whereby he moved for appointment in the bank management. The workman summoned certain documents from the management. The management by way of affidavit of Shri V. C. Bajpai, the branch manager of Chowk Branch, replied that in spite of all best efforts the attendance register and leave record could not be traced out and they however produced two attendance registers from December 78 to March 79 and April 79 to July 79 and leave record register from 25-5-77 to 14-7-79. Regarding the termination letter they said that they have not filed the same.

The averments made above show that the management was itself satisfied with the past working of the workman and unauthorised absence of the workman lastly on the point of rupee ten note the management got suspicion and after preliminary enquiry given him a memo to be replied on that very day by 5 p.m. The memo is in the nature of charge and giving just few hours to reply the same would be unjust and mala fide if the management was satisfied about the misconduct of the workman in having misappropriated the ten rupee note a proper charge sheet should have been given to him and enquiry made examining all those persons before whom the recovery was made after service of general office order to produce the same and thus proved the mala fide of the workman and it was only proof of mistake that the services could have been terminated by way of punishment. The test of discharge simplicitor is;

“Whether the same is bona fide or mala fide”

All that transpired on that day when the note was lost and produced and memo given shows that the management was itself satisfied with the conduct of the workman. It is not disputed that the management has two powers of dispensing with the services of the workman (i) his termination after proof of mistake by way of punishment and (ii) his discharge simplicitor under para 522(i) of the Shastri Award i.e. termination of the services of the workman without any mala fide and colourable exercise of powers. It is true that it is not always necessary to resort disciplinary proceedings before terminating the services. In *Bombay Municipal versus P. S. Malvenkar* 1978 (1) LLJ page 168 it was observed by Supreme Court thus :

“The question whether any particular order terminating the services of the employee is by way of punishment or not has to be determined on the facts and circumstances of each case and the form of the order is not decisive of the matter. If services of a workman suspected or misconduct, misbehaviour, negligence or insubordination is allowed to prevail it would naturally result

in the order of termination if passed on the subjective satisfaction of the appropriate authority. The court can always examine whether discharge simplicitor would bona fide or not”.

In the *Air India Corporation Vs V. A. Rabailo* 1972(1) LLJ page 509, it was held :

“If the termination of the services is colourable exercise of the powers vested in the management or as result of victimization or unfair labour practices, the industrial tribunal would have jurisdiction to interfere and set aside the termination. In order to find out this the Tribunal has ample jurisdiction to go into all the circumstances which lead to the termination simplicitor.”

In the instant case the management was led away that the workman was habitually absenting himself without prior sanction or leave. His behaviour with the staff members was not proper and lastly the workman found ten rupee note on the floor of the banking hall which he kept in the pocket and after enquiry he returned the same. It has not come in evidence that the note belong to the bank. Even if it belong to the bank, there is no cogent proof that the recovery was made from his pocket in the manner stated by the management bank and not returned in the manner suggested by the workman. This could have been settled only after a proper enquiry. Further the workman was not one of the staff dealing with the customers or handling cash and it could not be said that keeping such an employee in the bank would not be in the interest of the bank dealing with cash transaction.

Under these circumstances, I am of the opinion, that the loss of confidence in the instant case was not bona fide on the part of the bank management but a colourable exercise of the powers and hence the discharge simplicitor can not be allowed to stand.

Further discharge simplicitor is also termination and sec. 25-B of the Industrial Dispute Act is attracted. Admittedly no notice or notice pay was given to the workman, the termination becomes illegal on that count also.

In view of the discussions made above, I consequently hold that the action of the management of State Bank Of India in relation to their Chowk Branch, Lucknow, in terminating the services of Shri Ashok Part time Sweeper w.e.f. 23-3-80 is not justified.

The result is that he will be reinstated with all back wages

I therefore, give my award accordingly. Let six copies of this award be sent to the Government for publication.

Date 1-5-85

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[N. L-12012/277/83-D.IIA]

का. आ. 2409—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14)
की धारा 17 के अन्तर्गत से केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद श्रेष्ठ के प्रबंधन
से सम्बन्धित निष्ठाओं और उनके कर्मचारियों के बीच अन्तर्गत से निविष्ट औद्योगिक
विवाद से केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, बम्बई, के
पंखा को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-5-85 प्राप्त
हुआ था ।

S.O. 2409.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Allahabad Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th May 1985.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 2, BOMBAY (M.S.)

(CAMP AT JABALPUR)

Reference No. CGIT-2/3 of 1985(Bombay)

REFERENCE NO. CGIT/LC(R)(13)/1985 JABALPUR

PARTIES :

Employers in relation to the management of Allahabad Bank, Raigarh and their workman represented through the M.P.B.E. Association, C/O Punjab National Bank, Raigarh (M.P.)

APPEARANCES :

For Union—Shri L. N. Mahotra, Advocate.

For Bank—Shri P. S. Nain, Advocate.

INDUSTRY : Banking DISTRICT : Raigarh (M.P.)

AWARD

Dated : March 20, 1985.

By their Order No. L-120/2(120)/82-D.II(A) dated 7-5-1983 (transferred vide Order No. S-11025 (1)/85-D.IV(B) Dated 8th February, 1985 the Central Government on receipt of the failure report from the Labour Commissioner has referred the following dispute for adjudication :—

“Whether the action of the management of Allahabad Bank in relation to their Raigarh Branch in terminating the services of Smt. Shaila, Part-time Sweepress with effect from 27-1-82, is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?”

2. As the dispute stands it has arisen because of the alleged illegal termination of the services of Smt. Shaila stating to be working as a part-time Sweepress with effect from 27-1-1982. The contention of the Union who has espoused the cause of the workman is that though a part-time workman she was required to work for more than six hours per week but was being paid at the rate of Rs. 25 per month only when in fact she was liable to be paid at the rate of 1st 3rd wages of the pay scale. It is alleged that when there was a demand in this connection the management did not respond but terminated her service on 27-1-1982 and though wages were paid from June, 1980 to December, 1981, the wages for the month of January, 1982 remained unpaid. The Union, therefore, challenges this termination and seeks various reliefs.

3. The management has opposed the claim firstly on the ground that the appointment of the workman

was not regular but done by the Branch Manager without authority and without getting her name cleared by the competent authority. It is further stated that the termination occurred because the workman refused to perform her normal duties like cleaning the latrines, bath room etc. and further there is an assurance that the management has no objection to take her back in service provided the workman gives an undertaking to abide by the terms of employment and perform all the duties.

4. The points which therefore arise for determination in this reference and my findings thereon are as under :—

Issues	Findings
1. What is the nature of work undertaken by the workman whether to clean the latrines, bath rooms and other duties assigned to the Sweeper or the work was only to clean furnitures, bank premises and utensils and to store water for drinking and other purposes?	To clean the latrines bath rooms and to other duties assigned to the sweepers.
2. Whether the appointment of the workman by the Manager without the authority or jurisdiction and without getting her name cleared by the competent authority, creates any infirmity in the relationship of employer and employee?	No
3. If the appointment by the Bank is for the purpose of cleaning the latrines and bath rooms etc. as contended by them, what is the effect of the refusal of the workman to perform those duties on her rights?	The workman shall have to perform those duties and give undertaking to do so.
4. Whether the workman, in that case, is entitled to seek reinstatement?	Yes, only on giving the undertaking.
5. If not, is she entitled to any other relief?	} As per award.
6. To what Award?	

REASONS

5. Although there is an accusation or indictment of non-performance of the duties, as the record stands the management did not hold any enquiry, neither there was a chargesheet nor any enquiry report and therefore the termination is nothing but the retrenchment in violation of Section 25F of the Industrial Disputes Act. There is also no proof before the Tribunal about the alleged misconduct. Now the immediate result of this finding would be that the termination is bad and the workman would be entitled to be reinstated.

6. Normally the norms would be the payment of full back wages but in this regard it seems that the workman herself was under the impression that she was to perform duties of a peon or Farrash, namely cleaning the Bank premises, utensils, furnitures etc. and in the rejoinder the Union has contended that the workman was never engaged to do the sweepers work nor was required to clean latrines, bath rooms etc. In view of the impression which the Union and the

workman are carrying therefore the payment of full compensation would not be possible and the only relief therefore would be that the termination being wrong and illegal the workman shall be entitled to reinstatement from the date when she assumes the duties or the charge. The workman during the period from termination till she assumes the charge would be entitled to 1/3rd of what she would have got had she continued in service. This order of reinstatement is being passed on account of the undertaking by the workman to perform all the duties of a sweeper. In case she is not willing to perform those duties and does not give an undertaking to that effect at the time of commencement of service on reinstatement the Bank would be absolved from their duty to reinstate her.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.
[No. L-12012(120)|82-D.II(A)]

का. धा. 2410:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रिय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रिय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करते हैं, जो केन्द्रिय सरकार को 9-5-85 का प्राप्त हुआ था।

S.O. 2410.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th May, 1985.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE (RETD.),
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR

COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT|LC(R)(10)|1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Raipur and their workmen, S|Shri Yamuna Kumar Yadav and Mohanlal Yadav.

APPEARANCES :

For workmen.—Shri D. P. Tiwari and Shri S. D. Phadke.

For management.—Shri G. C. Jain, Advocate.

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Raipur (M.P.)
AWARD

Date : April, 25, 1985

The Central Government in exercise of its power under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication vide Notification No. L-12012(117)|82-D.II (A), dated 8th April, 1983.

"Whether the action of the management of State Bank of India in relation to their Phaphadi"

Branch under Control of Chief Regional Manager, Raipur in terminating the services of S|Shri Yamuna Kumar Yadav and Mohanlal Yadav temporary, sub-staff is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?

2. The workman was temporarily employed in the State Bank of India. They had put in services in the Bank from time to time but have not been regularised nor made permanent. Hence the above dispute. During the pendency of the dispute the parties have come to aicable settlement which is filed before me. The Agreement is fair and just and I am of the opinion that the terms of the settlement would be in the better interest of the workman. I, therefore, give this award the terms of which have been agreed upon between the parties under a settlement.

ORDER :

(i) The employee workman shall forego all claims to back wages.

(ii) That the management will provide an opportunity to the workman to work in the Bank in the same capacity as he was before the termination of services. The Bank shall for giving the workman an opportunity for his permanent absorption in the Bank interview the employee and the appointment would be subject to their selection.

(iii) That the workman will be considered for permanent absorption in the Bank subject to their being found physically fit and having stood the test in the interview taken for the purpose. Their character, credentials and antecedents shall be verified as required for the Bank services and the absorption shall be subject to the reports in this regard. The Bank also agrees to give a chance to those temporary employees for absorption in the employment in the same capacity as have completed more than 90 days temporary services as a special gesture of goodwill provided such persons forego their claim for back wages during the period they have remained unemployed.

This closes the present dispute. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer.

[No. L-12012|117|85-D.II(A)]

का. धा. 2411:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रिय सरकार, बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रिय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करते हैं, जो केन्द्रिय सरकार को 8-5-85 प्राप्त हुआ था।

S.O. 2411.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th May, 1985.

**BEFORE SHRI B. D. SRIVASTAVA, PRESIDING
OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUS-
TRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
KANPUR**

Industrial Dispute No. 80/1981

In the matter of dispute between

Shri Virendra Kumar Agrawal, C/o. General
Secretary, Bank of India Staff Union,
C/o. Bank of India, LIC Building, The
Mall, Kanpur, ..Workman

AND

The Assistant General Manager, Bank of India,
Hazratganj, Lucknow, ..Management

AWARD

1. The Central Government Ministry of Labour vide its Order No. 12012/72-80-D-II-A dated 17th June, 1981 has referred the following dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of Bank of India, Regional Office Lucknow, in terminating the services of Shri Virendra Kumar Agarwal, Clerk of their Kasturba Marg Branch, Kanpur, with effect from 9-10-1979 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

2. It is common ground that the workman was initially appointed in the services of the management bank for a period of one month in January, 1974, after being selected in interview and which was held by the bank. According to the workman he was appointed on 30-1-1974, but according to the management he was appointed on 21-1-1974. Initially the appointment of Shri Agarwal was continued till 16-3-1974 and thereafter Shri Agrawal worked as temporary employee during the following period :

16-4-74 to 15-6-74.

19-6-74 to 27-7-74.

02-8-74 to 21-10-74 &

28-10-74 to 17-02-75 &

19-2-75 to 14-03-75.

The appointment of the workman which was purely on temporary basis was terminated on 15-3-1975. According to the workman though he was temporary clerk but he was engaged against the clear permanent vacancy of clerk. It is admitted that the appointment of temporary employees depends upon the exigency of the work in the bank and the workman was appointed as temporary because of the branch expansion programme. According to the management Shri Agrawal appeared in the written test but failed and as such was not called for interview for appointment in the clerical cadre in the bank. The workman raised industrial dispute in which a settlement was drawn on 3-6-1978 and in pursuance of the same the workman was reinstated on 5-6-1978. The workman thereafter worked for more than six months in a permanent vacancy when on 5-4-79 he was required by the Regional Manager to apply for the post advertised by BSRB (hereinafter called Banking

Service Recruitment Board). The workman again protest through union as appearing in the test of BSRB was not one of the condition in the agreement. The management has however disputed that the workman ever worked in a permanent vacancy. Further the management bank asked him to apply BSRB for being absorbed in regular permanent cadre. The workman did not apply for the post advertised by the BSRB for which the Regional Manager called for his explanation. The workman replied the same that BSRB test was not departmental tests as stipulated in the settlement. He further mentioned that he was not able to appear as per terms of the advertisement of the BSRB. When threatened by the management to terminate his services in the event of his not applying for test, Shri Agrawal sent his application but could not appear in the examination due to illness. On this the A.G.M. issued him show cause notice as to why he did not appear in the test conducted by the Banking Service Recruitment Board. The management after about 4 months of receiving Shri Agrawal's explanation abruptly terminated his services w.e.f. 9th August 1979 after giving him notice pay and retrenchment compensation. The management bank stated that though the workman was not entitled to notice pay and retrenchment compensation yet the same was paid and also did not believe that the workman could not appear in the bank's examination on account of his illness. The union protested against the termination to Asstt. General Manager who once again turned down the demand. The management took the stand that after the constitution of the Banking Service Recruitment Board the appointment in the bank could only be made after passing the test from BSRB. On behalf of the workman it is contended that if the bank wanted to change or modify the terms of the settlement dated 3-6-1978 they could have done so by terminating the settlement as required under section 19 and 9-A of the I.D. Act.

3. On behalf of the workman it is contended that else the workman worked in permanent clerical vacancy for beyond three months under clause 20.8 of Bipartite settlement, he acquired the status of a permanent employee and that his employment did not fall in any of the three types of temporary employee defined in clause 20.7 of the said settlement. The workman has also contested that he was not paid full amount of compensation and on this ground the termination is illegal.

4. No preliminary objection was pressed at the time of framing issues hence only following issues were framed.

(a) As in terms of reference?

(b) Relief?

5. The management examined Shri M. N. Bhatt, Regional Manager Ghaziabad as its witness to support its contention. He had admitted the bank did not held any test for three months after 3-6-1978, the date of settlement in the conciliation proceedings though he was required to appear in departmental bank's test for permanent absorption in the bank's service. Normally the bank

should have conducted the departmental test for the workman soon after the conclusion of the agreement and not waited for three months for BSRB to be formed and intervene in the recruitment of the permanent bank employee. He further admitted that pay scale revision took place in view of settlement at Bombay on 1-8-1979 revising pay scales of clerk cadre w.e.f. 1-9-1978. The date of termination of Shri Agrawal is 9-10-1978, thus his pay would be effected in view of the revision. Admittedly the basic pay of the workman on 9-10-1979 was Rs. 604 as shown in para 19M of the claim statement. The management paid the difference amount after implementation of the revised scale on 19-1-1983 amounting to Rs. 191.13 paise. He further stated that retrenchment compensation amounting to Rs. 2398 was paid to the workman on 9-10-1979 was not less than what he was entitled to under the second Bipartite Settlement. He gave a chart of calculation as paper no. M-8-I. According to this chart the pay of the workman in August and September, 79 comes to Rs. 604 which is admitted. In July 79 his pay was only Rs. 586 and the D.A. in July 1979 was only Rs. 342 and in this way three months pay comes to Rs. 1741 and one months pay of October 1979 is Rs. 604 total amounting to Rs. 2398. For the purposes of retrenchment compensation the workman has to be paid one months pay for notice being wages for the period of notice which would come to Rs. 604 and for the purposes of compensation average pay at the rate of Rs. 156 pay for every concluded year of continuous service. Thus in any event the amount of retrenchment compensation from October 1979 would not come to more than 1794. The balance amount was made good on 19-1-1983 amounting to Rs. 191.13 paise as period for payment of difference amount was extended from time to time after revision w.e.f. 1-8-1978 and difference was paid in time.

6. The management has not filed the terms and condition of the Banking Service Recruitment Board when it was created some times in later half 1978. In the absence of such government notification creating BSRB for recruitment in permanent clerk cadre of banks it is not clear whether further vacancy were to be filled in through Banking Service Recruitment Board and the banks right to hold test and interview for appointment in clerical cadre was not seized altogether. In view of the agreement dated 3-6-1978, test for the recruitment of the workman was to be taken by the bank concerned and not by any out agency to be created in future. It has come in evidence that even at the time when the agreement was in completion and was actually signed the creation of the BSRB was likely in that event and it could have been stipulated in the agreement that the workman will have to appear in departmental bank test or test by any other agency created by the government for the recruitment in clerical cadre. This having not been stipulated and the terms and condition under which the BSRB was constituted being on record I am not inclined that the right of the Bank Management to hold departmental test particularly in the case of the workman in view of the agreement was taken away.

7. In these circumstances non appearing the BSRB test will not to be in contravention of the agreement dated 3-6-1978 and the termination of the workman's services on that account would be illegal. Further in consonance that the agreement dated 3-6-1978 in the conciliation proceedings the workman was given a letter of appointment dated 5-6-1978 Annexure W.B., in which it was mentioned as under :

"Please note that for being absorbed permanently in regular cadre in the service of the bank on merit you will have to appear and passed the test when so held for the purpose next."

In this letter also there was no mention that the workman will have to appear in the test held by BSRB and that no deptt. test for recruitment will be held.

8. Even if it is conceded for the sake of arguments that the bank had a right to ask to workman to appear in BSRB test for which the workman did apply but on the date of examination fell ill and in support of his illness files medical certificate. In the absence of a proof that he was really not ill and was taking merely a pretext not to appear in the examination it could be held that he was not really ill and his services may be terminated on that ground. But this has not been done hence on this ground the termination is illegal.

9. Thirdly it is not disputed that in view of the Bipartite settlement at Bombay on 1-8-1979 there had been a wage revision for the workman of the banks and consequently the pay of the workman was also effected. Retrenchment compensation was paid to the workman according to his pay at that time on 9-10-1979 which according to the calculation M-B-I come to Rs. 2398. For compliance of the agreement two months time was given which was extended from time to time. The difference amount having not been paid within the extended time but paid on 19-1-1983 when agitated shows that the management was not keen to make the retrenchment compensation in time.

10. After the agreement on 3-6-1978, the management had three month time to hold departmental test before Banking Service Recruitment Test and being interviewed. This circumstances also shows that the management was not keen in complying with the terms of agreement dated 3-6-1978 and holding departmental test as early as possible thereafter.

11. In view of the discussions made above, I hold that the action of the management of the bank in terminating Shri V. K. Agrawal workman of their Kasturba Marg Branch with effect from 9-10-1979 is not justified.

11. The result is that the workman will be reinstated and shall be entitled to back wages from 9-10-1979 till the date of reinstatement with this condition that the pay of Rs. 500 drawn by him as clerk in the Bank's Cooperative Society from June 1983 till the date of reinstatement will be adjusted.

I, therefore, give my award accordingly.

Let six copies of this Award be sent to the Government of Publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer.
No. L-12012(72)/80-D.II(A)]

ब. अ. 2411 : - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के धारा 17 के अनुसूची में केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, स. 2, बम्बई के पचास को प्रकाशित करने है, जो केन्द्रीय सरकार का 8-5-85 प्राप्त हुआ था।

S.O. 2412.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th May, 1985.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 2 BOMBAY (CAMP AT JABALPUR)

Reference CGIT-2(7) of 1985 (Bombay)
Reference CGIT/LC(R)(5) of 1983 (Jabalpur)

PARTIES:

Employers in relation to the management of State Bank of India, Bhopal and their workman represented through the State Bank of India Employees Union, Bhopal Circle, 8, Vasandhara, State Bank of India Housing Colony, Bhopal (M.P.)

APPEARANCES:

For Workman—Shri P. S. Nair, Advocate,

For Management—Shri G. C. Jain, Advocate.

INDUSTRY: Banking DISTRICT: Bhopal (MP)

AWARD

Dated March 19, 1985

By their Order No. L-12012/32/82/D-II(A) dated 17th March, 1983 (transferred vide Order No. S-11025(1)/85-DIV(B) dated 8th February, 1985) the Central Government has referred the following dispute for adjudication under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947:—

“Whether the action of the management of State Bank of India Hamidia Road, Bhopal in dismissing Shri P. N. Halviya, Official-in-charge of Pipariya Branch of the Bank from service from 12-2-80 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. In support of the contentions there is a statement of claim filed on behalf of the workman which has been replied to by the management denying each and every contentions. However, at the time of arguments only three points were raised viz, that Shri Malviya, the employee concerned, was not permitted to have a legal aid. Secondly it was contended that the chargesheet which was served on the workman was not signed by the disciplinary authority but by the Branch Manager which has invalidated the whole thing. Thirdly it was urged that the decision as required under paragraph 521.9 of the Sastry Award having not been communicated within three days from the date of decision, on this count also the enquiry is vitiated and therefore whatever ill effects are there by the workman having not challenged the oral evidence adduced against him during the enquiry stand vanished and the workman deserves relief as prayed for.

3. The points which therefore arise for determination in this proceedings and my findings thereon are as follows:—

Issues	Findings
1. Whether the enquiry suffered from the infirmities as stated in para 15 of the statement of claim?	No
2. Whether the workman was prohibited from adducing the defence evidence.	No
5. Was the enquiry fair and proper or are the findings of the Enquiry Officer perverse or they supported by the evidence on record.	(i) Yes (ii) No (iii) Yes
4. Whether the punishment is disproportionate and harsh?	No.
5. To what relief the workman is entitled?	Nil

Reasons:

4. As already stated although various contentions were raised on behalf of the workman against the enquiry and the subsequent actions and although all of them were denied by the management by their statement of claim and written statement respectively only three points were urged at the time of the arguments and therefore we can concentrate on the same. Now as the facts stand the charge against the workman was as follows:—

“Under instructions from the Regional Manager, Region II, you are hereby required to show-cause as to why disciplinary action should not be taken against you on the following charges:—

CHARGE I

While working as the Official-in-charge of the Bank's Bankhedli Sub-Office in the year 1977 you had made a large number of fictitious entries in the Registered Letters despatch register/Postage Register of the Sub Office, as detailed in the attached Annexure I and II and thereby misappropriated Bank's money.

CHARGE II

It is reported that during your aforesaid incumbency you had also resorted to the following malpractices at the Sub-Office.

- (i) You used to pay Rs. 5 per month to Shri Bagilal Sub Office sweeper. You were, however, debiting petty cash with Rs. 7.50 per month on account of monthly payment to the sweeper, since the month of June 1977. You were thus fraudulently debiting petty cash by more amount than what was actually expended by you on Bank's account by preparing the vouchers for higher amounts.
- (ii) You paid wages to the Badli watchman, Shri Halkebir for 2nd, 9th, 10th, 23rd, and 24th July, 1977 although from the Sub-Office attendance register he does not appear to have performed Watchman's duties on those days.
- (iii) Although you showed weekly payments of daily wages to the temporary employees in the petty cash book of the Sub-Office, in fact you did not pay the wages to these employees every week. For example, in the case of Shri Halkebir for performing duties as Badli Watchman/Temporary Watchman for 10 days in July 1977, you paid him at the end of the month only Rs. 92 against the wages of Rs. 134.40 actually earned by himyou debited the Bank's charges account with Rs. 134.40."

5. On going through the evidence as adduced before the Enquiry Officer it was concluded by him that Charge No. 1, II(i) to (iii) as contained in the chargesheet dated 26th August, 1978 was proved beyond doubt. At the same time he noted a finding in the negative on Charge No. II(ii). The Enquiry Officer, however, curiously enough further went on to denote that the charges in question as proved by the presenting officer were not acts of misconduct but were offences in terms of para 521(1) of All India Industrial Tribunal Award 1953. Of course, it was his own conclusion with which the disciplinary authority may or may not agree and the evidence indicate that on 24th of April 1979 the Disciplinary Authority agreed with the conclusions regarding the proof of the charges that disagreed with the observations that they did not amount to misconduct, held that it was a misconduct for which the workman was liable for disciplinary action in terms of para 521(5) and accordingly issued the notice. The statement therefore of the Enquiry Office was the conclusion that the points in question though proved did not amount to misconduct, no longer can carry any importance and ultimately whether it amounted to misconduct will have to be seen from the definition of the misconduct as laid down in para 521(4) of the Award and further whether the disciplinary authority was satisfied or not.

6. During the course of the enquiry the workman sought the help of a legal aid but it was not granted. Now it is an admitted fact that the discretion whether the legal aid was to be given or not vested in the

Bank and therefore if the said discretion was used against the workman, no grievance can be raised against him.

7. It was then urged that the chargesheet was signed by the Branch Manager when the Bank has declared Regional Manager to be disciplinary authority and therefore it was contended that the chargesheet is illegal, void and vitiates the entire enquiry. Under para 521(12) it is necessary for the Bank to decide which officer shall be empowered to take disciplinary action in the case of each office or establishment and that it should also make provision for appeals against the orders passed in disciplinary matters. It is not a point of dispute that it was the Regional Manager of the region who was appointed. Accordingly he was the disciplinary authority for the said region in which Shri Malviya was then serving. It is also not disputed that the chargesheet was signed by the Branch Manager and not by the Regional Manager viz, the Disciplinary Authority. The question, therefore, is whether the enquiry is vitiated. In this connection the Bank has produced on record a copy of the letter dated 24th March 1978 addressed by the Regional Manager to the Branch Manager, State Bank of India, Piparia Branch in whose jurisdiction the workman then was working. In that letter the decision to chargesheet the workman was communicated because the wording of the letter is as follows:—

"Appropose to your letter No. HO/PI/15/110 dated the 2nd November 1977 in reply to our letter No. RI/AS/22128 dated the 21st September 1977, we have decided to charge-sheet the above named employee. Please, therefore, serve upon Shri Malviya chargesheet on the lines of the attached draft against proper acknowledgement and after satisfying yourself beyond doubt that the particulars mentioned therein are correct and confirm to facts and forward a copy of the chargesheet for our information.

2. Please, confirm compliance and forward his explanation for further necessary action, at an early date."

8. By paragraph 1 of the letter the Branch Manager was asked to prepare the charge-sheet on the lines of the draft annexed to the said letter and by para 2 he was asked to confirm the compliance. Now the charge-sheet which was ultimately served on the workman was the same as the draft and there is no change whatsoever. The question, therefore, which poses for determination is whether there is any illegality committed or violation of the Award which is binding on both the parties, by the Branch Manager signing the charge-sheet. We have already seen that even in the opening part of the letter dated 24th March 1978 the fact that the Regional Manager has arrived at a decision to chargesheet the workman is enunciated. Naturally what was left to the Branch Manager was merely manual action, namely to copy the draft charge-sheet, in case necessary to supply the material dates but this was not required to be done and to serve it on the workman. The initiation of the enquiry therefore as required by para 521(12) was by the Disciplinary Authority and can never be said to be by the Branch Manager and as such if

the Branch Manager merely communicated the charge-sheet under his signatures which was the act of the Disciplinary Authority and nobody else, the subsequent communication of the service of the charge-sheet under his signatures would not reflect upon the action of the Regional Manager nor would it render the charge-sheet illegal. It still remains the decision of the Regional Manager and renders the Branch Manager to be merely a communicating authority. Therefore the contention that the charge-sheet itself having been signed by the Branch Manager is illegal, carries no force because it is a charge-sheet and a decision to launch a charge-sheet of the Regional Manager who was fully competent to do so.

9. Under one impression or the other Shri Malviya did not actively participate in the enquiry, and though he was physically present did not challenge the evidence adduced against him, allowing the whole material to go unchallenged. Certainly in the light of these circumstances he still would be entitled to point out the illegalities but having failed to challenge the evidence now he cannot dispute the correctness of the findings noted by the Enquiry Officer. Once it is held that the decision to launch the chargesheet was by the regional Manager, the whole force behind the arguments about the illegality on account of the signatures of the Branch Manager is taken away and the findings shall have to be read as they are.

10. It was then contended that under para 521(9) the decision to take disciplinary action has to be communicated within three days. It was contended that since the Regional Manager had taken the decision to launch action on 24th March 1978 when the chargesheet was served on 31-8-1978 there is a gap of almost four months and therefore there is a breach of para 521(9). However, the decision which is contemplated by the relevant clause is not an initial decision but the ultimate decision based on the findings and the report of the Enquiry Officer and therefore the alleged gap of four months carries no force. Further more, though the Award speaks of three days, it is not a period of limitation as laid down under Limitation Act and ultimately everything would be governed by it any prejudice caused to the workman. If there is no prejudice then at best it would amount to an irregularity not vitiating the enquiry or the order and since there is no proof of any prejudice before me, assuming that that there is some irregularity, it would not be of any use to the workman.

10. As indicated earlier the workman having not challenged the evidence of the witnesses, having not challenged the record produced on behalf of the Bank and having allowed the material to go on record as it was, it is now not possible to depart from or disagree with the findings noted by the Enquiry Officer and whatever is held by him and which ultimately weighed with the disciplinary authority shall have to be accepted. This then shall bring us to the question of punishment because even if the Bank had awarded punishment of dismissal still under Sec 11A of the ID Act it will have to be seen whether it is a proper punishment or harsh or disproportionate. When we peruse the chargesheet

there is the case of dishonestly attributed to the workman and acts of misappropriation of the Bank's money, when he was in service of the Bank and therefore duty bound to protect the property of the Bank, and so on proof or establishment of the charges, no other punishment could be said to have been legal. If on the strength of the material before him the disciplinary or the appellate authority ultimately decided to part with the services of Shri P. N. Malviya and passed an order of dismissal, in the light of the whole history, nature of the chargesheet and the proof of the charges, the said action of punishment can never be said to be harsh or disproportionate as such my findings would be that the Bank is justified in awarding the same. Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.

[No. L-12012/32/82-DII(A)]

का आ 2413.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के धारा 17 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिनियम, कानपुर के पंचाट का प्रकाशन करण है, जो केन्द्र सरकार को 8-5-85 प्राप्त हुआ था।

S.O. 2413.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th May, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT

KANPUR

Industrial Dispute No. 13/1983

In the matter of dispute between Shri :

Shri Anil Kumar Mishra C/o Asstt. General Secretary, UP Bank's Employees Union 165 Sohbatia Bagh, Allahabad.

Versus

The Assistant General Manager, Union Bank of India, Hotel Clarks Awadh Hazratganj, Lucknow.

PRESENT :

Shri Harmangal Prasad—for the workman & Shri S. L. Verma, representative—for the management.

AWARD

The Central Government Ministry of Labour vide its order No. L-12012/303/81-D-II(A) dated 2-12-82 has referred the following dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of Union Bank of India, in relation to their Naini Branch Allahabad in not absorbing Shri Anil Kumar Mehrotra clerk in the bank service

but terminating his services w.e.f. 11-11-78 is justified. If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

The applicant filed his statement of claim complaining that he worked for 336 days as temporary clerk at Naini branch of the management bank at Allahabad between 20-12-76 to 24-12-77 with breaks and as his termination was without giving him notice, notice pay or retrenchment compensation his termination was ab initio and he was entitled to be reinstated with full back wages.

The management contested the claim statement of the workman and averred that the workman concerned had not put in 240 days service or more within the preceding one year from the date of his termination which was 11-11-78 and not 24-12-77. After rejoinder by the workman the management filed documents but at the stage of evidence none appeared for the workman and his representative Shri V. N. Sekhri stated that he had no instruction from the workman.

Thus in these circumstances there being no evidence to substantiate the statement of the workman the reference is answered in negative namely that the action of the management of Union Bank of India in relation to their Naini Branch Allahabad in not absorbing the workman Shri Anil Kumar Mehrotra clerk in the bank's service but terminating his service w.e.f. 11-11-78 is justified, and the workman concerned is entitled to no relief.

I, therefore, give my award accordingly.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012/303/81-D II(A)]

नई दिल्ली, 20 मई, 1985

का. अ. 2414.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के धारा 17 के अन्वय में केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोक्ता और उनके कर्मचारियों के बीच, अन्वय में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पचास को प्रकाशित करने है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-5-85 प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 20th May, 1985

S.O. 2414.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th May, 1985

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE (RETD.),
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(39)/1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India and their workman Shri

Mothiram Sahu, Messenger-cum-Watchman
Bemetra Branch Raipur (M.P.).

APPEARANCES :

For Workman

Shri D. P. Hiwari and Shri S. D. Phadke.

For Bank

SHRI G. C. Jain, Advocate.

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Raipur (M.P.).

AWARD

Dated : April 25, 1985

The Central Government in exercise of its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication vide Notification No. L-12012(302)/82-D. II(A), dated 30th July, 1983.

"Whether the action of the management of State Bank of India in relation to its Bemetra Branch under control of Chief Regional Manager, Raipur in terminating the services of Shri Mothiram Sahu, Messenger-cum-Watchman with effect from 25-8-1981 and not offering him re-employment in service is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The workman was temporarily employed in the State Bank of India. They had put in services in the Bank from time to time but have not been regularised nor made permanent. Hence the above dispute. During the pendency of the dispute the parties have come to amicable settlement which is filed before me. The agreement is fair and just and I am of the opinion that the terms of the settlement would be in the better interest of the workman. I, therefore, give this award the terms of which have been agreed upon between the parties under a settlement.

ORDER :

(i) The employee workman shall forego all claims to back wages.

(ii) That the management will provide an opportunity to the workman to work in the Bank in the same capacity as he was before the termination of services. The Bank shall for giving the workman an opportunity for his permanent absorption in the Bank, interview the employee and the appointment would be subject to their selection.

(iii) That the workman will be considered for permanent absorption in the Bank subject to their being found physically fit and having stood the test in the interview taken for the purpose. Their character, credentials and antecedents shall be verified as required for the Bank services and the absorption shall be subject to the reports in this regard. The Bank also agrees to give a chance to those temporary employees for absorption in the employment in the same capacity as have completed more than 90 days temporary services as a special gesture of goodwill provided such persons forego their claim for back wages during the period they have remained unemployed.

This closes the present dispute. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer
[No. L-12012(302)|82-D-II(A)]

का आ. 2415.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के धारा 17 के अन्वय में केन्द्र सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अन्वय में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्र सरकार औद्योगिक अधि-करण, जबलपुर के पचाट को प्रकाशित करने है, जो केन्द्र सरकार का 9-5-85 प्राप्त हुआ था।

S.O. 2415.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th May, 1985.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE (RETD.),
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR

COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(9)/1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Raipur and their workman S/Shri Pannalal, Bhushan Kumar, Virendra Kumar, Gopi Chand Swarnkar, T. P. Pandey and Kamal Rai.

APPEARANCES :

For Workmen

Shri D. P. Tiwari and Shri S. D. Phadke.

For Management

Shri G. C. Jain, Advocate.

INDUSTRY : Bank DISTRICT Raipur (M.P.)

AWARD

Dated : April 25, 1985

The Central Government in exercise of its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication vide Notification No. L-12012(118)|82-D. II(A) dated the 8th April, 1983.

“Whether the action of the management of State Bank of India in terminating the services of S/Shri Pannalal, Bhushan Kumar, Virendra Kumar, Gopi Chand Swarnkar, T. P. Pandey and Kamal Rai, Sub-staff under Control of the Chief Regional Manager, Raipur is justified? If not, to what relief are the workman concerned entitled?”

2. The workmen was temporarily employed in the State Bank of India. They had put in services in the Bank from time to time but have not been regularised nor made permanent. Hence the above dispute. During the pendency of the dispute the parties have come to

amicable settlement which is filed before me. The Agreement is fair and just and I am of the opinion that the terms of the settlement would be in the better interest of the workmen. I, therefore, give this award the terms of which have been agreed upon between the parties under written settlement.

ORDER :

(i) The employee workmen shall forego all claims to back wages.

(ii) That the management will provide an opportunity to the workmen to work in the Bank in the same capacity as they were before the termination of services. The Bank shall for giving the workmen an opportunity for their permanent absorption in the Bank, interview the employees and the appointment would be subject to their selection.

(iii) That the workmen will be considered for permanent absorption in the Bank subject to their being found physically fit and having stood the test in the interview taken for the purpose. Their character, credentials and antecedents shall be verified as required for the Bank services and the absorption shall be subject to the reports in this regard. The Bank also agrees to give a chance to those temporary employees for absorption in the employment in the same capacity as have completed more than 90 days temporary services as a special gesture of goodwill provided such persons forego their claim for back wages during the period they have remained unemployed.

This closes the present dispute. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer
[No. L-12012(118)|82-D-II(A)]

का आ. 2416.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के धारा 17 के अन्वय में केन्द्र सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अन्वय में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्र सरकार औद्योगिक अधि-करण, जबलपुर के पचाट को प्रकाशित करने है, जो केन्द्र सरकार का 9-5-85 प्राप्त हुआ था।

S.O. 2416.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th May, 1985.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE (RETD.),
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM
LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

PARTIES:

Employers in relation to the management of State Bank of India, Jabalpur and their workman, Shri Kallo Singh, Part-time employee Shahnagar Branch, Distt. Panna (MP).

APPEARANCES:

For workman—Shri D. P. Tiwari and Shri S.D. Phadke.

For management—Shri G. C. Jain, Advocate.
INDUSTRY: Bank DISTRICT:

अधिकार, अहमदाबाद के पैदा की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को ५-५-८५ प्राप्त हुआ था।

AWARD

Dated: April 25, 1985

The Central Government in exercise of its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication vide Notification No. L-12012/95/83-D.II(A), dated the 30th September, 1983.

“Whether the action of the management of State Bank of India, in relation to their Shah-nagar Branch, Distt. Panna (MP) in terminating the services of Shri Kallo Singh Part-time employee, with effect from 10-11-79 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?”

2. The workman was temporarily employed in the State Bank of India. They had put in services in the Bank from time to time but have not been regularised nor made permanent. Hence the above dispute. During the pendency of the dispute the parties have come to amicable settlement which is filed before me. The Agreement is fair and just and I am of the opinion that the terms of the settlement would be in the better interest of the workman, I, therefore, give this award the terms of which have been agreed upon between the parties under written settlement.

ORDER:

(i) The employee workman shall forego all claims to back wages.

(ii) That the management will provide an opportunity to the workman to work in the Bank in the same capacity as he was before the termination of services. The Bank shall for giving the workman an opportunity for his permanent absorption in the Bank, interview the employee and the appointment would be subject to his selection.

(iii) That the workman will be considered for permanent absorption in the Bank subject to their being found physically fit and having stood the test in the interview taken for the purpose. Their character, credentials and antecedents shall be varified as required for the Bank services and the absorption shall be subject to the reports in this regard. The Bank also agrees to give a chance to those temporary employees for absorption in the employment in the same capacity as have completed more than 90 days temporary services as a special gesture of goodwill provided such persons forego their claim for back wages during the period they have remained unemployed.

This closes the present dispute. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer.

[No. L-12012/95/83-D.II(A)]

का. प्र. 2417-- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद लिमिटेड के प्रबंधन ने सम्बद्ध श्रमिकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुषंग में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक

S.O. 2417.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Gujarat as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Cooperative Bank of Ahmedabad Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th May, 1985.

BEFORE SHRI G. S. BAROT, INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT AHMEDABAD

Reference (ITC) No. 3 of 1980

ADJUDICATION

BETWEEN

The Co-operative Bank of Ahmedabad First Party
AND

The workmen employed under it Second Party.
In the matter of termination of services of Shri

A. B. Patel, Peon w.e.f. 1st December, 1976.
APPEARANCES :

Shri L. A. Dedia, Advocate for the First Party.

Shri Y. V. Shah, Advocate for the Second Party.

AWARD-PART I

This industrial dispute between the Co-operative Bank of Ahmedabad and the workmen employed under it has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, by the Government of India, Ministry of Labour's Order No. S. O. dated 7th April, 1980 to the Industrial Tribunal consisting of Shri R. C. Israni and subsequently transferred to me.

2. The dispute relates to a single demand which is as under :—

“Whether the Cooperative Bank of Ahmedabad Limited, Ahmedabad, is justified in terminating the services of Shri A. B. Patel, Peon with effect from 1st December, 1976? If not, to what relief is the said workman entitled?”

3. In this case the workman concerned has challenged the inquiry and it has been submitted that the inquiry held against him was illegal and improper inasmuch as principles of natural justice have been violated in this case. It was, therefore, decided that the question of validity or otherwise of the inquiry held be decided first.

4. Shri Y. V. Shah, the learned Advocate for the workman concerned and Shri L. A. Dedia, the learned Advocate for the Bank were heard.

5. In this case at this point of time it is only required to see whether the inquiry suffers from any infirmity or not.

6. It was alleged against the workman concerned that on 6-5-1976 he had abused one Bhagwandas Contractor the Cashier in the Bank and thereby committed

misconduct. The workman concerned had replied to the said memo dated 6-5-1976. Thereafter he was given a show cause notice/charge-sheet in this behalf and an inquiry was held by the Bank pursuant thereto. The workman concerned has examined himself at Ex. 29 wherein he has stated that though he has asked for the copy of the complaint of Bhagwandas, he is not supplied the same. Similarly, he has also asked for the papers regarding preliminary enquiry held but there also he was not given the same. He has then stated that though he was asked to cross-examine the witnesses i.e. Bhagwandas, Cashier and the Security Officer, he has not cross-examined them in the absence of the copy of the complaint given to him. He has also stated that thereafter the inquiry was held in his absence. He has also stated that he was not allowed any opportunity to examine defence witness. It is, however, true that in his cross-examination he has stated that the inquiry was held in his presence and that the statements of Bhagwandas and the Security Officer were recorded in his presence. He has also stated that some writing where his signature is to be found is in fact not his signature. He has also stated that only the writing upto the stage where Bhagwandas has signed was recorded in his presence and the writing thereafter was not made in his presence.

7. On behalf of the Bank the Inquiry Officer Shri Bhatt was examined at Ex. 57 wherein he has initially stated that he had given an opportunity to the workman concerned to bring his defence witnesses if he desired but he has not examined any. After the inquiry was over he had sent his report to the Board of Directors. He has stated that the charge-sheet was given to the workman concerned at the instance of the Manager. The copy of the finding was given to the Board but the same was not sent to the workman concerned. He has further stated that the Cashier Bhagwandas had made a complaint in writing and further stated that he had with him the said complaint when he started the inquiry on 28-9-1976. Then he had stated that he did not remember whether he had given the copy of the said complaint to the workman concerned. He has further stated that he had asked the workman concerned if he wanted to have a friend to conduct his inquiry and he had stated so orally.

8. From the oral evidence recorded it appears clearly that it is the say of the workman concerned that the principles of natural justice were violated in this case inasmuch as he was not furnished, though asked, the copy of the complaint of Shri Bhagwandas. That he was not allowed to engage a friend in conducting the inquiry and that he was not allowed to cross-examine. From the evidence of the Inquiry Officer it appears that though the Inquiry Officer had the complaint of Bhagwandas and though copy was asked by the workman concerned, the same was not furnished. Secondly, the Inquiry Officer admitted that there is no endorsement made in the inquiry papers that he had given any opportunity to the workman concerned to engage a friend. He had also admitted that though Bhagwandas the complainant was examined, his name was not shown in the list of the witnesses to be examined in the inquiry. The original complaint of Bhagwandas appears at Ex. 25 and it is dated 10-5-76. The complaint, however, refers to the incident of 6-5-1976 and in fact the workman concerned was

also charge-sheeted for the said incident. It is, however, surprising that the Cashier Bhagwandas who is alleged to have been abused by the workman concerned on 6-5-1976 has given him complaint in writing on 10-5-1976. After the inquiry was over in this case the finding was sent to the Board and the copy of the same was not furnished to the workman concerned. It appears that thereafter second show cause notice was given but there was no reply to the same from the workman concerned and, therefore, ultimately an order dismissing the workman concerned was passed. From the record it appears from the Ex. 56 that the workman concerned had passed on one apology for the incident in question but from the perusal of the said Ex. 56 it appears that the same was conditional. This aspect had not been taken into account. Thus from the evidence on record, it appears that this is a case where the inquiry suffers from certain infirmities and it can be said that principles of natural justice have not been fully complied with. When there was the complaint received a copy of the same should have been when he has specifically asked for the same. Moreover, the inquiry record does not show that the proper opportunity for engaging a friend or cross-examining the witnesses were properly given are required under the law. In my opinion, therefore, this is a case where the inquiry held appears to be defective as it suffers from certain infirmity. The employer, however, has asked for permission to prove the misconduct alleged before the Tribunal and as per the settled law in this behalf a permission, if the employer desires to avail of, should be granted to him.

9. For the above reasons the inquiry is held to be vitiated and the employer is given an opportunity to prove the misconduct before the Tribunal by leading evidence as it thinks fit. The employee is also allowed to rebut the evidence as deemed fit. No order as to costs.

Ahmedabad.

Date 4th April, 1985.

G. S. BAROT, Industrial Tribunal

[No. L-13012/13/79-D-II(A)]

को. आ. 2418-- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) का धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रिय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रिय सरकार औद्योगिक अधिकारण, जबलपुर के पचाट को प्रकाशित करने, है, जो केन्द्रिय सरकार का 9-5-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2418.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th May, 1985.

Case No. CGIT/LC(R)(12)/1984.

Employers in relation to the management of State Bank of India and their workman S/Shri Raj Kumar, Samson Karmakar and James Dayal, Messengers, Chhindwara Branch

For workmen—Shri D. P. Tiwari and Shri S. D. Phadke.

INDUSTRY : Bank—DISTRICT : Chhindwara (M P)

Dated : April 25, 1985.

“Whether the action of the management of State Bank of India, Jabalpur in relation to their Chhindwara Branch in terminating the services of S/Shri Raj Kumar, Samson Karmakar and James Dayal, Messengers with effect from 31-5-79, 11-8-79 and 15-5-79 respectively and not considering them per further employment while engaging fresh hands is justifiably? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?”

2. The workmen was temporarily employed in the State Bank of India. They had put in services in the Bank from time to time but have not been regularised nor made permanent. Hence the above dispute. During the pendency of the dispute the parties have come to amicable settlement which is filed before me. The Agreement is fair and just and I am of the opinion that the terms of the settlement would be in the better interest of the workmen. I, therefore, give this award the terms of which have been agreed upon between the parties under a written settlement.

(i) The employee workmen shall forego all claims to back wages.

(ii) That the management will provide an opportunity to the workmen to work in the Bank in the same capacity as they were before the termination of services. The Bank shall for giving the workmen an opportunity for their permanent absorption in the Bank, interview the employees and the appointment would be subject to their selection.

(iii) That the workman will be considered for permanent absorption in the Bank subject to their being found physically fit and having stood the test in the interview taken for the purpose. Their character, credentials and antecedents shall be verified as required for the Bank services and the absorption shall be subject to the reports in this

regard. The Bank also agrees to give a chance to those temporary employees for absorption in the employment in the same capacity as have completed more than 90 days' temporary services as a special gesture of goodwill provided such persons forego their claim for back wages during the period they have remained unemployed.

This closes the present dispute. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE; Presiding Officer

[No. L-12012(241)83[D,II(A)]]

का आ २४१७-औद्योगिक विवाह अधिनियम, १९१७ (१९१७ का ११) के धारा १७ के अनुसरण में केंद्रय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाह में केंद्रय सरकार औद्योगिक अधि-करण, जबलपुर के पश्चात् का प्रकाशित करता है, जो केंद्रय सरकार का ७-५-४५ प्राप्त हुआ था।

S.O. 2419.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th May, 1985.

BEFORE JUSTICE SHRI K .K. DUBE (RETD.)
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR
COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(48)/1983.

PARTIES:

Employers in relation to the management of State Bank of India, Jabalpur and their work, Sri Manmohan Yadav S/o Shri Sharda Pradsa Yadav; Messenger, Regional Office, Jabalpur (M.P.).

APPPEARANCES

For Workman—Shri D. P. Tiwari and Shri S. D. Phadke.

For Management—Shri G. C. Jain, Advocate.
INDUSTRY : Bank —DISTRICT : Jabalpur (M.P.)

AWARD

Dated : April 25, 1985

The Central Government in exercise of its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication vide Notification No. L-12012/21/83-D.II(A) dated the 25th August, 1983.

“Whether the action of the management of State Bank of India, Regional Office, Jabalpur in terminating the service, of Shri Manmohan Yadav S/o Shri Sharda Pradsa Yadav Messenger with effect from 5.1.82 and denying him preference in re-employment in the

Bank is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The workman was temporarily employed in the State Bank of India. He had put in services in the Bank from time to time but have not been regularised nor made permanent. Hence the above dispute. During the pendency of the dispute the parties have come to amicable settlement which is filed before me. The Agreement is fair and just and I am of the opinion that the terms of the settlement would be in the better interest of the workman. I, therefore, give this award the terms of which have been agreed upon between the parties under a written contract.

ORDER :

(i) The employee workman shall forego all claims to back wages.

(ii) That the management will provide an opportunity to the workman to work in the Bank in the same capacity as he was before the termination of services. The Bank shall for giving the workman an opportunity for his permanent absorption in the Bank, interview the employee and the appointment would be subject to his selection.

(iii) That the workman will be considered for permanent absorption in the Bank subject to their being found physically fit and having stood the test in the interview taken for the purpose. His character, credentials & antecedents shall be verified as required for the Bank services and the absorption shall be subject to the reports in this regard. The Bank also agrees to give a chance to those temporary employees for absorption in the employemnt in the same capacity as have completed more than 90 days temporary services as a special gesture of goodwill provided such persons forego their claim for back wages during the period they have remained unemployed

This closes the present dispute. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer
[No. L-12012/21/83-D-II-(A)]

का था 2110--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के धारा 17 के अन्वय में, केन्द्र सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन में सम्बद्ध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अन्वय में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिनियम, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करता है जो केन्द्र सरकार को 9-5-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2420.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and its workmen which was received by the Central Government on the 9th May, 1985.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE REID),
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR

COURT, JABALPUR (M.P.)

CASE NO. CGIT/LC(R)(38)/1983

PARTIES .

Employers in relation to the management of State Bank of India, Jabalpur and their, workman, Shri Rajaram Chakroborty, Messenger, Agricultural Development Branch, Shahpur (Bhitoni).

APPEARANCES .

For Workman.—Shri D.P. Tiwari & Shri S.D. Phalke, Shri P. C. Khan.

For Management.—Shri G.C. Jain, Advocate.
INDUSTRY : Bank DISTRICT : Jabalpur (M.P.)

AWARD

Dated : April 25, 1985

The Central Government in exercise of its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication vide Notification No. L-12012(272)/82-D. II. A. dated the 18th July, 1983.

"Whether the action of the management of State Bank of India, Jabalpur in relation to its Agricultural Development Branch, Shahpura (Bhitoni) in terminating the services of Shri Rajaram Chakroborty, Messenger, with effect from 18-10-80 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The workman was temporarily employed in the State Bank of India. He had put in services in the Bank from time to time but has not been regularised nor made permanent. Hence the above dispute. During the pendency of the dispute the parties have come to amicable settlement which is filed before me. The Agreement is fair and just and I am of the opinion that the terms of the settlement would be in the better interest of the workman. I, therefore, give this award the terms of which have been agreed upon between the parties under a written settlement ORDER :—

(i) The employee workman shall forego all claims to back wages.

(ii) That the management will provide an opportunity to the workman to work in the Bank in the same capacity as he was before the termination of services. The Bank shall for giving the workman an opportunity for his permanent absorption in the Bank, interview the employee and the appointment would be subject to his selection.

(iii) That the workman will be considered for permanent absorption in the Bank subject to their being found physically fit and having stood the test in the interview taken for the purpose. Their character, credential and antecedents shall be verified as required for the Bank services, and the absorption

shall be subject to the reports in this regard. The Bank also agrees to give a chance to those temporary employees for absorption in the employment in the same capacity as have completed more than 90 days temporary services as a special gesture of goodwill provided such persons forego their claim for back wages during the period they have remained unemployed.

This closes the present dispute. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer.

[No. L. 12012/272/82-D-II]

क्र. पा. 2421—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) का धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि-करण, जबलपुर के पंचद का प्रकाशन करना है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-5-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2421.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th May, 1985.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE (RETD.),
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)/(11)/1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India and their workman Shri R. K. Tiwari, Messenger, Ramjhi Branch, Jabalpur (M.P.).

APPEARANCES:

For Workman

Shri D. P. Tiwari and Shri S. D. Phadke.

For Bank

Shri G. C. Jain, Advocate.

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Jabalpur (M.P.).

AWARD

Dated : April 25, 1985

The Central Government in exercise of its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute for adjudication vide Notification No. 1-12012/242/83-D. II(A), dated 6th February, 1984.

"Whether the action of the management of State Bank of India, Regional Office, Jabalpur in relation to their Ramjhi Branch, Jabalpur in terminating the services of Shri R. K. Tiwari, Messenger with effect from 9-6-1979 and not

considering him also for further employment while engaging a fresh hand after termination of his services was justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The workman was temporarily employed in the State Bank of India. They had put in services in the Bank from time to time but have not been regularised nor made permanent. Hence the above dispute. During the pendency of the dispute the parties have come to amicable settlement which is filed before me. The Agreement is fair and just and I am of the opinion that the terms of the settlement would be in the better interest of the workman. I, therefore, give this award the terms of which have been agreed upon between the parties under a settlement.

ORDER :

(i) The employee workman shall forego all claims to back wages.

(ii) That the management will provide an opportunity to the workman to work in the Bank in the same capacity as he was before the termination of services. The Bank shall for giving the workman an opportunity for his permanent absorption in the Bank, interview the employee and the appointment would be subject to their selection.

(iii) That the workman will be considered for permanent absorption in the Bank subject to their being found physically fit and having stood the test in the interview taken for the purpose. Their character credentials and antecedents shall be verified as required for the Bank services and the absorption shall be subject to the reports in this regard. The Bank also agrees to give a chance to those temporary employees for absorption in the employment in the same capacity as have completed more than 90 days temporary services as a special gesture of goodwill provided such persons forego their claim for back wages during the period they have remained unemployed.

This closes the present dispute. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer

[No. L-12012/242/83-D. II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली 30 मई 1985

आदेश

का धा 2421—केन्द्रीय सरकार का राय है कि इसमें उपावद्ध अनुसूच में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारत का जवन व सा निगम से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

2 और विवाद का स्वरूप ऐसा है कि जिसमें एक से अधिक राज्यों में स्थित भारत का जवन व सा निगम के प्रतिष्ठानों का हित गन्तिहित होने या उनसे प्रभावित होने की संभावना है ;

3 और केन्द्रीय सरकार का यह राय है कि उक्त विवाद में राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णय किया जाना चाहिए

4 अतः अब केन्द्रीय सरकार—

(i) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) का धारा 7-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित करने है, जिसका मुख्यालय बम्बई में होगा और श्री आर. पा. कुलकर्णी को इस का पठामन अधिकार नियुक्त करने है और

(i) उक्त अधिनियम के धारा 10 के उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त औद्योगिक विवाद को उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना है,

उक्त अधिकरण उक्त अधिनियम के धारा 10 के उपधारा (2-क) के अनुसार उक्त विवाद में अपना पवाद छह माह के अवधि के अन्दर देगा।

अनुसूच

“भारतीय जीवन बीमा निगम के बचत” अस्थायी तथा अंशकालिक कर्मचारियों के मजदूर और अन्य सेवा शर्तें तथा उन्हें नियमित शर्तों में खपाने के शर्तें क्या हों चाहिए?”

[जिड-17011/2/83-ड-4 (ए)]

एन के वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th May, 1985

ORDER

S.O. 2422.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Life Insurance Corporation of India and the workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

2. And whereas, the dispute is of such a nature that establishments of Life Insurance Corporation situated in more than one State are likely to be interested in or effected by such dispute;

3. And whereas the Central Government is of the opinion that the said dispute should be adjudicated by a National industrial Tribunal;

4. Now, therefore, the Central Government :—

(i) in exercise of the powers conferred by section 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), hereby constitutes a National Industrial Tribunal with headquarters at Bombay and appoints Shri R.D. Tulpule as its presiding officer; and

(ii) in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 10 of the said Act, hereby refers the said industrial dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication;

The said Tribunal shall submit its award in the said dispute within a period of six months in accordance with sub-section (12A) of section 10 of the said Act.

SCHEDULE

“What should be the wages and other conditions of service of badli, temporary and part-time workmen of the Life Insurance Corporation of India as well as the conditions of their absorption into regular cadre?”

[Z-17011/2/83[D-IV(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 18 मई, 1985

का आ 2422—डेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिवृत्ता सख्या का. आ. 2303, दिनांक 11 जून, 1982 का 211 GI/85—19

अधिकरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अनुसूची के कालम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को निरीक्षक नियुक्त करती है जो उक्त अधिनियम द्वारा या इस के अधीन निरीक्षकों को प्रदत्त शक्तियों का उक्त अनुसूची के कालम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथानिर्दिष्ट उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करेंगे —

अनुसूची		
क्रमिक	अधिकारी	अधिकार-क्षेत्र
1	2	3
1.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली	संपूर्ण भारत
2.	संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली	संपूर्ण भारत
3.	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली और धनबाद।	संपूर्ण भारत
4.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय नई दिल्ली के प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली	संपूर्ण भारत
5.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय नई दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत
6.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, नई दिल्ली में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत
7.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), बम्बई और वरन्ड क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र गोवा, वमण और दीव तथा दादर और नुतगर हवेली
8.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता और कलकत्ता क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	पश्चिम बंगाल (वर्धमान, बंकुरा, बोरभूम और पुरुलिया के विभिन्न जिलों को छोड़कर) तथा मिझोरम राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
9.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मोहाटी और मोहाटी क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम
10.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मद्रास और मद्रास क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	तमिलनाडु और केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र पंडिचेरी और लक्षद्वीप

1	2	3	SCHEDULE		
			Sl. Officers No.		Jurisdiction
1	2	3	1	2	3
11. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर और मध्य प्रदेश राज्य जबलपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	12. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कामपुर और उत्तर प्रदेश कामपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त राज्य और मध्य (केन्द्रीय), और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी राज्य क्षेत्र दिल्ली (केन्द्रीय)	13. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त हरियाणा, पंजाब (केन्द्रीय) तथा सभी प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) जम्मू और कश्मीर राज्य तथा मध्य राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	1. Chief Labour Commissioner. (Central), New Delhi.	Whole of India	
14. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद और बिहार राज्य धनबाद क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और सभी प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	15. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद और आंध्र प्रदेश राज्य हैदराबाद क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	16. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर और राजस्थान और अजमेर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) गुजरात राज्य और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	2. Joint Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.	Whole of India	
17. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), आसनसोल और पश्चिम बंगाल आसनसोल क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	18. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर और उड़ीसा राज्य भुवनेश्वर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	19. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलौर और कर्नाटक राज्य बंगलौर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	3. Deputy Chief Labour Commissioners (Central), New Delhi and Dhanbad.	Whole of India	
4. Regional Labour Commissioners (Central), New Delhi in the Office of the Chief Labour Commissioner (Central). New Delhi.	5. Welfare Adviser to Chief Labour Commissioner (Central), Office of the Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi.	6. All Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in the Office of Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.	7. Regional Labour Commissioner (Central), Bombay and all Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in Bombay region).	The State of Maharashtra and Union Territories of Goa Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.	
8. Regional Labour Commissioner (Central), Calcutta and all Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in the Calcutta region.	9. Regional Labour Commissioner (Central), Gauhati and all Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in the Gauhati region.	10. Regional Labour Commissioner (Central), Madras and all Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in Madras region.	11. Regional Labour Commissioner (Central), Jabalpur, and all Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in the Jabalpur region.	The States of West Bengal (excluding the Civil Districts of Burdwan, Bankura, Birbhum and Purulia), Sikkim and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands.	
				The States of Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Manipur and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram.	
				The States of Tamilnadu, Kerala and Union Territories of Pondicherry and Lakshadweep.	
				The State of Madhya Pradesh.	

[एन-16025/26/84-एन डब्ल्यू III]

New Delhi, the 18th May, 1985

S. O. 2423.—In exercise of the powers conferred by sub-section, (1) of section 28 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 2303 dated 11th June, 1982, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Schedule below, to be Inspectors who shall exercise the powers conferred on Inspectors by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdictions as specified in the corresponding entries in column (3) of the said schedule :

1	2	3
12.	Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur and all Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in the Kanpur region	The State of Uttar Pradesh and the Union Territory of Delhi.
13.	Regional Labour Commissioner (Central), Chandigarh and all Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in the Chandigarh region	The States of Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Jammu and Kashmir and Union Territory of Chandigarh.
14.	Regional Labour Commissioner (Central), Dhanbad and all Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in the Dhanbad region	The State of Bihar.
15.	Regional Labour Commissioner (Central), Hyderabad and all Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in the Hyderabad region.	The State of Andhra Pradesh.
16.	Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer and all Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in Ajmer region	The States of Rajasthan and Gujarat.
17.	Regional Labour Commissioner (Central), Asansol and all Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in the Asansol region.	The Civil Districts of Burdwan, Birbhum Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
18.	Regional Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar and all Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in Bhubaneswar region	The State of Orissa
19.	Regional Labour Commissioner (Central), Bangalore and all Assistant Labour Commissioners (Central) and Labour Enforcement Officers (Central) in Bangalore region.	The State of Karnataka.

[No. S-16025/26/84-LW (iii)]

का. आ. 2421. -- ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2301, तारीख 11 जून, 1982 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को सरकार के राजपत्रित अधिकारी होने के कारण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त अधिनियम द्वारा या इसके अर्धेन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में पर्यावर्तित अधिकार क्षेत्रों में प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

अधिकारी	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)
सभी महायुक्त श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	सम्पूर्ण भारत

[संख्या एम.- 16025/26/84-एल. डब्ल्यू. (ii)]

S. O. 2421. - In exercise of the powers conferred by section 11 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 (37 of 1970) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 2301 dated 11th June 1982, the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in column (1) of the schedule below, being Gazetted Officers of the Government to be licensing officers who shall exercise the powers conferred on licensing officers by or under the said Act, having jurisdiction specified in column (2) of the said Schedule;

SCHEDULE

Officers	Jurisdiction
(1)	(2)
All Assistant Labour Commissioners (Central)	Whole of India

[No. S-16025/26/84-LW. (ii)]

का. आ. 2425 :-- ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2300, तारीख 11 जून, 1982 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, सरकार के राजपत्रित अधिकारी होने के कारण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त अधिनियम द्वारा या इसके अर्धेन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में पर्यावर्तित अधिकार क्षेत्रों में प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

अधिकारी	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)
सभी महायुक्त श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	सम्पूर्ण भारत

[सं. एम.- 16025/26/84-एल. डब्ल्यू. (i)]

ग. व. आन्ध्रप्रदेश, महानिदेशक (श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव

S.O 2425 :—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 (37 of 1970) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. 2300 dated 11th June 1982, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Schedule below, being Gazetted Officers of the Government, to be the registering officers who shall exercise the powers conferred on registering officers by or under the said Act, having jurisdiction as specified in column (2) of the said schedule.

SCHEDULE

Officers	Jurisdiction
(1)	(2)
All Assistant Labour Commissioners Whole of India. (Central).	

[No. S-16025/26/84-LW(1)]

A. K. SRIVASTAVA, Director General
(Labour Welfare)/J.L. Secy

नई दिल्ली. 18 मई, 1985

का. भा. 2436:—सैसस वि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, महाराष्ट्र वाहतुक भवत, डाक्टर आनन्तराव नायर मार्ग बम्बई-8 (एम-एच/1255) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकरण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 14) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2ख) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना हों, महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम अतिरिक्त उपदान एवं कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि स्कीम, 1976 के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी विशेष सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976, (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षणों प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) (3क) के अंड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम अतिरिक्त उपदान एवं कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि स्कीम, 1976 के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण, प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम अतिरिक्त उपदान एवं कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि स्कीम, 1976 के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन

की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाव, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजन किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम अतिरिक्त उपदान एवं कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि स्कीम, 1976 को मंदित करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम अतिरिक्त उपदान एवं कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि स्कीम, 1976 के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में अनुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम अतिरिक्त उपदान एवं कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि स्कीम, 1976 के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम अतिरिक्त उपदान एवं कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि स्कीम, 1976 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम में कम है तो कर्मचारी को उस वंश में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में वानों रकमों के बराबर रकम का सदाय करेगा।

8. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम अतिरिक्त उपदान एवं कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि स्कीम, 1976 के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और वहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, अतिरिक्त उपदान एवं कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि, स्कीम, 1976 के, जिसे स्थापन पहले अपन, चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम अतिरिक्त उपदान एवं कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि स्कीम, 1976, इसका प्रशासन करने में असफल रहता है और स्कीम को व्ययगत हो जाने विया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा भ्रष्टाचार के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की वंश में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व, नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम अतिरिक्त उपदान एवं कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि स्कीम, 1976 से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर मूनिष्वत करेगा।

[संख्या एम-35014/85/61-पां एफ-2 (एम एस-4)]

New Delhi, the 18th May, 1985

S.O. 2426.—Whereas Messrs. The Maharashtra State Road Transport Corporation, Maharashtra Vahatak Bhavan, Dr. Anandrao Nair Marg, Bombay-8 (MH/1255) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2B) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the regular employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Maharashtra State Road Transport Corporation Additional Gratuity-cum-Employees' Deposit Linked Insurance Fund Scheme, 1976 in the nature of Life Insurance which are more favourable under the Employees' than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2B) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the regular employees of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Maharashtra State Road Transport Corporation Additional Gratuity-cum-Employees' Deposit Linked Insurance Fund Scheme, 1976 including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Maharashtra State Road Transport Corporation Additional Gratuity-cum-Employees' Deposit Linked Insurance Fund Scheme, 1976, and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employee.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Maharashtra State Road Transport Corporation Additional Gratuity-cum-Employees' Deposit Linked Insurance Fund Scheme, 1976 and pay necessary premium in respect of him.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Maharashtra State Road Transport Corporation Additional Gratuity-cum-Employees' Deposit Linked Insurance Fund Scheme, 1976 appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefits available under the Maharashtra State Road Transport Corporation Additional Gratuity-cum-Employees' Deposit Linked Insurance Fund Scheme, 1976 are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Maharashtra State Road Transport Corporation Additional Gratuity-cum-Employees' Deposit Linked Insurance Fund Scheme, 1976 if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Maharashtra State Road Transport Corporation Additional Gratuity-cum-Employees' Deposit Linked Insurance Fund Scheme, 1976, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Maharashtra State Road Transport Corporation Additional Gratuity-cum-Employees' Deposit Linked Insurance Fund Scheme, 1976, as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay its contribution to the Maharashtra State Road Transport Corporation Additional Gratuity-cum-Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 and the scheme is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of contribution and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Maharashtra State Road Transport Corporation Additional Gratuity-cum-Employees' Deposit Linked Insurance Fund Scheme, 1976, the employer shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of the claim complete in all respects."

[No. S-35014/85/81-PF-II(SS IV)]

का. प्र. 3427—मैसर्स क्रोप ट्रैन्सपोर्ट प्रोपर्टीज लिमिटेड, डी-31/1, इंडस्ट्रियल एरिया, मेरठ रोड, भाजियाबाद (यू.पी./6904) (जिसे इससे उसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इससे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का भुगतान किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की मासिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निशेष सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

3. उक्त स्थापन के मध्य में निर्वाजन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायस्क, उत्तर प्रदेश को ऐसी शिवरनियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निनिश्चित करें ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारा का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संशय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (अ) के खंड (ब) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिनके अंतर्गत लेखाधारी का रखा जाना, विवरणियां का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाधारी का अंतरण निरीक्षण प्रभारा सदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब तक उन्में संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई एमा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का संचालन करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदा बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदा में समुचित रूप से वृद्धि का ज्ञान की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक न तुल्य हो जाय उक्त स्कीम के अधीन अंतर्भूत है।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदाय रकम उस स्कीम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संशय है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में वापस रकमों के अन्तर के अंतर रकम का सदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां विना संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देन में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तिपूर्वक अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम का उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पत्रों में अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों का प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्यक्त हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निशानिया या विधिवत वारिसों का जो यदि यह छूट न हो गई होता तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने वाले फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संघ में नियोजक, इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु पर उसके हस्ताक्षर नाम निर्देशितियां विधिवत वारिसों का बीमाकृत रकम का सदाय तत्पश्चात् में और प्रत्येक

दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/114/85-एसएस-4]

S O 2427—Whereas Messrs Crop Health Products Private Limited, D-31/1, Industrial Area, Meerut Road, Ghaziabad, (UP/6904) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1979 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5 Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner

shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption is liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/114/85-SS-IV]

का.सं. 2428 —मैसर्स प्रोप्रेटिव इंश्योरेंस लिमिटेड मशीन टूल्स, 12/4, जी.टी. रोड, साहिवाबाद, (ए.पी./5451) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी दृष्टक अधिभार या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निषेध सहस्र बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तम्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐत लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निश्चित करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निश्चित करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मूद्रम बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वांछित आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदा में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात का ह्रास हुआ हो, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में पदर हाना, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो निराश्रित कर्मचारी के विधिवत वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुसंधान के बिना नहीं किया जाएगा और अहाँ किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्राशस्तित भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को घटना वृत्तिकोण स्पष्ट करने को युक्तिपुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किस कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में अमफल रहता है, और पाणिनी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिरिक्त की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रवर्तन होने बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कदार नाम निर्देशितियों/विधिवत वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय करवाना से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/113/85-एस एस-4]

S.O. 2428.—Whereas Messrs Progressive Instruments and Machine Tools, 12/4 G. F. Road, Sanibabad, Ghazabad (UP) 5451) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhance, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014/113/85-SS.IV]

नई दिल्ली 20 मई, 1985

का.आ. 2428.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गेट दास इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, नं० 51, एन एम एम. रोड, अमीनजीकराय, मद्रास-29 नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम/35019 (214)/85-एम एस-2]

New Delhi, the 20th May, 1985

S.O. 2429.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shet-Dass Engineers (P) Limited No. 51, N.M.M. Road Aminjikarai, Madras-29 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(214)/85-SS.II]

का.आ. 2430—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तुफलीन (इंडिया) लिमिटेड, 147 कारापकम विलेज, मद्रास-600096, तमिलनाडु, नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम-35019 (186)/85-एमएस-2]

S.O. 2430.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Tuffin (India) Limited, 147, Karapakkam Village, Madras-600096, Tamil

Nadu have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(186)/85-SS-II]

का.आ. 2431—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुपर इंजीनियर्स लिमिटेड, मोटर हाउस, 1238, त्रिची रोड, कोयम्बटूर-641018, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(194)/85-एसएस-2]

S.O. 2431.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Super Engineers Limited, Motor House, 1238, Trichy Road, Coimbatore-541018, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(194)/85-SS-II]

का.आ. 2432—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भुवनेश्वरी कार्पोरेशन, 84 एम.के.एन. रोड, अलंदूर, मद्रास-32, और 14/15, ओल्ड ट्रंक रोड, मद्रास स्थित 'मावा कुरिच' नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(192)/85-एसएस-2]

S.O. 2432.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bhuvaneshwari Corporation, 84, M. K. N. Road, Alandur, Madras-32 including its factory at 14/15, Old Trunk Road, Madras have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(192)/85-SS-II]

का.आ. 2433—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फोम डेले (प्रा) लिमिटेड, नं० 8, पालुनोम रोड, मद्रास-2, तमिलनाडु 211 GI/85-20

और उसकी शाखा 1-2-54/7, दोमलगुडा, गगामहल, हैदराबाद-29 सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(191)/85-एसएस-2]

S.O. 2433.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Foam Dale (Private) Limited No. 8, Pattollos Road, Madras-2, Tamil Nadu including its Branch Office at No. 1-2-54/7, Domal-Guda, Gagamahal, Hyderabad-29 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(191)/85-SS-II]

का.आ. 2434—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दो मानावालाकुरिची एग्रीकल्चरल सर्विस को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., मानावालाकुरिची, पोस्ट, के.के. डिस्ट्रिक्ट और उसकी दो शाखाएँ—1, मानावालाकुरिची डिपो, 2, चिनाविलाई डिपो सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(190)/85-एसएस-2]

S.O. 2434.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Manavala-Kurichy Agricultural Service Co-operative Society Ltd., Manavala Kurichy Post, K. K. District, Tamil Nadu including its branches at (1) Manavala-Kurichy Depot (2) Chinnavillai Depot, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(190)/85-SS-II]

का.आ. 2435—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मिस्मा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, 56, केथेड्रान रोड, मद्रास-600086, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एन-35019(183)/85-एमएस-2]

S.O. 2435:—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sidma Press Private Limited, 56, Cathedral Road, Madras-600086, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(188)/85-SS-II]

का.आ. 2436—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड, एससीओ नं० 49-50, सेक्टर 26, मध्या मार्ग, चण्डीगढ़ और इसकी शाखा जितवाल कालन, तेह, मलरकोटला, कम्बारा संगरूर (पंजाब) नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अधिव्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एन-35019(187)/85-एमएस-2]

S.O. 2436:—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Steel Strips Limited S.C.O. No. 49-50, Sector-26 Madhya Marg, Chandigarh including its branch at Jitwal Kalan, Teh, Malerkotla, District Sangrur (Punjab) have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(187)/85-SS-II]

का.आ. 2437—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स के.एन.का.लेबर कान्ट्रैक्टर, प्लॉट नं० 61, नं० 4, पिलायर कोल 5थ स्ट्रीट, एक्कादुथंगल, गुन्दी, मद्रास-32 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अधिव्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एन-35019(193)/85-एमएस-2]

S.O. 2437:—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs K. Renuka, Labour Contractor, Plot No. 61, No. 4, Pillayar Koll 5th Street, Ekkaduthangal, Guindy, Madras-32 have agreed that

the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(193)/85-SS-II]

का.आ. 2438—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चम्पेगु इंडिया लिमिटेड हाउस 82, डॉ. एन्नी बेसान रोड, वर्ली, बम्बई-400018 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अधिव्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एन-35019(3)/85-एमएस-2]

S.O. 2438:—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Champaque India Ltd. Indage House, 82, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(3)/85-SS-II]

का.आ. 2439—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर.एस. कन्स्ट्रक्शन, 160, जी.ए. रोड, मद्रास-600021 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अधिव्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एन-35019(310)/85-एमएस-2]

S.O. 2439:—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs R. S. Construction, 160, G. A. Road, Madras-600021, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(210)/85-SS-II]

का.आ. 2440—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वैणाल रसाइट इंजिनरी, 17-1-211/1, मैराबाद हैदराबाद, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अधिव्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एन-35019(224)/85-एस.एस.-2]

S.O. 2440.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vaishal Allied Industries, 17-1-211/1, Saidabad, Hyderabad have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(224)/85-SS-II]

कां०आ० 141—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैमर्स वेड्डा प्रैक्टिसिंग मिल्स लि०, पुनामाल्ली हाई रोड, परियमेट, मद्रास-3 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एन-35019(223)/85-एस.एस.-2]

S.O. 2441.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Padma Petroleum Agency, 30, Poonamallee High Road, Periamet, Madras-600003 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(223)/85-SS-II]

कां०आ० 142—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैमर्स डॉ० राजावन्ताम हॉस्पिटल, 94, विवेकानन्द रोड, कोयंबटूर-9 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एन-35019(216)/85-एस.एस.-2]

S.O. 2442.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dr. Rajarajam Hospital 94, Vivekananda Road, Coimbatore-641009 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. 35019(216)/85-SS-II]

कां०आ० 143—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैमर्स पी० डेक्कन को० स्पिनिंग मिल्स एम्प्लाइज को० आर० क्रेडिट सोसाइटी लि० उच्चकरंजी जिला काल्हापुर नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एन-35018(5)/85-एस.एस.-2]

S.O. 2443.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Deccan Co-op. Spinning Mills Employees Co-op. Credit Society Ltd., Ichalkaranj District, Kolhapur have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(5)/85-SS-II]

कां०आ० 144—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैमर्स श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 33, बिप्लाबी राश बिहारी बोस रोड, कलकत्ता-1 और शाखाएँ पांच 1 हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश, 2 भञ्जपुरम, आंध्र 3 जमशेदपुर, बिहार, 4 मद्रास और 5 बम्बई-60 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एन-35017(55)/85-एस.एस.-2]

S.O. 2444.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sree Ganesh Transport Corporation 33, Biplabi Rash Behari Bose Road, Calcutta-I and its five Branches at (1) Hyderabad (2) Ichhapuram (A.P.) (3) Jamshedpur, Bihar (4) Madras (5) Bombay have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(55)/85-SS-II]

कां०आ० 2445—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैमर्स मोर्न ट्रांसपोर्ट एजेंसी लिमिटेड कोर्ट रोड, पोस्ट आफिस सिलीगुड़ी, डिस्ट. दार्जिलिंग (वेस्ट बंगाल) नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य

निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं. एस-35017(56)/85-एसएस-2]

S.O. 2445.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Modern Typewriter Agency, Hill Cart Road, P.O. Siliguri District Darjeeling (West Bengal) have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(56)/85-SS-II]

नई दिल्ली, 21 मई, 1952

का. आ. 2446.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स डा. अग्रवाल आई इंस्टीट्यूट 13 कैथेड्रल रोड, मद्रास-86। नामक स्थापना के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं. एस-35019(215)/85-एसएस-2]

New Delhi, the 21st May, 1952

S.O. 2446.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dr. Agarwal's Eye Institute, 13, Cathedral Road, Madras-86 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(215)/85-SS II]

का. आ. 2447.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स कामला एजेंसीज नं. 1, बालाकृष्ण स्ट्रीट तोल्ड आरी, मद्रास-600081, तमिलनाडु नामक स्थापना के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं. एस-35019(195)/85-एसएस-2]

S.O. 2447.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kamala Agen-

cies, No. 1, Balakrishna Street, Toluidare, Madras-600081, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(195)/85-SS-II]

का. आ. 2448.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स खैतान लेस्ट्रीकल लिमिटेड, प्लॉट नं. 14, सेक्टर 6, फरीदाबाद और उसका रजि. कार्यालय 7, कोटिया लैन्ड, कलकत्ता-29। नामक स्थापना के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं. एस-35019(196)/85-एसएस-2]

S.O. 2448.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Khaitan Electricals Limited Plot No 14, Sector-6 Faridabad including Regd. office at 7, Leyda Lane, Calcutta-29 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(196)/85-SS-II]

का. आ. 2449.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड स्वर्ण विला, बी-6, कबीर मार्ग, शान्ति पार्क, जयपुर और उसकी कोटा, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, दुर्गापुर, अलवर, अजमेर, मन्डोर, मिर्गोही, बलारुद, चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर में स्थित शाखा नामक स्थापना के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं. एस-35019(197)/85-एसएस-2]

S.O. 2449.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajasthan State Seeds Corporation Limited Swarn Village, B-6, Kabir Marg, Bani Park, Jaipur including its branches at Kota, Suratgarh, Sriganganagar, Durgapura, Alwar, Mandore, Sohi Bharatpur, Chittorgarh and Udaipur have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(197)/85 SS II]

का० भा० 2450—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सत्या मैकेनिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, चारमिनार, मिगरेट फेक्टरी रोड, अहमदाबाद, हैदराबाद नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(198)/85-एसएस-2]

S.O. 2450.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Satya Mechanical Works Private Limited Charminar Cigarette Factory Road, Azamabad, Hyderabad have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(198)/85 SS II]

का० भा० 2451—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गोपुराम एजेंसीज 377, सूर्यानारायण स्ट्रीट, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(199)/85-एसएस-2]

S.O. 2451.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gopuram Agencies, 377, Surya Narayana Street, Tondiarpet, Madras, 600081, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(199)/85-SS-II]

का० भा० 2452—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी संडापुर मिक्स प्रोड्यूसर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, टी पी डी-14 मेलपती (पोस्ट) गुडियाथम (तालुक), तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(200)/85-एसएस-2]

S.O. 2452.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Sendathur Milk Producers Co-operative Society Limited, T.P.D. 14, Mailpatti (Post) Gudiyatham (Taluk) Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(200)/85-SS II]

का० भा० 2453—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजीन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी, नं० 8 पातुल्लोस रोड, मद्रास-2, तमिलनाडु और उसकी शाखा 3, क्लब हाउस रोड, मद्रास-2 सहित नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(201)/85 एस एस-2]

S.O. 2453.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajind Trading Company No. 8, Patullos Road, Madras-2, Tamil Nadu including its branch at No. 3, Club House Road, Madras-2 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(201)/85-SS-II]

का० भा० 2454—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जी डी. नेडू चेरीटीज, अवनाशी रोड, कोयंबटूर-18, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(202)/85-एस एस-2]

S.O. 2454.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. G.D. Naidu Charities, Avanasashi Road, Coimbatore-641018, Tamil Nadu have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(202)/85-SS-II]

का० आ० 2455.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माटो भीजरमूटिक लिमिटेड, 105, डॉ० राधा कृष्णन सालाई, मेलापोर, मद्रास-600004, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स० एम-35019(203)/85-एमएस-2]

S.O. 2455.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Auto Measurematic Limited, 105, Dr. Radhakrishnan Salai Mylapore, Madras-600004, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(203) 85 SS-II]

का० आ० 2158.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कारथी फायर वर्क्स सर्वेसो० 1269, तथा 1271, अनूपन कुलुम विलेज, मिवा-काशी तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स० एम-35019(204)/85-एमएस-2]

S.O. 2456.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Karthi Fire Works, Survey No. 1269 & 1271, Anupan Kuluam Village, Sivakasi, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(204) 85-SS-II]

का० आ० 2457.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एगोसी फुड्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, 8, राघव वीरा एवेन्यू, पोम गार्डन, मद्रास 86 तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स० एम-35019(205)/85-एमएस-2]

S.O. 2457.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Agro Sea Foods Service Private Limited 8, Reghava Veera Avenue, Poes Garden, Madras 600086, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(205) 85-SS II]

का० आ० 2158.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि थंजावूर टेक्सटाईल्स एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, वाल्लम रोड, थंजावूर-5, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स० एम-35019(206)/85-एमएस-2]

S.O. 2458.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Thanjavur Textiles Employees Co-operative Stores Ltd, Vallam One Road, Thanjavur-5, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(206) 85-SS II]

का० आ० 2459.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गियोसोर्स (इंडिया) लिमिटेड, न० 147, कारापक्कम विलेज, मद्रास-600096, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स० एम-35019(207)/85-एमएस-2]

S.O. 2459.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Geosource (India) Limited, No. 147, Karapakkam Village, Madras-600096, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(207) 85-SS-II]

का. आ. 2460.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंदुप्रियम कार्पायन्स लिमिटेड, 85, सेक्टर-6, फरीदाबाद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[मं. एम-35019 (212)/85-एम. एम.-2]

S.O. 2460.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Khatan Industrial Complex Limited 85, Section-6, Faridabad in India its Registered office, at 7 Keyatala Lane, Calcutta-700029 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(212)/85 SS II]

का. आ. 2461.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि डा. सुदर्शन चक्रवर्ती भौमोरियल सेंटर फार मेडिकल रिसर्च ट्रीटमेंट पी-198, गुलटाङ्गा मेन रोड, सी. आर्. टी. स्कीम-7, एम, कलकत्ता-67 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[मं. एम-35017(57)/85-एम. एम.-2]

S.O. 2461.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dr. Sudarsan Chakrabarti Medical Centre For Medical Research and Treatment P-198, Ultradanga Main Road, C.I.T. Scheme VII-M Calcutta 67 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(57) 85-SS-II]

का. आ. 2462.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गमंडी इंस्ट्रुमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स प्रा. लि. मोहन बागन लैन्, कलकत्ता-700004 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[मं. एम-35017 (59)/85-एम.ए.ए.-2]

S.O. 2462.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs S. D. Instruments and Equipments 21/D Mohan Bagan Lane, Calcutta-700004, have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund, and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(59)/85-SS-II]

का. आ. 2463.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अनजान कनस्ट्रक्शन 114, एलियोट रोड, कलकत्ता-16, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[मं. एम-35017(60)/85-एम.ए.ए.-2]

S.O. 2463.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Anjan Construction 114, Elliot Road Calcutta-16 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(60)/85-SS-II]

का. आ. 2464.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साहा ब्रादर्स बीडी ब्रदर्स, प्रा. लि. धुलिया, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[मं. एम-35017 (61)/85-एम.ए.ए.-2]

S.O. 2464.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Saha Brothers Birt Works P.O. Dhulivan Dist. Murshidabad, West Bengal have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(61)/85-SS-II]

का. आ. 2463.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेरीडियन एडवर्टाइजिंग प्रा. लि. पी. 117, सी.आई.टी. रोड, कलकत्ता 14, नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[नं. एम-35017 (58)/85-एसएस-2]

S.O. 2465.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Meridian Advertising Private Limited, P-117 C.I.T. Road, Calcutta-14 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35017(58) 85-SS-II]

नई दिल्ली, 22 मई, 1985

का. आ. 2466 :— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मिनाशी इंडस्ट्रीज, 141, सेलम रोड, नानाकल-63700, सेलम जिला नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[नं. एस-35019(211)/85-एसएस-2]

New Delhi, the 22nd May, 1985

S.O. 2466.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Meenashi Industries 141, Salem Road, Namkkal-637001, Salem DT. have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35019(211)|85-SS-II]

का. आ. 2467 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कानासाबाती कोओपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., पी-93, मो.आई.टी. रोड, एकीम-65, एम (इसरी मंजिल) कलकत्ता-54 और इसकी शाखाओं में बारजोडा स्थित शाखाएँ नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[नं. एम-35017(62)/85-एसएस-2]

S.O. 2467.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kangsabati Co-operative Spinning Mills Ltd. P-93, C.I.T. Road, Scheme VI-M(2nd Floor) Calcutta-54 including its Panchat Borjora in Bankura, district have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(62)|85-SS-II]

का. आ. 2468 :— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेरज पार्ज गार्डन्स, जी-4, एस., भाकछा, काथोनी एस.वी. रोड, अंधेरी (वेस्ट), बम्बई-58, नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[नं. एस-35018 (4)/85-एसएस-2]

S.O.2468.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Merz Perz Gardens, G-4, S. Bharucha Colony, S. V. Road Andheri (West) Bombay-58, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(4)|85-SS-II]

का. आ. 2469 :— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि डी. डी. 9, वा उठानगरापी कोपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड, उठानगरापी पोस्ट धरमपुरी कच्चा और इसकी शाखाएँ (1) उठानगरापी, 2. कालवी और 3. सिगरापटी. नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[नं. एस-35019(217)/85-एसएस-2]

S.O. 2469.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs D.D. 9, the Uthangarai Co-operative Marketing Society Limited, Uthangarai (Post) Dharam-puri Distt. including its branches at (1) Uthangarai (2) Kaslavi and (3) Singarapettai have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(217)/85-SS-II]

का. आ. 2470 :— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आरएमपी, इंडस्ट्रीज, एन.एस. आर. आर. रोड गार्डबाबा मिशन पोस्ट, कोयंबटूर-11. नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019 (220)/85-एस.एस.-2]

S.O. 2471.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Aremppee Industries, N.S.R. Iyengar Road, Saibaba Mission Post, Coimbatore-11, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(220)/85-SS-II]

का. आ. 2471 :— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कार्टा प्रिन्टर्स न 192, 4, फ्रांस. के. एम. गार्डन, लालबाग, रोड बंगलूर-27. नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019(221)/85-एस.एस.-2]

S.O. 2471.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of

the employees in relation to the establishment known as Messrs Carto Prints No. 192, IV Cross, K. S. Garden, Lalbagh Road, Bangalore-27, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(221)/85-SS-II]

का. आ. 2472 :— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टार एग्रीकल्चर सर्विसेस कोआपरेटिव सोसाइटी, थिरुवत्तार पोस्ट, कन्याकुमारी कस्बा. नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(219)/85-एस.एस.-2]

S.O. 2472.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employee in relation to the establishment known as Messrs Attoor Agricultural Service Co-operative Society, Thiruvattar Post, Kanyakumari Distt. have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(219)/85-SS-II]

का. आ. 2473 :— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर. बालामुन्नय्यन, टैक्सटाइल मैनुफैक्चरर, 345-बी, सेलम मेन रोड, कोमरापालायम, पो. आ. (वाया) भवानी, सेलम जिला नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(218)/85-एस.एस.-2]

S.O. 2473.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employee in relation to the establishment known as Messrs R. Bala Subramaniyam, Textile Manufacturer, 345-B, Salem Main Road, Komarapalayam P.O. (Via) Bhavani, Salem Dt. have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(218)/85-SS-II]

का. आ. 2474.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स नेट वर्क कम्युनिकेशन सिस्टम प्रा. लि. 38, कम्युनिटी सेंटर बसंत लोक, वसन्त बिहार, नई दिल्ली-110057 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019(209)/85-एस. एस.-2]

S.O. 2474.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employee in relation to the establishment known as Messrs Network Telecommunication Systems Private Limited 38, Community Centre Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35019(209)]85 SS II]

का. आ. 2475.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स शालीमार थियेटर, तिलकनगर, मैसूर-570015, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019(226)/85-एस. एस.-2]

S.O. 2475.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employee in relation to the establishment known as Messrs Shalimar Theatre, Tilaknagar, Mysore-570015 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(226)]85-SS-II]

का. आ. 2476.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स अमर काफी प्लांटेशन बालपाराय पोस्ट, वाया पोलाची कोम्बेटूर कस्बा नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(225)/85-एस. एस.-2]

S.O. 2476.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employee in relation to the establishment known as Messrs Amar Coffee Plantation, Valparai-Post, Via, Pollachi, Coimbatore District have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds

and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(225)]85-SS-II]

का. आ. 2477.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स एन. एन. 36, रामनन्द कस्बा, फिशरमेन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, वेल्पट्टीनम पोस्ट रामानाथापुरम तथा चेन्नी और पूम्बन स्थित इसकी शाखाया नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019 (213)/85-एस.एस.-2]

S.O. 2477.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employee in relation to the establishment known as Messrs N. N. 36 Ramnand Dist. Fisherman Co-Operative Federation Limited Velipattinam P.O. Ramana'hapuram including its branches at Tondi and Pomban, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. 35019(213)]85-SS III]

का. आ. 2478.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स टारगेट टेक्स्टाइल, 42, मूर स्ट्रीट, द्वितीय फ्लोर, मद्रास-1 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (208)/85-एस. एस.-2]

S.O. 2478.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employee in relation to the establishment known as Messrs Target Textiles 42, Moore Street, 2nd Floor, Madras-1 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(208)]85-SS-II]

नई दिल्ली, 23 मई, 1985

का. आ. 2479.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स शक्ति मुरुगन ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि., 15/1, मिट्टूपात्तायम रोड, कोम्बेटूर-641043 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि

श्रीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(233)/85-एस एस.-2]
New Delhi, the 23rd May, 1985

S.O. 2479—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employee in relation to the establishment known as Messrs Sakthi Murugan Transports (P) Ltd., 15/1, Meitupalayam Road, Coimbatore 641045 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35019(233)/85-SS.II]

का. आ. 2480—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उप पैरा (i) के खंड (ख) के अनुसूचना में भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 अक्टूबर 1984 में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3321, तारीख 1 अक्टूबर, 1984 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 6 के गामा की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

6. श्री ई. जगन्नाथ राव,
संयुक्त प्रबंधक,
के. सी. पी. लिमिटेड, वुय्यूर,
कृष्णा जिला आन्ध्र प्रदेश

[सं. बी-20012/9/78- पी. एफ.-II]

S.O. 2480.—In pursuance of clause (a) of sub-paragraph (1) of the paragraph 4 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, The Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation No.S.O.3321 dated 1st October, 1984, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 20th October, 1984, namely:—

In the said notification, for the entry against serial number 6, the following shall be substituted:

6. Shri.E.Jagannatharao,
Plant Manager,
The KCP Limited, Vuyuru,
Krishna Distric,
Andhra Pradesh.

[No.V.20012/9/78-PF.II]

का. आ. 2481.—मैसर्स की पैरीयार मैट्रल कोर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, 20/91 पैरियार रोड, ईरोड-638001 (टीएन 12402) (जिसे हमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे हमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अतिरिक्त या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निधेय सहायक बीमा—
211 GI/85—22

स्कीम, 1978 (जिसे हमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की विधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के मन्त्र में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणों प्रेषित करने के लिए कहा गया है कि वे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी भूमिगत प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निरीक्षण करें

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रयोगों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निरीक्षण करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रयोगों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य भाषा का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भार्गव्य जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी की उस वंश में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और अतः किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, अतः प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुविशुद्ध अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी गति में कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में

असफल रहता है, और पॉलिसी को व्ययगत हो जाना दिया जाता है तो छूट खूब की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संचय में किये गए किसी व्यक्तिकम की दिशा में उन नून सदस्यों के नाम निर्देशनियों या विशिष्ट वारिसों का जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने, बीमा फायदों के संचय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सदस्य में त्रिपोजक, इस स्कीम के अर्थात् आने वाले किये सदस्य का मृत्यु हो पर उनके हकदार नाम निर्देशनियों विशिष्ट वारिसों को बीमाकृत रकम का संचय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[मख्या एस-35014/125/85-एन एस-4]

S.O. 2481.—Whereas Messrs The Periyar Central Co-operative Bank Limited, 20/91, Periyar St. Erode-638001 (TN/12402) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section(3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members cover under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No.S-35014/125/85-SS-IV]

कांआ.2482—मैसर्स अम्प्रो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पी-5, अपल रोड, हैदराबाद (ए०पी०/3774), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संचय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप महबूद बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा

निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड(क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाता विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम, का सदाय, लेखाओं का प्रबंधन, निरीक्षण प्रभारों सदाय आवि भी है जोने वाले सभी व्यक्तों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद सम्बन्धन के सूचना पट्टे पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसका स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम मूलतः दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का सदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुभूत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हों।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदैव एकम उस एकम से कम है जो कर्मचारी का उस दशा में सदैव होता है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस/नाम निर्देशितों का प्रतिफल के रूप में दोनो एकमों के अन्तर्ग के बराबर एकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को सुनिश्चित करेगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम को जिसे स्थापन पहले अपना चुक है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों का प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम तारीख के भीतर या भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पारिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत की वशा में उस मूल सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विविध वारिसों को बीमाकृत एकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत एकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

S.O. 2482.—Whereas Messrs Ampro Food Products Private Limited, P-5 Uppal Road, Hyderabad, (AP/3774) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishment, or the benefits to the employee and this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12 Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect

[No S 35014/117/85-SS IV]

A K BHATTARAI, Under Secy

नई दिल्ली, 20 मई, 1985.

का आ 2483 -- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एयर इंडिया, बम्बई के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच प्रमुख में निविष्ट एक शिकायत, उक्त अधिनियम का धारा 13 में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण न 2 बम्बई के पचाट या प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4 मई 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2483.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No II, Bombay, as shown in the Annexure, in respect of a complaint under Section 33A of the said Act, filed by Shri Mohan Bir Singh, a workman of Air India, Bombay, which was received by the Central Government on the 8th May 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer
Complaint No CGIT-2/1 of 1985

Arising out of Reference No. CGIT-2/16 of 1984

PARTIES :

Shri Mohan Bir Singh

President,

Air India Cabin Crew Association

Complainant

VS.

1. Air India, Bombay

2. Capt D. Bose, Managing Director.

3. Shri J. Naegamvala, Deputy Director, In-flight Service.

Respondents

APPEARANCES

For the Complainant—Shri Anil Mohan

For the Respondents —Shri F. M. Kaka, Advocate

INDUSTRY : Air Lines —STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 15th April, 1985

AWARD

This is a complaint under Section 33A of the Industrial Disputes Act whereby the complainant, admittedly a protected workman, in the service of the Respondents is complaining of the breach of Section 33 especially sub-Section (3) on the allegation that during the pendency of the proceeding before this Tribunal the conditions of service applicable to the complainant were altered and that he is being punished.

2. All these contentions have been refuted by the management by their written statement who further plead that there remains no cause of action the complainant having been assigned flying duties effective from 22-2-1985.

3. In all probability because of this change the complainant is no longer interested in prosecuting the complaint and therefore filed a pursis whereby he wants to withdraw the complaint to which the management has no objection. In view of the development therefore the complaint no longer survives and hence disposed of.

Order accordingly.

M A DESHPANDE, Presiding Officer

[No. I-11025(4)/25-D-IIB]

नई दिल्ली, 22 मई, 1985

का आ 2484 -- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, बेलम्पाल्ली डिविजन न 1 के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबद्ध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7 मई, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 22nd May, 1985

S.O. 2484.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employees in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division No 1, and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th May, 1985

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD

PRESENT

Shri J Venugopala Rao Industrial Tribunal

Industrial Disputes No 39 of 1984

BETWEEN

The workmen of Singareni Collieries Company Limited
Bellampalli Division-I, Adilabad District

AND

MEMORANDUM OF COMPROMISE

The Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division-I, Adilabad District.

Hon'ble Sir,

The respondent Management and the Petitioner Workmen jointly submit the following Memorandum of Compromise.

APPEARANCES :

Sri T. Deva Raj, Senior Personnel Officer, S.C. Co. Ltd. Bellampalli for the Management. None present for Workmen.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by its Order No. L-22011(102)/82-D. III. B/D.IVB dated 7-7-84 has referred to this Tribunal the following issues for adjudication in the industrial dispute between the workmen and the Management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division-I Adilabad District.

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, in refusing to refer Shri Meraboina Gattu, Tyndal, Workshop, Bellampalli to the Age Determination Committee/Medical Board for assessing his age is justified? If not, to what relief he is entitled?"

2. The reference was registered by this Tribunal as Industrial Disputes No. 39 of 1984 and notices were sent to parties concerned.

3. A memo dated 4-3-1985 was filed by the Workmen and the management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division-II praying for terminating the reference in terms of the Settlement. The said Settlement was filed in the Tribunal by Sri T. Devraj, Senior Personnel Officer of the Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli. Since Reddy for the workmen had already signed the Settlement and the same was filed by the Personnel Officer of the Management, Sri Nagiah Reddy who is signatory to the Settlement is called absent inspite of notice served. Perused the compromise Settlement signed by the Workers representative also and satisfied that the same is signed bonafide.

4. After having gone through the terms of the Settlement it can be stated that it is just and proper and it is in the interest of both the concerned workmen & also the Management. Such proper and just settlements have to be accepted in order to see that cordial relationships between the workmen and the Management are maintained. Hence, in the circumstance, it is a fit case for passing the award in terms of the Settlement, especially when it is stated that Clause 4 of the terms of Settlement was already implemented.

5. Award is passed accordingly in terms of the settlement between the parties. Copy of the Settlement is herewith attached as part of the Award.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 29th day of April, 1985.

Sd -INDUSTRIAL TRIBUNAL.

Appendix of Evidence

NIL

3-5 83.

J. VENUGOPALA RAO
INDUSTRIAL TRIBUNAL
HARI SINGH, Desk Officer

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL
(CENTRAL) HYDERABAD

Hyderabad, 6th March, 1985

I. D. No. 39 of 1984

BETWEEN :

The workmen of Singareni Collieries Co. Ltd.,
Bellampalli Division-II—Petitioners.

AND

The Management of Singareni Collieries Co. Ltd.,
Bellampalli Division-II—Respondents.

1. The Central Government vide their Order dated 7-7-1984 referred the I.D., registered as I.D. No. 39 of 1984 before this Hon'ble Tribunal. The matter under reference is "whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in refusing to refer Shri Meraboina Gattu, Tyndal, Workshop, Bellampalli, to the Age Determination Committee/Medical Board for assessing his age is justified? If not, to what relief he is entitled?"

2. It is submitted that even prior to the referral of the above dispute for adjudication to this Hon'ble Tribunal, the Management arrived at a Settlement under Section 12(3) of I.D. Act on 28-11-1982 with the President, Vendur Coal Mines Labour Union, representing the workmen. It was agreed under the terms of the settlement supra to refer the case of Shri Meraboina Gattu, Tyndal, Workshop, Bellampalli, to the Age Determination Committee/Medical Board to assess his age as per the procedure laid down by the Joint Bipartite Committee for Coal Industry. The copies of Settlement dated 20-11-1982 as also the proceedings dated 29-11-1982 of the Age Determination Committee/Medical Board are submitted herewith.

3. In terms of the Settlement cited, Shri Meraboina Gattu was referred to the Age Determination Committee/Medical Board on 29-11-1982 and on review his age was determined as 38 years as on 29-11-1982.

4. The concerned workmen accordingly continued in service for two more years and retired with effect from 1-12-1984.

5. In view of the fact that the dispute under reference has already been settled mutually even before a reference is made to this Hon'ble Tribunal for adjudication, the Respondent Management as well as the Petitioners pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to terminate the reference.

Yours faithfully,

Sd/--

for Management,

Addl. Chief Mining Engineer,
Bellampalli Division-II.

Sd/--

for Workmen.

Bellampalli

Dated, 4-3-1985.

President

Tandur Coal Mines Labour
Union, Bellampalli.

नई दिल्ली, 20 मई, 1975

का. प्रा. 2485:—औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय), नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के धारा 38 की उपधारा (1) के अधिनियम, श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना स. सा. का. नि. 1126 तारीख 19 अक्टूबर, 1984 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 27 अक्टूबर, 1984 के पृष्ठ 2770-2771 पर प्रकाशित किया गया था और उन मन्त्र. व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से तम दिन के अन्तिम के समाप्ति पर या उसके पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे,

और उक्त राजपत्र 27 अक्टूबर, 1984 की जनता का उपपत्र प्रकाशित किया गया था।

और उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में जनता में प्राप्ति आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप में विचार कर लिया गया है।

अतः, अध. केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में:—

(क) नियम 75-ख में:—

(1) उप नियम (1) में, “उपधारा- (2)” शब्दों, कोष्ठको और अंक के स्थान पर “(उपधारा (3))” शब्द, कोष्ठको और अंक रखे जाएंगे और “उपधारा (4)” (शब्दों, कोष्ठको और अंक के स्थान पर “उपधारा (5))” शब्द, कोष्ठको और अंक रखे जाएंगे।

(2) उप-नियम (3) में “उपधारा (4)” शब्दों, कोष्ठको और अंक के स्थान पर “उपधारा (5)” शब्द, कोष्ठको और अंक रखे जाएंगे।

(ख) नियम 76क में:—

उप-नियम (1) में, “खण्ड (ग) के अधिन सूचना” शब्दों और कोष्ठको के स्थान पर “(के अधिन, यथास्थिति, सूचना या आवेदन)” शब्द रखे जाएंगे और “उपधारा (3)” शब्दों, कोष्ठको और अंक के स्थान पर “उपधारा (4)” शब्द, कोष्ठको और अंक रखे जाएंगे।

(2) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा और उप नियम (3) और (4) को उप नियम (2) और (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

(3) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— “(3)” “संबंधित नियोजक, केन्द्रीय सरकार या ऐसे प्राधिकारी को, जिसे धारा 25-ड की उपधारा (1) के अधिन छंटनी की सूचना दी गई है या छंटनी की अनुज्ञा के लिए आवेदन दिया गया है, ऐसे और जानकारी देगा जो, यथा स्थिति, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकारी, यथा स्थिति नोटिस या आवेदन के बावत, निर्णय लेने के लिए आवश्यक समझे जब, कभी ऐसे प्राधिकारी द्वारा मांगी जाए, ताकि केन्द्रीय सरकार या प्राधिकारी धारा 25-ड की उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने अनुज्ञा या अनुज्ञा न देने का सूचना दे सके।

(ग) नियम 76ग में:—

उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“जैसे आवेदन के एक प्रति एक साथ स्थापन में कार्य कर रहे रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन (यूनियनों) के अध्यक्ष या अधिकारी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील के जाएंगे और इस संबंध में एक सूचना नियोजक द्वारा भेजा संबंधित कर्मचारियों के जानकारी के लिए स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर सहज दृश्य रूप से सूचना पट्ट पर या उस समय प्रदर्शित की जाएगी जब आवेदन केन्द्रीय सरकार को तामील किए जाएंगे।”

(2) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा और उप-नियम (3) और (4) को क्रमशः उप-नियम (2) और (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

(घ) प्रारूप-ग में “उपधारा (2)” शब्दों, कोष्ठको और अंक के स्थान पर “उपधारा (3)” शब्द, कोष्ठको और अंक और “उपधारा (6)” शब्दों कोष्ठको और अंक के स्थान पर “उपधारा (10)” शब्द, कोष्ठको और अंक रखे जाएंगे।

(ङ) प्रारूप-क “खण्ड (ग)” शब्दों और कोष्ठको के स्थान पर “खण्ड (ख)” पढ़ें।

(च) प्रारूप तख को हटा दिया जाएगा।

(छ) प्रारूप थक में, विद्यमान पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“4. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि कामबंदी के लिए अनुमति दे दिए जाने की दशा में, उस उपक्रम के प्रत्येक कर्मकार को जिसे उक्त धारा की 25-ग की उपधारा (8) लागू होती है, उस धारा में यथाविविधिष्ट प्रतिकार का सदाय किया जाएगा।”

(ज) फार्म थक का लोप किया जाएगा।

टिप्पणी:—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खण्ड 3, तारीख 10 मार्च, 1957 में पृष्ठ 1137-1159 पर अधिसूचना का. नि. प्रा. 770 तारीख 10 मार्च, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया जाए:—

- (1) अधिसूचना स. सा. का. नि. 141 तारीख 31-12-1967
- (2) अधिसूचना स. सा. का. नि. 1215 तारीख 12-12-1958
- (3) अधिसूचना स. सा. का. नि. 302 तारीख 23-4-1958
- (4) अधिसूचना स. सा. का. नि. 40 तारीख 31-12-1958
- (5) अधिसूचना स. सा. का. नि. 284 तारीख 31-1-1959
- (6) अधिसूचना स. सा. का. नि. 398 तारीख 21-3-1959
- (7) अधिसूचना स. सा. का. नि. 811 तारीख 3-7-1959
- (8) अधिसूचना स. सा. का. नि. 1151 तारीख 8-10-1959
- (9) अधिसूचना स. सा. का. नि. 1182 तारीख 19-10-1959
- (10) अधिसूचना स. सा. का. नि. 229 तारीख 22-2-1960
- (11) अधिसूचना स. सा. का. नि. 402 तारीख 31-3-1960
- (12) अधिसूचना स. सा. का. नि. 1220 तारीख 7-10-1960
- (13) अधिसूचना स. सा. का. नि. 857 तारीख 22-6-1961
- (14) अधिसूचना स. सा. का. नि. 1078 तारीख 4-8-1962
- (15) अधिसूचना स. सा. का. नि. 488 तारीख 16-3-1965
- (16) अधिसूचना स. सा. का. नि. 1253 तारीख 3-8-1966
- (17) अधिसूचना स. सा. का. नि. 908 तारीख 2-5-1967
- (18) अधिसूचना स. सा. का. नि. 1059 तारीख 30-5-1968
- (19) अधिसूचना स. सा. का. नि. 1283 तारीख 28-5-1969
- (20) अधिसूचना स. सा. का. नि. 1284 तारीख 28-5-1969

- (21) अधिसूचना स. सा. का. नि. 795 तारीख 5-6-1972
 (22) अधिसूचना स. सा. का. नि. 410 (अ) तारीख 13-9-1972
 (23) अधिसूचना स. सा. का. नि. 1151 तारीख 11-10-1974
 (24) अधिसूचना स. सा. का. नि. 931 तारीख 15-7-1975
 (25) अधिसूचना स. सा. का. नि. 111 (अ) तारीख 5-3-1976
 (26) अधिसूचना स. सा. का. नि. 1070 तारीख 28-7-1977
 (27) अधिसूचना स. सा. का. नि. 289 तारीख 2-3-1982
 (28) अधिसूचना स. सा. का. नि. 932 तारीख 18-8-1984

[फा. स. एस-65012/3/82-डी-1 (ए.)]

एस. एच. एस. अश्वर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th May, 1985

§.O. :—Whereas certain draft rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, were published as required by sub-section (1) of section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) at pages 2771-2772 of the Gazette of India, in part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 27th October, 1984, with the notification of the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour), No. G.S.R. 1126, dated the 19th October, 1984, inviting objections and suggestions from all persons, likely to be affected thereby, on or before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the official Gazette,

And, whereas, the said Gazette as made available to the public on the 27th October, 1984;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in the said draft have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, namely :—

(1) These rules may be called the Industrial Disputes (Central) (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957,-

(a) in rule 75 B,-

(1) in sub-rule (1), for the words, brackets and figure "sub-section (2)" the words, brackets and figure "sub-section (3)" shall be substituted and for the words, brackets and figure "sub-section (4)", the words, brackets and figure "sub-section (5)" shall be substituted;

(2) in sub-rule (3), for the words, brackets and figure "sub-section (4)", the words, brackets and figure "sub-section (5)" shall be substituted.

(b) in rule 76 A,-

(1) in sub-rule (1) for the words and brackets "under clause (c) of" the words, "or, as the case may be the application under" may be substituted, and for the words, brackets and figures "sub-section (3)", the words, brackets and figure "sub-section (4)" shall be substituted.

(2) sub-rule (2) shall be omitted and sub-rules (3) and (4) shall be re-numbered as sub-rules (2) and (3).

(3) for sub-rule (3), as so re-numbered, the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(3) The employer concerned shall furnish to the Central Government or the authority to whom the notice for retrenchment has been given or the application for permission for retrenchment has been made, under sub-section (1) of section 25-N, such further information as the Central Government or, as the case may be the authority considers necessary for arriving at a decision on the notice or, as the case may be, the application as and when called for by such authority so as to enable the Central Government or the authority to communi-

cate its permission or refusal to grant permission within the period specified in sub-section (4) of section 25-N";

(c) in rule 76C

(1) after sub-rule (1), the following shall be inserted namely :—

"A copy of such application shall be served simultaneously by registered post on the President or Secretary of registered trade union (s) functioning in the establishment and a notice in this regard shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board at the main entrance to the establishment for the information of all the concerned workmen at the same time when applications are served on the Central Government."

(2) sub-rule (2) shall be omitted and sub-rules (3) (4) shall be re-numbered as sub-rules (2) and (3) respectively;

(d) in Form O-3, for the words brackets and figure "sub-section (2)", the words, brackets and figure "sub-section (3)" and for the words brackets and figure "sub-section (6)", the words brackets and figure "sub-section (10)", shall be substituted.

(e) In Form PA, for the words and brackets "clause (c)" read "clause (b)".

(f) Form PB shall be deleted.

(g) in Form QA, for existing paragraph 4, the following shall be substituted, namely :—

"4. If we hereby declare that in the event of approval for the closure being granted, every workman in the undertaking to whom sub-section (8) of the said section 25-O applies shall be paid compensation as specified in that section."

(h) Form QB shall be omitted.

Note : Principal rules were published vide notification S.R.O 770, dated 10th March 1957 Gazette of India Extraordinary dated the 10th March 1957, Part II Section 3 pages 1137-1159

Subsequently amended by :—

- (i) Notification No. GSR 141 dated 31.12.1957,
- (ii) Notification No. GSR 1215 dated 12.12.1958,
- (iii) Notification No. GSR 302 dated 23.4.1958,
- (iv) Notification No. GSR 40 dated 31.12.1958,
- (v) Notification No. GSR 284 dated 31.1.1959,
- (vi) Notification No. GSR 398 dated 21.3.1959,
- (vii) Notification No. GSR 811 dated 3.7.1959,
- (viii) Notification No. GSR 1151 dated 8.10.1959,
- (ix) Notification No. GSR 1182 dated 19.10.1959,
- (x) Notification No. GSR 229 dated 22.2.1960,
- (xi) Notification No. GSR 402 dated 31.3.1960,
- (xii) Notification No. GSR 1220 dated 7.10.1960,
- (xiii) Notification No. GSR 857 dated 22.6.1961,
- (xiv) Notification No. GSR 1078 dated 4.8.1962,
- (xv) Notification No. GSR 488 dated 16.3.1965,
- (xvi) Notification No. GSR 1253 dated 3.8.1966,
- (xvii) Notification No. GSR 908, dated 2.5.1967,
- (xviii) Notification No. GSR 1059, dated 30.5.1968,
- (xix) Notification No. GSR 1283, dated 28.5.1969,
- (xx) Notification No. GSR 1284, dated 28.5.1969,
- (xxi) Notification No. GSR 795, dated 5.6.1972,
- (xxii) Notification No. GSR 410 (E) dated 13.9.1972,
- (xxiii) Notification No. GSR 1151, dated 11.10.1974,
- (xxiv) Notification No. GSR 931, dated 15.7.1975,
- (xxv) Notification No. GSR 11(E), dated 5.3.1976,
- (xxvi) Notification No. GSR 1070, dated 28.7.1977,
- (xxvii) Notification No. GSR 289, dated 2.3.1982,
- (xxviii) Notification No. GSR 932, dated 18.8.1984,

[F No. S-65012/3/82—D.1(A)]

S. H. S. TYFR, Under Secy.

